Seventh Series, Vol. XLII No. 9

Monday, December 5, 1983/
Agrahayana 14, 1905 (Saka)

Lok Sabha Debates

(Thirteenth Session)

सत्यमेव जयते

(Vol. XLII, contains Nos. 1-10)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi
Price- Rs 4.00

CONTENTS

	COLUMNS
No. 9, Monday, December 5, [1983/Agrahayana 14, 1905 (Saka)	
Oral Answers to Questions :	
*Starred Questions Nos. 162 *to* 165, 167 and 168	1—30
Written Answers to Questions :	30—292
Starred Questions Nos. 166 and 169 *to* 181	30—46
Unstarred Questions Nos. 1851 to 1905, 1907 to 1927, 1929 to 1939, 1941 to 2054, 2056 to 2078, 2080 and 2081	46—292
Correcting statement to US Q. No. 4495 dt. 22.8.83	292—298
Papers laid on the Table	298—305
Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	306
Reports of Study Tours	
Message from Rajya Sabha	306
Statement Re : Reported threat to Hindus in Punjab by Shri Jarnail Singh Bhindranwale,on December 1, 1983 at Amritsar ...	307—325
Shri P. C. Sethi	
Election to Committee	325—326
Animal Welfare Board	
Business Advisory Committee	326—329
Fifty-Third Report	
Bill Introduced—Public Financial Institutions (Obligation as to Fidelity and Secrecy) Bill	329—330
Matters under rule 377—	330—338
(i) Need to give alternative House sites to Scheduled Caste Families living in Chakdeo village in District Satara, Maharashtra	
Dr. Subramaniam Swamy	330—331
(ii) Need for a Committee to consider the problems arising out of the closure of Brick Kilns	
Shri Uma Kant Mishra	331
(iii) Unsatisfactory working of communication facilities in Amreli, District Gujarat	
Shri Navin Ravani	331—332

*The sign † mraked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

(iv) Non-payment of sugarcane arrears to cane growers in Eastern Uttar Pradesh

Shri Harikesh Bahadur ... ... 332—333

(v) Industrialisation of Saidpur constituency of Uttar Pradesh

Shri Rajnath Sonkar Shastri 333

(vi) Need for improving the working conditions of medical representatives

Dr. A. Kalanidhi 334

(vii) Demands of ticket checking staff of Indian Railways

Shri Ramavatar Shastri ... ... 334—335

(viii) Need for resolving the deadlock between management and staff of Canara Bank

Shri Satyasadhan Chakraborty 336

(iv) Need for financial assistance to complete on-going irrigation projects in Mirzapur

Shri Ram Pyare Panika ... ... 336—337

(x) Need for financial assistance and employment to people of Ghazipur in view of famine and floods in recent years.

Shri Zainul Basher. ... ... 337—338

Statutory Resolution *Re* : Disapproval of Tea (Amendment) Ordinance and Tea (Amendment) Bill— ... ... 338—376
381—389
426—428

Shri Krishna Kumar Goyal ... ... 338—342

Motion to Consider—

Shrimati Ram Dulari Sinha ... ... 343—344

Shri Ananda Pathak 345 348

Shri Sontosh Mohan Dev ... ... 348—353

Shri Era Mohan ... ... 353—356

Shri Xavier Arakal ... ... 356—360

Shri Ram Lal Rahi ... ... 360—364

Shri Mool Chand Daga ... ... 364—367

Shri Amar Roy Pradhan ... ... 367—371

Shri Girdhari Lal Vyas ... ... 371—376

Clauses—2, 3 and 1

Motion to Pass—

Shrimati Ram Dulari Sinha ... ... 381—389

Shri Ram Lal Rahi ... ... 427—428

Shri Ananda Pathak 428

Shri Mohammed Ismail 428

Statement *re* Commonwealth Heads of Government Meeting held in New Delhi from 23rd to 29th November, 1983. ... ... 376—381

Shri P. V. Narasimha Rao

	COLUMNS
Statement *re* New Oil Strike in Godavari Offshore	389—391
Shri Gargi Shankar Mishra	
Discussion on the Statement *re* Situation Arising out of Reported Training Camps of Extremists of Punjab in Neighbouring Areas of the State. ...	391—426 449—504
Shri Harish Rawat	391—396
Prof. Ajit Kumar Mehta	396—402
Shri Zainul Basher	402—408
Dr. Subramaniam Swamy	408—420
Shrimati Gurbrinder Kaur Brar	421—426
Shri Rajesh Kumar Singh	451—456
Shri G. L. Dogra	456—465
Shri Suraj Bhan	465—473
Shri P. K. Kodiyan	473—474
Shri Harikesh Bahadur	475—477
Shri Abdul Rashid Kabuli	477—488
Shri P. Namgyal	489—498
Shri Ram Vilas Paswan	498—501
Shri P. C. Sethi	501—504
Half-an-Hour Discussion	429—449
Free Medical Help to Poor	
Shri Ram Vilas Paswan	429—437 447—449
Shri B. Shankaranand	437—440
Shri Harikesh Bahadur	441—442
Shri Mool Chand Daga	443—445
Shri Rajesh Kumar Singh.	445—447

LOK SABHA

Monday, December 5, 1983/Agrahayana 14, 1905 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आबंटन

*162. **श्री निहाल सिंह :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी योजना के अन्तर्गत कितने लोगों के नाम पंजीकृत किये हैं और इस योजना के अन्तर्गत कितना धन एकत्र किया है ;

(ख) इन लोगों को फ्लैट और मकान कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "हुडको" तथा रोहिणी योजना के अन्तर्गत एकत्र किया गया सारा धन खर्च कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) 82,384 persons stand registered by D.D.A. under the Rohini Scheme. A sum of Rs. 2114.651 lakhs has been collected against registration under the Scheme.

(b) The Rohini Scheme is basically a Residential Scheme for allotment of plots. It does not envisage allotment of built up houses/flats to persons registered thereunder.

(c) The Delhi Development Authority has reported that the money realised under the HUDCO and Rohini Schemes has contributed towards the massive investment made in developmental and construction works by the Authority.

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा जो फीगर्स दी गई हैं, वे कुछ सही मालूम नहीं पड़ती है। जैसा कि अखबारों में आया है कि एक लाख 75 हजार व्यक्तियों ने इस स्कीम में रजिस्टर करवाया है और उनसे करीब सौ करोड़ रुपए से भी अधिक रुपया वसूल किया गया है और सारा रुपया खर्च कर दिया गया है। पांच वर्ष में सबको प्लाट देने का वायदा किया है, लेकिन अभी तक केवल दो ड्रा निकाले हैं, जिसमें बीस हजार व्यक्तियों को प्लाट दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि 90 प्रतिशत लोग अभी भी बाकी हैं और जब तक उनको देंगे तब तक कीमत दुगनी हो जाएगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एप्लीकेशन लेते वक्त जो कीमत घोषित की गई थी, क्या उसी कीमत पर आवंटित करते वक्त प्लाट देने का कष्ट करेंगे ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir it is not correct to say that the number of registered persons is over 1.75 lakhs. As stated by my hon. colleague, the number of registered persons is 82,384; out of that some people withdrew their applications and an amount of Rs.27.82 lakhs was refunded to those people. As you know Rohini is a very ambitious project, perhaps

the largest colony in this type of scheme. It is not easy to start construction of site without having all the infrastructure needed in a developed colony. Roads, electricity supply, water supply, sewerage, etc. have to be there. If it has taken time, it is because of these infrastructures. Now that we have crossed that st age and we have been able to lay the infrastructure, I think, within given time Rohini will be completed. Therefore he need not have any apprehension.

About the price it has been given out by DDA when it was registered, and it will be the same as decided on the date of registration.

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करते वक्त दस प्रतिशत ओवरसीयर, 30 प्रतिशत ठेकेदार, 10 प्रतिशत इंजीनियर और 20 प्रतिशत अधिकारी इस प्रकार 60 प्रतिशत तो ये सब मिलकर खा जाते हैं। इस प्रकार 50 हजार में मकान बनता है तो एक लाख रुपया वसूल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रतिशत बताया है, वह करीब 90 प्रतिशत हो गया, बाकी बचा कितना।

श्री निहाल सिंह : इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे गारन्टी देंगे कि पचास साल के अन्दर यदि मकान गिर जाता है तो उसको मुफ्त में मकान की मरम्मत करवायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : यह बड़ी असंभव सी बात है। ईश्वर का भी प्रकोप हो सकता है। इसलिए इतनी लम्बी अवधि देना मेरे लिए संभव नहीं है। जो प्रतिशत माननीय सदस्य ने दिए हैं, वे तथाकथित हैं और उनके मन के बनाए हुए हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि रोहिणी प्रोजैक्ट समय पर पूरा होगा। प्रश्न के सी भाग में कहा गया है कि जो रुपया क्लैक्ट हुआ था, वह हमने विकास के कामों में लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास के जिन कामों में रुपया लगाया है, वह रोहिणी प्रोजैक्ट में लगाया है या कहीं और लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी की बात की है।

श्री नवल किशोर शर्मा : शिकायत यह है कि रोहिणी प्रोजैक्ट में देरी का कारण प्लानिंग की कमी है, साधनों और रुपयों का अभाव है। मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि रोहिणी प्रोजैक्ट किन कारणों से डिले हुआ है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दिल्ली के अन्दर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मकानों की व्यवस्था की जा रही है तथा कुछ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी जमीन दी गई है। जो एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन सोसाइटीज धन के अभाव में हैं, क्योंकि पाबन्दी यह लगाई हुई है कि सोसाइटीज पहले अपना हिस्सा खर्च करें, उसके बाद उनको कर्जा मिलेगा। इस पाबन्दी के कारण गरीब आदमी मकान नहीं बना सकेगा, क्योंकि पहले उसको एक साथ पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए क्या यह मन्त्रालय इस बात पर पुनर्विचार करेगा ताकि दिल्ली में जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वे भी बड़ी तादाद में मकान बना सकें।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि प्लानिंग की कमी है, इसलिये देर लगी है.....

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री बूटा सिंह : मैंने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि इतना बड़ा प्राजैक्ट शुरू करने से पहले जहां पर एक करोड़ के करीब लोग आबाद होने जा रहे हैं, कितनी सर्विसिज की जरूरत पड़ेगी आप उसका अन्दाजा लगा सकते हैं। एक प्लाण्ड हाउसिंग प्रोजैक्ट बनाने के लिए पहले से सड़क, टेलीफोन, बिजली, पानी, इत्यादि का इन्तजाम करना निहायत जरूरी है, अगर ऐसा इन्तजाम किए बगैर इजा-

जत दे देते तो वही हालत होती जो आम नान-डवेलप्ड एरियाज में होती है। सड़क बन जाती है तो उसके बाद टेलीफोन वाले खोद रहे हैं, सीवर वाले खोद रहे हैं—So before this, in these under developed areas, compact and planned methods of working go into the construction of the housing complex of this magnitude. It is always better to start with to have all the basic services.

अब जहां तक रोहिणी की बात पूछीगई है—मैंने पहले ही बताया है कि रोहिणी का पैसा जो अभी तक वहां खर्च हुआ है—The expenditure incurred upto October 1983 on the Rohini Project is to the extent of Rs. 2056.07 lakhs which includes Rs. 202 lakhs advanced to D.E.S.U. for electrical works. Now, this is just one part of the whole phased programme. इसमें करीब 21 करोड़ रुपया इक्ट्ठा हुआ था और अब तक 20 करोड़ के करीब सर्विसिज पर खर्च हो चुका है। इसलिए यह संभव नहीं है कि रोहिणी के लिए इक्ट्ठा किया हुआ पैसा दूसरी तरफ खर्च करें।

ग्रुप हाउसेज के बारे में आप ने जो सुझाव दिया है, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से उन के लिए कोई ऋण की व्यवस्था नहीं है। वे खुद अपने फाइनेन्सेज रेज करते हैं, हम तो सिर्फ उन को प्लाट्स देते हैं.....

श्री नवल किशोर शर्मा : हुडको।

श्री बूटा सिंह : हुडको के बारे में भी यह कहना चाहूंगा कि यह एक सुझाव है जो उन को बतला देंगे। लेकिन डी० डी० ए० की तरफ से कोई लोन ग्रुप हाउसिंग के लिए नहीं दिया जा सकता।

श्री भीखा भाई : आपने कहा है कि जो कीमत रजिस्ट्रेशन के वक्त थी, वही ली जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी स्कीमों के अन्दर भी, जहां रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, यही फार्मूला लागू होगा?

दूसरा भाग—आपने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए अभी तक कोई प्लाट नहीं दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं—क्या शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स, विशेषकर शेडयूल्ड ट्राइब्स, के लिए भी प्लाट्स की व्यवस्था की गई है?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो रोहिणी का प्रोजेक्ट विचाराधीन है। अगर किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस देना होगा। आप ने कहा है कि आदिवासियों को इसमें कोई प्लाट नहीं दिए गए हैं। मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि इस योजना में भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए 25 परसेन्ट का रिजर्वेशन है। विडोज आफ डिफैन्स पर्सोनल (किल्ड-इन-एक्शन) के लिए 1 परसेन्ट, एक्स-सर्विसमेन के लिए 1 परसेन्ट और फिजीकली हैण्डीकैप्ड के लिए 1 परसेन्ट का आरक्षण किया गया है। इसलिए यदि आदिवासी और शेडयूल्ड कास्ट्स चाहेंगे तो उन को जरूर दिया जाएगा।

श्री सज्जन कुमार : दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से रोहिणी नाम की एक बहुत बड़ी कालोनी बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां रोजगार के लिए कोई इण्डस्ट्रीयल एरिया या कोई इन्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स भी बनाने की योजना है?

SHRI BUTA SINGH : As the hon. Member is very well aware, even in his own constituency, we are, in these days, considering providing composite work-centres for all those unemployed people and artisans. Within their residential areas they will have their works centres along with the marketing and shopping areas.

Rise in Pirce of Rapeseed Oil in Delhi

*163. SHRI P.K. KODIYAN : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of rapeseed oil supplied through ration shops in Delhi has been raised from Rs. 9.15 per kg. to more than Rs. 12 and thatalso will be issued in two kilo packs only;

(b) if so, the details and reasons for raising the price;

(c) whether Government are aware that the poor people find it difficult to buy two kilo packs at a time; and

(d) if so, will Government direct the ration shops to sell one kilo packs also ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Since distribution of imported edible oils in loose has neither been discontinued nor its prices have been raised, the question of difficulties of poor people in purchasing of 2 kg packs does not arise.

(d) Does not arise.

SHRI P.K KODIYAN : What will I do, Sir ? It is all does not arise.

PROF. MADHU DANDAVATE : He says supplementary does not arise.

SHRI P.K. KODIYAN : I would like to ask the Hon. Minister whether his attention has been drawn to the reports appearing in the Press that rapeseed oil meant for distribution through ration shops is being diverted to the open market by some unscrupulous ration dealers, and as a result of that the price has gone up very much in the open market ? If it is so, I would like to know whether any action has been taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Sir, there is no truth in the report that rapeseed oil has been diverted from public distribution system to the open market, because whatever we allow to the Delhi State it is all under the supervision of Delhi Supply Department. They have a number of agencies through which we go to the fair price shops. Therefore, there is no diversion.

In the latter part of the question, the Hon. Member has asked about the price. It is true that we had expected its price to come down during these months, but there has been some spurt in it.

SHRI P.K. KODIYAN : Sir, the Hon. Minister has said that whatever is allotted is being lifted by the ration shop dealerst and there is no problem. But because some of us overselves are also buying these essential things from the ration shops, in our actual experience we find that for weeks and months together rapeseed oil was not available at all in the ration shops. For example in the ration shop in the P Block nearby, where the Government employees and also a number of MPs are buying this oil it was available at all for months together.

(Interruptions)

If what the Hon. Minister says is true, then how does the nonavailability of rapeseed oil there happens ? Please explain the reason for this and what is the exact position of the demand and the its proper and total availability ? What is the total quanity of rapeseed imported ? Is there any shortage ? What is the actual position ?

AN HON. MEMBER : In the blackmarket you will get it.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, it should be understood whether it is a question of rapeseed oil or a question of, as some Members in whisper said about rice and wheat. It should be properly understood in the context that allotment from the Central Government is only supplementary. the entire availability in the ration shops is what the State Governments themselves manage and what is available in the open market. We are only supplementing. We are not giving full quantity on the basis of population per day or like that. For example 11,000 tonnes of the palm oil and 8495 tonnes of rape seed oil was given to the State Government. So, it should be understood that if in any shop there is temporary absence of it, it does not mean that the rapeseed oil is not available. It only means that possibly the allotment tothat shop might have been consumed and the open market will supplement that.

(Interruptions)

SOME HON. MEMBERS : In Delhi it is not available.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Sir, Delhi is a Centrally administered State though there is a Metropolitian Council. I just wanted to remind the Hon. Minister that I was the person who brought to his notice, that vanaspati is being aduelterated with beef tallow. I received his reply that it was not possible; and then again I brought to his notice that his Secretariat and staff were not giving him proper or correct information. Then it was discussed on the floor of the House.

Now I would like to remind the Minister: in Dehli, I had as a member of the Mahila Dakshata Samiti had brought to the notice of the Food and Civil Supplies Commissioner that edible oil was not available in the market, and that shop-keepers were keeving them, and indulging in blackmarketing. The same reply was given, viz. "We are only supplying. We have got the record. You can see that we have supplied these things." Then, when along with the Commissioner our members visited different shops, it was found that edible oil was there in the shop; but it was not being sold.

During the Janata regime, I would like to remind the Minister that rapeseed oil was being imported, to bring down the price of the other oil, i, e. the mustard oil from Rs. 13/- to Rs. 7/- Because of this rapeseed oil import it could be brought down. But I would like to remind him that at that time also, rapeseed oil was used for adulteration with mustard oil. The Ganesh Flour Mill is a Government-mill. DCM's licence was cancelled for refining i.e. because it was indulging in it indirectly.

MR. SPEAKER : Will you put the question ?

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Is it a fact that at that time it was proved that other oil mills were indulging in the adulteration of rapeseed oils, because the prices of other oils were higher than the price of rapeseed oil ? (*Interruptions*) It was adulteration. Mixing means adulteration.

I would like to ask the Minister whether he would verify, i.e. whether the oil is being diverted to *pakora wallas*, or private traders, so that scarcity is being created in fair prices shops, if so, is he going to take any action against it, because again this rapeseed oil also will be mixed, along which tallow ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I take all the reminders of the Hon. Member very seriously. I will certainly ask the Delhi Administration; but I have replied that we have got no information of the diversion.

As far as the first part of the question is concerned, I am eagerly awaiting the discussion on adulteration of vanaspati with tallow, to nail the lies they are always spreading in the country.

श्री मनीराम बागड़ी : इस पर कमीशन मुकरर कर दीजिए ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : As the Minister has replied that rapeseed oil is supplied to supplement its supply in the States, I would like to tell him that at least the quantity which is allotted to the States from the Centre should reach them, if it is meant to be supplementary. Is it a fact that the quota of rapeseed oil allotted for West Bengal was not delivered, in the last few months ? Even consignments were diverted to other places, thus creating great scarcity of oil, and raising of prices ?

MR. SPEAKER : I don't think it is relevant.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : It is he who gave this supplementary answer, where he said that it was a supplement. That is why I asked the question. If he had not gone into it I would not have asked it. Since he has gone into it, he should say whether he has given the allotted quota to the States.

MR SPEAKER : No.

SHRI RAJESH PILOT : The price list is not very much visible in the fair price shops these days. I have gone to some of the fair price shops. Normally, there is a Government's rule that they display the price list. So that there is no confusion as to the prices, in the minds of the customers when they go there. May I know from the hon. Minister whether or not the instructions of the department officially still prevail, viz. that all dealers or whosoever are controlling these fair price shops, are supposed to display the Price list ? Are they not supposed to

display the stock position in the fair price shop in the price list ? (B) Is the government planning to start fair price shops at block headquarters in the rural areas like in the urban areas ? We cannot start it from village to village, but we can have it, at block level which is containing everything; if so, when and if not, why not ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : So far as the first part of the question is concerned, we shall refer it to the Delhi Administration. I would verify from them what are the latest instructions about this; whether it is obligatory on the part of the fair price shops to do it and I will find out about. If it is so, as the hon. member says, then we shall ask them that they should be properly implemented.

Violation of Master Plan By D.D.A.

*164. SHRI AJIT KUMAR SAHA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the DDA itself is violating the Master Plan and the directions of the Urban Arts Commission;

(b) if so, details thereof; and

(c) steps to be taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF : (a) to (c) The Government ordered a preliminary enquiry in September 1977 into the cases involving violations of Master Plan of Delhi. A statement giving the position in regard to those concerning DDA is laid on the Table of the Sabha.

The Delhi Urban Arts Commission provides advice and guidance to any local body in repsect of any project of building operations or engineering operations or any development proposals which affect or are likely to affect the skyline or the aesthetic quality of surroundings or any public amenity provided therein. The Delhi Urban Arts Commission have reported that there are instances of advice rendered by the Commission in respect of which it has not been kept fully informed of the action taken in furtherance of such advice. These are indicated in the statement laid on the Table of the Sabha. DDA have intimated that the guidelines issued by the D.U.A.C. have been circulated to all local bodies and within D.D.A.

STATEMENT I

Name of the Scheme involving violation of Master Plan of Delhi	Present position
1	2
(i) Sidhartha Enclave (near Sulight Colony) in the area earmarked for residential use and and neighbourhood parks.	D.D.A *vide* resolution No. 21 dated 2-4-1979 droped the proposal for change of land use from residential to commercial and the site under reference has been put to its original use as earmarked in the Master Plan/ Zonal Development Plan.
(ii) Shopping complex infront of Jama Masjid in the area earmarked for recreational use.	The proposal does not involve any change of land use as it forms part os the re-development scheme of Jama Masjid area.
(iii) Shopping Centres under the Defence Colony bridge.	Change of land use in respect of 1.92 hects. (4.75 acres) from "circulation' to, commercial has finanlly been notified by the Ministry on 8/10-10-1979.

1	2
(iv) Multi-storeyed building at Indra-Prastha, Estate, Vikas Minar for the offices of the Delhi Development Authority.	The plot under reference on which the multi-storyed building has been constructed is earmarked for Govt. office use in the Master Plan/Zonal Development Plan. The office building has been constructed on this plot with increased FAR to the extent of 400 instead of 150 as permissible the D.D.A invited public objections/suggestions on the increased FAR vide public notice dated 21.8.1971 and only two objections/suggestions were received which were also considered by the Authority vide its resolution No. 290 dated 10th January, 1972. The resolution of DDA recommending the FAR of 400 was not approved by the Government.
Resettlement colonies the details are as under : (a) Patparganj Complex (Kalyan puri, Khichripur, Trilokpuri) (b) Sultanpuri in the east of G.T. Karnal Road	The policy of rehabilitating the persons evicted from improper land use by settling them in resettlement colonies has been accepted by the Government.

STATEMENT II

(i) Advice relating to group 'housing development in and around historical/archeological monuments in the vicinity of district greens and plots having an area of more than 3 acres. A case in point is the development in the vicinity of Vijai Mandel monuments. Another case is the development near Jahapanah forest.

(ii) Advice that a study be made of Delhi is characteristics in order to comprehend the underlying aesthetic relationship between the visual significance, i.e. the three dimentional form of which Delhi is composed.

(iii) Advice that a study be made of the aestetic characteristics on Delhi in the context of forthcoming "Second Master Plan" to provide a picture of the frame work for a future urban design. It was suggested that to start with the studies should be confined to limited pocktes, such as Shahjahanabad, Shahdara, Civil Lines and New Delhi.

(iv) Advice relating to upgradation or improvement of aesthetic characteristics of residential areas developed by the DDA, specifically the Muknirka Residential Scheme.

(v) Advice relating to promotion of creative aesthetics to spend 2% of the estimated cost of construction on any prestigious building on beautification, i.e., sculpture and painting in order that an artistic enviornment may be created.

SHRI AJIT KUMAR SAHA : In the statement, the Minister has admitted gross violation of advice and guidance of the Delhi Urban Arts Commission by DDA

itself. In view of this, may I khow what action has been taken by the government against those who have violated this guidance of the Master Plan of Delhi ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): As we all know, the job of the Delhi Urban Arts Commission is to advise; and the DDA while approving plan of any development in a housing complex or shopping centre or any other complex takes into account all the measures affecting this aesthetic sense, the skyline and the surroundings of Delhi. Therefore, to the extent possible, the advice rendered by the Urban Arts Commission is accepted; where it is not just possible, they follow the procedure laid down under the rules under which they also go in for notifying public objections and then they come to the Central Government and get approval. After all the process has been followed, only then they make slight modification here and there, but, generally, by and large, the advice of the Urban Arts Commission is accepted.

SHRI AJIT KUMAR SAHA : May I know from the Minister whether it is a fact that, after acquiring land at Re.1 per square yard from the poor farmers, they are selling at the rate of Rs. 15, 000 per square yard thus depriving them the benefit they should get. What measures the government has taken to compensate those farmers whose land has been required at such a low rate ?

SHRI BUTA SINGH: This question does not arise out of this question. I am prepared to answer this question provided a separate notice is given. But, I am afraid, the comparison offered by the hon. member does not exist in reality; it is all imaginary —Re.1 to Rs.15,000/—. I have not seen in my experience with the Ministry such a variance. But let the hon. member table a separate question and I will answer it.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*165. **श्री मनीराम बागड़ी†**
श्री भीखा भाई } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4435 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा था कि मजूरी का पुनरीक्षण किये जाने तक अंतरिम राहत देने की मांग गत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चौथे वेतन आयोग द्वारा मजूरी ढांचे में संशोधन करने सम्बन्धी निर्णय किए जाने तक भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा अन्य सुविधायें कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उपरोक्त निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO): (a) It was state that the demand for payment of interim relief pending wage revision was under consideration for some time.

(b) and (c) A decision on the question of payment of interim relief pending wage revision, within the framework of the existing Government policy, has already been taken and communicated to the Corporation.

श्री मनीराम बागड़ी : इसको फूड कारपोरेशन कहा जाए, फ्राड कारपोरेशन कहा जाए या कुरप्शन कारपोरेशन कहा जाए—

अध्यक्ष महोदय : आपको कौन सा जंचता है ?

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे दोनों जंचते हैं फ्राड एंड कुरप्शन ।

सरदार बूटा सिंह जी ने क्या बोला ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आजकल बहुत बुरी संगत में रहते हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप तो हमारी संगत छोड़ कर चले गए हैं । पुराने शिष्य हैं

आप हमारे।

श्री बूटा सिंह : तभी तो ध्यान आता है बार-बार।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा मत कहो, मेरे साथ बैठे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : ये प्रमिला जी के साथ बैठते हैं।

इनका जवाब यह मिला है कि फूड कारपोरेशन के कर्मचारियों को जो अंतरिम सहायता दी जानी है वह उनको बता दी गई है। जो बता दी गई है वह क्या है और कब तक वह उनको मिल जाएगी? क्या कोई निश्चित तिथि आप इसके बारे में बताने की कृपा करेंगे?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : निर्णय ले लिया गया है और फूड कारपोरेशन को कह दिया गया है कि इसको वह कार्यान्वित करे। अन्तरिम रिलीफ कैटेगरी 3 और 4 में जिनकी तनखाह तीन सौ से नीचे है उनको पचास रुपये और जिन की सात सौ से नीचे है उनको साठ रुपए देने की बात कही गई है। जिनकी तनख्वाह सात सौ या ऊपर है उनको सत्तर देने की बात कही गई है। यह आर्डर दे दिया गया है। हमें आशा है कि इसको फूड कारपोरेशन कार्यान्वित करेगी। जहां तक कैटेगरी 1 और 2 का प्रश्न है बहुत जल्दी, कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। कमेटी बिठाई गई थी इसके लिए। लेकिन एक बात समझ लेने की है। जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग है उनमें दो तिहाई तो इंडस्ट्रियल डी ए के अन्तर्गत आते हैं और एक तिहाई ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल डी ए नहीं लेते। एफ सी आई उन्हीं में से एक है जिन पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही ये और डी ए हैं। अब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डी ए के अन्तर्गत आ जाए। इसलिए क्लास एक और दो का फैसला हो जाएगा। बहुत जल्द मौज बहुत जल्द और उनको भी दे दिया जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : जल्दी का कोई मतलब नहीं है। जल्दी तो साल की भी हो सकती है। क्या आप एक निश्चित तिथि बता सकते हैं?

श्री भागवत झा आजाद : सौ साल को मैं जल्दी नहीं मानता। एक वर्ष को भी जल्दी नहीं मानता। मेरा कहना यह है कि यह निर्णय अभी कुछ दिन पूर्व एफ सी आई को दे दिया गया है और हमें विश्वास है कि एफ सी आई जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वित करेगी। जल्दी का अर्थ वही है जो जल्दी का अर्थ होता है।

श्री मनीराम बागड़ी : मंत्री महोदय बुद्धिमान आदमी है। बुद्धि के चक्र में आप सवाल को भ्रमित कर सकते हैं। आप निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं? जल्दी वाला फौरन बता सकता है कि एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते। हफ्तों की या दिनों की बात तो आप बता ही सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनों दिनों में या एक महीने या दो महीनों में दे दें?

मुझे एफ सी आई से एक शिकायत है उसने बाजरे को खरीदा ही नहीं। हिन्दुस्तान के गरीब किसान का बाजरा खरीदा ही नहीं गया उसके द्वारा। जब गरीब का बाजरा निकल गया और बड़े व्यापारियों और सरकारी व्यापारियों ने मिल कर खरीद लिया और उसका सारा बाजरा भ्रष्टाचार करके सस्ते दामों में ले गए, — चूंकि उनका गुजारा नहीं होता था इसलिए उनको बेचना पड़ा — तब कारपोरेशन ने हुकुम दिया इसको खरीद करने और अभी तक भी हरियाणा में वह उसके द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस हैसियत में हैं जो यह बता सके — (इंटरप्शंज) क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि फूड कारपोरेशन को बाजरा वक्त पर खरीदना था वह न खरीदने के कारण किसानों को घाटा लगा और अभी भी हुक्म देने के बाद जो हरियाणा में नहीं खरीदा जा

रहा है क्या किसानों को उसका मुआवजा देने की कृपा करेंगे ? और दीषी अफ़सरों ने जो बाजरा नहीं खरीदा उनके खिलाफ आप ऐक्शन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह है कि एक तो आप कहते हो कि काम नहीं करते, और दूसरी तरफ उनकी सिफारिश भी करते हो।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह भी काम नहीं करते हैं और आप मंत्री जी की सिफारिश करते हो, तो बराबर हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप मंत्री जी खरीद का बन्दोबस्त देख लेंगे।

श्री भीखा भाई : मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है वह यह है कि इन्होंने क्लास 3 और 4 को अंतिरिम सहायता दे दी है। दरअसल में मुख्य मांग अंतरिम राहत की नहीं हैं, बल्कि उनकी मुख्य मांग यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐप्लाईज के आधार पर जो वेज रिवीजन होना चाहिये वह कब करने जा रहे हैं ?

दूसरे यह कि इन्होंने जो बताया कि यह प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर का है इसमें दो तिहाई लोग इंडस्ट्रियल इंडैक्स से गाइड होते हैं और एक तिहाई को सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पर दिय जाता है, तो उसका कोई स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आया।...

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो भीखा भाई जी एक ही हो सकता है, इतने सारे नहीं। मंत्री जी आप बता दीजिये।

श्री भीखा भाई : रिवीजन कब तक करेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा एफ० सी० आई० कर्मचारियों की वेज और डी० ए० पैटर्न सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के आधार पर है लगभग। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐम्प्लाईज को जब जब डी० ए० इंस्टालमेंट मिला वैसा ही इस पर लागू हो जाता था। 1971 से कोई रिवीजन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐमप्लाईज का नहीं हुआ। एफ० सी० आई० ने बार-बार कुछ सालों से मांग की उनको इंडस्ट्रियल डी० ए० में लाया, जाय। हमने उनको अंतरिम राहत दी है और यह कहा है कि इंडस्ट्रियल डी० ए० फौरमूला के अन्तर्गत आने के लिए जो आवश्यकतायें हैं वह पूरी हों, जैसे (1) ऐसोसिएशन और यूनियन के सदस्य मैजारिटी से इस बात को कहें, (2) जो वर्किंग आवर टोटल और वर्किंग आवर के भिन्न भिन्न टाईपिंग हैं यह मान लें। ज्यों ही इन बातों पर निर्णय हो जायगा क्लास 1 और क्लास 2 द्वारा हम इनकी वेज पर विचार कर सकते हैं।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था

167. **श्री सज्जन कुमार†** :
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में पानी और सीवर की व्यवस्था करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और दिल्ली में इन पुनर्वास कालोनियों के नाम क्या हैं, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान पानी और सीवर की लाइनें डालने का कार्य शुरू हो जायेगा और यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार ने इस काम को शीघ्र करने के लिए कोई निर्देष जारी किये हैं और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details are contained in the statement which is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

(b) The scheme sanctioned by the Govt. envisages provision of the following additional facilities in the resettlement colonies:—

1. water supply lines for individual connections;

2. Sewerage;

3. Improvement of storm water drains and culverts;

4. Improvement of roads and paths;

5. Peripheral services; and

6. Over-head tanks and under-ground tanks.

The DDA who are implementing the scheme have intimated that during 1983-84, work on the scheme for providing water supply and sewerage lines is being commenced in the following colonies after getting the requisite approvals form the MCD:—

1. Madipur.
2. Khyala
3. Hastsal
4. Pankha Road
5. Seelampur
6. Nand Nagri
7. Gokalpuri
8. Old Seemapuri
9. New Seemapuri

(c) The DDA has stated that the work is being expedited as per the policy of the Government.

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष जी, दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियां हटा कर करीब 12 लाख लोगों को दिल्ली की पुनर्वासित कालोनियों में बसाया गया, और मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में नहीं, शायद दुनियां के किसी देश में एक साथ 12 लाख लोगों को हटाकर शायद ही कहीं पर रीसैटिल किया गया होगा, वहां बहुत सी नागरिक सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन पहली बार प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जो इनको पीने का पानी देने और सीवर डालने की योजना शुरू की है। दिल्ली के सभी क्षेत्रों में उसका स्वागत किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन कालोनीज़ के नाम दिए गए हैं, क्या उनके अलावा और पुनर्वास कालोनीज़ में भी सरकार काम शुरू करने जा रही है, यदि हां, तो वह काम कब तक शुरू किया जाएगा और वह कब तक पूरा किया जाएगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इतने विस्तृत प्रोग्राम हो हाथ में लेकर डी डी ए और दिल्ली प्रशासन ने इतने थोड़े समय में जिस तरह काम किया है, वह बहुत सराहनी है। इतने थोड़े समय में वाटर सप्लाई लाइन्ज़ 46 किलोमीटर, रोड एंड पाथ इम्प्रुवमेंट 110 किलोमीटर, स्टार्म वाटर ड्रेन्ज़ एंड कल्वर्ट्स इम्प्रुवमेंट 69 किलोमीटर और सीवर लाइन्ज़ 10 किलोमीटर का काम किया गया है और चार ओवरहैड एंड अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए हैं। 20-नुकाती प्रोग्राम का जितना अच्छा इम्प्रूमेंटेशन दिल्ली में, और खासकर पुनर्वास कालोनीज़ में, हुआ है, इसमें संदेह नहीं है कि यह एक आल-टाइम रिकार्ड है। जिन कालोनीज़ के बारे में स्टेटमेंट में विवरण किया गया है, उनके अतिरिक्त डी डी ए की तरफ़ से सरकार के पास त्रिलोकपुरी कम्पलेक्स, रघुवीरनगर, नारायना, पांडवनगर, चौखंडी, ज्वालापुर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई फ़ेज़ 1, 2, 3, जहांगीरपुरी, शकूरपुर, बज़ीरपुर, दक्षिणपुरी, मदनगीर, सनलाइट कालोनी ओर मोतीबाग के बारे में सुझाव और योजनाएं पहुंच चुकी हैं। प्राधिकरण की तरफ़ से यह भी मांग की गई है कि इसके लिए अधिक धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी। माननीय सदस्य ने जिन सार्वजनिक सुविधाओं का उल्लेख किया है, उनका

प्रावधान इन कालोनीज में दिया जाएगा। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली में अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पीने का पानी, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग और सीवरेज की सर्विसिज़ दे सकें। डी डी ए की तरफ़ से इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने नागरिक सुविधाएं देने के सम्बन्ध में 9 कालोनीज के अलावा और कई कालोनीज का नाम लिया है। मंत्री महोदय ने प्रश्न (ग) के जवाब में कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार कार्य शीघ्र ही किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी नीति क्या है और 9 कालोनीज के अलावा जिन और कालोनीज का नाम मंत्री महोदय ने लिया है, डी डी ए ने उनके सम्बन्ध में जो योजना मंत्रालय के पास भेजी है, उस पर कब तक विचार कर लिया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में अब और कितनी ऐसी कालोनीज शेष रह गई हैं, जिनमें यह कार्य प्रारम्भ करने की योजना है। दिल्ली के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों को प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय बड़ी जागरूकता प्रदर्शित कर के दिल्ली में नई दिशा और नई रोशनी और झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब मजदूरों को पानी और बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है, मंत्री महोदय या उनके उच्चाधिकारियों ने उसका निरीक्षण किया है, ताकि कार्य में कोई गड़बड़ी न हो और कार्य तेजी से हो, जल्दी हो।

MR. SPEAKER : Shri Bhiku Ram Jain.

PROF. N. G. RANGA : What about the reply ?

MR. SPEAKER : He is satisfied.

PROF. N.G. RANGA : How many colonies, how many of them are re-settlement colonies and by what time ?

MR. SPEAKER : He has already enumerated them, that he is going to start work.

PROF. N. G. RANGA : The number he has not given.

श्री भीखू राम जैन : मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह लिखा है—Schemes sanctioned by the Government envisages provision of the following additional facilities in the resettlement colonies. मैं इस बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में जमीन की कीमतें बाकई बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर 1 रुपये का 50 हजार नहीं है तो ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दिल्ली को इस तरह बड़ाते जाओगे तो और क्या होगा ?

श्री भीखू राम जैन : मैं उसकी जिम्मेदारी इस बात पर लगाना चाहता हूं कि दिल्ली में जो मकान बनाने की इजाजत दी जा रही है, कहीं दो मंजिल कहीं 3 मंजिल, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पर मल्टीस्टोरीड बिल्डिगें बनाने की इजाजत दी जा रही है, डी० डी० ए० ने खुद जो फ्लोर एरिया रेशियो पहले 150 था उसे ऊंची बिल्डिग बना कर 400 किया है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सीवर डाले जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, पीने का पानी का इन्तजाम किया जा रहा है, क्या वह इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए जो ऊंची बिल्डिगें बनाई जा रही हैं, उनमें इन सारी बातों का पूरा इन्तजाम किया जा रहा है या नहीं? कहीं दो चार साल के बाद यह कहने का मौका तो नहीं आयेगा कि सीवर की लाइन छोटी है पानी की लाइन छोटी है, सड़कें छोटी हैं इसलिये और ऊंची बिल्डिग बनाने की जरूरत नहीं है ? अगर इस प्रकार का विचार है तो क्या मंत्री जी बतायेंगें कि दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिगें क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा बनाई जायें ताकि दिल्ली में जो जमीन की कीमतों की समस्या है, वह हल हो सके ?

SHRI BUTA SINGH: The hon. Member would agree with me that for some time past now we have changed the whole concept. We have now decided that we will have high density houses, where more people could be accommodated within the same place. This has resulted really in a reduction in land prices in Delhi, which should be complimented.

I agree with the hon. Member that the shortage of land in Delhi has become very very acute. I propose to hold a meeting with the hon. Members especially those from Delhi to have their views and co-operation on the future development of Delhi. As I mentioned and a little while ago by Shri K C Pande, the 20-Point programme of the Government would serve the people of Delhi. We would welcome suggestions from all Members of Parliament especially from Delhi, and we will seek their co-operation to see that the development of Delhi takes place, according to the prescribed norms and rules.

Meeting of State Food and Civil Supplies Ministers

*168. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of State Ministers of Civil Supplies was held recently with the Central Minister in New Delhi in November, 1983;

(b) if so, whether the working of the fair price shops in the States and also the items catered by them was considered at the meeting and if so, brief details thereof;

(c) whether the meeting considered the desirability of expanding such fair price shops in the difficult and rural areas with more items so that the benefit may reach to the population who are cut off and are being exploited by petty traders; and

(d) the decision taken in this regard, if any ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) to (d) Yes, Sir. The fourth Meeting of the Advisory Council on Public Distribution, of which the Civil Supplies Ministers of States/Union Territories are its members, was held on the 7th of November, 1983. At this meeting the expansion of the public Distribution System through opening of more fair price shops, including mobile shops, in the far flung areas and widening the 'scope of coverage of commodities distributed through the Public Distribution System, *inter alia* was reviewed. Keeping in view the important role played by the Public Distribution System in the supply of essential commodities of mass consumption to people at reasonable prices, the general consensus in the Meeting was that the base of the Public Distribution System should be strengthened through planned expansion, proper management and its accessibility to remote and sparsely populated areas. The State Governments and Union Administrations should make efforts to open more fair price shops to achieve the norm of 2000 units per fair price shop. For making fair price shops viable, State Governments and Union Territory Administrations, may include in addition to the essential commodities, for which supplies are made by the Central Government, as many items as could be possible to widen the commodity coverage.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: In part 'C' of my question I have asked whether the meeting considered the desirability of expanding such fair price shops in the difficult and rural areas. In reply to that, the Minister has generalised the problem and not given any specific plan. If any plan has been discussed in the meeting, let the Minister indicate that and then the answer will be complete.

As you are aware, the public distribution system needs to be strengthened and more shops are to be opened in rural and difficult areas. What steps are being taken by the Central Government of making these fair price shops viable ? If viability is not coming, then how will the Central Government ensure more items to the fair price shops and see that they work properly in rural and urban areas ? How will the Government arrange to distribute essential items to the people in general in those areas where there are no fair price shops ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Exactly these are the issues that we take up in the meetings that we hold with the State Supply and Food Ministers. Regarding viabilty of the fair price shops, we supply seven items from the Central Government. It is true that viability possibly cannot come out of these seven items. That is why it has been left to the State Governments to include as many items as they like from their own precurement for disbursal from these shops. These are States like West Bengal, Kerala, Orissa which have included a large number of items apart from the seven that we give from the Central Government, in the fair Price shops. Therefore the viability of the fair price shops can come only when the State Governments include the items which they consider they can procure and distribute through them.

We also discuss about the difficult and non-accessible areas. We are emphasising on the State Governments that they should cover such areas which are still not covered by the fair price shops. This point was considered in the fourth meeting also. We hope that the State Governments which are responsible for this will fix up their targets for opening fair price shops in such areas and we also hope that they are taking action in this regard.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Rotten foodgrains are supplied through fair price shops because the shopkeepers do not have the option of selection. Will the Government ensure supply of good quality wheat through fair price shops to the consumers ?

The Central Government has allotted levy, sugar to the Government of Rajasthan from Maharashtra. But for the last six months not a grain of sugar has been lifted by the concerned authorities. In such a situation, how would the fair price shops distribute levy sugar to the consumers. Will the Government look into it?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Whenever complaints come about the quality of the foodstuff, there is a joint inspection by the representatives of the State Government and the FCI. The State Government has got the right to reject the foodstuff if the quality is below what is prescribed by us. Therefore, there is enough precaution taken and the State Governments before taking foodgrains from the FCI, have to satisfy themselves that this quality is good for consumption. Secondly, after that is done, the State Government have got there, some were in the *halkas* and some were attached to the fair price shops, the vigilance committees to look into the complaints. If such complaints come from the States, I would also request the hon. Members that they should complain to the State Governments. I must admit that it is not possible for the Central Government all over the country to see what every fair price shop is doing. Therefore, every Member of the State Legislative Assembly or State Government has to see that in their areas quality is distributed and secondly, where it is not available, why it is not available. Sir, from here what we do is, as I told you, that we call the State Food Ministers, we discuss with them about the quality and about the expansion of the fair price shops. That is how the Central Government monitors about these things.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Sir, my second question is: Why levy sugar is not lifted by the Rajasthan Government. (*Interruptions*.) Recently the levy sugar is distributed through the fair price shops so that it is a very low price sugar and the consumers are denied their rights. The Minister may kindly reply.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Prof. Kurien.

PROF. P.J. KURIEN: The hon. Minister said that the State Governments have decided to strengthen the public distribution system. That is very good. But you know that Kerala is having a very effective public distribution system and at the time when southern food zone was abolished, the Central Government had given assurance that Kerala's requirement of food would be met. And in spite of the fact that we are having an effective public distribution system, we are not given adequate quantity of rice to be supplied through the ration shops. At the same time the Government is not permitted to buy rice from the surplus States. I would like to ask the Minister: When you are not able fulfil your commitment of supplying

sufficient rice, why don't you allow States like Kerala to purchase rice from other States which are having surplus ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, so far as the supply from our side is concerned, I think we have done the maximum for the Kerala State. (*Interruptions*). Hon. Members may not be satisfied and may like to say that they should have more. I have already said—I cannot say about individual States—that this is not a question of the States demanding as much as they wish and the Central Government supplying them all that they need. As I have said, the food management policy of the Central Government is depending upon what the State Governments themselves manage, what is the availability in the market and what is available to the Central Government which is procured from the surplus States in the country which are few and therefore, it is not that the Central Government do not want to give it, but it depends upon these factors, as I have said. Under those conditions we have given maximum to the State Government of Kerala. The second point.....

(*Interruptions.*)

PROF. P.J. KURIEN: Why don't you allow the State agencies to purchase.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That is what I am telling about.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shrimati Sushila Gopalan.

SHRIMATI SUSHILA GOPALAN: It is correct that the State Governments have taken the responsibility of the public distribution system. But many of the items have to be procured by the Central Government and it has to be given. The seven items which are allotted for procurement by the Central Government itself is not enough. At least 14 essential items should be procured by the Government and given to the State Governments. Not only that. At present when the harvesting season is going on——here you will see that a question from Mr. A.K.Roy is there wherein he said that there is a fall in price and the farmers are not getting proper prices. On the other side,—people are getting them at a high price. So, if you have to procure the essential things properly the wholesale trade of essential articles, I mean, foodstuffs, should be taken over. That is one of the major things to be done by the Central Government.

MR. SPEAKER: The time will be up now.

(*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHILA GOPALAN: I am coming to that. And whatever is agreed by the Government to allot to the State Governments, that should be allotted. With regard to Kerala as you say they are giving 10,000 tonnes less than what is to be given. I want to know from the Government whether they are prepared to stand by the commitment to allot the particular quantity to the State Government.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have already replied to this question—that we are doing as far as possible to give maximum help to the different States. We have not made any discrimination so far as Kerala is concerned. There is nothing like 10,000 tonnes Less.

We have given them an allotment to the extent of 1,10,000 tonnes and we had also allowed them to purchase from the surplus States. Therefore, they are getting whatever is due.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Distress Sale of Paddy

*166. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether he is aware that the distress sale of paddy has started because of the non-starting of the procurement by the States ; and

(b) if so, facts in details and the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): (a) and (b) Central Government have not received any report of distress sale of paddy in the States. However, the FCI, State Governments, and their agencies, have already been directed to make necessary arrangements for procurement of paddy

under price support operations wherever necessary.

Land Racket in Capital

*169. SHRI DIGAMBAR SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether some powerful group of land racketeers in Delhi has made crores of rupees by encroaching on public land in connivance with some court, police and local officials;

(b) whether he is aware of the huge constructions coming up without any approved plan in various areas of Delhi and huge shopping complexes in Chandni Chowk, Sadar Bazar and other commercial areas and conversion of residential buildings into commercial buildings including multi-storeyed guest houses;

(c) the particulars of those people who are including in unauthorised constructions in Delhi and action taken or proposed to be taken against them and the local official who connive with them;

(d) whether the sale of land on power of 'attorney' is the regular feature of land racketeering in the Capital; and

(e) how do Government propose to check it ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) to (c) A report on the subject has been received by the Ministry of Home affairs. It is not in public interest to disclose the details at this stage pending examination thereof.

(d) and (e) It has come to notice that certain unscrupulous persons, have instead of executing regular transfer deeds, taken recourse to the execution of general power of Attorney in favour of the purchasers with a view to circumventing compliance with the provisions of the Delhi Lands (Restrictions on Transfers) Act, 1972. In other to tackle the situation, a proposal to amend this Act is under consideration.

Modification of Master Plan

*170. SHRI R.L.P. VERMA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the future Master Plan to acquire lands for extension of Delhi for the use of public and semi-public facilities;

(b) whether Government are modfying the plan to leave green-belt and agricultural lands of cultivators;

(c) whether Government purpose to provide reasonable compensation to land owners and also allot a flat to them; and

(d) if so, details of the plan ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) The Delhi Development Authority are revising the Master Plan of Delhi with a new perspective covering the period 1981-2001. This would cover areas in Delhi as well as New Delhi.

The revised Plan when finalised will indicate the requirement of land for public and semi-public facilities and other uses and also extentions in the urban limits.

(b) The open green spaces and green belt are necessary component of integrated planning. The increase in urban population and the process of urban development may require modification of land use including green belt and agricultural lands within the framework of the Master Plan.

(c) The land is acquired under the provisions of Land Acquisition Act, 1894 and compensation is also paid in accordance with the provisions of this Act. Besides the compensation, DDA gives one residential plot at pre-determined rates to the persons whose land is acquired. It also reserve 10% of shops for allotment to them at pre-determined rates.

(d) The details of the Master Plan perspective for 1981-2001 would be available only after its finalisation.

उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की आटे की मिलों से मैदा रहित आटे की खरीद के बारे में किया गया भुगतान

*171. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दिल्ली की आटा मिलों द्वारा बेचे जाने वाले मैदा रहित (रिजल्टेंट) आटे के लिए मिलों को किस दर पर भुगतान करती है ;

(ख) सरकार उत्तर प्रदेश की आटा मिलों से खरीदे जाने वाले मैदा रहित (रिजल्टेंट) आटे का भुगतान इन मिलों को किस दर पर करती है ;

(ग) सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली की आटा मिलों को गेहूं की आपूर्ति किस दर पर करती है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश की आटा मिलों से कम दरों पर तथा दिल्ली की मिलों से ऊंची दरों पर मैदा रहित रिजल्टेंट आटा खरीदे जाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति जितनी मात्रा में परिणामी आटा उठाया गया था, वह दिल्ली की रोलर फ्लोर मिलो ने 180/– रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए निकासी मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति जितनी मात्रा मे परिणामी आटा उठाया गया था वह उक्त राज्य की रोलर फ्लोर मिलों द्वारा 125/– रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निकासी मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ।

(ग) रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं 208/– रुपये प्रति क्विंटल के समान मूल्य पर सप्लाई किया जाता है जिसमें कर शामिल नहीं हैं ।

(घ) सरकार द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं में से रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए गेहूं के उत्पादों के निकासी मूल्य, उन्हें उपयुक्त मिलिंग मार्जिन देने के बाद राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । रोलर फ्लोर मिलों द्वारा तैयार किए गए गेहूं के सभी चार उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद मिलिंग मार्जिन का हिसाब लगाया जाता है । तदनुसार, गेहूं के चार उत्पादों के मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं । हालांकि उन राज्यों में अनुमेय मिलिंग मार्जिन वही क्यों न हों ।

Stagnation in Marine Fish Production

*172. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of stagnation in marine fish production;

(b) whether Government have identified constraints in the development of deep sea fishing ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken in this matter ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Average annual production of marine fish in the trienniam ending 1982 touched a record level of 14.81 lakh tonnes against the corresponding figures of 14.77 and 14.43 lakh tonnes in the preceeding two triennia.

(b) and (c) Major constraints in the development of deep sea fishing have been identified as :

(i) need for a massive investment of capital involving a high degree of risk ;

(ii) need for trained personnel ;

(iii) lack of adequate infrastructure of harvest and post harvest technology ;

(iv) rising cost of fishing operations;

(v) need for fuller fishery resources data and

(vi) low consumer preference for the majority of deep sea fishes.

(d) Some of the important steps taken in this matter are :—(i) Encouragement by the States in diversifying fishing activities ; (ii) enactment of legislation based on the model circulated by the Central Government for regulating fishing in different fi hing areas within the territorial waters by different types of fishing craft ; (iii) augmeatation of deep sea fishg fleet through judicious mixture of indiinous, imported and chartered fishing vesneels ; (iv) providing 33 per cent subsidy ougs thecost of hidigenously constructed vessels ; (v) providinig loans on soft terms for purchase of fishing velles; through the Shipping Development Fund Committee ; augmentation of fisheries surveps; (vii) assistance for construction of fishing harqours at major and mino ports and of landing and berting facilities at smaller fishing centres ; (viii) augmentation of raining facilities and (ix) regulation of fishing by foreign vessels in the Excusive Economic Zone. For this purpose, The Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981' has come into force with effect from 2nd November, 1981.

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" से फसलों को हानि

*173. **श्री हरीश रावत :**
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" नामक कीड़े से फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस कीड़े से फसलों की समुचित रोकथाम हेतु उपलब्ध कीटनाशक बहुत मंहगे हैं था इस क्षेत्र के गरीब किसान इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कीड़े को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ! उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में "कुरुमुला" से फसलों की क्षति होने की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) "कुरुमुला" (बड़े तथा छोटे दोनों) के नियंत्रण के लिए अनेक कीटनाशी औषधियों की सिफारिश की गयी है । इन कीटनाशियों की लागत भिन्न भिन्न है, जो प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशी की किस्म तथा नियंत्रित किए जाने वाले कीट की अवस्था पर निर्भर करती है । आयातित कीटनाशी दवाओं की नई किस्में मंहगी हैं । तथापि, उनके स्थान पर बी० एच० सी० जैसे सस्ते कीटनाशी, जो समान रूप से प्रभावी हैं, सुगमता से उपलब्ध हैं ।

(ग) (1) वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार फसलों की "कुरुमुला" से होने वाली हानि को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के परामर्श से राज्य कृषि विभाग द्वारा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नियंत्रण नीति तैयार की गयी है ।

(2) भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत "कुरुमुला" कीट के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है । तथापि, वे इस सहायता का स्वयं लाभ नहीं उठा रहे हैं । क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उनके पास राज सहायता की अपनी योजना है ।

Neradi Barrage Project

*174. SHRI GIRIDHAR GOMANGO Will l the Minister of IRRIGATION be eased to state :

(a) whether Government of Andhra Pradesh have submitted a revised Neradi Barrage Project on river Vamsadhara to his Ministry and to Government of Orissa for examination as per the agreement between two States ;

(b) if so, when it was received and action taken by Government of Orissa and his Ministry on the report ;

(c) whether both the States are in a position to settle the differences on certain points of these will be reffered to his Ministry to settle the dispute ; and

(d) the present position of the project and the dispute ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d) The revised project report of Neradi Barrage, a component of Vamsadhara Project Stage-II, was received in July 1982 in the Central Water Commission from the Government of Andhra Pradesh, which was also forwarded by Andhra Pradesh to the Orisssa Government. The report indicated an area of 1266 acres as coming under submergence in Orissa. The Government of Orissa informed in September 1982 that their concurlence to the revised project could be given only after ground verification about submersible area in their territory is done by their Engineers. In July 1983, the Orissa Government informed that certain details in connection with design, flood discharge, corresponding back water and submergence of land other facilities as a result thereof etc. need to be re-examined and adequately provided for in the project estimate. The views of Government of Orissa on the project were conveyed to the Government of Andhra Pradesh have informed in November, 1983 that to sort out the matters, an official level discussion with the Government of Orissa is proposed to be held shortly at Bhubaneswar.

सिद्धमुख नहर और नौहर नहर योजनाएं

*175 **श्री दौलत राम सारन : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सिद्धमुख नहर और नोहर नहर योजनायें कब बनाई गई थीं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई सचिव ने रावी-व्यास ससमझौते के उपबंधों के अनुसार राजस्थान की सिद्धमुख और नौहर योजनाओं के बारे में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ 31 दिसम्बर, 1981 को विस्तृत विचार विमर्श किया था और 15 जनवरी, 1982 को निर्णय दिया था जिसके अनुसार सिद्धमुख और नौहर क्षेत्रों के लिए पानी की आवश्यकता 4.7 लाख एकड़ फुट आंकी गई थी और उसमें इस पानी की सप्लाई करने की पद्धति का भी उल्लेख किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ;

(ग) उक्त निर्णय राजस्थान सरकार को कब प्रेषित किया गया ; और

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं को जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है और यदि हां, तो कब और इन योजनाओं की अब क्या स्थिति है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से मूल नोहर सिंचाई एवं सिद्धमुख सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में क्रमश : 1977 और 1979 में प्राप्त हुई थीं। रावी-व्यास के अधिशेष जल के बटवारे पर हुए 31.12.1981 के करार के अनुसरण में, भारत सरकार के सिंचाई मंत्रालय के सचिव का निर्णय राजस्थान सहित सभी संबंधित राज्यों को 15.1.1982 को भेज दिया गया था, इससे संबंधित उद्धरण विवरण में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त निर्णयों पर आधारित आशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

सचिव, सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 15.1.1982 का निर्णय :

तीन राज्यों के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् तथा सभी सम्बन्धित पहलुओं को

ध्यान में रखते हुए सचिव, सिंचाई, भारत सरकार ने 15.1.1982 को निम्नलिखित निर्णय दिए थे :—

1. जल प्रवाह द्वारा नोहर तथा सिद्धमुख क्षेत्रों की सिंचाई के लिए राजस्थान की उपयुक्त आवश्यकता 0.47 मिलियन एकड़ फुट आंकी गई है तथा जल प्रवाह सिंचाई की व्यवस्था के लिए इस मात्रा को उपयुक्त समझा गया है। राजस्थान का नांगल में 00.47 मिलियन एकड़ फुट से अधिक व्यास के व्यपवर्तित जल का दावा न्यायोचित नहीं है।

2. जल प्रवाह सिंचाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसकी सप्लाई की निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाना चाहिए :—

(क) राजस्थान के भाखड़ा क्षेत्रों को जिन्हें अभी दक्षिणी घग्गर नहर तथा जंडवाला शाखा नहर द्वारा सिंचित किया जा रहा है, राजस्थान पोषक को स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए और इस तरह बचाए गए जल को इस प्रणाली का भाखड़ा प्रणाली के लिए नांगल में क्षमता फेक्टर पर 0.30 मिलियन एकड़ फुट जल ले जाने के लिए पुनर्रूपण करके फतहबाद शाखा, किशनगढ़ उपशाखा तथा बारूवाली शाखा के जरिए नोहर तथा सिद्धमुख क्षेत्रों को व्यपवर्तित कर दिया जाए। ऊपरी भागों में वर्तमान भाखड़ा प्रणाली अप्रभावित रहेगी। इसे राजस्थान सरकार के खर्चे पर किया जाना चाहिए।

(ख) शेष 0.17 मिलियन एकड़ फुट की शेष मात्रा, जो लगभग 3000 क्यूसेक के बराबर है, पहले नांगल बी एम एल के जरिए राजस्थान को व्यपवर्तित किया जाएगा। सचिव (सिंचाई), भारत सरकार द्वारा 7.11 1981 को की गई बैठक में जिसमें पजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह सर्वसम्मत से पहले ही निर्णय किया जा चुका है कि बी एम एल को उसकी 12,500 क्यूसेक की मूल अभिकल्पित क्षमता तक पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए और इस कार्य को तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए। राजस्थान व्यस्ततम समय में सप्लाई अवधि के दौरान बी एम एल के जरिए राजस्थान-हरियाणा सीमा पर सम्पर्क स्थलों पर 855 क्यूसेक की क्षमता का उपयोग कर रहा है। बी एम एल के इसकी मूल क्षमता तक पुनः प्रतिष्ठित किए जाने के पश्चात् राजस्थान एक्स—नांगल से छोड़े जाने वाले 0.17 मिलियन एकड़ फुट जल के समतुल्य नोहर और सिद्धमुख क्षेत्रों के लिए 300 क्यूसेक जल क्षमता का और हकदार होगा। राजस्थान को अपने हक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बी एम एल में क्षमता के पुनः प्रतिष्ठित करने की लागत का भुगतान करना चाहिए।

3. बीएसएल परियोजना के जरिए व्यास के व्यपवर्तित जल की अधिकतम कुल मात्रा 3.82 मिलियन एकड़ फुट है। इसमें से 1981 के करार में किए गए आबंटन के अनुसार 0.20 मिलियन एकड़ फुट जल दिल्ली के लिए रिजर्व रखा जाएगा और शेष 3.62 मिलियन एकड़ फुट में से राजस्थान 0.17 मिलियन एकड़ फुट तथा हरियाणा शेष 3.45 मिलियन एकड़ फुट का हकदार होगा। हरियाणा, राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर को जोड़ने वाले लिंक चैनल के आरडी 496250 पर प्रतिप्रवाह में किसी उपयुक्त स्थान से राजस्थान फीडर के जरिये पहले के हरिके से शेष 0.05 मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त करेगा। तथापि, हरियाणा जल प्रवाह द्वारा अपने भाखड़ा क्षेत्रों को जल सप्लाई करने के लिए इस प्रबंध द्वारा 0.08 मिलियन एकड़ फुट तक जल प्राप्त कर सकता है। हरियाणा अपने हित में, उपयुक्त समय में रावी-व्यास जल के अपने हिस्से का अधिकतम उपयोग करने

के लिए अधिकतम सीमा तक इस मात्रा में वृद्धि करने के लिए व्यवहार्यता की जांच कर सकता है।

Reduction in Diesel Price For Small Fishing Boats

176. SHRI K. B. CHOUDHARI :
PROF. P. J. KURIEN :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to reduce the diesel price for small fishing boats by exempting Central excise duty as has been done in the case of deep sea fishing trawlers; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) The scope of exemption presently admissible to fishing trawlers including deep sea fishing vessels is being maintained for the time being at the same level.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के बारे में वास्तविकता जानने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट

*177. श्रीमती किशोरी सिन्हा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वास्तविकता जानने के लिए बनायी गई समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान अति दयनीय और कमजोर है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और संचो (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति ने 180 योजनाओं में से 26 योजनाओं का निरीक्षण किया और 13 योजनाओं में कार्य की कोटि को अपेक्षाकृत घटिया पाया। समिति द्वारा बनायी गयी सामान्य त्रुटियां चिनाई तथा सीमेंट कंक्रीट की घटिया कोटि असन्तोषजनक गारा मिश्रण, खारे पानी का प्रयोग तथा अपर्याप्त स्थल निरीक्षणों से संबंधित थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुव्यवस्थित सर्वेक्षण तथा त्रुटियों को सुधारने, सुदृढ़ीकरण उपायों का कार्यान्वयन, निरीक्षण पद्धति को सरल बनाने, सख्त पर्यवेक्षी अनुशासन को सुनिश्चित करने कार्य स्थल पर सामग्रियों की जांच से संबन्धित उचित रजिस्टर रखने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, दोषी ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने आदि के लिये कार्यवाही की है।

Restriction on Purchase of Rice from Surplus States

*178. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR :
SHRI SKARIAH THOMAS :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether there is any restriction on Government agencies of any State for purchasing rice from other surplus states ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government of Kerala have requested Union Government for full freedom to the Kerala State Civil Supplies Corporation to purchase rice from open market in the surplus States ; and

(d) if so, the details of the request and the action by Government thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) The whole country is treated as single zone for inter-State movement of rice through normal channels. Levy free rice can be moved freely within the country by the traders. The State Government or their agencies are, however, required to obtain prior approval of the General Govern-

ment for inter State movement of levy free rice on State Government account.

(c) and (d) Central Government have received requests from time to time from the Government of Kerala to allow them to purchase 30,000 to one lakh tonnes of levy free rice from the surplus States. Taking into account availability in the surplus States, Kerala Government were allowed to purchase during 1982-83 Kharif marketing season, 75,000 tonnes of rice in all, 15,000 tonnes from Punjab/Haryana, and 60,000 tonnes from Andhra Pradesh.

Increase In Pure Ghee Prices

*179. SHRI MOHANLAL PATEL :
SHRI CHINTAMANI JENA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pure ghee prices are shooting up day by day not only in private sector but in public sector also;

(b) if so, the reasons for the increase in pure ghee prices throughout the country; and

(c) the steps being taken to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) There has been some increase in the prices of Desi Ghee both in private and public sectors.

(b) The production and marketing of Desi Ghee is largely in the hands of private-sector Desi ghee is also not subject to any price control. Increase in prices of desi ghee appears to have been influenced by the behaviour of the prices of edible oils, feed, fodder and milk and prices of other essential commodities.

(c) Government has consistently undertaken a number of programmes in the Central sector and State Plans for development of livestock and dairies for increasing production of milk and to maintain the price of milk and milk products at reasonable levels keeping the interest of producers and consumers in view.

सूरत, गजरात में कमान्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए सहायता

*180. श्री छोटू भाई गामित : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उकाई काकाडापुर कमान्ड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, सुरत, गुजरात ने भारत सरकार से कमांड एरिया के विकास की योजना में सहायता करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजना के लिए कुल कितनी राशि की सहायता की मांग की गई है और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (घ) गुजरात सरकार के अनुरोध पर उकई ककरापार परियोजना 1974 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थापना, सर्वेक्षणों, फील्ड चैनलों का निर्माण करने, भूमि समतल करने, फील्ड ड्रेनों का निर्माण करने तथा वारबंदी लागू करने जैसी आइटमों पर हुए व्यय के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को बराबर की सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार से कार्यक्रम में सम्मिलित सभी परियोजनाओं के लिए दावे प्राप्त होते हैं न कि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग। गुजरात सरकार ने वर्ष 1983-84 के लिए 256.22 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में दी गई है, पहली किस्त पिछले वर्ष में व्यय न की गई शेष राशि को समायोजित करते हुए एक वर्ष में देय राशि की लगभग आधी थी। 1982-83 में गुजरात सरकार को दी गई कुल राशि में से व्यय न की गई 30.07 लाख रु० की शेष राशि को हिसाब में लेते हुए, 102.55 लाख रुपए की राशि दी गई है। जनवरी, 1984 तक वास्तविक कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष

के शेष भाग के दौरान संभावित कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के पश्चात् राज्य सरकार को देय राशि फरवरी, 1984 में दे दी जाएगी।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1983-84 के दौरान उकई ककरापार परियोजना के लिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए भौतिक लक्ष्यों में, 30,200 हैक्टेयर को शामिल करने के लिए फील्ड चैनलों का निर्माण करना, 5,500 हैक्टेयर से अधिक भूमि समतल करना, 7,850 हैक्टेयर को शामिल करने के लिए फील्ड ड्रेनों का निर्माण करना तथा 10,000 हैक्टयर से अधिक में वारबंदी लागू करना शामिल है।

Bomb Scare in Nehru Stadium

*181. SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Will the Minister of SPORTS be pleasedto state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item regarding a bomb scare at the Jawahar Lal Nehru Stadium recently ;

(b) if so, whether in view of recent upsurge in extremist activities in and around the capital, adequate security arrangements have been ensured to protect the life of persons using it and assests of the said stadium ;

(c) whether Government are thinking to create a special Security force for the protection of the stadium and its users ;

(d) if so, details thereof ; and

(e) if not, how the people using the stadium and the stadium itself are being kept out of bound of such extremist elements ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) to (e) Attention of Government has been drawn to the news item regarding a bomb scare at the Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi on the 24th October, 1983. The bomb scare proved to be a hoax.

The watch and ward functions in the Jawarharlal Nehru Stadium and in the other Asiad stadia are being discharged by private agencies. The security arrangements at the Asiad Stadia, in general, and those at the Jawaharlal Nehru Stadium, in particular; were reviewed at a meeting held on 28th October, 1983 which was attended among others by the Delhi Police authorities. At this meeting, certain additional measures aimed at tightening security arrangements were decided upon. So far, the security arrangements at the various Asiad stadia have proved satisfactory. There is no proposal at present to create a special security force for the protection of the stadia and their users.

Strike In Eastern Zone of F.C.I. On Deputationists And Grant of Interim-Relief

1851. SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government have been informed about the strike by F.C.I. Employees Union in East Zone on 4 October, 1983 opposing the proposal to absorb 4000 deputationists of State Government of West Bengal in F.C.I. ;

(b) if so, the action taken by Government against F.C.I. authorities for considering absorption of deputationists ;

(c) whether a case in this matter is pending before the Supreme Court involving all concerned as party ;

(d) whether it is also a fact that the deputationists of West Bangal in F.C.I. have been given interim-relief and other monetary benefits for which recovery is being made from the Government of West Bengal ; and

(e) if so, whether consent of State Government has been taken for such payments and if not, the action being taken to withdraw this benefit ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) It is true that some of the Unions of the Food Corporation of India have expressed themselves against absorption of deputationists of State Government of West Bengal in F.C.I. However, th question of absorption of deputationists ise being considered on merits.

(c) Some of the deputationists have filed a petition before the Supreme Court against their reversion to the State Government and the case is pending in the Court.

(d) and (e) The Food Corporation of India has been paying interim relief to the West Bengal deputationists with he consent of the State Government.

Sale of Spurious Napthaline Balls

1852. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) how many items apart from napthaline balls in plain polythene bags without the manufacturer label are being sold in the market in violation of the standards of Weights and measures Act, 1976 and what action is proposed to be taken to enforce strictly the provisions of the Act ;

(b) whether the halwais can weight carton alongwith the sweets ; and

(c) if not, whether there is any proposal to check the cheating of the buyers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) No specific complaints have been received in this regard. In case there is a violation of the Standards of Weights and Measure Act, 1976, appropriate legal action is taken by the State Enforcement officials.

(b) and (c) As weighing carton along with the sweets would result in short delivery of the actual commodity, the practice is violative of the Weights and Measures (Enforcement) Acts of the States. The State Enforcement officials have a system of regular checking of the activities of traders including halwais to prevant short delivery.

Casual Labour

*1853. SHRI R.N. RAKESH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of casual labourers employed under his Ministry and how many of them have been working over 1 year, 2 years, 3 years, and above ; and

(b) whether this is in keeping with the policies and programmes of Government and if not, the reasons for this neglect of of labour ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Governments Accommodation For Doordarshan Cameramen

*1854 SHRI RAM SINGH SHAKYA : SHRI R.L.P. VERMA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the reasons for which the Doordarshan Cameraman are not being allotted residential accommodation applied for between 1980 and 1983 and are eligible to get hostel accommodation ;

(b) whether the T.V. Cameramen have odd hour service conditions but are still waiting for their turn for hostel accommodation ;

(c) particulars of the T.V. Cameramen who have applied for the hostel accommodation between 1980 and 1983 ; and

(d) when are they likely to be allotted the hostel accommodation on priority basis, if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) The day an officer starts drawing either Rs.700/-or Rs.1,000/-, as the case may be, is counted as his date of priority for single suite and double suite hostel accommodation respectively and a seniority waiting list is prepared accordingly. Whenever the turn of an officer is reached in the waiting list, allotment of accommodation is made in his favour.

(c) It is not feasible to furnish the particulars as the Computerised Master Waiting List does not give details about the designations of the officers.

(d) The T.V. Cameramen will be allotted General Pool hostel accommodation as soon as their turn is reached in the relative Waiting List.

Supply Of 'Ganga Jal' To Delhi

1855. SHRI G.Y. KRISHNAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a scheme to be introduced for supplying Ganga Jal' to the residents of Delhi ; and

(b) if so, when it is likely to come in to operation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir, there is a scheme.

(b) As reported by the Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking, the first phase of the Scheme is likely to be commissioned by the end of 1983.

Nuclear Energy for Increasing Rice Production

1856. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether any experiments have been made by the Indian Agricultural Research Institute in producing superior variety of rice combining nuclear and conventional breeding methods with yield potential of more tonnes per hectare ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the areas in the country considered suitable for cultivation of this variety of rice ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir. In the Nuclear Research Laboratory, Indian Agricultural Research Institute, a number of strains of rice have beeh developed through the combined use of nuclear and conventional breeding methods.

(b) The mutants isolated by IARI, possess new maturity and adaptation characteristics, better responsiveness to fertiliser application, better protein quantity and quality and disease resistance. These lines have been used in breeding programmes.

(c) At present, the rice strains are under trial at various locations in the country. The areas in the country where they are considered suitable for cultivation cannot therefore be indicated at this stage.

Discouraging the Construction of High Rise Buildings Due to High Energy-Use

1857. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any opinion has been expressed by experts that construction of high-rise buildings should be discouraged as they are major users of electricity for air-conditioning and cooling equipment besides operation of lifts;

(b) if so, whether Government propose that urban buildings designed for possible air-conditioning, must be subjected to clearance from the point of view of energy saving technology incorporated ; and

(c) whether Government would also like to educate designers and manufacturers of construction products to make them conscious of need for creating energy saving devices ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) (a) to (c) : An Expert Group has been set up by the Government to consider ways and means for curbing growing energy demands of commercial offices and hotels. This Group is to submit its report by the end of December, 1983. Since the deliberations of the Group are not yet over it is not possible for the Government to comment upon the views expressed by its members, during the meetings held from time to time or to initiate any action in this regard.

Assistance to Small and Marginal Farmers to Increase Agricultural Production

1858. SHRI ARUN KUMAR NEHRU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the States which have agreed to implement the Centrally sponsored programme to small and marginal farmers for increasing agricultural production ; and

(b) the amount which has been released in favour of such States and details of the progress made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) All States and Union Territories except Rajasthan have agreed to implement the Centrally Sponsored Scheme of assistance to small and marginal farmers for increasing agricultural production. Acceptance from Rajasthan is awaited. Dadra & Nagar Haveli do not however, need any funds under this scheme.

(b) Two instalments of funds amounting Rs. 67.2198 crore for the first and second quarters ending June and September, 83 have been released as central share to the concerned States and Union Territories. Many States Governments have reported that State level coordination committee have been constituted and they have worked out district-wise and block-wise targets and funds for each component of the scheme and communicated to the concerned implementing agencies. For Minor Irrigation work the beneficiaries are being identified by the States for construction of dug-wells and installation of pump sets/tubewells. Some States have identified beneficiaries and have started forwarding applications of the beneficiaries to financial institutions for credit and availing the subsidy available under the scheme. Certain components like minikit distribution and plantation of fuel and fruit trees have been implemented by a number of States.

विदर्भ के संतरा बागानों में बीमारी फैलना

1859. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या किसी रहस्यमयी बीमारी के कारण विदर्भ क्षेत्र में संतरे के बाग धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूना के संतरा अनुसंधान केन्द्र ने इस बीमारी का पता लगाया है ;

(ग) किसानों को इस सम्बन्ध में अब तक कितनी मदद दी गई है ; और

(घ) यदि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) यह बताया गया है कि विदर्भ क्षेत्र में संतरे के बाग "कोल्शी" नामक रोग से प्रभावित हुए हैं जो मुख्यतया सफेद/काली मक्खियों के प्रकोप से होता है। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है क्योंकि यह एक सुअभिज्ञात रोग है।

(ख) पूना में कोई संतरा अनुसन्धान केन्द्र नहीं है।

(ग) स्थानिकमारी क्षेत्रों में खरपतवार नियन्त्रण सहित कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट एवं रोगों पर नियन्त्रण पाने तथा उसके उन्मूलन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत् महाराष्ट्र सरकार को इसी प्रयोजन के लिए राज सहायता के केन्द्रीय अंश के रूप में 25.20 लाख रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। वर्ष के प्रथम तीन तिमाहियों के लिए धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Survey of Encroachement in Forest and Revenue Land in Andaman and Nicobar Islands

1860. SHRI BABU RAO PARANJPE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a comprehensive survey of encroachment in forest and revenue lands in Andamans and Nicobar Islands is being done ; and

(b) if so, the findings as yet and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes Sir, a comprehensive survey has recently been done.

(b) The findings of the comprehensive survey of revenue and forest lands are as follows :

(1) Revenue land-2384 ha. with 3877 persons as encroachers.

(2) Forest land-2847 ha. with 1795 persons as encroachers.

The findings of the survey are under examination of the Andaman & Nicobar Islands Administration.

Districts Included in Narmada Valley Project

1861 SHRI A. K. ROY : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) names of districts of different States included in the Narmada Valley Project, facts in details;

(b) whether there are scheduled areas in that, if so, names and details of that giving its percentage of the total area; and

(c) whether there is any special constitutional provision to deal with the scheduled areas before any dam is constructed there, if so, details of that and steps taken on that facts in details ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The Honourable Member is presumably referring to the names of districts coming under submergence under the inter-State Sardar Sarovar Project on Narmada River. The Sardar Sarovar Project involves a submergence of 34,882 hectares as per district-wise details given below :

State	District	Gross area coming under submergence (in hectares)	Scheduled area* in the district
Gujarat	i) Vadodara	3310	Naswadi and Chhota Udaipur Taluks
	ii) Bharauch	4159	Nanded Taluk
Maharashtra	i) Dhule	6684	Nawpur, Akalkuwa and Akrani Taluks.
Madhya Pradesh	i) Dhar	8902	Sardarpur, Dhar, Kukshi and Manawar Tahsils
	ii) Khargone	8229	Barwani, Rajpur, Sendhwa, Bhikangaon, Khargone & Maheshwar Tahsils.
	iii) Jhabua	3598	Full district
	Total :	34882	

* The above districts include Scheduled Areas but the details regarding areas out of these Scheduled Areas coming under submergence are not available.

(c) There is no specific Constitutional provision to deal with scheduled area which comes under submergence due to construction of dams.

Promotion of Sports in Rural Areas

1862. SHRI ASHFAQ HUSAIN : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether there is any programme to give promotion to sports in rural areas ;

(b) if so, details of the programme and funds allocated therefor, year-wise for the period beginning with 1 April, 1980 to 31 March, 1983 ; and

(c) funds allocation for this programme during the remaining years of Sixth Five Year Plan, year-wise ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Scheme of Rural Sports Tournaments has the object of involving a major segment of our youths in rural areas in sports activities. Under the scheme, competitions are organised by State Governments/State Sports Councils at Taluka/District/State levels. The expenditure is met partly from grants given by the Central Government and partly by State Governments/State Sports Councils. Selected players or team, on the basis of these competitions participate in All India Rural Sports Tournaments which are conducted at various places in India annually. Rural Sports Centres are located in schools in rural areas or at other places where grounds are available. The expenditure under this scheme is also shared by the Central and State Government concerned on fifty-fifty basis. Besides, 182 sports coaches have also been attached to Nehru Yuvak Kendras with a view to promoting sports in rural areas.

The funds allocated for the above programme are given below :—

Scheme	Funds allocated for the years			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
Rural Sports Tournaments	6 lakhs	10 lakhs	10 lakhs	14 lakhs

No earmarked funds are allocated for setting up of Rural Sports Centres but grants are given for this purpose to the State Governments/State Sports Councils on the basis for proposals received from them and approved by Department of Sports, under the scheme of Grants to State Government/State Sports Councils. The funds allocated for the scheme last mentioned were as under :—

Scheme	Funds allocated for the years			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
Grants to State Governments/State Sports Councils	50 lakhs	60 lakhs	60 lakhs	80 lakhs

(c) The allocation of Plan funds for 1984-85 is yet to be finalized in consultation with the Planning Commission.

Ranuala Irrigation Project

1863. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Ranuala Irrigation Project's execution has been delayed beyond the target date of its execution ;

(b) if so the main reasons for the delay in executing that irrigation project ;

(c) whether the execution of the above irrigation project can be completed during the Sixth Plan period ; and

(d) if so, steps being taken to complete the execution of that irrigation project expeditiously by the end of the Sixth Plan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) The Honourable Member is presumably referring to the Ramiala medium irrigation project in Dhenkanal district under execution in Orissa. The Government of Orissa have reported that the project was originally targetted to be completed by June 1983 and that the revised target date of its completion is March 1985.

(b) The main reason for delay in the completion of the project has been reported to be the non-availability of forest land in time, delays in land acquisition and inadequate funding by the State.

(c) and (d) As against the latest estimated cost of the project at Rs. 12.77 crores an expenditure of Rs. 10.76 crores has been incurred upto September 1983. The above bottlenecks are also being remedied expeditiously to complete the project by end of VI Plan.

Reorientation of Deep Sea Fishing Policy

1864. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the steps have been taken by Government to reorientate their Deep Sea Fishing (DSF) policies towards quick expansion of the DSF fleet to effectively exploit the two million square k.m. of our exclusive economic zone and increase the marine fish production substantially for export as well as domestic markets ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Some of the important measures taken are :

(i) Augmentation of deep sea fishing fleet through a judicious mixture of indigenous, imported and chartered deep sea fishing vessels;

(ii) providing 33% subsidy on the cost of indigenously constructed deep sea vessels;

(iii) providing loans on terms for purchase of deep sea fishing vessels through the Shipping Development Fund Committee (SDFC) ;

(iv) augmentation of training facilities ;

(v) augmentation of fisheries rveys ;

(vi) assistance for the onstruction of fishing harbours at major and minor ports and of landing and berthing facilities at smaller fishing centres ;

(vii) regulation of fishing by foreign vessels in the Exclusive Economic Zone by promulgating the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Ve s Act, 1981 ; and

(viii) Stipulation of a condition of obligatory purchase of deep sea fishing, fishing vessels under progra me of charter of foreign vessels.

Construction of Link Roads in Bihar

1865. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the roads, tanks etc. to be undertaken during 1983-84 and 1984-85 in Bihar and particularly in the district of Madhubani and Darbhanga under the programme announced by the Prime Minister on 15 August, 1983,

(b) whether Bisfi (birth place of Poet Vidyapati) and Benipatti, Benipatti and Shahasghat (Madhawapur block) Bisfi and Jaley and such other inter bloc Headquarters link-roads in Madhubani and Darbhanga districts are included in this project ; and

(c) if so, details thereabout?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISHRA) : (a) No proposal under the Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP), announced by the Prime Minister on 15th August, 1983 has been received by the Ministry of Rural Development from the Government of Bihar.

(b) and (c) Question does not arise.

मध्य प्रदेश को उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन

*1866. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने **वाला** एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि **वर्ष** 1982-83 **और** 1983-84 ः ः द्वारा **मध्य प्रदेश** को जिनमें खद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल,खाद्य तेल आदि सहित उपभोक्ता वस्तुओं के आवंटन **का** ब्यौरा सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को विभिन्न वस्तुओं के किए गए आबंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

गेहूं : वर्ष 1982 के **दौरान** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3.02 लाख मीटरी टन गेहूं का आबंटन किया गया, जबकि वर्ष 1983 के लिए 3.03 लाख मीटरी टन मात्रा आबंटित की गयी है ।

चावल : वर्ष 1982 के दौरान 2.67 लाख मीटरी टन चावल का आबंटन किया गया ।

वर्ष 1983 के लिए चावल का आबंटन 2.45 लाख मीटरी टन किया गया है।

चीनी : अप्रैल, 1982 से सितम्बर, 1983 तक 22,156 मीटरी टन चीनी का मासिक आबंटन किया गया। अक्तूबर, 1983 से इसका कोटा बढ़ाकर 23,276 मीटरी टन प्रतिमाह कर दिया गया है।

मिट्टी का तेल : वर्ष 1982-83 के दौरान, मिट्टी के तेल का 2,20,200 मीटरी टन आबंटन किया गया; वर्ष 1983-84 (सितम्बर 1983 तक) के दौरान 1,15,560 मीटरी टन मात्रा आबंटित की गई।

खाद्य तेल : तेल वर्ष 1982-83 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान 17,420 मीटरी टन मात्रा आबंटित की गयी। माह नवम्बर, 1983 के लिए 3,000 मीटरी टन मात्रा आबंटित की गयी है।

ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम

1867. **श्री राम लाल राही** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के प्रयास किए हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने के लिए उनके लिए चलाये गये विकास कार्यक्रमों का उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्रामीण स्त्रोतहीन बेरोजगार व्यक्तियों को संगठित करके एक नई योजना शुरू करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाने तथा उनका विस्तार करने और प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सुलभ कराने की गारंटी देने के उद्देश्य से "ग्रामीण भूमिहिनों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" नामक एक नया कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से शुरू किया गया है।

Lotus-Cum-Fish Culture Programme

1868. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry has taken up programme under which lotus-cum-fish culture has been carried out by landless mers;

(b) if so, the names of the States where s ch an experiment has been successfully carried out ; and

(c) the details of the programme of the Centre in sponsoring such scheme for promoting lotus-cum-fish culture?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not ise.

Amount Earma d for Rural Water Supply Scheme or the Year 1983-84

1869. SHRI NAVINI RAVANI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the amount earmaked for Rural Water Supply Scheme in country for the year 1983-84;

(b) the number of villages likely to be covered in each State ;

(c) the number of villages which are still ignored for the drinking water facilities in each State ; and

(d) whether any target has been fixed for providing such fac throughout the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The funds for Rural Water Supply for 1983-84, under the State Sector Minimum Needs Programme and the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme are :

(i)	MNP :	Rs. 319.414 crores
(ii)	ARP :	Rs. 199.60 crores
(iii)	Under the Centrally Sponsored incentive scheme based on performance :	Rs. 75.00 crores
	Total	Rs. 593.014 Crores

(b) The total number of problem villages likely to be covered during 1983-84 is 48846. The State-wise target number of villages is given in the enclosed Statement at A.

(c) The number of villages which will remain to be covered during 1984-85 out of the total of 230784 as on 1.4.80, will be 82998. Statewise details are in Statement 'B'.

(d) It is proposed to cover all the identified problem villages (i.e. 230784) by March 1985.

STATEMENT 'A'

Sl. No.	State/U.T.	Target (No. of Problem Villages) for 1983-84.
1.	Andhra Pradesh	1478@
2.	Assam	2380
3.	Bihar	2760@
4.	Gujarat	1000@
5.	Haryana	355
6.	Himachal Pradesh	800
7.	Jammu & Kashmir	460
8.	Karnataka	7728*
9.	Kerala	200@
10.	Madhya Pradesh	6000
11.	Maharashtra	3563
12.	Manipur	145
13.	Meghalaya	415
14.	Nagaland	80
15.	Orissa	5060@
16.	Punjab	125
17.	Rajasthan	3200@
18.	Sikkim	88@
19.	Tamil Nadu	1400
20.	Tripura	633
21.	Uttar Pradesh	8000@
22.	West Bengal	2400
23.	A & N Islands	63
24.	Aruncahal Pradesh	430
25.	Chandigarh	—
26.	Delhi	12
27.	Dadra & Nagar Haveli	—
28.	Goa, Daman & Diu	14
29.	Lakshadweep	—
30.	Mizoram	39
31.	Pondicherry	30
	Total	48846

@ Includes partially covered problem villages.

* Includes full coverage of partially covered villages of previous years.

STATEMENT 'B'

Sl. No.	State/U.T.	Target (No of Problem villages for 1983-84	Balance No. of problem villages on 1.4.84
1.	Andhra Pradesh	1478	1568
2.	Assam	2380	9524
3.	Bihar	2700	4059
4.	Gujarat	1000	2500
5.	Haryana	355	2200
6.	Himachal Pradesh	800	3049
7.	Jammu & Kashmir	460	3211
8.	Karnataka	7728	NIL
9.	Kerala	200	682

1	2	3	4
10.	Madhya Pradesh	6000	981
11.	Maharashtra	3563	1451
12.	Manipur	145	620
13.	Meghalaya	415	219
14.	Nagaland	80	340
15.	Orissa	5060	9765
16.	Punjab	125	143
17.	Rajasthan	3200	654
18.	Sikkim	88	10
19.	Tamil Nadu	1400	899
20.	Tripura	633	818
21.	Uttar Pradesh	8000	13104
22.	West Bengal	2400	16677
23.	A & N Islands	63	49
24.	Arunachal Pradesh	430	510
25.	Chandigarh	—	—
26.	Delhi	12	NIL
27.	Dadra and Nagar Haveli	—	—
28.	Goa, Daman & Diu	14	14
29.	Lakshadweep	—	—
30.	Mizoram	39	132
31.	Pondicherry	30	10
	Total	48846	82988

Assistance for Rural Water Supply Programme in Rajasthan

1870. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government have released assistance for Rural Water Supply Programme in Rajasthan ; and

(b) if so, the details of schemes under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes;, Sir.

(b) So far; 9143 Rural Water Supply Schemes covering 10974 villages at an estimated cost of Rs. 12511.415 lakhs have been approved under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme since 1977-78 for the state of Rajasthan. During the Sixth Plan, an amount of Rs. 7971.75 lakhs has been allocated under the ARP for Rajasthan. The details of the funds released are as follows :—

Year	Fund released
1980-81	559.10
1981-82	1504.19
1982-83	2229.50
1983-84	3363.83(upto 16-11-83)

In addition, an amount of Rs. 401 lakhs has been released for Rajasthan under the new Centrally Sponsored Incentive Scheme based on performance.

रिहायशी मकानों के लिए धोबी सुधार समिति, दिल्ली द्वारा दिया गया ज्ञापन

1871. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के धोबियों के एक संगठन "धोबी सुधार समिति" ने उन्हें कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने मांग की है कि उन्हें "धोबी घाट" के पास ही आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जांय ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से हाकी प्रशिक्षक बुलाना

1872. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशों के हाकी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में, जहां इस खेल का जन्म हुआ, कोई प्रशिक्षक नहीं है ; और

(ग) यदि भारत में हाकी प्रशिक्षक हैं, तो फिर उन्हें नियुक्त न करने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय प्रशिक्षकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय हाकी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Fish Development in Orissa

1873. SHRI MANMOHAN TUDU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether some Centrally sponsered schemes have been introduced for fish development in Orissa during the last three years;

(b) if so, the amount of Central assistance given to Orissa for fish development in the above mentioned years ; and

(c) the details of the fish development programmes taken up in Orissa during that period ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Under the Centrally Sponsored Scheme of Island Fisheries Project with World Bank assistance, Fish farmers' Development Agencies have been set up in seven districts of Orissa, viz. Balasore, Cuttack, Puri, Ganjam, Bolangir, Sambalpur, and Phulbani for development of 16,000 ha of water area for intensive fish farming. These FFDAs have so far brought a water area of more than 4500 ha under scientific fish culture upto June 1983. Under the same project four commercial fish seed hatcheries are to be set up in Orissa for producing quality fish seed out of which three hatcheries are already under construction. A sum of Rs. 38 lakhs has already been released to Orissa so far out of Rs. 105 lakhs earmarked as Government of India's contribution for implementation of this Scheme in Orissa.

The Fish Farmers Development Agencies are also operational in the Districts of Dhankanal and Mayurbhanj under the Centrally Sponsored Scheme on Development of Aquaculture. An amount of about Rs. 6 lakhs has been released during 1982-83 under this scheme.

A new Scheme of brackish water fish farming with area development approah has also been introduced in Orissa in the year 1982-83. A sum of Rs. 2 lakhs has been released to Government of Orissa during 1982-83 on ad-hoc basis for taking up the project work.

Under the Centrally Sponsored Scheme on provision of landing and berthing facilities for fishing craft at minor ports, adminis-

trative approval to the Government of Orissa has been given in December, 1982 for Rs. 2.07 lakhs for construction of fishery jetty at Sabelia (Rambha). A sum of Rs. 50,000/- has been released to Government of Orissa 1982-83 under this scheme.

A centrally Sponsored Scheme on subsidy for group Accident Insurance Scheme for active fisherman has been introduced in Orissa. A sum of Rs. 60,000 has been sanctioned to Government of Orissa during 1983-84.

Lower Lagyap Hydel Project Ranipal Sikkim

1874. SHRI ANANDA PATHAK : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Lower Lagyap Hydel Project Ranipal, Sikkim has been completed and is to be handed over to the State Government ;

(b) if so, whether Government are taking steps to absorb the work-charged employees engaged for this project in alternate jobs ;

(c) whether he is aware that these work charged employees have expressed their willingness to go outside Sikkim if they are offered regular service with service benefits, seniority etc. ;

(d) if so, steps Government are taking to absorb them elsewhere outside Sikkim ;

(e) whether Government are aware that work charged employees of Lower Lagyap Hydel Project, Sikkim are currently on peaceful agitation demanding their absorption in alternate jobs in view of their threatened retrenchment on completion of the Project ; and

(f) if so, steps Goverment are taking to their agitation and to provide them alternate employment ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Efforts are being made to absorb them to the extent possible.

(c) to (f) : Some of the work-charged employees are only willing to go outside Sikkim. Some of the employees have been absorbed in the field offices of Central Water Commission and efforts are also being made for providing alternate jobs to the extent practicable for the remaining likely surplus staff. From the information available, the work-charged employees of Lower Lagyap Hydel Project Ranipal, Sikkim went on relay hunger Strike from the 28th October, 1983 and 9 employees went on indefinite hunger strike from the 31st October, 1983. However, the strike has since been unilaterally withdrawn with effect from the 5th November, 1983. The Government is exploring possibilities for absorbing the surplus staff in other offices of the Central Government and State Government and other Engineering Organisations at the Centre to the extent practicable. The Government of Sikkim have also been requested for the absorption of the likely surplus work-charged staff.

Exemption of 'Rehab litation Residential Lease' Holders from Convenants of Lease Deeds

1875. SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to reply to Unstarred Question No·4589 on 22 August 1983, and state :

(a) Particulars of Delhi colonies along with number of 'Rehabilitation residential leases, in each colony along with the land rates applicable to each colony or groups of colonies ;

(b) number of 'rehabilitation residedtial leases' in each colony between 200 to 400 square yards; 400 square yards to 600 square yards; 600 square yards to 800 square yards; 800 square yards to 1000 square yards; 1000 square yards and above;

(c) lay a copy of the terms contained in the rehabilitation residential leases as prescribed in the rules framed for the purpose on the Table of the House ; and

(d) whether Government have received representation from lesses other than rehabilitation lesses to ban inspection on such leases, if so, details thereof and Government reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :(a) The information in respect of the rehabilitation residential leases currently being administered by Land and Development Office, is given in the statement.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The terms are contained in various appendices as provided in the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955, a published and accessible document and as such, it is not proposed to lay any copy.

(d) No, Sir.

STATEMENT

Sl. No.	Residential Colony	Total No.	Present residential rate per square Metre (In Rupees)	Present commercial rate per square Metre (In Rupees)
1	2	3	4	5
1.	Aliganj	1046	1000	2000
2.	Andha Mughal	714	1000	2000
3.	Bharat Nagar	375	800	1600
4.	B.S.A.	930	800	1600
5.	Defence Colony	1710	2000	6000
6.	Edward Line	115	800	1600
7.	Golf Link	34	2000	6000
8.	Gur ki Mandi	138	800	1600
9.	Gulabi Bagh	124	800	1600
10.	Hathi Khana	65	1000	2000
11.	Hudson Line	1190	800	1600
12.	Indra Nagar	292	800	1600
13.	Jungpura	1986	1200	2400
14.	Jheel Kuranja	3425	800	1600
15.	Kalkaji	2530	1200	2400
16.	Lajpat Nagar Ist	1779	1200	2400
17.	Lajpat Nagar IInd	1325	1200	2400
18.	Lajpat Nagar IIIrd	485	1200	2400
19.	Lajpat Nagar IV CPCT & Double Storey A Type	3234	1200	2400
20.	Lajpat Nagar Vinobapuri	206	1200	2400
21.	Malviya Nagar	2180	1200	2400
22.	Malka Ganj	1025	1200	2400
23.	Moti Nagar	2775	1000	2000
24.	Hakikat Nagar	369	800	1600
25.	Narela	193	400	800
26.	Nicholson Road	77	1000	2000
27.	Nizammuddin	617	1600	4800
28.	New Qutab Road	195	2000	4800
29.	New Rajinder Nagar	1766	1600	4800
30.	Old Rajinder Nagar	2548	1600	4800
31.	Outram Line	1546	800	1600
32.	Old Rohtak Road	282	1200	2400
33.	Patel Nagar East	1060	1600	4800
34.	Patel Nagar West	3950	1600	4800

1	2	3	4	5
35.	Patel Nagar South	257	1600	4800
36.	Ramesh Nagar	3140	800	1600
37.	Rameshwari Nehru Nagar	490	1000	2000
38.	Sarai Rohilla	390	800	1600
39.	Sewa Nagar	72	800	1600
40.	Tilak Nagar	2525	800	1600
41.	Tihar I	2540	800	1600
42.	Tihar II	1765	800	1600
43.	Teliwara	88	1000	2000
44.	Timarpur	62	800	1600
45.	Vijay Nagar	590	1000	2000
46.	Motia Khan	242	1000	2000
47.	Kasturba Nagar	41	800	1600
48.	Ansari Market	26	1000	2000
49.	Bhagat Singh Market	70	2000	6000
50.	Gokhle Market	25	1000	2000
51.	Khan Market	65	2000	6000
52.	Lehna Singh Market	34	1000	2000

Government Accommodation Allotted to Political Parties and Labour Organizat ons

1876. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the details of Government accommodation (along with the covered area and address of each) in Delhi allotted for the purpose of offices/residences of staff of various political parties and labour organisations ;

(b) the arrears of dues in each case;

(c) which of the above political parties are not represented in the Parliament; and

(d) guidelines (paragraph-wise) for making allotments in such cases?

*THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) : Only such of the political parties or Groups as has been recognised as such by the speaker, are allotted accomodation. Otherwise, general pool accommodation is normally allotted to eligible Central Government Offices and their employees located within Delhi/New Delhi. However, requests for allotment of general pool accommodation to non-eligible offices/persons are also considered on merits of each case and allotments are made in exceptional cases with the approval of the competent authority.

Role of Bad Tendency Law in Aggravation of Urban Housing Shortage

1877. SHRI N. E. HORO : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether bad tendency laws contribute significantly to aggravating the urban housing shortage ;

(b) whether many people like to keep the houses vacant in the fear that they cannot get them vacated easily and sizeable number of houses are lying vacant in the Capital as well as in other cities for this very reason; and

(c) if so steps Government propose to take in this regard to give guarantee to the houseowners so that they may give their houses on rent without fear?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) and (c) It has been brought to the notice

of the Government that the Rent Control Legislation is acting as deterent to housing activiity. Therefore, it is proposed to amend the Delhi Rent Control Act, 1958 suitably.

(b) No such information is maintained by the Government.

Allotment of Land by DDA/Land D.O. to Educational and Cultural Organisations

1878. SHRI D.P. YADAV : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the maximum area of a plot of land allotted to an educational institution for educational purposes by DDA/L&DO which can be utilised by the educational institution for construction of residential quarters for its staff ; and

(b) whether Cultural Organisations are given the same facility as other educational organisations ; if not, the rules applicable to them in regard to (a) above ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The allotment of land for educational institutions such as primary schools, higher secondary schools and colleges is made on the basis of the norms provided in the Master Plan. A maximum of 15 per cent of the plot-area may be utilised for the residential quarters as a facility to their staff.

(b) The cultural organisations are allotted land under the category of public and semi-public facility areas and the residential component in such institutions is confined to the facility as watch and ward and hostels attached to such institutions. The total area under this facility is not to exceed 25 per cent of the total floor area achieved on the institutional plot as per the Master Plan provisions.

Financial Assistance by EEC for Drinking Water Supply Scheme in H.P.

1879. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR :Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any financial assistance has been given by the E.E.C. (European Economic Community) for the execution of any drinking water supply scheme in Himachal Pradesh during the last 3 years including the current financial year ;

(b) if so, the names and estimated cost of each one of these schemes alongwith the latest progress regarding the execution, disrict-wise;

(c) whether there are any constraints on account of (i) lack of finance (ii) shortage of material etc.for any one of these schemes ; and

(d) if so, the motive thereof and the remedial measures adopted/proposed to be adopted in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of the schemes are given in the statement attached. Progress reports on the execution of these schemes are awaited from State Governments.

(c) The State Government have not brought to the notice of this Ministry any such constrainst.

(d) Does not arise.

STATEMENT

Details of the Rural Water Supply Schemes to be assisted by the European Economic Community in Himachal Pradesh

S. No.	Name of Distt.	No. of Schemes	Population (1971) to be benefited	Villages included	Cost of construct on (Rs. in lakhs)	Period of completion
1.	Una	16	27,528	64	107.77	
2.	Kangra	17	21,205	114	131.00	
3.	Chamba	59	24,273	111	134.95	
4.	Bilaspur	20	34,176	139	148.39	
5.	Sirmour	31	17,601	155	169.53	Three
6.	Hamirpur	16	37,103	223	189.95	Years
7.	Solan	28	30,777	185	132.06	
8.	Mandi	17	25,892	139	207.26	
9.	Kulu	27	17,272	30	98.85	
10.	Simla	85	48,187	267	236.92	
	Total	316	2,84,014	1427	1556.68	

Attainment of Self Sufficiency in Edible Oil

1880. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the quantity of edible presently being imported by India and its cost ;

(b) whether this continued import is draining a considerable chunk of country's foreign exchange reserves ;

(c) whether despite the country's adequate resource endowments, the action taken to develop them in the sphere of elible oils has been seriously deficient and lacking in finding any substitute for this import ; and

(d) if so, what concrete steps Government propose to take to achieve self-sufficiency in the production of edible oil?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) The quantum of edible oils to be imported each year is decided by the Government taking into consideration the demand for and production of indigenous oils in the country, foreign exchange availability and international prices etc. The quantity of edible oil imported on Government account during the financial year 1982-83 was 9.80 lakh MT and its cost was Rs. 417.41 crores.

(b) In the context of the existing gap between the demand and supply of edible oils from indigenous sources which is estimated to be ranging between 10 to 12 lakh tonnes per year, it has beome necessary for the Government to import edible oils at competitive prices in the interest of the consumers.

(c) and (d) Concerted efforts are being made to attain self-sufficiency in vegetable oils in the country. Apart from the schemes under implementation by various State Governments, the Department of Agriculture & Cooperation are taking following measures to increase oilseeds production :

(1) Intensive programme for development of oilseeds in oilseed producing States. The Scheme aims at demonstration on farmers' fields, strengthening of seed production and distribution arrangement, expansion of plant protection measures extension of irrigated area etc.

(2) Launching of special projects on production of groundnut in Saurashtra region of Gujarat and soyabean in Madhya Pradesh.

(3) Better incentive to producers through fixation of minimum support prices.

(4) Intensification of research efforts for increasing the productivity of oilseeds.

(5) Increase in area under non-traditional oilseeds crop like soyabean and sunflower and exploitation of oilseeds of tree and forest origin, rice bran etc.

(6) Aprropriate oil usage policy by the vanaspati industry to encourage greater use of non-traditional oils.

Taking over of Wholesale trade of Potato and Onion

1881. SHRI AJIT BAG : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the retail and wholesale price of potato and onion in different States during the last six months, State-wise and month-wise details thereof;

(b) whether there is any proposal to take over the wholesale trade and supply of these items to different parts of the country at a afair price rate;

(c) if so, when and the details thereof ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR.M.S. SANJEEVI RAO): (a) The retail and wholesale price of potatoes and onions at selected centres in various States during the past six months is given in statement I and II.

(b) to (d) There is no proposal under consideration of the Union Government to take over the wholesale trade in potatoes and onions in the country as it would be a stupendous task to procure and sell them in a vast country like ours.

STATEMENT—I

Month-End Retail Prices of Potatoes and Onions

(Rs. per kg.)

STATE/CENTRE	POTATOES						ONIONS					
	JUNE 83.	JULY 83.	AUG. 83.	SEP. 83.	OCT. 83.	NOV. (11.11.83)	JUNE 83.	JULY 83.	AUG. 83.	SEP. 83.	OCT. 83.	NOV. (11.11.83)
Andhra Pradesh/ Nizamabad	2.40	2.50	2.40	2.40	NR	2.80	1.60	1.90	2.40	3.00	NR	2.80
Bihar/Patna	2.20	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	NR	1.80	2.00	2.75	2.25	2.50
Gujarat/ Ahmedabad	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Karnataka/ Bijapur	3.00	3.00	3.00	2.80	2.00	2.00	1.25	2.50	2.80	3.25	2.00	2.00
Maharashtra/ Bombay	2.60	2.80	2.80	2.50	3.00	3.00	1.80	2.20	2.20	3.00	3.00	3.00
Punjab/ Ludhiana	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00	2.00	2.50	3.00	3.50	3.50	4.00
Rajasthan/ S. Madhopur	2.00	2.50	2.00	2.00	2.40	NR	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
Tamil Nadu/ Madras	NR	2.50	2.80	2.00	2.30	2.70	1.80	2.00	2.60	2.60	2.40	2.00
West Bengal/ Gr. Calcutta	1.80	1.80	2.00	2.00	2.20	2.60	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.00
U.T./Delhi	2.20	2.20	2.20	2.20	2.50	2.50	2.00	2.60	3.00	4.00	4.00	5.00
U.P./Kanpur	1.80	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	NR	2.00	2.40	3.80	3.50	3.50

NR=Not Reported

STATEMENT—II

Month-End Wholesale Prices of Potatoes

(Rs. per quintal)

State/Centre	Variety	June 83	July 83	Aug. 83	Sept. 83	Oct. 83	Nov. 83
BIHAR Patna	Deshi White	190	190	200	200	200	200 (18.11.83)
GUJARAT Deesa	Dhankri	217	179	184	181	180	190 (18.11.83)
ORISSA Sambalpur	Imported/ Nainital/ Pahari	200	210	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
HARYANA Karnal	White/ Red	135	160	160	180	180	180 (18.11 83)
HIMACHAL PRADESH Mandi	Desi/ Table	102	170	175	118	N.R.	220 (18.11.83)
KARNATAKA Banglore	Superior	250	200	160	170	170	190 (11.11.83)
MAHRASHTRA Bombay	Telegaon No. 1/ Military	205	280	325	215	235	210
PUNJAB Jullundur	White/ Chandra-mukhi/ 2708	135	145	150	160	170	170 (18.11.83)
Ludhiana	White	130	135	140	175	185	180 (11.11.83)
UTTAR PRADESH Furrukhabad	Military	150	150	160	165	185	180 (18.11.83)
Kanpur	Deshi	130	170	180	170	185	170 (18.11.83)
Mainpuri	Military 1645/K22	125	130	135	135	140	N.R.
WEST BENGAL Calcutta	Deshi Nainital	145	150	165	168	225	225 (11.11.83)
DELHI	Special Numberi/ U.P. Gola	140	170	170	160	180	190

N.R.=Not Reported

Month-End Wholesale Prices of Onions

(Rs. per quintal)

STATE/CENTRE	VARIETY	JUNE 83	JULY 83	AUG. 83	SEPT. 83	OCT. 83	NOV. 83
ANDHRA PRADESH	Bellary	172	185	N.R.	200	125 (7.10.83)	N.R.
Cuddapah							
Hyderabad	Red No. 1	120	110	140	210	170 (18.11.83)	160
BIHAR	Dry	80	140	180	240	200	235
Patna						(18.11.83)	
GUJARAT	Red	N.R.	N.R.	N.R.	250	220	300
Jamnagar	(Deshi)					(11.11.83)	
MAHARASHTRA	Nashik	140	168	205	205	250	275
Bombay	No. 1						
Nasik	Pole/Red	125	140	175	225	225 (18.11.83)	220
Lasalgaon	Pole	125	155	212	204	232 (11.11.83)	251
TAMIL NADU	Small Kar	180	230	260	180	180	210
Madras						(11.11.83)	
Dindigul	Small Second	130	200	120	100	120 (18.11.83	160
UTTAR PRADESH	Red	98	160	180	275	310	320
Kanpur						(18.11.83)	
WEST BENGAL	Bombay	155	188	170	280	325	325
Calcutta						(11.11.83)	
DELHI	Mahua/ Desi/ Nasik	125	200	220	220	275	250

N.R.=Not Reported

Implementation of IRDP & NREP in Jammu & Kashmir, West Bengal and Andhra Pradesh

1882. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Governments of Jammu & Kashmir, West Bengal and Andhra Pradesh are not implementing IRDP and NREP programmes effectively ;

(b) if so, action taken by Government to improve the progress in above programmes ; and

(c) their progress and fund utilisation during 1982-83 and 1983-84 till today?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA): (a) The Integrated Rural Development Programme and National Rural Employment Programme are being implemented in

Jammu & Kashmir, West Bengal and Andhra Pradesh and the effectiveness of these programmes varies from District to District and Block to Block.

(b) The implementation of the programme is periodically reviewed by the Ministry in respect of all States. Central teams are sometimes deputed to undertake field visists in different States. Specific issues in the implementation of these programmes are discussed with the State Governments and other concerned institution and for taking suitable action.

(c) A statement showing the progress and utilisation during 1982-83 and 1983-84 is enclosed.

STATEMENT

(A) Statement showing progress and fund utilisation during 1982-83 and 1983-84 under the IRD Programme.

(Rs. in lakhs)

		J & K	WEST BENGAL	ANDHRA PRADESH
(i)	Number of blocks	75	335	324
(ii)	PHYSICAL TRAGET (No. of families to be assisted)	45,000	201,000	194,400
(iii)	TOTAL NO. OF FAMILIES ASSISTED			
	(a) 1982-83	353,45	95,607	284,783
	(b) 1983-84	5,309*	6,923**	47,727***
(vi)	CENTRAL RELEASE			
	(a) 1982-83 Rs.	159.00	362.00	1265.00
	(b) 1983-84 Rs.	26.00	Nil	604.00
(v)	TOTAL FUNDS UTILISED INCLUDING STATE SHARE			
	(a) 1982-83 Rs.	349.82	656.96	3126.91
	(b) 1983-84 Rs.	44.52	55.92**	594.08***

* Upto May, 1983,
** Upto May, 1983,
*** Upto September, 1983.

(B) Statement showing the progress and fund utilisation during 1982-83 and 1983-84 under the NREP.

(Rs. in lakhs)

(i)	TOTAL RESOURCES MADE AVAILABLE DURING			
	(a) 1982-83	366.47	5415.38	5275.72
	(b) 1983-84	275.31	2374.96	3245.53
(ii)	RESOURCES UTILISED			
	(a) 1982-83	240.76	3401.80	3977.84
	(b) 1983-84	69.71*	1530.25*	433.42**
(iii)	MANDAYS OF EMPLOYMENT GENERATED (LAKH MANDAYS)			
	(a) 1982-83	17.08	360.22	336.00
	(b) 1983-84	4.14*	174.95*	73.58***

* Upto September, 1983
** Upto June, 1983
*** Upto October, 1983

गांव-वासिवों को स्वा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण योजना

1883. **श्री छांगुर राम :** क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से गांव-वासियों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रशिक्षण योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में यह योजना शुरू की गई है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में लक्ष्य क्या हैं ; और

(घ) किस मानदंड के आधार पर गांवों और ब्लाकों का चयन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हाँ। ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की एक योजना केन्द्र और राज्यों द्वारा बराबर बराबर अंशदान के आधार पर शुरू की गयी है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश को लिया गया है और यह लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को शुरू की गयी है।

(ग) प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या नीचे दी गयी है :—

संख्या लाख में

वर्ष	लक्ष्य	प्रशिक्षित व्यक्ति
1979-80	1.00	0.402
1980-81	2.00	1.226
1981-82	2.00	2.024
1982-83	2.00	2.343 (अपूर्ण)

(घ) इस योजना के अन्तर्गत देश के सभी खण्डों एवं गांवों को लिया गया है।

Waiting List For D.D.A. Flats

1884 Dr. A.U. AZMI : will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to USQ No. 7794 on 18 April, 1983 regarding waiting list for D.D.A. flats and low quality constructions and state :

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, will the same be laid on the Table of House; and

(c) if not, reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Implementation statement has since been laid by the Department of Parliamentary Affairs on the Table of the Sabha on 21.11.1983.

Using Ozone Instead of Chlorine as Safeguard Against Waterborne Viruses

*1885 SHRI SUSHIL BHATTACHARYA : will the Minister of WORKS AND HOUSING be please to state whether Government contemplate switching over of the water works in the country to using ozone instead of chlorine as a much more effective safeguard againsts everal waterborne, harmful chemicals and viruses ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) :

The Government does not contemplate switching over to dis-infection by ozone in place of chlorine. For this method of disinfection; the energy requirments are high and need in-site manufacturing. Moreover, ozone, under cholorine was no residual disinfecting action for protection against contamination in the distribution system.

Floods in Madhya Pradesh

1886. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in Madhya Pradesh floods had affected 2,261 villages in 22 districts damaging

crops in more than 62,000 hectares and Government property worth Rs. 14.26 crores ;

(b) whether the State Government have sought Central assistance for flood relief operation ; and

(c) if so; the details thereof and the response of the Centre to the needs of Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMED KHAN) : (a) Yes; Sir. The Government of Madhya Predesh sent a memorandum in which the following damages have been indicated :

1. No. of districts affected	: 17
2. No. of villages affected	: 2261
3. Total population affected	: 713411
4. Total No. of human lives lost	: 27
5. Total No. of cattle lost	: 999
6. Total cropped area affected	: 71137 ha
7. Total No. of Houses damaged	: 12971
8. Total loss of public properties	: Rs. 13. 12 crores

(b) and (c) The State Government sought Central assistance of Rs. 2260.17 lakhs which included Rs. 343.19 lakhs for repair/restoration of National Highways. Subsequently the State Government submitted revised demand amounting to Rs. 2392.80 lakhs to the Leader of the Team which visited the State from 19.10.83 to 22.10.83. The Report of the Central Team has been received and is under processing.

Assistance to Small And Marginal Farmers.

1887. SHRI UTTAMBHAI H. PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Centre has made provisions for States for the assistance to small and marginal farmers in the country ;

(b) how much amount has been provided for the same ;

(c) how many States have utilised the provisions and implemented the schemes ;

(d) how many farmers are benefited in Gujarat and other States thereof ;

(e) whether some amounts of Central funds out of the sum provided are likely to remain unutilised by some State during the current financial year ;

(f) if so; the reasons given by Gujarat and other States therefor ; and

(g) the action taken by Centre in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMED KHAN) : (a) Yes Sir.

(b) An outlay of Rs. 125 crore has been provided in 1983-84 as Government of India share of the scheme on assistance to small and marginal farmers for increasing agricultural production. Union Territories are being given 100 per cent assistance under this scheme.

(c) All the States and Union Territories except Rajasthan are implementing the scheme and utilising the funds. Dadra & Nagar Haveli, however, do notr equire any funds for this scheme.

(d) About 600 farming families of the small and marginal farmers per block; depending upon the availability of funds have been planned to be benefitted in each State including Gujarat.

(e) Efforts are being made to utilise central funds for this scheme by the end of the current financial year.

(f) Does not arise.

(g) The implementation of the scheme is being closely followed up by Govt. of India and State Governments. All possible steps are being taken for fully implementing the different components of the scheme in the field.

ICAR Cattle Project

1888. SHRI KAMALA MISHRA MADHUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the ratio between males and its females mates specified in ICAR cattle programme with basis for large variation among centres between 1:11 at IVRI but 1:4 at Jabalpur and Rahuri ;

(b) the reasons why on 1 April, 1983 though there were 24 male calves upto six

months old, the corresponding females number was nil at Haringhata and the reasons to include number of calves born in 1983 quarter-wise and sex-wise ; and

(c) the number of calves born, quarter and sex-wise, in 1983 at each centre, genetic group-wise with corresponding age-wise mortality percentage ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Lok Sabha in the course of time.

Sale of Commercial Space And Position of Car Ramps In . otel Meredien

1889. SHRI RATANSINGH RAJDA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether pure drinks was allowed to sell commercial space before the starting of the Hotel Meredien ;

(b) the progress in the construction of the Hotal Meredien ; and when it is expected to be completed ; and

(c) whether the car ramps of the Hotel are protruding outside the hotel land and overhanging the footpath ; if so; what is planned to be done ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The Government has not allotted any land to M/s Pure Drinks (New Delhi) Ltd. However, the NDMC has reported that there is no condition in the licence agreement entered into by them with M/s Pure Drinks (New Delhi) Ltd. (now M/s C.J. International Hotels Ltd.) to give any portion on lease or rent, but that the hoteliers may sublicence; within the period of licence, for running car parking, cycle scooter stand for parking and shopping arcades, banks offices (within the shopping arcades), etc. subject to the provisions of the licence agreement.

(b) The NDMC reported that the strublural work of one block is complete, fifteen etore floors of the tower block are yet to lc consrtucted and that the licence has been umowed to complete the Hotel by the 30th aJne, 1985.

(c) The NDMC has denied that the car ramps of the Hotel protrude outside the land and overhang the footpath. Hence the question of taking any action on this account does not arise.

Action Based On Basu Committee Report

1890. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have taken action against the former Director, CSWRI based on Basu Committee Report, if so details of the guilt established and punishment given ;

(b) whether Government have decided further action for irregularities during his tennure as Dirictor CSWRI which have been found to be punishable ;

(c) if so, whether it took time to establish these irregularities but without awaiting the outcome he got promotion ; and

(d) if so, the details thereof and if not the basis therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) The former Director; Central Sheep and Wool Research Institute has been held to have not exercised adequate supervision and he has been given appropriate punishment commensurate with this lapse.

(b) No further action is contemplated against him as the above punishment is considered to be adequate.

(c) and (d) As regards his appointment to the post of Deputy Director-General (AS), it is stated that he was considered and selected for this post by the Agricultural Scientists Recruitment Board in response to an open advertisement. The ASRB is an independent body like UPSC and the selections are made by duly constitued Selection Committees of the Board. This selection was therefore approved by the President, ICAR subject to whatever disciplinary action that may be necessary on receipt of the findings of the Inquiry Committee. As stated above the disciplinary action is now complete and punishment has been awarded.

Thefts In I.I.S.R. Lucknow

1891. SHRI VILAS MUTTEMWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether on 15 August, 1979, 4 January, 1983, 30 January, 1983 some thefts had been committed in the Chemical Store, Guest House and Cattle Yard of the Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow ; and

(b) if so, action taken by the concerned authorities in order to fix the responsibility for the thefts and for making recoveries from those who were held responsible therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE : (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes Sir.

(b) These thefts were reported to the local Police Authorities. Departmental enquiries have also been instituted in all these cases. In the case of the Chemical Store theft the employee involved has been punished and the amount ordered for recovery by the disciplinary authority has been realised. The loss due to theft in the Guest House is also being recovered from the employees concerned. In the case of the theft in the Cattle Yard the enquiry has been completed and appropriate action will be taken by the competent Authority.

Consumption of Sugar

1892. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPELIS be pleased to state :

(a) whether, while formulating the export policy, the domestic requirement of sugar has been taken into account; and

(b) if so, the present consumption thereof in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir. The requirements for interenal consumption are invariablyn taken to account while deciding quantum of sugar for export.

(b) On account of bumper production during two successive seasons of 1981-82 and 1982-83, the availability of sugar has been very comfortable. The monthly sugar allocations were increased to 2.94 lakh tonnes in April, 1982 and further in October, 1983 to 3.13 lakh tonnes per month. The releases of free sale sugar are also being made on liberal basis. The total internal consumption of sugar during 1982-83 season was 64.61 lakh tonnes as against 57.11 lakh tonnes during 1981-82 season.

Prospects of Cotton Crops

1893. SHRIMATI USHA PRAKASH CHOUDHARI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the cotton crops prospects, current arrival and the estimated demand by the various sections of the users ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : According to available information, the prospects of cotton crop in the country in the current year are reported to be bright except in Punjab and Haryana where the crop has been damaged by bollworms, excessive vegeta tive growth and interruption of spray sehdule by intermittent and heavy showers.

Market arrivals of kapas in the current marketing season as reported from 501 markets in different parts of the country totalled 501.3 thousand quintals till the second week of November.

The likely consumption of cotton during the current season has been forecast at 82.65 lakh bales (comprising 78.00 lakh bales in the mill sector and 4.65 lakh bales by ex-factory user).

Price Rise of Essential Commodities

1894. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be plesed to state :

(a) whether it is a fact that since January 1980 the prices of the essential commodities and foodgrains have constantly been rising ; and

(b) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) There has been rise in the prices of various commodities since January, 1980.

(b) The movement of monthly index numbers of wholesale prices of selcted commodities since January, 1980 is indicated in a statement laid on the Table of the House [Placed in library *See* No. Lt-7154/83]

Recovery of Loans Hampers Development of Cooperative Banks

1895. SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether recovery of loans has come in the way of speedier development of co-operative banking ;

(b) whether any study has been carried out to find out the factors behind the poor repayment of loans which hampers the movement ;

(c) if so, whether the survey shows that a large number of recovey for loans has remained unrealised and this has resulted in a great loss to the co-operative banking; and

(d) if so, the steps Union Government have taken to improve the cooperative loans recovery and how much has been recovered during 1983 ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) to (c) Poor recovery of loans advanced by the Cooperative banking structure affects further flow of credit, as the operations of the credit institutions depend mainly on the recycling of funds. Studies had been conducted by the Reserve Bank of India in the past to ascertain the causes of overdues and suggest remedial measures to be taken by the banks and the State Governments. At the end of Cooperative year 1981-82, the percentage of overdues to demand stood at 43 at the Primary Agricultural Credit Society Level 35.3 at the Central Cooperative Bank evel 40.4 at the State Cooperative Land Development Bank level and 41.3 at the Primary Land Development Bank level.

(d) The eligibility conditions for refinance facilities from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) prescribed for Cooperative Banks aim at improving recovery of overdue amounts. Necessary steps for improving recoveries will have to be taken by the Cooperative Banks concerned and the State Governments. The Central Governments advises the State Governments from time to time to launch special recovery drives. The Union Minister for Agriculture has requested the Chief Ministers of States recently to intensify the recovery drive in the context of good Kharif production during 1983. However, the results of recovey efforts will be known only at the close of the Cooperative year in June, 1984.

Record Foodgrains Production

1896. SHRI HANNAN MOLLAH :
SHRI SUNIL MAITRA :
SHRI MOHAMMAD. ASRAR AHMAD :
SHRI SUDHIR KUMAR GIRI :
SHRI M.V. CHANDRASHEKHARA MURTHY :
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK:
SHRI ANANTHA RAMULU MALLU :
SHRI NAVIN RAVANI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the country is expecting record wheat and rice production this year ; and

(b) if so, the expected production of the two items ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) and (b) : In April/May, 1983, the country has harvested a record wheat crop of 42.5 million tonnes. This crop formed part of the 1982-83 rabi season. As regards the rabi season of 1983-84, the sowings of wheat are in progress under favourable conditions. Intensive rabi production effort has also been launched and in case the weather and rainfall conditions are favourable, the present record level may be exceeded. With regard to rice, according to the present expectations, the prospects for a record crop of rice during 1983-84 are bright. If the north-east monsoon and weather and rainfall conditions for summer rice are favourable, it would be possible to achieve a record level of 57 million tonnes.

Increase in Price of D.M.S. Milk

1897. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :

Will the Minister fo AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the reasons for the recent 50 per cent increase in the price of Delhi Milk Scheme milk ;

(b) how the increase in the price of milk by D.M.S. has affected the low and middle income group consumers ; and

(c) how far the steep rise in the price of milk is in consonance with the White Revolution and to what extent the Indian Dairy Corporation and the National Dairy Development Board have been able to fulfil their task of raising milk production in the capital's neighbourhood ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The revision of the price of toned milk supplied by Delhi Milk Scheme from Rs. 1.80 to Rs. 2.70 per litre with effect from 9th September, 1983, after a period of over 5 years, was necessitated due to increase in the cost of raw material and other inputs which resulted in the increase in the cost of production.

(b) Increase in price has affected all the consumers of DMS Milk.

(c) The price of milk like other commodities is governed by various economic factors. The milk production in the country has increased, but it has not been able to keep pace with the growing demand. Operation Flood Projects and other Animal Husbandry and Dairy Development Programmes of the Central and State Governments have contributed to increasing milk production. However, contribution of Indian Dairy Corporation/National Dairy Development Board cannot be specifically identified.

Sale of Asiad Flats to non-Resident Indians

1898. SHRI XAVIER ARAKAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether the flats constructed during the Asiad are going to be sold to the non-resident Indians ; if so, the details ;

(b) the land acquisition and the construction costs per flat and the selling prices to the non-resident Indians and the rationale in selling to the non-resident Indians ; and

(c) how are Government going to solve the housing problems of the poor Indians ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir. The details of the Scheme are given in the statement.

(b) The cost of construction roughly come to Rs. 1800/-per sq.mtr. of the plinth area. The cost of flats ranges between Rs. 7,20,000/- to Rs. 15,65,000/- depending upon the type & size of the flat. This decision has been taken with a view to earning scarce foreign exchange and help Indians returning from abroad to settle properly.

(c) : The DDA have introduced other schmes like New Registration Scheme, 1979, Self Financing Scheme and Special Registration Scheme for Retired/Retiring persons to solve their housing problem.

STATEMENT

The Government of India have decided to dispose of all the 853 flats in Asian Games Village to the following categories of Indian Nationals :—

(i) Indian Nationals residing abroad ;

(ii) Indian Nationals serving in International Organisations either in India or abroad we can legitimately pay in foreign exchange ; and

(iii) Indian Nationals who were International employees until recently but have returned to India and would be able to pay in foreign exchange within the permitted period of maintenance of a foreign account.

The DDA has invited applications from the eligible persons by 30-12-83. The cost of dwelling unites ranges between Rs. 7,20,000 to Rs. 15,65,000 depending upon the type & size of the dwelling unit including the cost of fixtures & furnishings and also the cost of garages & servants quarters whenever provided. There are, in all 29 type designs. The payment will be received in U.S. dollors only, through the following six banks :—

(1) State Bank of India

(2) Central Bank of India

(3) Bank of Baroda

(4) Indian Overseas Bank

(5) United Commercial Bank

(6) Bank of India

Efforts are being made by the DDA to complete the sale by 31st March, 1984.

Survey Report Regarding Extension of Lilwa Branch of Rajasthan Canal

1899. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the progress about the completion of the survey report regarding extension of Lilwa Branch of Rajasthan Canal upto Gadra Road ;

(b) whether project report of the scheme had been prepared by the Rajasthan Government and presented to Central Government ;

(c) the amount sanctioned for the said scheme ; and

(d) the time by which the work on the said branch will be started ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d) The State Government has intimated that preliminary alignment of extension of Sagarmal Gopa (Lilwa) Branch of Rajasthan Canal upto Gadra Road has been laid at site and detailed snrvey of the Command is proposed to be got done from the Survey of India. The Project Report of the Scheme has not been prepared and no provision of funds for the Scheme was made in the Current Financial Year. The State Government has proposed to take up preliminary work on the Scheme during 1984-85.

दिल्ली में राशन में गेहूं और चीनी का सप्लाई किये जाने वाला कोटा

1900. श्री भीम सिंह :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री रतन सिंह राजदा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गेहूं और चीनी के राशन में दिये जाने वाले कोटे में हाल में कमी की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष देश में गेहूं और चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) दिल्ली में कार्डधारियों को वितरित किये जाने वाले गेहूं के कोटे की मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है । तथापि, प्रति माह प्रति यूनिट दी जाने वाली चीनी की मात्रा को 900 ग्राम से घटा कर 800 ग्राम किया गया है, क्योंकि अन्य राज्यों में प्रति यूनिट 400-425 ग्राम के अखिल भारतीय औसत की तुलना में दिल्ली में दी जाने वाली मात्रा दोगुनी से अधिक थी ।

(ग) वर्ष 1980-81 में 363 लाख मी० टन तथा 1981–82 में 375 लाख मी० टन की तुलना में वर्ष 1982-83 के दौरान गेहूं का 425 लाख मी० टन के लगभग उत्पादन हुआ है । जहां तक चीनी का संबन्ध है, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार इसका उत्पादन 1981-82 के दौरान हुए 84.78 लाख मी० टन उत्पादन की तुलना में 1982-83 में थोड़ा सा घट कर 82.32 लाख मी० टन पर पहुच गया है ।

Adulteration of Vanaspati with Beef Tallow

1901. PROF. MADHU DANDAVATE : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the factors that have led to adulteration of vanaspati with beef tallow ;

(b) whether a wide gap between the prices of edible oils and beef tallow have encouraged such adulteration ; and

(c) steps taken to prevent such adulteration ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) (a) and (b) : The analysis of samples of banaspati taken from the various manufacturers has not shown any adulteration with animal tallow. Even at trade level only two samples of vanaspati were reported to have contained tallow by the Punjab Government so far.

(c) Import of tallow of all types has stopped by the Government since 1.10.1983.

The field staff of the Government are keeping a constant check and vigil on the quality of vanaspati being produced in the country. The State Governments have also been alerted to draw samples from the market, analyse them and take appropriate action under PFA Act.

Introduction of Land Acquistion Amendment Bill

1902. SHRI UTTAM RATHOD : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Land Acquisition Amendment Bill was introduced in the House and later on withdrawn ;

(b) whether it is also a fact that there is great discontent among land holders whose lands have been acquired for public purposes with meagre compensation ; and

(c) if so, action Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) A bill to amend the Land Acquisition Act, 1894 (Bill No. 67 of 1982) was introduced in the Lok Sabha on April 30, 1982. It has not been withdrawn.

(b) and (c) Representations have been received from time to time that some land owners consider the compensation payable to them under the Land Acquisition Act as inadequate. This is being examined.

Bogus Agents for Delhi Lotteries

1903. SHRI RAJESH KUMAR SINGH : SHRI NAWAL KISHORE SHARMA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some DDA officials are involved in appointing bogus agents for the Delhi Lotteries and have pocketed huge sums ; and

(b) if so, the details thereof stating the result of the inquiry conducted by Government in the matter and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा

1904. **श्री अनवर अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमेटिड ने 1975 से अपने वार्षिक लेखों को उनकी लेखा परीक्षा किसी पंजीकृत लेखाकार से कराकर अनुमोदन के लिए अपनी जनरल बाडी के समक्ष प्रस्तुत किया है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है कि जनरल बाडी के सामने लेखापरीक्षा लेखे प्रस्तुत किये जायें तथा जब तक लेखों का अनुमोदन न हो जाय तब तक प्रबन्ध समिति इस सोसायटी के धन को खर्च न करे ;

(ख) क्या पंजीकार, सहकारी समिति ने इस सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा पंजीकृत लेखाकारों से कराने के बजाए लेखा परीक्षकों से कराई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा लेखों की पंजीकृत लेखाकारों से लेखापरीक्षित कराने के बाद जनरल बाड़ी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस सोसायटी की प्रबन्ध समिति के चुनाव 1975 से नहीं कराए गए हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कब कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस समिति की आम सभा करने का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है । इसलिए, समिति का वार्षिक लेखा जोखा जनरल बाडी के प्रस्तुत करने के मौके का प्रश्न ही नहीं उठा ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विद्यमान प्रबन्ध समिति द्वारा व्यय

किया जाना है।

(ख) बकाया लेखा परीक्षा को शीघ्र पूरा करने तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए इस समिति के लेखों की विभागीय लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा करा ली गई है। लेखा परीक्षा किये गये इन लेखों को जनरल बाडी के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं आया क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

(ग) नये चुनाव कराने का मामला भी दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। चुनाव के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख तथा समय निर्धारित करना है।

बाढ़ के कारण जन जीवन और पशुधन की हानि के लिए मुआवजा

1905. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल की बाढ़ में मारे गए लोगों तथा पशुओं के लिए मुआवजा दिए जाने के बारे में कोई राशि निर्धारित की गई है या निर्धारित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस संबन्ध में भारत सरकार केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए सहायता के निम्नलिखित मापदंड अपना रही है :—

(1) मानव की मृत्यु होने के मामले में अधिक से अधिक 1,000 रुपए की अनुग्रह अनुदान की रकम ;

(2) (क) बाढ़ों या तूफानों में बैलों के मर जाने के मामले में देशी बैलों की प्रति जोड़ी के लिए 2,000 रुपए की दर पर राज सहायता दी जाती है।

(ख) प्रतिदिन 5 लिटर दूध देने वाली देशी गाय के मामले में 1000 रु० की दर पर और भैंस के लिए 2,000 रु० की दर पर राज सहायता दी जाती है।

लाभानुभोगियों के लिए मात्रा आई० आर० डी० की सहायता की पद्धति पर परिकिलत की जाती है।

Housing Shortage in the Country

1907. SHRI B.V. DESAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether the housing shortage during 1981 has been estimated at 00.1 million units for the entire country taking the criterion of providing each household with only a pucca house ;

(b) if so, whether the National Sample Survey Organisation has made a survey and has reported that if this norm is taken to include semi-pucca houses, the shortage of houses is 51.7 million and 23.5 million in terms of serviceable kutcha units ;

(c) if so, the States where this shortage has been the highest ;

(d) the States where shortage has been less ;

(e) whether any directive has been issued by his Ministry to the State Governments in regard to the housing shortage in their States, and

(f) if so, steps being taken by Union Government to improve position of housing shortage during 1983-84 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) (a) to (d) : The National Sample Survey has not conducted any survey but the National Buildings Organisation has estimated the housing shortage on the basis of the data of 1981 census on housing stock and households as follows :

Criteria of housing unit to be provided to eash household	Shortage (in millions)
(i) Pucca	88.75
(ii) Pucca or Semi-Pucca	49.62
(iii) Pucca, Semi-Pucca or Serviceable Kutcha	21.10

Based upon the criterion at (ii) above, the States having a housing shortage of over

3 million units are Bihar and Uttar Pradesh and the States having housing shortage of less than 1 million units are Nagaland, Punjab, Manipur, Himachal Pradesh and Haryana.

(e) and (f) : Housing is a State subject. Within the approved plan allocations, the State Governments are free to implement various social housing schemes according to their needs and priorities. During the current financial year a total outlay of Rs. 318.57 crores has been approved for housing. In addition, Housing & Urban Development Corporation aims at investing Rs. 132 crores in housing projects of various States/U.Ts. Housing finance from commercial banks of the order of about Rs. 150 crores would also be available in 1983 to individuals belonging to different income groups for construction of houses.

राजस्थान में सूखा

1908. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति के बारे मे किए गए सर्वेक्षण के आधार पर केन्द्र को कोई रिपोर्ट भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में सूखे और बाढ़ के कारण हुई क्षति का पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण के आधार पर कुल कितनी राशि की मांग की है ; और

(घ) केन्द्र का विचार इस राज्य को कितनी तथा किस रूप में सहायता देने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ख) सूखे से क्षति होने के संबंध में प्रश्न ही नहीं होता। बाढ़ से हुई क्षति नीचे दी गई है :—

1. प्रभावित जनसंख्या	4.95 लाख
2. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	0.17 लाख हैक्टेयर
3. क्षतिग्रस्त मकानों/ झोपड़ियों की संख्या	21439
4. मृत मानव	36
5. मारे गए पशु	482
6. सरकारी सम्पत्ति की हानि	590.31 लाख रुपए

(ग) अब तक सूखा राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई मांग नहीं की गई है।

(घ) उपरोक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

Hike in Prices of Tickets for Cricket Test Match

1909. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether Government realise that the outrageous hike in the prices of the season tickets for India VS. West Indies cricket test match in New Delhi from Rs. 30 to Rs. 50 and from Rs. 300 to Rs. 500 placed the match well out of the reach of the lower and middle income people and weaker sections have to stick only to small transistors ; and

(b) if so, whether Government propose to give chance to the economically weaker-sections of the people by lowering the price of the cricket tickets ?

THE MINISTER OF PARLIMENTARY AFFAIRS SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) The Government are aware that the prices of the season tickets fixed-by the Board of Control for Cricket in India for the test match in New Delhi in November, 1983 were higher than earlier test matches held in the city.

(b) The Government are not expected to interfere in the internal matters, like pricing of season tickets of the Board of Control for Cricket in India.

बक्सर-कोएलवार बांध का कार्य

191. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बक्सर-कोएलवार बांध-योजना का काम लगभग 15 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और क्या इस योजना का अभी आधा काम भी पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) क्या इस बांध के पूरा न होने के कारण प्रति वर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है ; और

(ग) इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम पर मुख्य कार्य 1973-74 में आरम्भ किया गया था । बिहार सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 2/3 कार्य जून 1983 तक पूरा कर लिया जाएगा ।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रों में 1971-78 की अवधि के लिए औसत वार्षिक बाढ़ हानि लगभग 815 लाख रुपए आंकी गई है । इसमें से लगभग 740 लाख रुपए की हानि फसलों तथा शेष हानि मकानों एवं सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि को हुई है ।

Machinery to Control the Distribution, Price and Quality of Pesticides

1911. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal for creating machineries to control the distribution, price and quality of the pesticides ; and

(b) if so, essential features thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) (a) and (b) : Pesticide is an essential Commodity under the Essential Commodities Act. The possibility of formulating a Control Order on the distribution, price etc. of pesticides has been under examination of the Government for some time past. However, taking into consideration the complexities of the measure, it has been decided to study the various aspects of bringing pesticides under statutory price control in consultation with various concerned Ministries and the Bureau of Industrial Costs and Prices.

2. As regards the quality control of the pesticides is concerned, Government have sanctioned two schemes for 'Setting up of Regional Pesticides Quality Control Laboratories' and 'Setting up of Quality Control Enforcement Cell' in addition to the Central Insecticides Laboratories already in existence at Faridabad, Bombay and Hyderabad. Under the Insecticides Act, 1968, powers are also vested in the State Governments for enforcement of quality of the pesticides manufactured, distributed and used in the States.

Delay in Completion of Dehang and Subansri Dam of Brahmaputra

1912. SHRI BISHNU PRASAD : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the estimates regarding the completion time and total cost of Dehang and Subansiri Dams of Brahmaputra ; and

(b) whether the projects are behind schedule and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) (a) Based on the reports prepared by Brahmaputra Board, the cost of the two projects is as below :

		(*Rs. Crores*)
Dehang Dam Project...	...	8300
Subansiri Dam Project	...	2575

(b) The projects are yet to be scrutinised and investment decision on the projects are yet to be taken.

Forest Revenure

1913. SHRI G. NARSIMHA REDDY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the gross and net forest revenue State-wise, for the last five years; and

(b) the amount allotted and actual expenditure on afforestation for the last five years, State-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The State-wise information available for last five years is laid on the Table of the House (placed in library see No. LT-7155/83)

(b) The State-wise information available for last five years is enclosed in Tables 2.1 to 2.5

Water Logging

1914. SHRI T.S. NEGI Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the details and seriousness of water logging problem affecting agriculture productivity at present; and

(b) the steps to tackle this problem ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The National Commission on Agriculture has reported that an area of about 6 million hectares is afflicted with the problem of waterlogging in the country. Out of this, about 3.4 million hectares is subject to surface flooding mostly in the States of West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Punjab, U.P., Gujarat, Tamil Nadu and Kerala. The remaining area of 2.6 million hectares represents waterlogging due to rise in ground water table. A study of the effect of waterlogging on crop production has indicated that crops like cotton, maize, bajra during Kharif and gram and barley in rabi are affected to a considerable extent by waterlogging.

(b) The remedial measures adopted for tackling waterlogging problems are (1) Drainage of either surface or sub-surface or both to remove surplus water;

(ii) Lining of canals to prevent seepage and rise of water table;

(iii) Sinking of tubewells and utilising water for irrigation, thereby lowering water table and augmenting recharge of ground water;

(iv) Connecting, where possible, all high water table tracts with-low water table tracks; and

(v) Adoption of proper crop management.

The Central Groundwater Board has proposed to take up studies on waterlogging in about 20 canal command areas for remedial measures during the 7th Five year Plan period.

More slums coming up in cities like Bombay and Bangalore

1915. SHRI T.R. SHAMANNA : Will the minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that in recent years large number of new slums are coming up in cities like Bombay, Bangalore etc; and

(b) effective steps being taken to remove the slums and rehabilitate the slums dwellers with the cooperation of State Governments ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) Definite information regarding increase of population living in slums is not available. Major schemes for environmental improvement of urban slums are taken up by States as part of the State Plan under the Minimum Needs Programme. Under this programme, basic amenities like water supply, sewers, storm water drains, community baths and latrines, widening and paving the existing lanes and street lighting are provided in the identified slum areas. In the face of the growing problem, the emphasis is now on the environmental improvement of slums rather than massive clearance and relecation.

Irrigation Facilities to Southern Parts of Bihar During Sixth Plan

1916 SHRI RAM SWARUP RAM : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to provide irrigation facilities for the southern portions of Tikari Block, Pariya, Delagang, Guruva in the district, Gaya (Bihar) before the end of the Sixth Five Year Plan; and

(b) if so, what are the proposals and details of the same ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) Two major and one medium on-going irrigation schemes benefit the areas in Gaya district of Bihar before the end of the Sixth Five Year Plan. However, details regarding blocks covered under irrigation are not maintained at the Centre. The details of the projects concerned are as under :

(Rs. lakhs/'000 ha.

Name of the Scheme	Latest estimated cost	Anticipated expenditure upto 3/84	Ultimate Potential	Target potential by the end of the VI Plan
MAJOR				
1. Sone H.L. Canal	5500	4537	161.40	160.40
2. North Koel Reservair	25639	8936	131.00	10
MEDIUM				
3. Understhan	448	398	24.89	24.89

Minor irrigation schemes have been taken up by the State Government in these blocks, details of which are not available at the Centre.

Malrpactices In Seed Exchange Pacts

1917. SHRI GHULAM MOHAMMAD KHAN :
SHRI SANAT KUMAR MANDAL :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of growing incidence of malpractices in seed exchange pacts with various countries ;

(b) whether good varieties of seed and planting material had been taken away by certain countries in exchange of inferior material ; and

(c) if so, the steps proposed by Government to check the abuse of seeds of wheat cotton, a variety of fruits and vegetables and its rich genetic material ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) No Sir.

(b) No Sir.

(c) The question does not arise.

Allocation of Palm Oil to Kerala

1918. SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Kerala has demanded allocation of more palm oil to meet its growing demand ; and

(b) if so, the quantity demanded and the total quanitity supplied by the Centre during the current year, month wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) Kerala Govt. had demanded 5000 MTs. of Palmolein per month from Sept., 1983. During the Oil year 1982-83 starting from November 1982 Kerala has been allocated the following quantities :

(Qty. in M. tonne)

Month	*Quantity allocated*
November, 1982	2,420
December, 1982	1,560
January, 1983	1,560
February, 1983	1,560
March, 1983	1,560
April, 1983	1,950
May, 1983	1,950
June, 1983	2,325
July, 1983	3,325
August, 1983	3,325
September, 1983	4,300
October, 1983	5,000
November, 1983	5,000
	35,835

Opening of more Fair Price Shops

1919. SHRI SONTOSH MOHAN DEB : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether a scheme of Central assitance for stepping up the supply of essential commodities through fair price shops had been offered to the North-Eastern State Governments ; and

(b) if so, the details thereof and the extent of benefits utilised by them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) Yes, Sir. In view of the weak resources base of the North-Eastern States, in the Sixth Five-Year Plan, there is a provision for assisting such States in setting up Civil Supplies Corporations as also for assisting these Corporations for constructing godowns for accelerating the supply of essential commodities under the public Distribution system. None of the States has taken advantage of this scheme so far.

Distribution And Waters From Rangwan Canal Dam And Gangau Dam Between Uttar Pradesh And Madhya Pradesh

1920. DR. VASANT KUMAR PANDIT: will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have represented to Central Government to direct U ttar Pradesh Government to give more water for irrigation from the Rangwan Canal Dam and Gangau Dam ;

(b) whether according to the 1972 agreement, U.P. Government had agreed to modify the structure of these dams to provide additional storage ;

(c) whether the above dams constructed by U.P. Government in Madhya Pradesh led to growing discontentment among the farmers and is causing a law and order situation ; and

(d) steps taken by the Centre to remove the dispute regarding equal distribution of water from the above Dams ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d) No representation from Government of Madhya Pradesh has been received in this regard. The 1972 agreement between Uttar Pradesh and Madhya Pradesh inter-alia, provides for sharing the waters of Rangwan Dam by the two States. In regard to the Gangau dam it was agreed that since this was silted up, and was not supplying adequate water for irrigation in Uttar Pradesh, the existing structure may be modified to provide for additional storage which will be equally shared between the two states, after meeting the shortage at Rangwan Dam. The Government of Uttar Pradesh has represented before the Central Zonal Council that Madhya Pradesh has built certain works in the catchment of Rangwan dam, diminishing the flows into it and therefore, they have pleaded for a review of the 1972 agreement. The matter is to come up before the next meeting of the Central Zonal Council where both Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are represented.

Report On Utilization Of Water Of West-Flowing River

1921 SHRI K.T. KOSALARM : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the recomendations made by the High Level Technical Committee which has submitted its reports on the utilisation of waters of West-following rivers ; and

(b) the action taken on these recommendations as also on the recommendations made by the Irrigation Commission in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The Irrigation Commission in their report of 1972 have observed that the Westflowing rivers of India constitute a significant source of water, and have suggested that it may be possible to divert a limited quantity of water from these rivers eastward for irrigation, and supply of drinking water. The recommendations of the Irrigation Commission had been circulated to the States for appropriate action. Subsequent to this a Technical Committee was constituted by the Central Government in December 1976 under the Convenorship of Member (Water Resource) Central Water Commission with representatives of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu to examine the feasibility of Eastward diversion of Westflowing rivers of Kerala and Karnataka Presumably, the Hon'ble Member of Parliament is referring to this High Level Technical Committee.

The Committee in its report submitted in March 1981 has stated that surplus waters

are available in some river basins of Kerala and Karnataka for Eastward Diversion. The Committee has also inter-alia recommended that the Government of Tamil Nadu may initiate discussions with the Government of Kerala on a bilateral basis for taking up of investigations of Projects for diversion of the surplus waters from these basins. The Committee have also further recommended that the State Governments of Tamil Nadu and Karnataka should frame suitable proposals for utilising the surplus waters available for irrigating areas in their drought-prone districts to the East of Westernghats The report of the Technical Committee was forwarded to the State Governments of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu for taking further necessary action in July 1981.

In accordance with the recommendation of the Committee in order to oversee and monitor the investigations to be carried out in respect of its West-flowing rivers and formulation of feasibility reports on projects, the Government of India has also constituted in July-August 1981 Coordination Committees separately for Karnataka and Kerala headed by a Central representative and consisting of representatives of Kerala and Tamil Nadu and Karnataka.

Loss Due To Floods in Uttar Pradesh

1922. SHRI RASHEED MASOOD : Will the Minister of AGRICULTTURE be pleased to state :

(a) Whether a Central team visited Uttar Pradesh to assess the loss due to the floods and the State's need for the relief work; and

(b) if so, the details there of stating the nature and extent of Central relief given to the State Government of U.P. to meet the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Yes, Sir. A Central Team visited some of the flood affected areas in Uttar Pradesh (i) from 10th to 13th October, 1983 and (ii) between 17th and 25th October 1983 to assess the damages caused by recent floods.

(b) Report of the Central Team has since been received and is under processing In the meantime, the Government of India have sanctioned a sum of Rs. 30 crores as Ways and Means advance to the Government of Uttar Pradesh to enable them to meet the emergent relief expenditure in the State. Government of U.P. have also got a Margin Money of Rs. 10.80 crores.

World Bank Housing Assistance To Maharastra

1923. SHRI R.R. BHOLE : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether financial assistance is being given by the World Bank to Maharashtra Government for housing the poor and middle class during 1984-85 ; if so, the amount of assistance ;

(b) how many houses will be built and where in Greater Bombay ; and

(c) whether the vacant land will be taken over under the Urban Land Ceiling Act and houses built there for the homeless and slum dwellers of Greater Bombay from this assistance ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (c) A multi-component urban development project for Bombay consisting mainly of provision of sites and services, slums upgradation and urban renewal is currently under discussion with the World Bank. It is not possible at this stage to indicate the timing of the project and the quantum of assistance.

Delay In Completion Of Ban Sagar Dam

1924. SHRI RAM PYARE PANIKA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that progress of Ban Sagar Project, by which three States-Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar are going to be benefited, is not going ahead according to fixed target ; and

(b) if so, what are the constraints in completion of the project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The execution of the project is

not progressing according to the accepted schedule, due to shortfall in the funds being made available by the beneficiary States and also the delays and in acquisition and rehabilitation.

Planning Commissions Clearance for Six Kerala Towns

1925. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission is yet to clear the six more towns to be included in the scheme suggested by Government of Kerala;

(b) whether it is also a fact that the total expenditure incurred on the scheme is far below the target; and

(c) if so, whether Government will take steps to get clearance from Planning Commission for inclusion of the towns which are suggested by Government of Kerala?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Under the Centrally Sponsored Scheme for Integrated Development of Small and Medium Towns 9 towns were allocated to Kerala State out of a total of 231 towns to be assisted. However the request of many States a proposal to enlarge the scope of the scheme to cover more towns, is being considered in consultation with Planning Commission and the Ministry of Finance. No final view has yet been taken on it.

(b) No. As far as the Government of Kerala is concerned, the physical and financial progress of the scheme is quite satisfactory. As against the release of Rs. 231.40 lakhs the State has incurred an expenditure of Rs. 283.90 lakhs upto June, 1983.

(c) The Ministry is trying to arrive at an early decision on the proposal.

हिमाचल प्रदेश में वन लगाने हेतु धन राशि का आवंटन

1926. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में और वन लगाने के लिए सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की ; और

(ख) कितने हैक्टेयर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पेड़ लगाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में वनरोपन के लिए दी गई कुल धनराशि तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत लाया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :—

दी गई धनराशि	755.20 लाख रुपए
कवर किया गया क्षेत्र	36898 हैक्टेयर

Import of Dangerous Pesticides

1927. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have since stopped the import of harmful/dangerous pesticides from Britain and other European countries which has killed thousands of persons annually due to pesticides poisoning; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) (a) and (b) : The question of stopping the import of harmful/dangerous pesticides from Britan and other European countries does not arise, because such pesticides were not and cannot be imported at all in view of the various safeguards provided in the present system.

2. Only those insecticides are allowed to be imported into the country which are duly registered by the Registeration Committee which satisfies itself fully about the safety and bio-efficacy of the product before granting Registration. Any chemical thought to have insecticidal properties has to be included in the schedule to the Insecticides Act, 1968, by a notification in the offical gazette by Government of India on the advice of the Central Insecticides Board. After inclusion in the Schedule to the Insecticides Act, the chemical is recognised as an insecticide in India. Any person desiring to import from other countries or manufacture inside this country such

an insecticide, has to apply to the Registration Committee and get a certificate of Registration. The Registration Committee comprising experts in different disciplines, registers the insecticides and issues a certificate of Registration only after satisfying itself as regards the efficacy of the insecticides in question and its safety to human beings and animals. No registration is granted in respect of an insecticide which is considered harmful/dangerous to human beings or animals by the Registration Committee. Even for the import of small quantities of an insecticide for research and trial purposes, permission of the Registration Committee is required to be obtained. Further, the Customs authorities do not clear any consignment of insecticides to any party without producing a valid Registration Certificate. All these checks ensure that only those insecticides are imported into this country which are registered by the Registration Committee after satisfying itself as regards their efficacy and safety.

Ongoing Projects of Orissa

1929. SHRI RASABEHARI BEHRA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the details of the ongoing irrigation project of Orissa with the amount sanctioned project-wise, upto date ;

(b) the details of the percentage of work completed so far ; and

(c) the appropriate date of completing the projects with details of the action being taken for the completion, project-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c) 5 major and 26 medium Irrigation Projects of Orissa taken up prior to VI Plan are at present under execution. The details of these projects giving the sanctioned cost, latest estimated cost, anticipated expenditure to be incurred upto March, 1984, percentage of work completed and likely year of completion, are given in the statement appended. Details of minor irrigation projects are not maintained at the Centre.

It has been impressed upon the State Government on various occasions to give first priority for completing the on-going projects by allocating maximum possible funds and other resources in preference to new schemes. The Centre has also been assisting the State Government in the removal of bottlenecks such as in the matter of supply of cement, explosives etc. Certain projects are also included under World Bank credit assistance, which enables the State to get some additional resource to their plan.

STATEMENT

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Scheme	Latest cost reported by State	Approved estimated cost	Anticipated expenditure-upto 3/84	Expected date of completion	% of work anticipated to be completed upto 3/84 in financial terms
1	2	3	4	5	6	7
A. MAJOR SCHEME						
1.	Rengali					
	(a) Dam	2954.32	1006.08	2672.91	12/84	90%
	(b) Irrign.	69443.00	21289.00	3669.33	8th Plan	8%
2.	Upper Kolab					
	(a) Dam	3280.00	758.64	1952.30	3/86	60%
	(b) Irrign.	6774.85	1696.12	1411.81		21%
3.	Upper Indravati					
	(a) Dam	10035.00	3491.65	2156.51	1990-91	21.5%
	(b) Irrign.	7383.80	4274.06	651.85	7th & 8th plan	9%
4.	Anadadpur Barrage	1128.00	1128.00	1039.15	1984-85	92%

1	2	3	4	5	6	7
5.	Mahanadi Birupa Barrage	9265.00	4208.70	3353.97	1985-86	36%
B.	MEDIUM SCHEME					
1.	Ramiala	1277.00	1155.66	1136.72	1984-85	89%
2.	Ramal	1111.45	520.56	1033.30	1984-85	93%
3.	Daha	1299.20	759.00	1201.24	1984-85	92%
4.	Pillasalki	756.32	380.00	689.95	1984-85	91%
5.	Dumarbahal	322.62	349.00	316.63	1984-85	98%
6.	Gohira	1663.30	1086.00	1382.10	1984-85	83%
7.	Senei	2276.00	986.00	1385.89	1984-85	67%
8.	Kauria	1115.00	661.00	976.74	1984-85	88%
9.	Jharabandha	283.74	228.54	239.91	1984-85	84%
10.	Sarafgarh	456.71	380.91	446.00	1984-85	97%
11.	Harabhangi	3039.78	1557.00	742.27	1986-87	24%
12.	Talasara	537.00	518.26	555·45	1983-84	100%
13.	Kanjhari	1646.40	1269.00	1072.59	1986-87	65%
14.	Hariharjore	2330.96	1479.00	817.53	1986-87	36%
15.	Barsuan	330.00	330.00	23.51	1986-87	7%
16.	Kansabahal	1300.56	677.00	289.68	1986-87	22%
17.	Upper Jonk	2100.72	990.00	102.14	1984-85	5%
18.	Bankabal	1552.72	960.00	377.50	1983-84	24%
19.	Ong.	1800.00	210.12	1079.97	1986-87	60%
20.	Sundar	639.00	160.48	533.78	1986-87	84%
21.	Kale	632.77	196.21	632.78	1986-87	100%
22.	Dadraghati	801.08	136.62	582.27	1984-85	73%
23.	Aunli	224.42	53.19	188.91	1984.85	84%
24.	Upper Suktel	297.00	127.83	196.78	1984-85	66%
25.	Baghue Stage-II	523.00	327.58	50.71	1986-87	10%
26.	Bendapipili	466.57	148.85	352.51	1985-86	76%

* % have been calculated on the basis of latest estimated cost.

Survey Conducted For Ground Water In Pali District

1930. SHRI MOOL CHAND DAGA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the particulars of villages, in Pali district of Rajasthan where surveys had been conducted for ground water during or before Sixth Five Year Plan and whether those places have been identified where drinking water and water for irrigation is available ;

(b) if so, the particulars of those villages and whether there are some more villages yet to be surveyed ;

(c) if so, their number and the time by which their survey is likely to be completed ;

(d) the number of villages where work for utilisation of underground water has been done during the Sixth Five Year Plan and expenditure incurred theeron by Central and State Governments ; and

(e) the number of villages which have water for drinking and irrigation purpose and area of land brought under irrigation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (b) The Central Ground Water Board had up to March, 1983 surveyed the whole of Pali district covering 12,387 sq. km. and comprising 841 villages and 8 urban establish-

ments under hydrogeological surveys. The availability of ground water for drinkinx and irrigation needs has been identified. Development and utilisation of water is a State subject. The priorities for development of water including ground water are to be decided by the State. During the Sixth Plan, the programmes of ground water so far completed in Pali District include construction of 94 tubewells under development shemes and 27 under exploration programme in addition to construction of 17 new wells, deepening of 22 wells and installation of 45 pumpsets. An expenditure of Rs· 636.32 lakhs was incurred up·o end of March 1983. Districtwise break up of figures of Sixth Plan or for the Annual Plan for 1983-84 for ground water development are not available. As per information made available by the State upto April, 1982, 525 villages and 8 urban areas had been provided drinking water. Water supply shemes for 99 villages were under construction and new scheme for 140 villages had been planned for implementation during 1982-83. An area of 2.35,278 hectares had been brought under irrigation upto 1979-80.

Rafi Ahmed Kidwai Award for 1977.

1931. SHRI SURAJ BHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rafi Ahmed Kidwai Award to the Head of the Biochemistry Division at Indian Agricultural Research Institute (New De·hi) was initially withheld in December, 1977 at the time of the award function and it was given afterwards in March, 1978 ; if so, he details and reasons thereof ;

(b) who were the members of the Judging Committee which recommended his name for the award and was there any biochemist expert in the Committee ; and

(c) the citation of his scientific achievements to his credit and the practical utility of his contribution to increasing agricultural production for which the award was given ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir. The award of the prize to Dr. M. S Naik was not made on the day of award function held on 8.12.1977, owing to receipt of a letter from the late Shri Jyotirmoy Bosu alleging that since Dr. M.S. Naik had been involved in a controversy which had arisen out of a complaint made by Shri Y.P. Gupta, Bio-Chemist, IARI to the Shah Commission for malpractices and excesses committed against him, the award of the prize be withheld till he was cleared by the concerned authorities. The letter of the late Shri Jyotirmoy Bosu was considered in detail subsequently and it was decided with the approval of the then President, ICAR that award given to scientists are for excellence in their scientific works and should not be withheld for extraneous reasons. The award was then presented to Dr. M. S. Naik on 27.3.1978.

(b) The members of the Judging Committee were (i) Dr. G. P. Talwar, Professor and Head, Department of Bio-chemistry, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (ii) Dr. K. N. Sareen, Professor and Head Department of Biochemistry, Punjab Unversity, Chandigarh and (iii) Dr. S. P. Raychaudhri, Chief Agrenomist, Shriram Khad Programe, New Delhi. Out of these three, two members namely Dr. G.P. Talwar and Dr. K. N. Sareen are experts in the dtscipline of Biochemistry.

(c) The citation in respect of Dr. M.S. Naik is enclosed.

As regards the practical utility of Dr. Naik's contributions, the work of Dr. Naik for which the award has been given is basic and foundamental. His work has helped us to understand several useful aspects of bio-chemical reactions in crop plants such as nitrate assimilation in plants, role of light in the induction and activation of nitrate reductase, factors controlling biological values of grain proteins, role of enzymes in phosphorylation of the leaf blight causing becterial organi m in rice etc. These studies are not directly related to rroduction but are aimed only at understanding the fu ndamental aspects thereof.

STATEMENT

The Rafi Ahmed Kidwai Memorial Prize for Agricultural Research for the bionnium 1974-75 is awarded to Dr. Manohar Shridhar Naik, Head, Division of Bio-chemistry, Indian Agricultural Research

Institute, New Delhi for his outstanding contributions in the field of Bio-chemistry. Dr. Naik and his students and co-workers have carried out bio-chemical studies on nitrate assimilation in crop plants, protein synthesis in developing grains of cereals and millets and bacterial blight of paddy. These biochemical investigations have shown a close relationship between photosynthesis and nitrate assimilation. The role of light in the induction and activation of nitrate reductase has been specified. The significance of the presance of an inhibitor of nitrate reductase in the roots has also been studied. The link between the two molybdoproteins-nitrate reductase and nitrogenase has been established and the similarities in nitrate assimilation and biological nitrogen fixation have been shown. The factors controlling the biological value of the grain protein have been studied at the molecular level. The enzymes involved in respiration and oxidative phosphorylation in Xanthomones Oryzae, the causative pathogen, have also been investigated.

The studies carried out by Dr. Naik have, thus helped to understand several usefull aspects of biochemical reactions in crop plants.

Opeing of Sports Medicine and Treatment Centre in Delhi.

1932. SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY: Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to open sports medicine and treatment Centre in Delhi and if so, details thereof ; and

(b) whether Government have received any-representation from the sports organisation in this regard ; if so, details thereof indicating the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) There is no such proposal under consideration with the Government.

(b) The Government have not received any such representation so far from the sports organisations.

भूमिहीन श्रमिक बेरोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा योजनाएं तैयार किया जाना

1933. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार द्वारा भूमिहीन श्रमिक बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी योजनायें बनाकर, केन्द्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी गई है और उनके क्रियान्वयन के फल स्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : ग्रामीण भूमिहीनों के लिग रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार से अभी तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Conference of Whips in Simla

1934. DR. PRATAP WAGH :
SHRIMATI MADHURI SINGH :
DR. KRUPASINDHU BHOI :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
Will the Minister for PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Whips Conference was held at Shimla recently ;

(b) if so, the main recommendation of the Shimla Conference ; and

(c) the steps to be taken to implement the recommendation ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) to (c) The Ninth All India Whips Conference was held at Shimla on 27th and 28th October, 1983. A Copy of recomendations adopted at the Conference is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—7156/83 The Conference also adopted a resolution to set up a Working Group under the Chairmanship of the Union Minister for Parliamentary Affairs to examine and scrutinise the recommendations of all Whips' Conferences and suggest administrative and legislative measures for implementing them.

Implementation of Drinking water supply Scheme

1935. SHRI P. M. SAYEED : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether in 1980 at the start of U. N. Water Decade. India has 1,90,000 thirsty villages which was 1/3rd of its nearly 5,70,000 villages had been declared problem areas for the point of drinking water scarcity ;

(b) whether there are 11,317 villages which are such that either no water is available or the water available is so blackish that it cannot be used for human consumption ;

(c) how many villages are still without water ; and

(d) by what time the Government are likely to provide drinking water to the thirsty villages ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) At the commencement of the International Decade, India had 204806 problem villages to be covered.

(b) The norms prescribed by the Govt. of India for identification of problem villages cover various aspects of water availability and quality. According to this criteria the total number of problem villages identified as on 1.4.80 is 230784, which are targeted to be covered fully by the end of the Sixth Plan Period.

(c) During the first three years of the Plan, a total of 101659 problem villages has been covered i. e. provided with at least one safe source of potable water. The target for 1983-84 is 48846 villages.

(d) The Sixth Plan envisages a target of 100% coverage of the identified 230784 problem villages by the end of the plan Period.

Dissatisfaction about the P.D.S. through Fair Price Shops

1936. SHRI DEEN BANDHU VERMA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of dissatisfaction about the Public Distribution System through fair price shops in regard to quality and quantity, weights and measures, irregular supplies and unfair service by the shop-keeper ;

(b) whether Government propose to modernise the Public Distribution System like pre-cleaning of foodgrains, packing pulses, maida, suji and sugar in polythene etc. ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJVEEVI RAO) : (a) to (c) : Under the present scheme of public distribution of essential commodities, the organisation and administration of the Pulic Distribution System in the respective States is primarily the responsibility of the concerned State Government. In the guidelines given by the Central Govt., the State Governments have already been asked to review the working of the system from time to time and to see that it works in a smooth and effective manner. For maintaining the supply-line, the State Governments have been urged to effect a greater degree of coordination in respect of lifting, storage, transportation and distribution of essential commodities through the fairprice shops. They are also to see that these commodities do reach the *bona fide* consumers at pre-fixed prices. Checks, both regular and surprise, to be undertaken by the local authorities of the State Government on the working of the fair-price shops to see that irregularities do not take place. Wherever such irregularities are detected, strict action under the law is to be taken. In order to associate the general public with the working of the System, the State Governments have been told to set up Advisory/Vigilance Committees at the field level which could keep a watch on the working of the Public Distribution System in their areas. Reports received from the State Governments show that they have been taking action in accordance with the above guidelines. Complaints about dissatisfaction with the Public Distribution System, which are received by the Central Government are passed on to the concerned State Government for appropriate action.

Under the present scheme of Public Distribution the Central Government supplies wheat, rice, sugar, imported edible oils,

kerosene, soft coke and controlled cloth through the System. Generally speaking the Central Government is in favour of issue of these commodities in bulk rather than in packed form so as to cut down on the cost of distribution and thus to keep the issue-prices of these commodities at a level where they could be afforded by even the weaker sections of the society. Nevertheless, as the system is administered at the local level by the State Governments, it is for the latter to consider whether it would be feasible to pack any of these commodities before issue.

डी० डी० ए० की "न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना 1979" के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

1937. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "न्यू पेटर्न पंजीकरण योजना 1979" के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के लिए, अलग-अलग, किस-किस तारीख को ड्रा निकाले गए ;

(ख) क्या उक्त ड्रा में सफल हुए सभी पंजीकृत व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन पत्र भेज दिए गए है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें आवंटियों को आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं और वे पत्र प्राधिकरण को वापस मिल गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो डी० डी० ए० की अवन्तिका कालोनी के जनता फ्लैटों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के आवंटन पत्र कब तक भेजे जाने का विचार है ; और

(ङ) अब तक आवंटन पत्र न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नवीन पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटनार्थ निम्नलिखित तारीखों पर चार ड्रा निकाले गए हैं :—

पहला ड्रा 31.3.1981

दूसरा ड्रा 30.3.1982

तीसरा ड्रा 13.5.1983 (विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए)

चतुर्थ ड्रा 1.2.1983

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सिवाय निम्नलिखित मामलों के पहले, दूसरे तथा तीसरे ड्रा में किए गए आवंटन के सभी आवंटितियों को फ्लैटों के आवंटन पत्र जारी कर दिए हैं :—

श्रेणी	ड्रा	योजना	फ्लैटों की संख्या
एल०आई०जी०	दूसरा	पीतमपुरा पाकिट "डब्ल्यू"	504
जनता	दूसरा	दिलशाद गार्डन	963

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि चतुर्थ ड्रा के सफल आवंटियों को अभी आवंटन पत्र जारी नहीं किए गए हैं क्यों कि फ्लैट अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटन एवं मांगपत्र आवंटियों द्वारा अपने आवेदन पत्र अथवा पता बदलने की सूचना देने वाले पत्रों में दिए गए पतों पर रजिस्टर्ड ए० डी० द्वारा भेजे जाते हैं। जहां डाक प्राधिकारियों की सूचनानुसार आवंटी उन पतों पर नहीं मिलते, आवंटन निरस्त कर दिए जाते है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनता फ्लैटों के आवंटन पत्र आवन्तिका कालोनी के लिए सफल व्यक्तियों को जारी कर दिए गए हैं परन्तु 39 मामलों में अवितरित पत्र वापिस मिल गए हैं तथा पत्रों के वितरण की सभी संभावनाओं की खोज के बाद आवन्टन निरस्त कर दिए गए थे।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित

किया है कि केवल उन्हीं मामलों में जहां कि आवंटियों द्वारा फ्लैट कब्जे के लिए पूर्ण नहीं हैं, आवंटन पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं ।

Self-Sufficiency in Milk

1938. SHRI CHITTA MAHATA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country has more of less achieved self-sufficiency in milk and milk products ;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ; and

(c) the annual demand and production of milk and milk products ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (c) The National Commission on Agriculture (1976) has recommended 201 gms of milk per head per day as the average minimum nutritional requirement. The per capita availability of milk and milk products has been steadily increasing from 109.6 gms in 1973-74 to 125 gms in 1979-80. The per capita availability of milk is always related to rate of growth of population. While milk production has increased significantly, there has also been a sizeable increase in population.

Increasing Cultivation of Soyabean in Madhya Pradesh

1939. KUMARI PUSHPA DEVI SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have taken several measures to increase areas under soyabean cultivation in Madhya Pradesh and other soya growing States ;

(b) if so, the measures taken, target set and achievement made in soya production during the Sixth Plan (year-wise) in Madhya Pradesh and other soya growing States ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In order to increase the production of soybean in the country, two schemes viz. special project on Soybean production in Madhya Pradesh and the Centrally Sponsored Scheme for he development of soybean in U.P., H.P., Bihar, Rajasthan and Gujarat is in operation during the Sixth Plan. These project/scheme provide subsidies on supply of seeds, plant protection, chemicals, seed minikits, demonstrations, etc. Planning Commission fixes targets for the oilseeds as a group and not for individual oilseeds. As such, is not possible to furnish State-wise and year-wise targets of individual oilseeds for the Sixth Five Year Plan. However, according to the Working Group Report on Agriculture and Cooperation set up in the Planning Commission to consider the Annual Plan proposals for 1983-84, the soybean production targets fixed for Madhya Pradesh were 7 lakh tonnes for 1982-83 and 69 lakh tonnes for 1983-84. For other soybean producing States like Uttar Pradesh, no separate targets for soybean were fixed by the Planning Commission.

The achievement in production of soybean State wise for the last three years of Sixth Five Year Plan is as under :

Production (,000 tonnes)

	State	1980-81	1981-82	1982-83
1.	Gujarat	4.5	4.5	4.5
2.	Madhya Pradesh	350.0	350.0 (P)	358.6
3.	Rajasthan	2.5	6.5	6.5
4.	Uttar Pradesh	84.0	101.8	117.4
5.	Others	1.2	3.7	3.9
	All India	442.2	466.5 (P)	490.9

P—Provisional

Subsidy Scheme for Fishing Trawler Industry

1941. SHRI K. RAMAMURTHY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the details of the subsidy scheme introduced in 1970 for encouraging indigenous fishing trawler industry;

(b) whether it is a fact that no subsidy had been given to Mazagaon Docks and Chowgules and another private company which built about 17 fishing trawlers during the period 1970 to 1980 ;

(c) whether not a single Paisa has been disbursed as late as September, 1983 for Chowgules who have agreed to build 5 trawlers ; and

(d) the agency presently implementing this scheme and whether this agency is still reluctant to take a final decision about the implementation of subsidy scheme to Indian trawler builders ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) A copy of the Notification dated the 15th June, 1970, is laid on the Table of the House (Placed in Library. *See.* No. LT-7157/83)

(b) to (d) In continuation of the notification dated the 15th June, 1970, the Government of India by a supplementary notification dated the 25th October, 1972, decided to grant a subsidy of Rs. 2 lakhs for each 57 feet deep sea steel fishing vessel manufactured indigenously on the conditions indicated in the notification dated 15th June, 1970. It was also notified that the subsidy was valid up to 31st March, 1973.

The claims of subsidy preferred by the trawler builders were examined and were found that their claims are not sustainable in terms of the conditions stipulated in the notification. The companies were informed accordingly on 17th September, 1983.

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न का नष्ट होना

1942. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 के दौरान सरकार (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा वसूल किए गए गेहूं, चावल अथवा अन्य खाद्यान्नों में से कितना प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो गया है और उसका रुपयों में मूल्य कितना है ; और

(ख) इसके नष्ट होने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों में से कोई भी स्टाक 1983 के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ बताया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों के किसानों को बीजों और उर्वरकों के लिए राज सहायता

1943. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान अनुसूचित जातियों के किसानों को बीजों और उर्वरकों के लिए कितनी राज सहायता दी गई और उसका राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों को किस एजेंसी के माध्यम से बीज और उर्वरकों के लिए सहायता दी जाती है और क्या इसके लिये एजेंसी अलग-अलग है अथवा एक ही है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गयी है कि क्या राज सहायता हरिजन किसानों तक पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि विभाग में केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के तहत इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में घाटमपुर में चीनी कारखाने स्थापित किए जाना

1944. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या खाद्य और

नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान घाटमपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही चीनी मिलों की ओर दिलाया गया है जहां पर गन्ने की पैदावार नगण्य है जब कि राज्य में ऐसे बहुत से गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा उन क्षेत्रों के भारी संख्या में गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए चीनी मिलों की स्थापना की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(ग) घाटमपुर जिले के अन्य क्षेत्रों में 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान कहां कहां और कितनी चीनी मिलों की स्थापना की गई है और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र में 1250 मीटर टन प्रतिदिन की क्षमता की एक चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इस आवेदन पत्र पर इस मन्त्रालय की जांच समिति द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विचार किया गया था। लाइसेंस प्रदान करने के समर्थन में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया की लगभग 8615 हैक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती की जाती है और प्रस्तावित फैक्ट्री क्षेत्र में 1988-89 में यह बढ़कर 16,000 हैक्टेयर हो जाएगी। अत: नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के समर्थन में काफी शक्ति है। अतः जांच समिति ने घाटमपुर में नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी और उद्योग मंत्रालय द्वारा तदनुसार प्रस्तावित फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 10 जून, 1983 को एक आशय पत्र प्रदान किया गया है।

(ग) घाटमपुर के अन्य क्षेत्रों में कोई चीनी मिल स्थापित नहीं की गई है।

Replacement of all India Service Officers by Retired Sportsmen

1945. SHRI KAMAL NATH : Will the Minister of SPORTS be pleased to state whether there is any proposal with Government to replace a number of All India Service Officers who are holding offices in various sports organisations viz. hockey, cricket, football and athletics by retired leading sportsmen ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : No, Sir.

Sponsored Foreign Charter Fishing Trawlers

1946. SHRI DAULATSINHJI JADEJA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of foreign charter fishing trawlers which were permitted prior to 1980, the names of India sponsoling companies and the corresponding number of foreign charter boats ;

(b) whether such Indian companies were supposed to buy, acquire or import trawlers for being permitted to charter foreign boats ;

(c) The number of such fishing trawlers acquired or bought as per the conditions of charter ;

(d) whether any Indian companies violated this particular condition and did not acquire boats ;

(e) if so, the names of such companies ; and

(f) the action taken against such violating companies who chartered foreign boats prior to 1980 ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) The number of foreign chartered fishing vessels permitted prior to 1980, the names of Indian companies permitted and the number of vessels permitted are as stated below :

(i) M/s New India Fisheries Ltd. ... 2
(ii) M/s International Sea Foods Pvt. Ltd. ... 2
(iii) M/s Kelbex International Co. Ltd. ... 1
(iv) M/s Peejay Indo Bulgarian Fisheries Ltd. ... 2
(v) M/s Tata Oil Mills Co. Ltd. ...25
(vi) M/s Golden Hind Shipping (India) Pvt. Ltd. ...25
(vii) M/s Universal Food Pvt. Ltd. ...20

Although two more companies viz. M/s Asra Sea Foods Pvt. Ltd. and M/s Aqua Marine Products Pvt. Ltd. were permitted to charter one vessel and four veessels respectively, these companies did not operate any vessels on charter.

(b) The Company at Sl. No. (V) referred to in part (a) was asked to acquire three vessels while extending the letter of permission. The companies at Sl. Nos (vi) and (vii) referred to in part (a), were to make irrevokable arrangements for purchasing vessels either by import or from an Indian shipyard before the expiry of the charter period.

(c) The company referred to at Sl. No. (v) in part (a) has informed that they have brought two wooden trawlers.

(d) to (f) M/s Golden Hind Shipping and M/s Universal Food, who were to make irrevokable arrangements for purchasing vessels as per the charter conditions, have not acquired any vessels. No extension was given to these companies to charter foreign fishing vessels.

Housing Scheme Approved by HUDCO

1947. DR. KRUPASINDHU BHOI :
SHRI HARIHAR SOREN :
Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether HUDCO has approved any housing scheme recently ;

(b) the States to be covered under the scheme ;

(c) whether any revision of HUDCO's programme in different States have been made so far ; and

(d) if so, the proposed action to be taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) During 1983-84 and as on 31.10.83, HUDCO has sanctioned 272 schemes with project cost of Rs. 223.93 crores and HUDCO's loan commitment of Rs. 144.64 crores. These schemes are spread over the States/UTs of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh, Delhi and Pondicherry.

(c) and (d) The revised pattern of financing of HUDCO has been effective since 1.7.82. As regards programme of financing, there has been no change during the current year except a marginal rise in the target of loan sanctions.

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए माही नदी का पानी

1948. श्री विरदाराम फुलवारिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान एवं गुजरात राज्य सरकारों के बीच वर्ष 1966 में एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत माही नदी पर कड़ाना में बांध बनाकर माही नदी के पानी से गुजरात के ऊंचे क्षेत्रों और राजस्थान के शुष्क जिलों जालौर, सिरोही और बाड़मेर में सिंचाई की योजना थी ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने पूर्व प्रस्तावित योजना के अनुसार खेड़ा जिले में नर्मदा नदी के बजाए माही नदी के पानी से ही सिंचाई करने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस योजना के स्वीकृत होने के मामले में राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को माही नदी का पानी प्राप्त नहीं होगा जो कि न्याय संगत नहीं है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्थान के जालौर, सिरोही और बाड़मेर

जिलों में 1965 के समझौते के आधार पर माही नदी के पानी से सिंचाई हो केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजस्थान तथा गुजरात के बीच 1966 में हुए करार में गुजरात में एफ० आर० एल० 419 तक कडाना बांध तथा राजस्थान में एफ० आर० एल० 921 तक बजाज सागर बाँध का निर्माण करके माही जल का समुपयोजन करना शामिल है। इस करार में इसके साथ-साथ यह व्यवस्था है कि बाद में जबकि माही क्षेत्र नर्मदा द्वारा शामिल कर लिए जाते हैं और कडाना जल का एक भाग राजस्थान के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया हो, तब राजस्थान को ऐसे उपयोग के लिए गुजरात को बाँध की एक उचित लागत अदा करनी चाहिए, जब नर्मदा का विकास हो जाता है और जब नर्मदा के जल से माही क्षेत्र को पोषित किया जाता है तथा बंसवाड़ा में माही जल राजस्थान के उपयोग के लिए छोडा जाता है, राजस्थान को, गुजरात सरकार द्वारा बंसवाड़ा परियोजना की दी गई लागत का भुगतान कर देना चाहिए ।

(ख) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा के जल को गुजरात को आबंटित किए जाने के आधार पर, गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए एक परियोजना तैयार की है, जिसमें माही बेसिन मे नर्मदा जल के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए माही जल के दिए जाने तथा 1966 के करार की व्याख्या सम्बन्धी मुद्दा उठाया था। इन मामलों को हल करने की दृष्टि से केन्द्र, दोनों राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए कार्यवाही कर रहा है। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री द्वारा दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ पिछली बैठक अप्रैल, 1983 में आयोजित की गई थी। मुख्य मंत्रियों ने विभिन्न संभावित वैकल्पिक हलों पर विचार-विमर्श करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत करने पर सहमति जाहिर की थी। यह भी सहमति हुई थी कि इसके पश्चात् दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के साथ विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच आगे विचार-विमर्श अभी किया जाना है ।

Distribution of essential commodities through consumer cooperative societies

1949. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether the proposal to give agencies to the consumer cooperative societies for distribution of fertilizers and other essential commodities in rural areas is under the consideration of Government ;

(b) if so, when the above proposal is expected to be implemented ; and

(c) the steps taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) No Sir, However the National Cooperative Development Corporation is implementing a scheme to assist the Agricultural Credit Societies in rural areas for distribution of consumer articles and at secondary level to Marketing Cooperatives or Wholesale Consumer Stores for supplying consumer goods in rural areas.

(b) and (c) Question does not arise.

Allotment of Delhi Development Authority Flats to Retired/Retiring Government Employees

1950. SHRI JITENDRA PRASADA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government introduced a special scheme for the allotment of Delhi Development Authority flats to Government employees who retired or were retiring within 3 years ;

(b) if so, the number of applications received from 15 December, 1982, to 15 February, 1983 ;

(c) the number of applicants out of (b) to whom flats have been allotted and the reasons for not allotting flats to the remaining applicants till now ;

(d) whether special consideration has been given to the applications of those employees whose dependent family members are handicapped and are destined to stay at Delhi after retirement ;

(e) if so, the details thereof ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) The DDA have reported that 1428 applications under MIG category 1744 application under LIG category and 268 applications under Janata category have been received under this scheme.

(c) the DDA have reported that no allotment has so far been made under this scheme.

(d), (e) and (f) No, Sir. However, reservation is available to those registrants who are physically handicapped.

Funds under CSARWSP in Tamil Nadu

1951. SHRI ERA ANBARASU : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to release funds for the rural water project under Centrally Sponsored, Accelerated rural Water Supply Programme in Tamil Nadu ;

(b) if so, the total amount to be released for the project ; and

(c) if not, whether he will consider to release sufficient funds for this project in Tamil Nadu ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) Funds have already been released for the first 3 years of the Sixth Plan as well as for the current year. Funds provided under the ARP for the Sixth Plan period are Rs. 26.67 crores for Tamil Nadu. The details of the release are ;

1980-81 : Rs. 500.00 lakhs

1981-82 : Rs. 563.71 lakhs

1982-83 : Rs. 850.50 lakhs

1983-83 : Rs. 344.00 lakhs (upto 16.11.83, against an approved outlay of Rs. 688.31 lakhs for 1983-84).

In addition to this, Rs, 106.00 lakhs have been released to Tamil Nadu on 22.11.1983 under the new Centrally sponsored Incentive Scheme based on performance.

(c) The question does not arise in view of the reply to parts (a) & (b) above.

Sale of spurious nepthalene balls by Super Bazar, Willingdon Hospital New Delhi

1952. SHRI HARIKESH BAHADUR : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLITES be pleased to state :

(a) whether he is aware that spurious nepthalene balls used for storage of woollens sold by the Super Bazar, Willingdon Hospital, New Delhi sometime in April/May, 1983 had instead of protecting the clothes damaged them considerably and reduced them to shambles ;

(b) if so, whether he will order an investigation into the purchase of such spurious articles by the Super Bazar authorities, in whom the public has got implicit faith for supply of genuine commodities ;

(c) which is the firm from whom this lot of balls was purchased ; whether any inspection about its quality and genuineness was made ; if so, by whom ; and

(d) what action he proposes to take against the authorities in Super Bazar for such indiscreet and shady deals and also against the firm concerned ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) No complaint regarding the quality of napthalene balls sold by willingdon Hospital branch of Super Bazar has been received by Super Bazar.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Super Bazar generally procures napthalene balls from M/s Bengal Chemicals which is a reputed concern, manufacturing napthalene balls and other goods. As stock was not available with M/s Bengal Chemicals, Super Bazar procured its requirements from M/s Premier Dye Stuff Agency, Delhi, during the months of March, April and May, 1983. The Super Bazar has reported that inspection about its quality and genuineness was made by Purchase Manager on the spot, which was found to be satisfactory after visual inspection. The napthalenee balls presently on sale and purchase from the same party were also tested by Super Bazar Laboratory, located at Lady Irwin College, and found to be satisfactory.

नर्मदा परियोजना के प्रथम चरण का कार्य

1953. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा परियोजना के प्रथम चरण पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) माननीय सदस्य संभवतः नर्मदा घाटी विकास के प्रथम सोपान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नर्मदा सागर परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच करने तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। परियोजना के आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों, सड़कों का मोड़ना, ड्रिलिंग कार्य, खाइयों की खुदाई, शाफ्ट तथा एडिट जैसे पूर्व-निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। बांध की नींव की खुदाई तथा व्यपवर्तन सुरंग के कार्य को चालू वित्तीय वर्ष में हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना को 921 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की अपेक्षा अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) परियोजना को 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

F. A. O. Specialist Group on Animal Breeding

1954. SHRI B. D. SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Food and Agriculture Organisation of United Nations had constituted a specialist group to meet shortly on animal breeding and conveyed names of ICAR officers for participation therein ;

(b) the names of ICAR officers included in this group, its term of reference and scheduled date of first meeting ;

(c) whether the ICAR officials attended the first meeting and if not, the reasons therefor ;

(d) whether these ICAR officers have visited abroad during 1981, 1982 and in 1983, if so, the date-wise, place-wise details for each with purpose of visit and reasons for allowing them now, officer-wise ; and

(e) the details of rules/procedure ICAR follows on such international participations ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) The FAO of the United Nations had consititued an FAO/UNEP Joint Panel of Experts on Animal Genetic Resources Conservation and Management. The first meeting of the Expert Panel was fixed for October 24-27, 1983. The list of Experts proposed by FAO to serve on the Panel in their personal capacity for a period of 4 years included the names of (i) Dr. R. M. Acharya, Deputy Director General (Animal Science), ICAR, and (ii) Dr. P. N. Bhat, Director, Central Institute for Research on Goats.

(c) No, Sir. Due to some administrative reasons, these two officers could not be spared to accept the membership of the Panel. Consequently, they were not deputed to attend the first meeting of the Panel.

(d) Yes, Sir. During 1981 and 1982, these two Officers were deputed abroad in

public interest. So far, they have not been deputed abroad during 1983. The details of their visits abroad during 1981 and 1982 are given in the enclosed statement.

(e) As per guidelines formulated for this purpose.

STATEMENT

S. No.	Name & Designation of the Officer	Period of visit	Country visited	Purpose
1.	Dr. R. M. Acharya, Dy. Director-General (A.S.), ICAR.	23.8.81 to 7.9.1981	Democratic People's Republic of Korea.	Deputed to attend Symposium of the Non-Aligned and other Developing Countries on Increasing Food and Agril. Production.
2.	—do—	31.5.82 to 11.6.82	U. S. A.	Deputed to attend Second Session of the Indo-US Sub-Commission on Agriculture.
3.	—do—	11.9.82 to 20.9.1982	Netherlands	For discussion with Govt. of Netherland on cooperation in the field of Animal Husbandry and also to visit centres/ stations doing research in Animal Husbandry.
4.	Dr. P. N. Bhat, Director, Central Institute for Research on Goats.	4.5.81 to 8.5.81	Malaysia (Kuala-Lumpur)	Deputed to attend the 4th International SABRAO Congress.
5.	—do—	5.9.1982 to 16.9.1982	USSR	Deputed as a member of the Indian delegation to USSR to finalise Indo-Soviet Protocol on Agril. Research & Education.

Central Assistance to A. P. for Urban Development

1955. SHRI ANANTHARAMULU MALLU : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether the State Government of Andhra Pradesh have approached the Central Government regarding the financial assistance to be provided to that State for the Integratred Urban Development Schemes in that State ;

(b) if so, the details regarding the amount so far granted and utilised during last three year-wise ; and

(c) the details regarding providing water supply to small and medium-size towns during 1982-83 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHMMED USMAN ARIF) : (a) Yes.

(b) Under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns a sum of Rs. 255.75 lakhs have so far been released to Govt. of Andhra Pradesh. The expenditure incurred by the State Govt. upto June 1983 on the Scheme is Rs. 188.94 lakhs. The year-wise details are as under :—

1979-80	Rs. 42.00 lakhs
1980-81	Rs. 16.95 lakhs
1981-82	Rs. 123.80 lakhs
1982-83	Rs. 53.83 lakhs
1983-84	Rs. 19.17 lakhs
Total :—	Rs. 255.76 lakhs

(c) Water Supply schemes are not being funded by Central Government under this Scheme. As such no figures on this account are available with us.

Commissioning of lock and lock-gates of Farakka Navigational canal

1956. SHRI SATYAGOPAL MISRA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether there is any scheduled programme for the commissioning of the lock and the lockgates of the Farakka Navigational canal ;

(b) if so, the details of the programme (including the actual date of commissioning) ; and

(c) the reasons for delay ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c) The work of designs, manufacture, supply, erection and commissioning of the gates for the navigation lock at Farakka was awarded to M/s Westinghoue Saxby Farmer Ltd., a Govt. of West Bengal undertaking in November, 1976. According to the scheduld agreed to, the work was to be completed by November 1978. Though the work on the various components like mitre gates and hoists, radial gates and their conirol arrangement and bulk head gates had been substantially completed by April, 1982, the progress on the further work had been slowed down by the firm. After taking up the issue with the Govt. of West Bengal, the firm has expedited the remaining work and has now planned to complete the work by March, 1984. On completion of the erection, painting etc., the coffer dams will have to be removed and water let into the lock chamber, whereafter the various components have to be tested before acted actual commissioning, which would take about 3 months time.

अकाल और बाढ़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता

1957. **श्री जैनुल बशर : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अकाल और बाढ़ से हुई हानि के लिए सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की गई और प्रत्येक मामले में सरकार ने कितनी सहायता की मंजूरी दी है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर कुल सहायता में से राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि दी है ?

कृषि मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी हां ! उत्तर प्रदेश सरकार से 27-9-83 को सूखा तथा बाढ़ प्रत्येक पर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने बाढ़ों के लिए 566.93 करोड़ रुपए तथा सूखे से राहत के लिए 36.09 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी है केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है और इसकी रिपोर्ट पर राहत संबंधित उच्चस्तरीय समिति ने 28-11-83 को हुई अपनी बैठक में विचार भी किया है । केन्द्रीय सहायता की अधिकतम मंजूरी होने तक भारत सरकार ने साधनोपाय के रूप में 31 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि मंजूर की है ताकि राज्य सरकार अपने राज्य में तत्काल राहत संबंधी व्यय पूरा करने में समर्थ हो सके । उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 1080 लाख रुपए की सीमान्त धनराशि भी मंजूर की गई है ।

गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या

1958. **श्री विजय कुमार यादव : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना अब तक देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठाये गए लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें

अत्याधिक बढ़े-चढ़े आंकड़े उपलब्ध कराती है जो कि भ्रामक और झूठे होते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन आंकड़ों की सत्यता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरि नाथ मिश्र) : (क) चालू वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में अक्तूबर, 1983 तक सहायियत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना एक धीमी तथा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और लाभभोगी परिवारों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने से पहले इसमें समय लगेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अक्तूबर, 1983 (1983-84) माह के अन्त तक सहायियत लाभभोगी,—10-11-83 की स्थिति

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अक्तूबर, 1983 तक सहायियत लाभभोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	47727
2.	असम	23068
3.	बिहार	119530
4.	गुजरात	55615
5.	हरियाणा	4122 *
6.	हिमाचल प्रदेश	22645
7.	जम्मू और काश्मीर	5309***
8.	कर्नाटक	43247
9.	केरल	26701**
10.	मध्य प्रदेश	87951
11.	महाराष्ट्र	38922
12.	मणिपुर	3110
13.	मेघालय	373
14.	नागालैंड	5045
15.	उड़ीसा	74300
16.	पंजाब	43074
17.	राजस्थान	47384
18.	सिक्किम	272
19.	तमिलनाडु	126357
20.	त्रिपुरा	2758**
21.	उत्तर प्रदेश	147866
22.	पश्चिमी बंगाल	6923***
	केन्द्र शासित क्षेत्र	
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	41*
24.	अरुणाचल प्रदेश	281*
25.	चंडीगढ़	असूचित
26.	दादरा और नगर हवेली	39
27.	दिल्ली	1406
28.	गोआ, दमन और द्वीव	3722
29.	लक्षद्वीप	139
30.	मिजोरम	2391
31.	पांडिचेरी	931
	अखिल भारत:	941249

***सूचना मई, 1983 तक
*सूचना जून, 1983 तक
**सूचना जुलाई 1983 तक

लक्ष्य वे हैं जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

Shifting of NDRI Branch at Goregaon, Bombay

1959. SHRI UTTAMRAO PATIL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a branch of National Dairy Research Institute located at Goregan, Bombay in Maharashtra is being shifted to some other State ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that Government of Maharashtra have to Vidarbha of Maharashtra ; and

(d) if so, the point in shifting this branch to some other State ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A suggestion from the Government of Maharashtra was received regarding shifting of the Goregaon branch of National Dairy Research Institute to Phalghar which has exmined been and found to be not acceptable.

(d) Does not arise.

Change in Date of Birth of Financial Advisor of F. C. I.

1960. SHRI BHEEKHABHAI :
SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Managing Director of FCI had changed the date of birth of Financial Adviser of FIC and re-designated him as Chief Commercial Manager ;

(b) if so, the authority and the rules under which this change in date of birth and designation was allowed and the action taken/being taken against the officers concerned ;

(c) whether it is also a fact that the FCI has allowed one officer involved in vigilance case to function as Zonal Manager (South) ; and

(d) if so, the objection for not allowing other officials involved in vigilance case to function at higher posts on promotion ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) On receipt of a representation from the then Financial Adviser, the Food Corporation of India issued orders in November, 1980, with the approval of Managing Director, altering the date of birth of the officer. The question whether this decision was taken in a legally valid manner is being examined.

The Financial Adviser was later on specifically selected for appointment as Chief Commercial Manager after the post fell vacant. The post of Financial Adviser has been filled by another incumbent.

(c) and (d) The post of Zonal Manager (South) is lying vacant and the present Deputy Zonal Manager (South) is only looking after the current charge of duties pending appointment of a regular incumbent. Since disciplinary proceedings are pending against him, he is not empowered to exercise statutory powers.

Storage and transit losses in F. C. I.

1961. SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri K. V. Seshadri, Ex. Managing Director. F.C.I. was appointed to go into the question of storage and transit losses of Food Corporation of India ;

(b) if so, whether he has submitted the report ;

(c) the main points brought in the report for consideration of Government alongwith recommendations and also the reaction of Government on the same ;

(d) whether it is also a fact that a large quantity of paddy is still lying in Punjab since 1978-79 for milling causing huge losses to FCI ; and

(e) if so, the details of losses suffered by FCI due to delayed milling of paddy, yearwise since 1978-79 onwards ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) The Administrative Reforms Wing of the Department of Personnel and Administrative Reforms undertook a study relating to shortages of foodgrains during transit and storage in Food Corporation of India. The study was conducted under the guidance of Shri K. V. Seshadri, the then Additional Secretary in the Department of Personnel & Administrative Reforms.

(b) and (c) The report has since been submitted and is under examination by an Empowered Committee constituted by the

Department of Food. The points touched in the report and the recommendations made mainly relate to super-inspection system, losses in Central Warehousing Corporation/ State Warehousing Corporations, paddy losses, weighment procedure, quality of jute bag and jute twine, physical verification of stocks, movement of foodgrains and inter-fac ing with the Railways etc.

(d) A quantity of 16778 tonnes of paddy relating to crop years 1978-79 to 1981-82 which has been categorised as millable under related specifications by the inspection committee was awaiting milling in Punjab. It was expected that this quantity would be milled by the end of November, 1983.

(e) It is difficult to quantify losses suffered only on account of delayed milling of paddy and no separate accounts have been maintained in this regard.

Impact of Automation in CPF Section of F. C. I.

1962. SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be please to state :

(a) whether it is a fact that in Food Corporation of India the employees have not been given annual account slips for the contribution of the Provident Fund they have made since 1981 and also that whatever account slips are being issued are full of mistakes ; if so, the reason for delaying the account slips and also for the mistakes ;

(b) whether it is also a fact that the quality of work in CPF sections of FCI was better before the computer system was introduced, if so, the reasons for spending huge amount on computer instead of providing addi ional staff ;

(c) the details of amount spent on computer service, year-wise, and also the possible expenses if additional staff would have been provided for the same work ; and

(d) action being taken to stop computer service and to provide additional hands for improving the working in CPF Division ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) The Corporation has reported that account slips in respect of Provident Fund Contributions which were in order have already been issued upto 1981-82. The account slips for the year 1982-83 are expected to be issued by the end of December, 1983. Mistakes in the account slips are reported to be rare.

(b) The quality of work relating to provident fund account maintenance has considerably improved after the introduction of computer system.

(c) The expendi.ure incurred for getting the work done through computers including the cost of stationery was Rs. 3.56 lakhs for 1980-81 and Rs. 3.43 lakhs for 1981-82. It is estimated that the cost of providing additional staff would have been around Rs. 18.22 lakhs annually, excluding the cost on stationery, accommodation and furniture etc.

(d) It is not proposed to make any change in the system.

रांची में गेहूं का खराब होना

1963. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची के पास वाले नामकुंज स्टेशन पर आयातित गेहूं बरसात के इस मौसम में खुले में पड़ा भीगता रहा है ;

(ख) क्या इस भीगे हुए गेहूं से दुर्गन्ध आती है और क्या सरकार इस सड़े गेहू को "मनुष्यों के उपयोग न करने योग्य" घोषित करेगी ताकि यह लोगों को सप्लाई न हो ; और

(ग) क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) नामकुंज स्टेशन पर वर्षा के कारण बारियों में भरे हुए आयातित गेहूं की कुछ मात्रा बाहरी तौर पर मामूली गीली हो गई थी। लेकिन गेहूं को क्षतिग्रस्त होने से पूरी तरह बचा लिया गया था और किसी

प्रकार के नुक्सान के बिना उसे रोलर फ्लोर मिलों को जारी कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Low Market of Fertilizers

1964. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sale of chemicals and fertilizers is not picking up due to poverty of farmers ;

(b) if so, the corrective steps taken/proposed ;

(c) whether Government will take steps to utilise fully vast quantities of animal dung and other organic matter and wastes as fertilizers and thereby conserve energy and also enrich our soil better than chemical fertilizers ; and

(d) whether as a first step Government will ban burning of animal and plant wastes in Delhi where this is happening at every street corner due to laziness of MCD/NDMC DDA staff ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) No Sir.

(c) In order to promote the use of organic manures, a Central Sector Scheme on Development of Local Manurial Research through setting up of mechanical compost plants, sewage/sullage utilisation and installation of biogas plants was implemented during V plan period. As per decision of National Development Council, the programme was transfered to State Sectors with effect from 1.4.1979. The State Governments are being pursued to implement these programmes effectively.

(d) For effective use of animal and Plant waste in Delhi, the Municipal Corporation of Delhi has already set up a Mechanical Compost Plant to convert it into manure. A similar plant is being set up by New Delhi Municipal Committee.

Lease Money Due From Bharat Hotels And Hotel Meredien

1965. SHRI DIGAMBAR SINGH ; Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to State :

(a) the total lease money due from the owners of Bharat Hotels, C.P. and Meredien Hotels, Raisina Road at present,

(b) the amount which has been capitalised for want or non-payment of whose payment had been deferred or moratorium given;

(c) the steps being taken to enforce the recover of outstanding lease money ;

(d) whether while giving land to these hotelies it was stipulated that their shoping centres should be limited, and if so, to what extent; and

(e) whether these hoteliers are putting up more shopping centres to make more ready money by getting fabulous rents and advances from the prospective buyers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the table of House.

Diversion of Irrigated Areas Under Sugarcane to Foodgrains Production

1966. SHRI DIGAMBAR SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) wheather it is a fact that recently he stated publically that he would like some of the irrigated areas under sugarcane to be diverted to produce more foodgrains since Central Government are finding it diffcult to dispose of the mounting sugar stocks owing to bumper production in the last two seasons;

(b) whether it is also a fact that India had imported sugar sometime back;

(c) the stocks of sugar laying undisposed at the commencement of the current crushing season both with the mills and Central Government;

(d) whether there is any buffer stock of sugar kept by Government for public distribution system in exisgencies and if so, details thereof; and

(e) which of the areas Government would like to reduce or stop sugarcane production

and what incentives Government propose to offer for foodgrains production and which of the particular commodities Government would like to be grown ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) In a general discussion on agricultural situation in the country with the Press, Minister of Agriculture had mentioned that diversion of some of the irrigated area from sugarcane to foodgrain crops would be welcome because of comfortable sugar supply situation and sufficient stock of sugar.

(b) we imported small quantities of sugar in 1980 and 1981, but we have also been exporting sugar and the exports have been sizeable since 1982.

(c) The undsiposed stocks lying at the commencement of current 1983-84 season were as under :

	Lakh tonnes
i) Carry-over stocks with factories	46.05
ii) Stocks at Port and transit with export agency for export purpose	0.82
iii) Stocks available with the F.C.I. in ISA/pipe line stocks	3.33

(d) In view of high sugar production during 1981-82 and 1982-83 seasons there is sufficient availability of levy sugar for meeting the requirement of the public distribution system. However, a buffer stock of 10.0 lakhs tonnes of sugar out of the free sale portion has been created and is maintained by the factories out of their 1982-83 season's production.

(c) Under the present conditions of demand and supply of sugar and sugarcane a marginal shift in cultivated area from sugarcane to wheat or paddy would be beneficial both for the need for the farmer and the country. Government does not envisage the need for major shifts to be induced through special incentives for alternative crops.

Lifting Restrictions on Inter-State Movement of Foodgrains

1967. SHRI CHINTAMANI JENA :
SHRI MOHANLAL PATEL :
Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is restrictions on the movement of food stuff in the country;

(b) whether the Federation of All India Foodgrains Dealers Association has urged Government to lift all trade restrictions in view of the anticipated record food production this year and help in reducing the prices of all essential commodities to ensure easy availability; and

(c) if so, the reaction of Union Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS, AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) The country is treated as one zone for the movement of wheat and levy-free rices. A movement levy is imposed on wheat by some States. Inter-State movement of paddy on trade account is not permitted by certain States. There is no restriction on the movement of kharif coarse grains, except for maize from Madhya Pradesh.

(b) Yes, Sir.

(c) The Central Government does not consider it necessary to review its present policy regarding inter-State movement of foodgrains.

Target And Achievment Under The N.R.E.P.

1968. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the details regarding the targets of cash expenditure, food-grains distribution and creation of man days under National Rural Employment Programme for each of the States during the last three years ; and

(c) the actual cash expenditure, foodgrains distribution and creation of man days in these years in each State ?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) (a) and (b) Statements I to III indicating the details of the cash funds and foodgrains allocated and mandays targetted including the actual cash expenditure incurred, foodgrains distributed and mandays generated under National Rural Empoyment Programme in different States during the years 1980-81 to 1982-83 are laid on the Table of the House, [Placed in Library *See* No. LT—7158/183)

Consumption of Butter Oil and Skim Milk by DMS and Mother Dairy

1969. SHRI BABURAO PARANJPE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the Quantity of butter oil and skim milk powder consumed by DMS and Mother Dairy during last two years and the particulars and address of parties from which these were procurred and the price paid by them for the same ;

(b) the use to which this butter oil and skim milk powder was put to by DMS and Mother Dairy in these years ;

(c) the quantity of each product other than toned/full cream milk produced by DMS and Mother Dariry in the last two years along with sale prices of each and sales revenue earned from these items in last two years ; and

(d) the particulars and addresses of outlets through which such products are sold and the quantity of each product sold at each such outlet during last two years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The quantity of Butter Oil (B. O.) and Skimmed Milk Powder (SMP) consumed by Delhi Milk Scheme (DMS) and Mother Dairy (MD) are indicated below :

(Figures in tonnes)

Year	D. M. S.		M. D.	
	B.O	S.M.P.	B.O.	S.M.P.
1981-82	2074.93	7858.39	2448.62	11533.51
1982-83	738.41	6360.19	464.16	9840.55

The items were purchased from the Indian Dairy Corporation, Baroda. (IDC)

The rates paid (excluding taxes, freight etc.) are as follows :

Butter Oil (*Rate per tonne in Rs.*)

D.M S		*Mother Dairy*	
Period	*Rate*	*Period*	*Rate*
1.4.81 to 31.12.81	13,000	1.4.81 to ,30.9.81	13,000
1.1.82 to 31.1.83	18,000	1.10.81 to 31.12.81	14,000
		1.1.82 to 31.3.83	18,000

Skimmed Milk Powder (*Rate per tonnes in Rs.*)

D. M. S.		*Mother Dairy*	
Period	*Rate*	*Period*	*Rate*
1.4.81 to 31.12.81	9,000 *23,000	1.4.81 to 31.12.81	9,000 13,500
1.1.82 to 31.12.82	12,000	1.1.82 to 31.12.82	12,000
1.1.83 to 31.3.83	14,000	1.1.83 to 31.3.83	14,000

* Price paid to a State Coperative Milk Producers Federation for purchases made through I. D. C.

All other prices are at pool rates.

(b) These items were used by D. M. S./ Mother Dairy for reconstitution/recombination of milk. Apart from Butter Oil given for recombination, Indian Dairy Corporation also supplied to Mother Dairy butter oil to be sold as cooking medium.

(c) The quantity of milk products other than tonned/full cream milk produced by D. M. S./Mother Dairy and the sales revenue earned therefrom during 1981-82 and 1982-83 are as under :

DELHI MILK SCHEME

Item	*Quantity*	*Sales revenue*
		(Rs. in lakhs)
1. Ghee	512.30 Tonnes	158.16
2. White Table Butter	25.72 ,,	
3. Salted Table Butter	142.83 ,,	39.84
4. Yoghurt	2,19,541 Kullars	2.28
5. Flavoured milk.	1,04,248 Bottles	1.50

MOTHER DAIRY

Item	*Quantity (in lakh Ltd.)*	*Sales revenue (Rs. in lakhs)*
1. Cow milk	1.19	3.13
2. Standardised	1,010.83	2,192.69

Sale price of the above items are indicated below :

DELHI MILK SCHEME

(in Rupees)

	As on 31.3.82	*As on 31.3.83*
1. Ghee (1 kg. tin)	Rs. 40.00	Rs. 38.00
2. White Table Butter (50C gms.)	Rs. 16.25	Rs. 15.50
3. Salted Table Butter (500 gm).	Rs. 15.25	Rs. 14.50
4. Yoghurt (Plain) (1 Kullar)	0.90	0.90
5. Yoghurt (Sweet) (1 Kullar)	Rs. 1.00	Rs. 1.00
6. Flavoured milk (1 bottle)	—	Rs. 1.25

MOTHER DAIRY	*Rs. litre*
1. Cow Milk	2.70*
2. Standarised milk	2.20**
	3.10***

* Supplied in sachet upto 15.5.81
** Supplied upto 6.11.81
*** Supplied to sachet to ITDC for ASIAD

(d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Mother Dairy Booths

1970. SHRI BABURAO PARANJPE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to U.S.Q. No. 2552 on 8 August 1983 regarding D. M. S. and Mother Dairy and state :

(a) how many Mother Dairy automatic vending booths and other type of retailors are located in Delhi along with a list of particulars of vendors, their location along with the average daily quantity of milk sold at each outlet ;

(b) the particulars and addresses of public institutions and private organisations which are being supplied milk in bulk along with the average daily quantity of milk purchased by each such purchaser ; and

(c) the average daily quantity of toned milk and full cream milk sold at each of the above milk retail outlets and sold to bulk buyers, separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) As on 31.10.83, there were 302 milk vending booths, 290 insulated containers and 219 shops selling milk of Mother Dairy. Particulars of vendors with location, average sale of milk during October, 1983 in respect of the above three categories of distributors are indicated in the statements I, II and respectively. (Placed in Library. *See*. No. LT 7159/83)

(b) The names and addresses of the Government/Public and the private organisations who are being supplied milk in bulk are mentioned IV and in statements V respectively. (Placed in Library, *See* No. LT-7159/83) Average daily quantity of milk purchased by such organisations in October, 1983 is indicated in column 3 of the statements IV and V against each.

(c) Average daily quantity of toned milk sold in October, 1983 through milk vending booths and insulated containers is indicated in column 5 of the statements I and II respectively. Full cream milk sold in October, 1983, through shops is indicated in column 4 of the statement III.

The particulars of average daily sale of toned milk to bulk buyers through the milk vending booths in October, 1983 is indicated in column 4 of the statement I.

Relationship Between Mother Dairy and Booth Vendors

1971. SHRI BABURAO PARANJPE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the nature of relationship between Mother Dairy and persons manning milk vending booths and lay and copy of the agreements between the two on the Table of the House ;

(b) the milk vending hours at automatic booths and other type of retail outlets and who is responsible for the quality of the milk sold ; and

(c) the chemical composition of toned and full cream milk sold by Mother Dairy along with a copy of the test report on the basis of which this composition was determined ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) :(a) The nature of relationship between Mother Dairy and the persons manning bulk milk vending booths called concessionaire is contractual and commercial in nature. A copy of the agreement would be placed on the Table of House separately.

(b) Sale hours at bulk vending booths are as under :

	Morning	*Evening*
April to October	5.30 am to 8.30 am	4.30 pm to 7.00 pm
November to March	6.00 am to 9.00 am	4.00 pm to 7.00 pm

The concessionaire is responsible for the quality of Mother Dairy milk sold to the customers from the booths as per provisions of the agreement.

(c) The composition of the Fat and Solid Not Fat in the toned and full cream milk marketed by the Mother Dairy are determined according to the standards applicable as per the Prevention of Food Adulteration act, 1954 which are as follows :

Type of Milk	*Fat*	*Solid Not Fat*
Toned	3.0	8.5
Full Cream	6.00	9.0

Villages to be Submerged with Construction of Narmada Valley Project

1972. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) total number of people and the villages to be displaced with the construction of Narmada Valley Project with the State-wise break-up ;

(b) percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in that ; and

(c) whether any plan has been drawn up for their resettlement by different States ; if so, facts in details ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Presumably, the Honourable Member is referring to villages and population to be displaced by Sardar Sarovar Project on the Narmada river in Gujarat taken up for execution. As per the latest information available, the details are given below :

State	*No. of villages to be affected*	*Population/ families*
Madhya Pradesh	182	45000 persons (7500 families)
Maharashtra	37	11747 persons (1358 families)
Gujarat	19	10593 persons (1900 families)

(b) These details are not maintained at the Centre. However, the people affected in Gujarat are reported to be mostly tribals.

(c) The Narmada Water Disputes Tribunal in its Award has specified the norms for land acquisition and rehabilitation measures for the affected population. The displaced persons would be resettled in the irrigation command area of Sardar Sarovar Project in Gujarat for such of those oustees who wish to migrate or alternatively, the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra would identify land for their settlement and provide rehabilitation measures and amenties without creating much of cological disturbance to the people. The States are carrying out necessary surveys and studies in this regard. The cost of land acquisition and rehabilitation would be a charge on the Sardar Sarovar Project.

Rate of Deforestation and Afforestation

1973. SHRI A. K. ROY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have made any study about the rate of depletion of the forests in the country and the rate of afforestation ; if so, the details thereof ;

(b) whether it is a fact that the firewood used as fuel in the country per year is more than the firewood that the country's forests could produce without depletion ; if so, the details thereof ; and

(c) whether Government have any comprehensive plan of afforestation to make up the loss since independence and to restore the forest area to the optimum level ; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) 43.28 lakhs ha. forest area was disforested in India from 1951-52 to 1979-80 at an average rate of 1.5 lakh ha. per annum. From 25.10.80 when Forest (Conservation) Act 1980 came into force to 30.10.83, the Central Government has allowed disforestation of 10800 ha. forest area bringing down the rate of disforestation to about 3600 ha. per annum.

35.57 lakh ha. area was afforested during the period 1951-52 to 1979-80 at an average rate of afforestation of 1.18 lakh ha. per annum. Afforestation programme has been stepped up during the Sixth Five Year Plan Period. Total area covered (upto Nov. 1983) and to be covered during 1980-85 Plan period will be 22.56 lakh ha. at an average afforestation rate of 4.51 lakh ha. per annum.

(b) Present fuelwood consumption in India is 133 million tonnes whereas present production from recorded sources is 39 million tonnes only, thereby leaving a gap of 94 million tonnes between requirement and availability of fuelwood.

(c) Afforestation programme has been undertaken as a plan activity. Afforestation efforts have been intensified with the introduction of the new 20 point programme. Various Centrally Sponsored, State Plan and Foreign aided afforestation including Social Forestry Programmes are being implemented.

Forest Conservation Act 1980 has been enacted to check disforestation.

Taming of River Rapti

1974. SHRI ASHFAQ HUSAIN : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the details of different proposals and plans under active consideration of Government to tame the river Rapti in India and in Nepal;

(b) results of the negotiation with the Government of Nepal on these proposals;

(c) whether Government are hopeful of success of negotiations; and

(d) if so, will Government include this in Seventh Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d) Government of Uttar Pradesh propose to plan small reservoirs in the Rapti Basin for providing irrigation to an area of about 24000 hactares.

Multipurpose storage scheme on River Rapti in Nepal will, in addition to benefits of irrigation and hydel power generation also afford flood control benefits to areas in Nepal and Uttar Pradesh. Discussions with Nepal at the level of Secretaries, have been going on since 1979 on the proposal made to Nepal to consider the construction of a High Dam at Balubhang on River Rapti. The last round of discussions was in April 1983.

Government of Uttar Pradesh have not yet finalised their proposals for projects to be included in the Seventh plan.

Optimum Use of Asiad Set-Ups and Their Maintenance

1975. SHRI MOHAN LAL PATEL : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether optimum use of Asian Games infra-structure in New Delhi is being made ;

(b) if so, the details of each of the infrastructure; and

(c) the annual cost of their maintenance and the annual income from the use of these structures approximalely ?

THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) The Asiad stadia mentioned in the Question are being used for sports activities including coaching/training of s port-persons. Schemes have since been drawn up for the further utilisation of these stadia for sports, pending the formation of the Sports Authority of India. As and when the stadia are not required for any sports activity, they are allowed to be used on demand for non-sports activities, such as cultural programme, conferences, etc. on payment. This is done to recover some money for meeting the expenditure to that extent on the maintenance of the stadia. A statement giving the events organi-

sed in the stadia, alongwith the charges, is laid on the Table of the House. [Placed in Liaberary *See* No. LT.7160/83]

(c) The annual cost of the maintenance of Asiad stadia and annual income from their use approximately, as intimated by the concerned agencies in Delhi, at present is given below :—

Name of the Stadium	Annual cost of main enance	Annual income from use
Jawaharlal Nehru Stadium	Rs. 40,31,000/-	Rs. 6,03,900/- (So far after IX Asian Games)
National Stadium	Rs. 11,00,000/-	Rs. 10,545/- (So far after IX Asian Games)
Hauz Khas Lawn Tennis Stadium	Rs. 1;85,000/-	Rs. 5,475/- (So far after IX Asian Games)
Tughlakabad Shooting Ranges	Rs. 96,000/-	Rs. 3,790/- (So far after IX Assan Games)
Yamuna Velodrome	Rs. 12,00,000/-	Rs. 21,235/- (So far after IX Asian Games)
Indraprastha Indoor Stadium	Rs. 1,30,00,000/-	Rs. 18,19,470/- (So far after IX Asian Games)
Talkatora Swmming Pool	Rs. 72,00,000/-	Rs. 4,00,000/- (So far after IX Asian Games)
Talkatora Indoor Stadium	Rs. 11,60,000/-	Rs. 2,25,000/-
Shivaji Stadium	Rs. 4,76,000/-	Rs. 7,600/-

Corruption Among Block Staff and Bank Employees in Rural Development Programme

1976. SHRI DAYA RAM SHAKYA :
SHRI RAM JETHMALANI :
Will the Minister of RURAL DEVEOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are complaints of wide-spread corruption among block staff and bank employees connected with the implementation of rural development programmes ;

(b) i so, the steps taken or being taken by Government to check corruption; and

(c) what are the feed back reports in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) to (c) There are isolated compliants of malpractices among government and semi-government employees connected with the implementation of rural development programmes.

Specific allegations when received are referred to the concerned State Governments and local authorities for suitable enquiry and necessary action. There are safeguards provided in the guidelines for the rural development programme such as the close involvement of the Gram Sabha and the

local bodies in the planning and implementation process. These safeguards are calculated to minimise malpractices.

Grant Given to West Bengal Under IRDP

1977. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state the amount of matching grant given by the Central Government during the current year to West Bengal for their I.R.D. Programme particularly for the very poor and weaker sections of the rain-prone and marshy areas in Sunderbans of that State ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHAN MISRA) : Central grants for implementation of Intergrated Rural Development Programme are released to District Rural Development Agencies in to instalments every year on the basis of the actual utilisation of funds reported by the District Rural Development Agencies in respect of the preceding year. Provision of a utilisation certificate, audited statement of accounts and certain other procedural requirements are also to be met by the District Rural Development Agencies to enable them to obtain Central Grants-in-aid. In the current year (1983-84), it has not been possible to release any funds to any of the District Rural Development Agencies in West Bengal on the basis of the pace of absorption of funds in the preceding year.

Implementation of Urban Land Celling Act

1978. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the progress made so far in the implementation of the Urban Land Ceiling Act in the various States and Union Territories;

(b) whether this Act has not been enforced in many of the States; if so, which are these and the reasons therefore; and

(c) the total area of land acquired in Delhi under this Act so far and how this land is likely to be utilised for the benefits of weaker and poorer sections of the society ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMEND USMAN ARIF) : (a) According to the information received so far from the various States and Union Territories, 361034 persons holding vacant land in excess of the ceiling limit under the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976, have filed statements out of which 86016 statements have been disposed of. So far 5723 hectares of excess vacant land have been acquired and vested with the State Govts. Under Section 21 of the Act, a person may be permitted to hold vacant land in excess of the ceiling limit for constructing dwelling units for the weaker section of the society in accordance with the terms and conditions prescribed. Out of 5783 schemes received for this purpose. 1258 have been approved covering 2206 hectares of land envisaging 166867 dwelling units.

(b) Tne Act has not been adopted by Jammu & Kashmir, Kerala, Nagaland, Sikkim and Tamil Nadu. Jammu & Kashmir and Kerala wanted to have their own legislations to suit local conditions. In Nagaland and Sikkim there is no pressure on urban land. In Tamil Nadu there is a State law which has been in force from 14.5.1978.

(c) Delhi Administration have intimated that 19978 sq. metres of land in village Geharoli has been acquired and handed over to the Delhi Development Authority for utilisation.

Misuse of Rehablitation Colony Premises for Commercial Purposes

1979. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to reply given to U.S.Q. No. 4636 on 22nd August 1983 regarding misuse of rehablitation colony premises for commercial purposes and state :

(a) whether the requisite information has since been collected;

(b) if so, whether he will now lay it on the Table of the House;

(c) if not, the difficulties which lie in his way in collecting this information from the local authorities although a period of more than 3 months has elapsed since the above reply was given; and

(d) when he will collect the requisite information completely and lay it on the Table ?

THE DEPUTY MINISTER OF WORKS HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) The Statement is fulfilment of the Assurance given to the Lok Sabha Unstarred Question No.4636 dated the 22nd August, has already been laid on the Table of the Lok Sabha on the 21st November, 1983.

(c) and (d) Does not arise in view of the reply given to part (b) of the question.

खाद्यान्नों और दालों का उत्पादन और मांग

1980. **श्री सत्यनारायण जोटिया** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 से 1982-83 की अवधि के दौरान देश में खाद्यान्नों और दालों का कितना उत्पादन हुआ और उनकी मांग कितनी थी ; और

(ख) उनकी मांग तथा पूर्ति की तुलना में खाद्यान्नों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) छठी योजना के दस्तावेज में योजना के अन्तिम वर्ष के लिए जिन्स की मांग तथा सप्लाई के सन्तुलन के आधार पर जिन्स उत्पादन के अनुमान दिए गए हैं। मांग के वर्षवार आंकड़े विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ।

1980-81 से 1982-83 तक धान्य, दलहन और कुल खाद्यान्न के उत्पादन के अनुमान निम्नलिखित हैं :—

	उत्पादन (दस लाख मीटरी टन)		
वर्ष	**धान्य**	**दलहन**	**कुल खाद्यान्न**
1980-81	119.0	10.6	129.6
1981-82	121.8	11.5	133.3
1982-83	116.8	11.6	128.4

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार

(2) उर्वरकों का अधिक और सक्षम उपयोग

(3) उत्तम प्रकार के बीजों के वितरण में वृद्धि

(4) विस्तार किए गए क्षेत्रों में वनस्पति संरक्षण के पर्याप्त उपाय

(5) अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार

(6) चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना और बीजों के मिनिकिटों के वितरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को तीव्र करना

(7) मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा बारानी खेती की उन्नत पद्धतियों पर अधिक जोर देना

(8) प्रशिक्षण और दौरों की पुर्नगठित विस्तार पद्धति के माध्यम से प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

(9) किसानों और विस्तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(10) अनुसंधान को तीव्र करना, और

(11) उचित मूल्य नीतियों को लागू करना ।

उत्पादन से संबन्धित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष मुख्य फसल मौसमों (खरीफ और रबी) के दौरान उत्पादन अभियान चला रही है । इस अभियान के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय कृषि आदान पखवाड़े आयोजित किये जाते हैं। समस्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों और निजी तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को किसानों के लिए सात अत्यावश्यक आदानों अर्थात् प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, कीटनाशी औषधियां, उपस्कर, सिंचाई और ऋण उपलब्ध कराने के लिए संगठित किया जाता है ।

राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धान्य और दलहन के उत्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

National Institute on Disaster Management

1981. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is an imperative need for the establishment of a crops of personnel well-versed in the art disaster management and capable of accepting the responsibility for such management when the time comes;

(b) whether there is an utmost importance of establishing a national institute for looking into totality of disaster management from the socio-economic agro-climatic, metereological, administrative and engieering angles; and

(c) if so, whether any attention has been paid in this behalf ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURAL (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) to (c) Yes, Sir. A proposal to establish a 'National Bureau of Disaster, Training and Management which will look into different aspects of disaster Management, is under active consideration of Government of India.

Double Cropping System in Black Soils

1982. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the Minister of AGRICUTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry has introduced double cropping system in the black soils ;

(b) if so, the schemes introduced by Government for the purpose ;

(c) the target set by Government for introducing double cropping system in 1983-84 ; and

(d) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) to (d) There is no specific scheme of this Ministry for introducing double cropping system in the black soils. However, farmers are being motivated to go for double cropping by way of adoption of improved technology.

A Central Sector Scheme of Pilot Project for propagation of water conservation/harvesting technology in dry farming areas is being implemented from this year with a objective to elevate and stabilize production in rainfed areas including the black soil areas in two districts in Madhya Pradesh and in one district of Maharashtra. Besides, under Indian Council of Agricultural Research an All India Coordinated Project on Dryland Agriculture is in implementation. The Project is in operation at 23 centres, out of which six centres, Bellary and Bijapur in Karnataka, Sholapur and Akola in Maharashtra and Indore and Rewa in Madhya Pradesh are located in black soil regions of the country. The main objective of this project is to provide technology to satabilize the agricultural production in rainfed areas. During the last one decade the project has developed suitable crop production technology for rainfed areas of different regions.

Holding Universiad 1983 in Delhi

1983. SHRI NAVIN RAVANI : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether Government propose to hold Universiad 1983 in Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) The World University Games are held by members of the International University Games Federation. The member in India is the Association of Indian Universities. They have sent a proposal for holding the World Universities Games in 1987 in New Delhi.

Central Assistance to Gujarat under Integrated Urban Development Scheme

1984. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Union Government are providing financial assistance regarding Integrated Urban Development Scheme to the State ;

(b) the details regarding the amount granted by the Central Government to the Gujarat state in respect of Centrally Aided Integrated Urban Development Scheme during last three years, year-wise ; and

(c) the amount so far utilised by the State Government for providing water supply to small and medium size towns during last three years, year-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, in respect of certain identified small and medium towns.

(b) The Central Govt. have released so far Rs. 256.03 lakhs to Gujarat Govt. under the Centrally Sponsored Scheme for Intergrated Development of Small and Medium Towns. The year-wise details are as under :

1979-80	Rs. 39.48 lakhs
1980-81	Rs. 34.25 lakhs
1981-82	Rs. 93.00 lakhs
1982-83	Rs. 63.30 lakhs
1983-84	Rs. 26.00 lakhs
Total :	Rs. 256.03 lakhs

(c) Water supply schemes are not funded by the Central Govt. under this scheme. Hence, no figures are available on this account with us.

मकानों के निर्माण के लिए कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता

1985. **श्री छोटू भाई गामित** . क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए राज्यों में कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती 1 ;

(ख) यदि हां, तो उसके मानदण्ड क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात को कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और राज्य सरकार ने कितनी राशि व्यय की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) आवास के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य क्षेत्र के परिव्यय के एक भाग के रूप में है और यह सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना से सम्बद्ध नहीं होती है । आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के लिए छठी योजना अवधि में निर्धारित कुल परिव्यय 485 करोड़ रुपये हैं । इसके अतिरिक्त, योजना अवधि के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा 600 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत इस वर्ग के लिए उद्दिष्ट है ।

(ख) योजना नियतनों के अलावा, 138868 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ हुडको द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान गुजरात सरकार को 55.87 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से 120876 रिहायशी एकक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए थे । राज्य सरकार द्वारा खर्च की राशि के बारे में सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय फुटबाल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को किराया दिया जाना

1986. **श्री हरिश कुमार गंगवार** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब और भारत के बीच 1 अक्तूबर, 1983 को दिल्ली में कोई फुटबाल मैच हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो यदि किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय फुटबाल प्रशिक्षण शिविर में बुलाया जाता है और उसका चयन नहीं होता है तो क्या उसे दोनों तरफ का हवाई जहाज का

किराया तथा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 26 रु० की दर से भोजन आवास व्यय किया जाता है ;

(ग) क्या उनको हवाई जहाज के किराए तथा निजी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि राष्ट्रीय फुटबाल प्रशिक्षण शिविरों के लिए खिलाड़ियों के चयन को अन्तिम रूप अखिल भारतीय फुटबाल संघ द्वारा दिया जाता है, सरकार की खिलाड़ियों के आवास/खान-पान पर व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी 26/—रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक ही सीमित है।

(ग) और (घ) सरकार यात्राओं अर्थात् रेल हवाई जहाज किराया इत्यादि और व्यक्तिगत भत्तों पर खर्च को वहन नहीं करती है।

वनस्पति घी की खपत में कमी

1987. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने वनस्पति घी तथा आयातित तेल के उपयोग में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह कमी वनस्पति घी तथा आयातित तेल में गाय की चर्बी की मिलावट के कारण आई है ; और

(घ) यदि हां, तो गाय की चर्बी की मिलावट करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Amount Released to Goa, Daman and Diu Under the Csarwsp

1988. SHRIMATI SANYOGITA RANE : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the amount released to the Union Territory of Goa, Daman and Diu under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme ; and

(b) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) An amount of Rs. 102.5 lakhs has been provided during the Sixth Plan under the Centrally sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme for Goa, Daman & Diu. The details of funds areas follows :

Year	Funds released (Rs. lakhs)
1980-81	11.46
1981-82	14.25
1982-83	20.94
1983-84	51.07 (upto 16.11.83)

In addition, an amount of Rs. 4 lakhs has been released to this Union Territory under the new Centrally Sponsored Incentive scheme based on performance.

निर्यात के लिए रखी गई चीनी का खराब हो जाना

1989. **श्री निहाल सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भाण्डागार निगम, खंडवा के गोदाम में निर्यात के लिए रखी गई अतिरिक्त एक लाख तीस हजार बोरी चीनी अब निर्यात के लिए नहीं रही है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी खराब हो जाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस कारण से सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 31-10-1983 तक विशेष स्टाक के रूप में सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के खण्डवा के भण्डागार में 1,37,409 चीनी की बोरियां रखी थीं ताकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय करार, 1977 के अन्तर्गत अपने दायित्वों को निभा सके। इस स्टाक की निर्यात के लिए आवश्यकता हो भी सकती है अथवा नहीं भी। सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने सूचित किया है कि वर्षा के मौसम के दौरान नमी से ग्रस्त होने के कारण इसमें से कुछ स्टाक प्रभावित हुआ है। नमी-ग्रस्त स्टाक को निर्यात-बाजार में स्वीकार नहीं भी किया जा सकता है।

(ख) सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

राज्य बीज निगमों द्वारा सस्ती दरों पर बीजों की सप्लाई

1990. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य बीज निगमों को रबी की फसलों के लिए सस्ती दरों पर बीज सप्लाई करने के लिए निदेश दिए थे ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को पृथक-पृथक बीजों की उत्पादवार कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गयी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं। तथापि, सरकार ने बीजों के मूल्यों का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की है और उसकी रिपोर्ट अभी आनी है।

(ख) रबी 1983-84 के दौरान सप्लाई किए जाने वाले बीजों की राज्यवार तथा फसलवार अनुमानित मात्रा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०-7161/83]

Installation of water Taps in Gandhi Nagar and Kailash Nagar, Trans-Yamuna Colonies

1991. SHRI NIHAL SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the reasons for which water taps have not been installed in the oldest Trans-Yamuna colonies of Gandhi Nagar and Kailash Nagar by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, whereas comparatively new colonies and resettlement colonies have been provided with this facility ; and

(b) the time by which water taps would be installed in both these colonies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking have reported that Gandhi Nagar and Kailash Nagar are regularised colonies. They have stated that the policy of the Undertaking is to provide water supply and sewage in regularised colonies, subject to technical feasibility, on payment of development charges by the beneficiaries and work is taken in hand if 10 per cent of the estimated cost is received in advance. According to the Undertaking, the work could not be taken in hand in these two colonies since the minimum development charges have not been received.

(b) The Undertaking has informed that the time for laying of water mains would depend on receipt of 10 per cent of estimated cost of development charges from the beneficiaries.

Amount Released to States for rural water Supply Scheme

1992. SHRI ANANDA PATHAK : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) total amount sanctioned and released to the States/Union Territories for rural water supply during the last five years, year-wise and State-wise details thereof ;

(b) number of problem villages remained

till October, 1983, State-wise details thereof ; and

(c) exepected time by when all these villages would be provided with drinking water ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The Statement of releases under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme, year-wise and State-wise, is enclosed at 'A'.

(b) and (c) A total of 230784 villages have been identified as problem villages for the Sixth Plan period. Out of this, the number of villages covered during 1980-83, i. e., the first three years of the Plan, the target for 1983-84, and the balance number of villages on 1.4.84, are given in the enclosed statement 'B'. The Sixth Plan envisages a target of 100% coverage of the identified 2. 31 lakh problem villages.

STATEMENT A'

ACCELERATED RURAL WATER SUPPLY PROGRAMME

(Rs. in lakhs)

S. No.	States/U.T.s	Funds released for Works Component during				
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andhra Pradesh	347.00	215.60	432.23	370.75	473.50
2.	Assam	144.13	323.15	427.11	400.75	581.50
3.	Bihar	500.00	680.45	503.36	862.50	863.75
4.	Gujarat	254.85	126.20	354.00	396.25	281.00
5.	Haryana	197.00	259.00	355.00	335.00	273.00
6.	Himachal Pradesh	422.00	388.86	561.77	364.50	273.73
7.	Jammu & Kashmir	200.00	181.55	313.00	424.75	1055.50
8.	Karnataka	105.00	65.00	248.81	485.50	941.50
9.	Kerala	275.00	282.35	328.40	526.25	641.00
10.	Madhya Pradesh	290.00	353.15	690.00	1033.75	1397.50
11.	Maharashtra	397.97	372.30	659.00	552.00	716.50
12.	Manipur	50.00	48.55	105.00	146.00	154.00
13.	Meghalaya	100.00	106.60	149.00	242.00	200.48
14.	Nagaland	91.00	133.57	150.00	178.50	149.18
15.	Orissa	212.00	203.00	307.00	593.00	766.50
16.	Punjab	170.00	68.40	128.95	88.17	183.00
17.	Rajasthan	348.90	205.00	559.10	1504.19*	2229.50
18.	Sikkim	39.09	20.00	19.50	69.74	62.43
19.	Tamil Nadu	402.00	213.52	500.00	563.71	850.50
20.	Tripura	110.00	91.15	112.44	85.50	81.50
21.	Uttar Pradesh	614.00	703.55	944.95	1018.13	1940.99
22.	West Bengal	530.00	670.05	448.50	571.30	887.50

1	2	3	4	5	6	7
23.	A & N Islands	18.50	5.00	6.00	19.50	6.64
24.	Arnachal Pradesh	30.00	44.20	35.00	35.00	30.00
25.	Chandigarh	—	—	—	—	—
26.	Delhi	12.00	11.10	13.50	9.50	NIL
27.	Dadra & Nagar Haveli	—	—	—	—	—
28.	Goa, Daman & Diu	7.50	9.95	11.46	14.25	20.94
29.	Lakshadweep	—	—	—	—	—
30.	Mizoram	18.50	17.05	26.25	NIL	3.00
31.	Pondicherry	15.00	12.00	7.00	12.00	14.00
	Total	5901.44	5820.30	8391.33	10902.49	15079.14

* includes Rs. 71.00 lakhs paid as customs duty for ADP Rigs.

STATEMENT 'B'

Sl. No.	State/U.T.	No. of Problem villages covered during 1980-83	Target (no. of Problem villages) for 83-84	Balance No. of Problem villages on 1-4-84
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	5160	1478	1568
2.	Assam	3839	2380	9524
3.	Bihar	8375	2760	4050
4.	Gujarat	1818	1000	2500
5.	Haryana	885	355	2200
6.	Himachal Pradesh	3366	800	3649
7.	Jammu & Kashmir	1027	460	3211
8.	Karnataka	10469	7728	NIL
9.	Kerala	274	200	684
10.	Madhya Pradesh	17963	6000	981
11.	Maharastra	7919	3563	1453
12.	Manipur	447	145	620
13.	Meghalaya	315	415	2197
14.	Nagaland	229	80	340
15.	Orissa	8795	5060	9761
16.	Punjab	207	125	1435
17.	Rajasthan	10056	3200	6547
18.	Sikkim	102	88	100

1	2	3	4	5
19.	Tamil Nadu	4410	1400	839
20.	Tripura	1349	633	818
21.	Uttar Pradesh	7401	8000	13104
22.	West Bengal	61665	2400	16677
23.	A & N Islands	61	63	49
24.	Arunachal Pradesh	790	430	520
25.	Chandigarh	—	—	—
26.	Delhi	77	12	NIL
27.	Dadra & Nagar Haveli	—	—	—
28.	Goa, Daman & Diu	38	14	14
29.	Kakshadweep	—	—	—
30.	Mizoram	43	39	132
31.	Pondicherry	78	30	10
	TOTAL	1,01,059	48846	82998

Includes partially covered problem villages. £ Districtwise details under the Zila Parishad Programme to be furnished by the State.

Loss Of Records In Land And Development Office

1993. SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4650 on 22 August, 1983 regarding loss of records of Land and Development Office and state :

(a) whether CBI in a letter dated 17 February, 1973 infonmed the Land and Deveploment Offfce about the result of their enquiry and results thereof ;

(b) whether the Land and Development Officer in his reply No. Adm. 14 (4)/33/67 dated 27 February, 1973 reported to CBI reprehensible conduct of certain officers to falsely implicate the person mentioned in the news report in two cases to provide defence for hushing up the case of corruption exposed by him ; and

(c) action taken or proposed to be taken against the erring officers of L&DO and his Ministry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMAD USMAN ARIF) : (a) The CBI letter dated 17th February, 1973 do not convey the result of its enquiry, but it contained some suggestion in the matter of dealing with the case.

(b) and (c) Land and Development Officer in his letter dated the 27th February, 1973 to CBI, indicated the steps taken to tackle the allegation of corruption in a particular case. The particular case was in the Delhi High Court and action was taken in accordance with the Govt. judgement. Government does not contemplate any further action now.

Practice By Doctors And Running Of Nursery Schools In Residential Units Of D.D.A. And L&DO

1994. SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4478 on 22 August, 1983 regarding practice by doctors and running of Nursery Schools

in residential units of D.D.A. and state :

(a) whether there is any provision to carry out some occupation like those of Doctors, Nursery Schools, etc., in residential units of D.D.A. colony or L&DO Colony ;

(b) if so, details of all such trades which can be carried out by the owners to earn their livelihood ; and

(c) whether approval from D.D.A. and/or L&DO is required in such cases, if so, the procedure for obtaining the permission ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISRTY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) *Delhi Development Authority Colonies* :

(1) Professionals such as doctors, lawyers, architects, engineers, chartered accountants, business consultants and journalists are permitted to use a part of their residential premises for their professional work subject to the condition that portion so used does not exceed 500 sq. ft. or 25% of the covered area of the residential premises occupied by them whichever is less.

(2) Nursery schools in the residential "use zones" are permitted under the provisions of the Master Plan.

(3) Health/beauty saloons are also permitted in residential premises subject to the following conditions :-

(i) The applicant should be resident of the premises.

(ii) Not more than 3 persons including the owner are employed.

(iii) Not more than 500 sq. ft or 25% of the covered area whichever is less, should be under use for professional work.

(4) Formal approval from DDA has to be obtained in each case under these categories.

L&DO Colonies :

(1) Accommodation used by the occupants for professional work such as, Doctors, hakims, vaids, lawyers, architects, engineers, Charted Accoutants, business consultants and journalists when it is used by the occupants of the whole or major part of the residential premises subject to the condition that the portion being used for the purpose does not exceed 30% of the covered area or 500 sq. feet whichever is less. For leases upto 200 sq. Yards, the permissible area is 500 sq. feet (without the limit of 30%).

(2) (i) For doctors, hakims and vaids, who utilise part of their residences for examining their patients who do not stay for any length of time ;

(ii) For general practioners, who maintain a small dispensary in the chambers with or without dispensary giving medicines to their patients as part of their medical service;

(iii) For dentists having a small clinic-cum-opertion theatre ;

the condonable area in all these cases is not morethan 500 sq. feet.

(3) Music school if it is being run by the occupant residing in the premises or in major part of the premises.

(4) Self-employed lessees/occupants/ tenants with the help of an assistant or two such as, journalists, goldsmiths, photographers and small technicians and mechanics, if the accommodation is being used by occupants, who are residing in the premises and the misuse is not more than 300 sq. feet.

(5) Running of classes of shorthand/ typewriting, music, painting dance and nursery, primary schools, etc., provided they are run by resident lessees/tenants.

(b) and (c) Besides the permissible uses indicated in reply to part (a), the household industries indicated, in the statement are permitted by the competent authority under special appeal. The DDA has delegated powers to local bodies i.e., MCD and NDMC in this regard. These are, however, subject to the following conditions :-

(i) In an approved residential area, not more than 300 sq. ft. of floor space of the dwelling alongwith residence of the owner of the family.

(ii) Number of workers should be not more than four.

(iii) Power load 1 KW domestic power single phase load and 2 KW power with three-three phase load.

(iv) The units would not be considered for alternative allotment and licences would given to them on a regular basis.

Prior approval of the concerned local body is necessary in each case and the applicant has to apply for the same.

In L&DO colonies similar household trades are permissible and permission of lessor is not required.

STATEMENT

1. Agarbati & other products.
2. Calico & textile printing.
3. Cane & Bamboo products.
4. Clay Modelling.
5. Coir & other Fibre products.
6. Zari Zardezi.
7. Hosiery.
8. Jwellary work.
9. Stone engraving.
10. Manufacture of :
    (i) Blance cakes
    (ii) Brushes
    (iii) Crayons
    (iv) Ice Cream & confectionary.
    (v) Jam, Jellies & Fruit preserves.
    (vi) Narrow fabrics and lace work material.
    (vii) Musical instruments including repairs.
    (viii) Ornamental leather goods such as purses hand bags.
    (ix) Small Electronics Components.
11. Paper Stationary items including book binding.
12. Framing of pictures and looking glasses.
13. Pithwork manufacturing of pith hats, garland and flowers.
14. Tailoring.
15. Thread balls and Cotton Filling.
16. Umbrella assembly.
17. Wood carving & artistic wood wares.
18. Vermicelli and macaroni.
19. Assembly and repairing of Electronic items.
20. Ivory carving.
21. Card Board Boxes.
22. Plastic and PVC Products with one moulding machine of one KW.
23. Toys & Dolls.
24. Paper Machine.
25. Copper & Brass Artware.
26. Lac products.
27. Candles
28. Cordage, Rope & Twine Making.
29. Batik work.
30. Corpentary.
31. Sports goods.
32. Leather Footwear.
33. Assembly & repair of Electrical Gadgets.
34. Dari & Carpet weaving.
35. Wool Balling and Lachee making.
36. Khadi & Handloom.
37. Leather & Rexian made ups.
38. Perfumary and cosmetics.
39. Assembly repair of sewing machines.
40. Surgical bondage rolling, cutting.
41. Repair of watches and clocks.
42. Fountain pens and Ball pens.
43. Village oil (Oil Shani) Industry with power load upto 2 K. W.
44. Manufacture of Soap with non-edible. oils.
45. Blacksmith.
46. Village Pottery industry with power load upto one K. W. — Provided the trade is run without using Bhatti.

Implementation of Development Schemes by DRAD

1995. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the particulars of various Central development and welfare schemes being implemented by District Rural Development Agency Units in various States and in what manner and the guidelines for each scheme ;

(b) particulars of such districts in the country where no such implementation unit works ;

(c) suggestions received from various States and also those that have appeared in the press to stimulate/make more effective the working of the above ;

(d) whether complaints have appeared in the press that many of the deserving persons in various areas are not getting the intended benefits ; and

(e) how the above complaints have been redressed ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) The District Rural Development Agencies were constituted for the implementation of IRD Programme. Later on they were asked to handle NREP. A brief note on the guidelines on these two programmes is enclosed.

Recently the Ministry of Agriculture has also advised the State Governments to entrust the implementation of the scheme of assistance to Small and Marginal Farmers for increasing agriculture production to the DRDAs.

(b) The DRDAs or their sub-agencies are in operation in all the districts in the country excepting Chandigarh which has only one block.

(c) No specific suggestion has come to the notice of the Central Government.

(d) and (e) Wherever specific complaints are brought to notice, the State Governments are requested to take appropriate action.

STATEMENT

GUIDELINES RELATING TO IRDP AND NREP

(*1*) *Integrated Rural Development Programme*

Under IRD programme, subsidy ranging from 25% to 50% is provided to the target group consisting of small farmers, marginal farmers and agricultural labourers, artisans, etc. who are below the poverty line for taking up economically viable activities for improving their economic condition. The balance of the amount is provided as institutional credit. 15 million families are to be assisted during the Sixth Five Year Plan on an average of 3,000 families per block. For this purpose, each block is given an allocation of Rs. 35 lakhs in the Sixth Five Year Plan. An outlay of Rs. 1,500 crores has beed approved for the scheme for the Sixth Five Year Plan.

(*2*) *National Rural Employment Programme*

The NREP has been designed to provide employment to the needy in rural areas. It is expected o generate 300 million to 400 million mandays every year. The employment is generated through creation of durable community assets. An outlay of Rs. 1620 crores has been approved for the scheme during the Sixth Five Year Plan. 10% of the resources are earmarked for schemes of Social Forestry and another 10% for works directly benefiting members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Nominal Ground rent charged by L & DO from Sagar Apartment as Premium for Covering Additional Floor area

1996. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether out of 21 multistoreyed buildings on L & DO land in Delhi, only 6 have paid charges as additional premium for additional floor area covered and as ground rent running into several lakhs of rupees and out of them 6, Tilak Marg housing the Sagar Apartments, were chargnominal ground rent only at heavily concessional rate ;

(b) the actual amounts charged from each one of these buildings for additional area covered and for ground rent and at what rates ;

(c) whether 6, Tilak Marg, has now made further additional constructions without permission of L & DO; if so, the dues being charged under the usual rates of L & D.O. for additional construction ; and

(d) steps taken to streamline the functioning of the L. & D.O. and their results ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) It is correct that only six have paid the required charges for additional floor area created in the construction of multistoreyed buildings. In the case of 6, Tilak Marg, no

concession was given in the charges which were in accordance with the instructions applicable to such cases at the relevant time.

(b) The amounts of additional premium and additional ground rent in respect of the six buildings are indicated as under :—

S. No.	Name of the Property	Additional Premium (Rs.)	Additional ground rent (Rs.)
1.	18, Curzon Road	36,96,516	1,84,836 P.A.
2.	20, Curzon Road	36,96,516	1,84,836 "
3.	25, Curzon Road	14,25,689	71,285 "
4.	Bank of Baroda	2,88,124	44,406 "
5.	State Bank of India	8,41,676	42,084 "
6.	6, Tilak Marg	—	88,140 "

(c) It is a fact that the lessee of 6 Tilak Marg has made some additional constructions after getting the plans sanctioned from New Delhi Municipal Committee but without the lessor's permission. No decision has yet been taken on the action to be taken against the lessee for the branches of the lease conditions.

(d) So far as the above cases are concerned, there does not appear to have been any inaction on the part of the L & DO requiring modification of the existing procedures of that Office.

Former M. Ps in Possession of Government Accommodation

1997 SHRI N. E. HORO : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the details regarding the former M. Ps, Party-wise, who are still in possession of Government accommodation ;

(b) the details regarding the rent so far paid or to be paid by them and since the time they are occupying the Government accommodation ; and

(c) the details regarding the rules followed in charging the rent so far and action Government have taken or are going to take in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (b) The details are shown in the enclosed statement.

(c) The details regarding the rules of recovery of rent are available in the Housing & Telephone Facilities (Member of Parliament) Rules 1956, and the instructions issued as per Accommodation Circular. For recovery of Government dues the matter is being pursued with the concerned former M. Ps. If necessary action will be taken in appropriate cases for recovery under the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1981.

STATEMENT

S. No.	Name	Party Affliation before ceasing to be an M. P.	Rent Paid for the period since the date of cancellation of Accommn. Rs.	Balance due Rs.
1	2	3	4	5
1.	Prof. D.P. Chattopadhyay	Congress (I)	34,953.40	8,712.50
2.	Sh. Om Mehta	—do—	513.66	95,051.51

1	2	3	4	5
3.	Sh. Dinesh Singh	—do—	1,771.65	1,18,669.25
4.	Sh. Mohd. Hassan Khan	Lok Dal	3,199.70	14,047.20
	Sh. A. P. Sharma	Congress (I)	—	76,473.05
6.	Sh. S. S. Sisodia	—do—	46,379.70	3,473.25
7.	Sh. D. K. Barooah	Congress	21,005.06	—

Streamlining the Functioning of PADI

1998 PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps for streamlining the functioning of PADI (People's Action for Development of India) and constituted its governing body and other organisations ;

(b) if so, the constitution of the governing body as at present and the details about the project taken up under this programme, State-wise during the first three years including the current financial year ; and

(c) if not, what action Government propose to streamline the functioning of the organisation ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) The Governing Council and the General Body have been reconstituted in accordance with Society's Rules and Regulations.

Detailed proposals for streamlining the procedures of work and strengthening of the organisation are being worked out.

(b) The present composition of Governing Council is given in enclosed Statement—I.

A State-wise list of projects sanctioned during the last two years i. e., 1981-82 and 1982-83 is given in enclosed Statement—II. During the current financial year, sanction of new projects is being processed.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Composition of Governing Council of PADI Society

Chairman

Members

INSTITUTIONS :

1. Secretary, Ministry of Rural Development.
2. Shri Manibhai Desai,
   Director,
   Bharatiya Agro-Industries Foundation,
   Urulikanchan, PUNE (Maharashtra).
3. Shri Jagdish Deen,
   Secretary,
   Rajendra Kusht Seva Ashram,
   Mairwa, Dist. Siwan (Bihar).
4. Principal,
   Loka Siksha Parishad,
   Ramakrishna Mission Ashram.
   Narendrapur,
   (West Bengal).
5. President,
   All India Panchayat Parishad,
   New Delhi.
6. Chairman,
   Khadi & Village Industries Commission,
   Bombay.
7. Shri Prem Bhai,
   Secretary,
   Agrindus Institue,
   Banbasi Ashram,
   Mirzapur (U.P.).

EX-OFFICIO

8. Joint Secretary (Finance) in the Ministry of Rural Development
9. Secretary,
   North Eastern Council,
   Shillong.
10. Commissioner-cum-Secretary for Rural Development,
    Government of Gujarat.
11. Secretary for Rural Development,
    Government of Madhya Pradesh.
12. Executive Director,
    Central Social Welfare Board,
    Jeevandeep Building, New Delhi.

INDIVIDUALS

13. Shrimati Ela Bhat,
General Secretary,
Sell-Employment Women Association,
Ahmedabad (Gujarat).

14. Dr. M. S. Neelkantha Rao,
WHO Consultant in Leprosy and
Executive Director,
Gandhi Memorial Leprosy Centre,
WARDHA

15. Shri Sanjeet B. Roy,
Social Work Research Centre,
Village : Tilonia 305812
AJMER (RAJASTHAN).

16. Shri Rameshwar Thakur,
Senior Partner,
Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.,
Chartered Accountants,
212, Deen Dayal Marg (Urdu Ghar),
New Delhi-110002.

Principal Executive Officer of the Society

17. General Secretary (PADI)—Member Secretary.

STATEMENT

Statewise Projects sanctioned by PADI during 1981-82 to 1982-83 to voluntary organisation. (As on 24.11.1983y)

Sl. No.	Title of the project	Location	Date of sanction	Amount sanctioned (In Rs.)	Donor Agency
1.	.	3.	4.	5.	6.
	MAHARASHTRA				
1.	Foot & Mouth Disease Vaccine II Phase.	Urlikanchan Poona Distt.	16.6.81	1,42,49,000	DANIDA Denmark
2.	Lift Irrigation Scheme at Bhogawati Implemented by Shri Shivaji Shikshan Prasarak Mandan, Gaudgaon Distt. Solapur	Gaudgaon Distt., Solapur	15/20 Oct. 22	5,42,00	DANIDA Umbrella
3.	Establishment of a Dairy for Community of Minche	Kolhapur Distt.	3.4.82	3,26,300	F. A. O.
	BIHAR				
4.	Gram Seva Yojana, Earn & Learn Centre Monghyr Implemented by Shram Bharati, P·O. Khadigram, Distt. Monghyr.	Manghyr Distt.	19.3.82	2,30,000	S. D. C.
	UTTAR PRADESH				
5.	Scientific Pest Management to increase the Productivity of Mango.	Allahabad Distt.	11.2.82	8,46,000	DANIDA Denmark
	KERALA				
6.	Backyard Poultry Project implemented by Thainad Cooperative Society Ltd. Puthenchanthai, Trivandrum.	Punthen-chanthai	9.2.83	1,77,000	DANIDA Umbrella

1	2	3	4	5	5
	WEST BENGAL				
7.	Integrated Rural Development for Small and Marginal farmers at Kapgari implemented by Seva Bharati at Kapgari Distt. Midnapore.	Kapgari, Midnapore Distt.	17.3.83	7,14,456	DANIDA Umbrella
8.	Integrated Development of Mandra Village Distt. Hoogly, West Bengal implemented by Samsad, Village & P. O. Pandra, Distt. Hoogly.	Mandra, Hoogly Distt.	18.1.83	1,07,600	DANIDA Umbrella
9.	Extension of Artificial insemination facility to Sundarban farmers. 24, Parganas	Sunderban 24 Paragans Distt.	11.10.82	5,39,000	S. D. C.
	Survey work (Preinvestment)				
1.	Survey work at Mahendragarh Distt., Haryana			9,400	
2.	Gurgaon District, Haryana			5,800	
3.	Samastipur, Bihar and Malda, West Bengal			10,000	
			Total :—	1,77,56,556	

Note :— During the current financial year, sanction of new projects is being processed.

Test Reports of soft Drinks

1999. SHRI SATISH AGARWAL : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1180 on 3 August, 1983 regarding sweetening agents used in alreted water ; Unstarred Question No. 4587 on 22 August, 1983 regarding quality of juice of various soft drinks, fruits products licensed under F. P. O. ; Unstarred Question No. 4588 on 22 August, 1983 regarding composition of fruit juice in aerated water and state :

(a) the specific and exact contents/copies of test reports of Rasika (Mango, Guava, Pineapple and Apple) ; Appella ; Funday and Cola lite on the basis of which information has been supplied in abovementioned questions along with the place, date of analysis and particulars of inspecting officers/analysers certifying test report ; and

(b) the reason that Rasika appears by taste and density to have more than 15 per cent Print juice content as compared to taste and density of Appella ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) Samples are drawn and inspections carried out under the Fruit Products Order, 1955 to ensure that the minimum specifications laid down in the Order are observed. It is not considered desirable to place the specific and exact contents/copies of the test reports on the Table of the House as this would mean divulging the formulations of the products in question.

Other information asked for has already been furnished in replies to the Question referred to.

(b) The reason is that Rasika apple drink contains about 85% apple juice as compared to Appella which contains about 50% fruit juice.

Apprisal of Schemes

2000. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether mid-term apprisal of various schemes under his Ministry has been completed ;

(b) if so, what is the outcome of review ;

(c) whether Government also worked out some special action plan for fast implementation of NREP, IRDP and Job Guarantee Scheme under his Ministry during 1983-84 and 1984-85 ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) Yes, Sir.

(b) Relevant extracts from the chapter on Rural Development from the mid-term appraisal report of the Planning Commission are laid on the Table of the House (Placed in library *See* No. LT—7162/83)

(c) and (d) Government has taken a number of steps to speed up the implementation of the programmes as well as their qualitative improvement. Modifications have also been made in the guidelines taking into account the shortcomings that were noticed in the implementation. In order to ensure durability of assets the non-wage component under National Rural Employment Programme (NREP)/Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) has been enhanced to 50 per cent. The new guidelines lay emphasis on proper preparation of shelf of projects under National Rural Employment Programme (NREP)/Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP). The State Governments have been assisted in strengthening the block administration which is responsible for the implementation of Integrated Rural Development Programme. The performance of the State Governments is assessed periodically in review meetings and by team visits.

Allocation of Funds to Orissa under I. R. D. P.

2001. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the funds allocated to Orissa for I.R.D. P. during the current year ; and

(b) whether in view of the poverty and the backwardness of this State, Government will considerability of granting adequate funds to that State for providing gainful empolyment opportunities to weaker section of the community i. e., small farmers, marginal farmers, agricultural labourers, non-agricultural labourers and artisans in rural areas ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) and (b) Funds are allotted to the State Governments on the basis of the number of blocks. In Orissa for 314 blocks, Rs. 1256/- lakhs will be the Central Share of allocation for 1983-84. An equal amount is also to be provided by State Government.

Assistance for Preventing Shifting Cultivation in Orissa

2002. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Orissa Government have approached the Centre for the grant of additional special central assistance for implementing comprehensive programme for prevention of shifting cultivation which has affected about 15.00 lakh hectares of land along the hill slopes in tribal areas in that State ; and

(b) it so, the Centre's reaction thereto and the funds released for taking up this programme during the current year and onwards ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) and (b) It is a fact that the Government of Orissa requested to provide Central financial assistance for revival and implementation of the

Pilot Project on Shifting Cultivation. Since a Task Force was constituted by Government on Shifting Cultivation, its report was awaited for taking a decision. The report of the Task Force, was submitted in the last week of October, 1983 and is presently under examination.

Rules Pertaining to Visit of Ministers/ Secretaries Abroad

2003. SHRI P. K. KODIYAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government allow Cabinet Minister of Economic Ministries and Secretary of the same Ministry to be on tour abread and absent themselves from the country simultaneously ;

(b) If not, the rules followed and how the position is monitored ;

(c) whether despite programme of Cabinet Minister of Agriculture to be abroad in mid-October, 1983 same Secretaries of Ministry went abroad for a visit paid by external agency in contravention of the established practice ; if so, particulars and date of each Secretary, who was abroad during the second and third week of October, 1983 with dates of departure and return and purpose of visit with agency financing it, Secretary-wise ;

(d) reasons for exceptions from the established practice and date on which approval of the Competent Authority was taken for each ; and

(e) the action Government propose to take where procedurc was violated ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) No, Sir. Normally the Minister and the Secretaries of the concerned Ministry do not proceed on deputation simultaneously and such deputations of too functionaries are duly coordinated as per guidelines of the Cabinet Secretariat. Where some overlap is unavoidable, the fact is specifically brought to the notice of Prime Minister while submitting the case for her approval.

(c) The Union Minister of Agriculture paid an official visit to the Federal Republic of Germany from 14 to 18 October, 1983 (including travel time). The Secretary, Department of Agricultural Research & Education under the Ministry of Agriculture was also deputed by the Government to Bangkok to participate in the World Food Day celebrations held by the Regional Office of the FAO on 17th October, 1983. He left Delhi on 16.10.1983 (Sunday) and returned on the night of October 18-19, 1983. The FAO met all expenses on travel and per-diem of Secretary (DARE).

(d) The established practice in such cases is to obtain the approval of the Competent Authority after bringing out all details of the case. This procedure was followed in this case and so there was no departure from the established practice. The approval of the Competent Authority was obtained on 14.10.1983.

(e) The question of taking any action does not arise since there has been no violation of the prescribed procedure.

Review Committee of ICAR Cattle Project

2004. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1266 no 1 August, 1983 regarding Review Committee of ICAR Cattle Project and state :

(a) the reasons why in November 1981 ICAR Headquarters representative, a member of Committee, did not visit Haringhata Centre along with other two members and the reasons for drawing up review report by a single common member visiting it ;

(b) the details of role and function of Chairman and each Member of Review Committee specified on appointment with reasons for specifying it, if for only some member ; and

(c) the details of ICAR views centre-wise, wherever these differ from those given in notes submitted to Review Committee by ICAR Headquarters representative and Government views also, centre-wise, if also different ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) There appears to be no particular reasons for the Indian Council of Agricultural Research Headquarters representative not visiting the Haringhata Centre in November, 1981.

The review committee report drawn up was unanimously accepted by all its members who were present in the final meeting of the Committee held from 7th to 9th January, 1983 at the Central Institute for Research on Goats, Makhdoom. The I. C. A. R. representative did not attend this meeting.

(b) The Council had constituted a Review Committee consiting of subject matter specialists, for midterm review of the working of the All India Coordinated Research Project on Cattle and for making suitable recommendation (i) for continuation of the centre (ii) to improve the working or (iii) closing the centre. No specific role or function as such was given to the Chairman or Members.

(c) The views expressed by the I.C.A.R. representative through his written notes submitted to the Review Committee were taken into consideration by the Committee while finalizing the report. It has been clarified by the ICAR representative to the Review Committee that all the notes while he had submitted to the Committee contained his personal views and not the views of the ICAR. The report has already been examined by the Council & put up for information of the Governing Body of the I. C. A. R. in its last meeting. The recommendations made by the Committee were also discussed at the last workshop of the project and the units have been instructed to implement those expeditiously.

Allocation of Funds to States During 1983-84 for Supply of Drinking Water to the Problem Villages

2005. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 91 on 21 February, 1982 regarding participation of India in the International Drinking Water supply and sanitation Decade and State :

(a) the progress made so far in the supply of safe drinking water to the problem villages in the country and the number of problem villages covered by the supply, State-wise as on 31-3-1983 and the percentage of such villages to the total problem villages in each State ;

(b) the allocations for the financial year 1983-84 for each one of the States and Union Territores in this regard ; and

(c) the likely date by which 100 percentage coverage of the problem villages would be ensured under this programme in each State/Union Territory ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MUHAMMED USMAN ARIF) : (a) as in enclosed Statement (I).

(b) as in enclosed Statement (II).

(c) All efforts are being made to achieve the target by March, 1985.

STATEMENT I

S. No.	State/U. T.	No. of problem villages as on 1.4.1980.	No. of problem villages provided with water supply during 1980-83 (3 Years)	Percentage of problem villages covered.
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	8206	5160@	62.88
2.	Assam	15743	3839	24.39
3.	Bihar	15794	8375@	55.12
4.	Gujarat	5318	1818@	34.19
5.	Harayana	3440	885	25.73
6.	Himachal Pradesh	7815	3366	43.07
7.	Jammu & Kashmir	4698	1027	21.86

1	2	3	4	5
8.	Karnataka	15456	10469@	67.73
9.	Kerala	1152	274@	23.66
10.	Madhha Pradesh	24944	17963@	72.01
11.	Maharashtra	12935	7919@	61.22
12.	Manipur	1212	447@	36.88
13.	Meghalaya	2927	315	10.76
14.	Nagaland	649	229	35.29
15.	Orissa	23616	8793@	37.24
16.	Punjab	1767	207	11.71
17.	Rajashan	19803	10056@	50.78
18.	Sikkim	296	102@	34.46
19.	Tamil Nadu	6649	4410@	66.33
20.	Tripura	2800	1349	48.18
21.	Uttar Pradesh	28505	7401@	25.96
22.	West Bengal	25243	6166£	24.43
23.	A & N Islands	173	61@	35.26
24.	Arunachal Pradesh	1740	790	45.40
25.	Chandigarh	—	—	—
26.	Delhi	99££	77	86.52
27.	Dadra & Nagar Haveli	—	—	—
28.	Goa, Daman & Dui	66	38	57.58
29.	Lakshadweep	3/4	—	—
30.	Mizoram	214	43	20.09
31.	Pandicherry	118	78	66.10
	TOTAL :	230784	101659	44.05

@ Includes partially covered problem villages.

£ Does not include coverage during 1980-81 & 1981-82 under Zila Prishads programme of spot sources under the minimum Needs prog.

££ 3 problem villages transferred to the Delhi Development Authority and 7 problem villages deserted.

STATEMENT II

Funds for 1983-84

S. No.	State/U. T.	ARP	MNP
1.	Andhra Pradesh	561.88	3000.00
2.	Assam	768.63	1060.00
3.	Bihar	761.55	7375.00
4.	Gujarat	113.61	1600.00
5.	Haryana	Nil	1800.00
6.	Himanchal Pradesh	Nil	1000.00
7.	Jammu & Kashmir	1446.26	1125.00
8.	Karnataka	714.73	1377.00
9.	Kerala	1121.30	711.00
10.	Madhya Pradesh	1244.20	1920.00
11.	Maharashtra	720.05	6000.00
12.	Manipur	107.89	430.00
13.	Meghalaya	692.11	400.00
14.	Nagaland	235.26	260.00
15.	Orissa	307.82	725.00
16.	Punjab	53.38	800.00
17.	Rajasthan	3363.85	1300.00
18.	Sikkim	227.06	145.00
19.	Tamil Nadu	688.31	1300.00
20.	Tripura	36.63	250.00
21.	Uttar Pradesh	4091.16	3500.00
22.	West Bengal	1552.28	790.00
23.	A & N Islands	56.56	100.10
24.	Arunachal Pradesh	134.87	450.00
25.	Chandigarh	—	—
26.	Delhi	Nil	6.20
27.	Dadra & Nagar Heveli	—	100.00
28.	Goa, Daman & Diu	51.87	122.00
29.	Lakshadweep	—	10.27
30.	Mizoram	13.94	175.00
31.	Pondicherry	25.00	20.10
	TOTAL :	19500.00	31841.40

N. B. An additional amount of Rs. 250 lakhs has been released each to Gujarat, M. P., Haryana, Punjab, & Rs. 74 lakhs to Tripura.

Report on Agriculture Secretary's Visit Abroad

2006. SHRI KAMALA MISHRA MADUKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government require a report from every Secretary visiting another country on return ; if so, how much maximum time is allowed after return ;

(b) the date in 1982 when a Secretary from Agriculture Ministry visited China, his particulars places visited datewise and date of return along with date when his report was submitted and its majors findings ;

(c) whether Government have taken any action for delay in submission of report by him ; if not, the reasons therefor and corrective measures proposed to aviod such delay ; and

(d) whether his report has been examined and timely action taken and if not, when and what action is proposed to be taken ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir. According to the existing procedure every officer deputed abroad on official visited is required to submit a report within one month on return from deputation.

(b) and (c) A 6- member multi-disciplinary delegation on agriculture comprising officers from three different Government Departments and the ICAR system was deputed to China for a period of 10 days exclusive of to and fro journey period, from 14th August, 1982. The delegation was led by the Director General, ICAR & Secrectary, Department of agricultural Research & Education. The delegation visited Beijing, Zenngshon (Henam Province), Changsha (Hunan Province) and Gangshon (Gwendun Province). The delegation came back to India on August 27, 1982. Immediately after coming back to India, the Secretary (DARE) as the leader of the delegation, verbally reported the salient features of the visit to the Minister of Agriculture. This was followed up by collection of draft reports from each participating member in respect of his specialised area by the Coordinator designated by the leader for compli lation of meterial and report writing It took some time to collect and collate all thh reports and contributions made by thl individual members of the delegation. Teeg report has since been submitted to t ye Government already. The major findin reported by the delegatidn relate to :

(i) Breeding and production technologies relating to Hybrid-rice;

(ii) Recycling of farm and animal was s and Biogas technology

(iii) Azolla culture and biological nitrogen fixation,

(iv) Insentive crop production technologies and integrated crops-livestock-fish farming systems,

(v) Inland aquaculture,

(vi) Agro-forestry,

(vii) Soil & Water management for irrigated agriculture, &

(viii) Rice transplanter.

(d) Action on some to the items in the report has already been taken. Others are under examination and action would be taken as required.

Disturabances During One-day Crickets Test Match Between India and West Indies in Shrinagar

2007. (SHRI R.N. RAKESH) : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the exhibition of some unpleasant incidents during the recent one-day Circket Match between India and West Indies at Shrinagar Government have decided not to hold another international match in the State ; and

(b) if so, the reasons that have compleled the Government to take such a view ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Defective Construction of DDA Houses

2008. SHRI ARUN KUMAR NEHRU : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of D.D.A. built houses whose construction has been found defective since January 1983 ;

(b) the number of cases where such defects have been rectified to make them structurally safe and sound ; and

(c) action taken against those responsible for defective construction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Re-Introduction of Price Tags System

2009. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether in view of the unabated trend of rise in prices, Government propose to reintroduce the price tags system and other such regulations to curb price rise enforced during 1975-76 ; and

(b) if so, the steps taken by the Government in that direction so far ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) The question of re-introduction of the scheme for displaying prices of essential commoidities does not arise as all the State Governments/U.Ts. have already issued price/stock display orders under the Essential Commodities Act, 1955 and are duly enforcing them. Price display is also mandatory on packaged commodities under the Standards of Weights & Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

Production And Demand of Coconut oil

1010. SHRI SKARIAH THOMAS : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state the total demand for coconut oil is edible oil and its production in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : The specific demand for coconut oil is not readily available. However, the total demand for all edible oils in the country is estimated to be around 42 to 42 lakh tonnes. The Prodution of coconut oil during the seed year 1981-82 was 1.70 lakh tonnes approximately.

Import of Fertilizers

2011. SHRI HARISH KUMAR GANGAWAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is the quantum of the import of fertilizers and the foreign exchange India had to spent on this item during the last three years, year-wise ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) ; The total quantity of fertilizers imported and the C & F value thereof in terms of ruppees (in crores) is given below :

Year	Quantity (in lakh tonnes of nutrients— 'N' + 'P' + 'K')	C & F Value (in crores of rupees)
1980-81	27.59	925.22
1981-82	20.41	716.62
1982-83	11.32	273.53
Total :	59.32	1915.37

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

2012. श्री छोटू भाई गामित :
श्री त्रिलोक चन्द :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल चीनी, खाद्य तेलों, अनाजों, दालों, कपड़े आदि के मूल्यों में, जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1983 तक, महीने-वार कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ; और

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा०

एम० एस० संजीवी राव) : (क) चुनी वस्तुओं, जिनमें अनाज, दालें, खाद्य तेल तथा कपड़ा शामिल है, के जनवरी, 1983 से सितम्बर, 1983 तक के महीनों के थोक मूल्य सूचकांक सभापटल पर रखे दिए गए विवरण में दर्शाए गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-7163/83]

(ख) सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन गढ़ाने पर दिया जा रहा है, सार्वजनिक विवरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। कुछ वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं का निर्यात विनियमित किया जाता है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को लागू कर रहे हैं।

Import of Fertilizers

2013. SHRI CHINTAMANI JENA : will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state ;

(a) the amount invested in the import of fertilisers during the year 1982-83 ;

(b) through which agency the import of fertilisers was made and how it was distributed to the states :

(c) whether any planning has been made in regard to the import of fertilisers to be imported during the year 1984-85 ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) The C & F value of fertilisers imported during 1882-83 is Rs. 273.53 crores.

(b) Fertilisers are imported through the Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd. Imported fertilisers are distributed among the states to meet the gap between requirements and allocation of the indigenous fertilisers and to ensure adequate availability of this vital agricultural input.

(c) and (d) Yes, Sir. But it is not in the public interest to disclose details of imports planned for 1984-85.

Augmentation and Streamlining the distribution System of Fertilizers at Ports

2014. Dr. A. U. AZMI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it was envisaged in the Sixth Plan to augment and streamline the distribution system of fertilisers by increasing port handling capacities, etc. ;

(b) whether suitable infrastructural arrangements were created to bring about improvement in the distribution system ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Additional facilities as follows have been created during the Sixth Five Year Plan by the Ministry of Agriculture to augment fertiliser handling facilities at various ports :

(i) Provision of two fertiliser storage godowns at Madras port.

(ii) Provision of high speed unloading and storage facilities at Haldia port under a joint project with Ministry of Shipping and Transport.

(iii) Provisional of medium speed fertiliser unloading storage and handling facility at Bombay port.

(iv) Provision of Dock-side bagging, stitching and standardisation facilities at Tuticorin, New Mangalore, Navalkhi and Bhavnagar ports.

पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं की बोरियों की चोरी

2015. श्री निहाल सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में चराह और आन्दल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं की दो लाख से अधिक बोरियों की चोरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितने लोग दोषी पाये गए तथा अब तक इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) निगम को चराह और अंडाल के अस्थायी भण्डारण काम्पलेक्सों में क्रमश: 14,344.3 मीटरी टन और 10,736.3 मीटरी टन और 10,736.3 मीटरी टन खाद्यान्नों की हानि उठानी पड़ी थी।

(ख) इस संबंध में प्रत्यक्षत: चार अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया है। ये सभी अधिकारी पश्चिमी बंगाल सरकार से प्रतिनियुक्ति पर थे। इनमें से एक अधिकारी पहले ही सेवा-निवृत्त हो चुका है। तीन अन्य अधिकारियों से मुख्य सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। निगम के जोनल प्रबन्धक (पूर्वी) से भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कनिष्ठ स्टाफ के विरुद्ध अनुशासकीय कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली के किसानों को वर्षा के कारण हुआ नुकसान

2016. **श्री सज्जन कुमार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983-84 के दौरान दिल्ली के किसानों को वर्षा के कारण हुए नुकसान के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए किसानों को कोई मुआवजा दिया है और यदि हां, तो किस हिसाब से मुआवजा दिया है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली प्रशासन ने सर्वेक्षण किया है, जिससे खड़ी फसल को 38 से 100 प्रतिशत तक के बीच नुकसान होने का पता चला है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार 1983-84 के दौरान 47 ग्रामों में लगभग 45,000 बीघा कृषि भूमि की क्षति हुई थी।

(ग) भारत सरकार की नीति फसल की हानि का मुआवजा देने की बजाय पुन: स्थापित करना है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने धनराशि की उपलब्धता के अनुसार उन किसानों को मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है, जिनकी फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1983-84 के दौरान मकानों का आबंटन

2017. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1983-84 के चालू वर्ष के दौरान अब तक श्रेणी-वार कुल कितने मकानों का निर्माण कार्य किया है तथा इनमें से कितने मकानों का आबंटन कर दिया है ; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष (1983-84) की शेष अवधि में जिन मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणियों के लगभग 52,000 मकानों में से, लगभग 20,000 मकान 1983-84 के दौरान पूर्ण हो जाने की आशा है। श्रेणीवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

स्ववित्त घोषित योजना	3,700
मध्यम आय वर्ग	7,200
निम्न आय वर्ग	4,800
जनता	3,700
सी० एस० पी० आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	600
योग	20,000

ये मकान निर्माण का 50 प्र० श० से पूर्ण होने तक की सीमा में प्रगति के विभिन्न सोपानों में हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान आबंटित फ्लैटों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

मध्यम आय वर्ग	54	सामान्य योजना के तहत रह आबंटन में से इन फ्लैटों का आबंटन किया गया है
निम्न आय वर्ग	23	
जनता	45	

स्व-वित्त घोषित योजना

श्रेणी-I	160
श्रेणी-II	2053
श्रेणी-III	1601
योग	3814

Procurement of Foodgrains

2018. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government procure only about 12.5 per cent of the total Food grain that come into the market and this is used for distribution to States ;

(b) whether it is also a fact that in the years when there is drought or floods, this procurement goes down ;

(c) whether some of the State Governments have been found to inflate their demands for foodgrains for Central allocation at a time when they are themselves responsible for carry over the stocks because of their inability to distribute the foodgrains and thereby holding the Centre responsible for non-supply of foodgrains ; and

(d) if so, the names of the States where such incidents are taking place and whether Centre would advise them to streamline the distribution machinery and make realistic demand of foodgrains from the Centre ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) The procurement of cereals for public stocks was about 12.5% of their production during 1981-82 and 13.2% during 1982-83. These grains are used for meeting the requirements of public distribution and also for maintaining the buffer stock.

(b) Generally, procurement goes down with the shortfall in production caused by drought or floods.

(c) and (d) The State Governments are requested to intimate every month their realistic requirements of foodgrains from the Central Pool for issue through public distribution system, after taking into account the stocks available with them and procured by them locally. Although various State Governments tend to over-pitch their demands, the Government do not attribute it to the failure of the State Governments to distribute the foodgrains allocated to them from the Central Pool.

The State Governments have been requested to undertake periodic review of the public distribution system and also for strengthening and streamlining the system. Their attention has also been drawn to the need to ensure greater degree of coordination between procurement, transportation, storage and distribution.

वनस्पति घी में चर्बी की मिलावट :

2019. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**
श्री दया राम शाक्य :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बाबूराव परांजपे :
श्री राम प्रसाद अहिरवार :
श्री राम जेठमलानी :
श्री सत्यनारायण जटिया :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित विवरण दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वनस्पति घी निर्माताओं के अपने नाम पर अथवा निकट संबंधियों के नाम पर साबुन बनाने के कारखाने हैं और यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ;

(ख) क्या इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि उनके द्वारा आयात की गई पशु चर्बी की वनस्पति घी में मिलावट की जा सकती है, इन कारखानों में निर्मित वनस्पति घी के भंडार की उनके मंत्रालय द्वारा नियमित जांच की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वनस्पति घी में चर्बी की मिलावट के

पता लगे मामलों का निर्माताओं के नामों सहित वर्षवार ब्यौरा क्या है और वर्ष 1977 1980 वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में कितने मामले लाए गए ; और

(घ) वनस्पति घी में चर्बी की मिलावट के बारे में उपभोक्ताओं के मन से सन्देह को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर क्या प्रबन्ध किए हैं और उन प्रबन्धों का किस प्रकार उपयोग किया जाना है ?

इलेक्ट्रानिकी तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) : से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वनस्पति घी में चर्बी की मिलावट के बारे में श्री रतीलाल प्रसाद वर्मा श्री दया राम शाक्य श्री फूल चन्द वर्मा, श्री बाबूराम परांजपे, श्री राम प्रसाद अहिरवर, श्री राम जेठमलानी श्री सत्यनारायण जटिया श्री कृष्ण कुमार गोयल द्वारा पूछा गया लोकसभा अताराकित प्रश्न संख्या 2019 के सम्बन्ध में विवरण ।

(क) साबुन बनाने की यूनिटों के मालिक या उनसे निकट सम्बन्ध रखने वाले वनस्पति विनिर्माताओ की एक सूची अनुबंध-1 में दी गई है । बनस्पति विनिर्माताओं के निकट सम्बन्धियों के स्वामित्वाधीन साबुन यूनिटों के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) व (ग) वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के फील्ड कर्मचारी वनस्पति कारखानों का दौरा नियमित रूप से करते हैं और वनस्पति के स्टाक तथा कारखाना परिसर से कच्चे तेलों के स्टाक में से नमूने लिए जाते हैं। इनका विश्लेषण वनस्पति निदेशालय की सुसज्जित प्रयोगशाला में किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद निर्धारित विशिष्टियों को पूरा करता है और इसमें केवल अनुमत तेलों का प्रयोग किया गया है। इसलिए, वनस्पति एककों द्वारा साबुन बनाने के प्रयोजन से प्राप्त की गई चर्बी का वनस्पति तैयार करने में प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता । अभी तक विभिन्न विनिर्माण करने वाले एककों से लिए गए वनस्पति के नमूनों के विश्लेषण से किसी भी नमूने में किसी भी प्रकार की पशु चर्बी नहीं पायी गई है।

(घ) निदेशालय के फील्ड कर्मचारियों के अलावा, जो देश में तैयार होने वाले वनस्पति की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखते हैं, राज्य सरकारों को भी सतर्क किया गया है कि वे व्यापारियों के स्तर पर निरन्तर जांच-पड़ताल करें और इसके लिए वे चर्बी का पता लगाने के प्रयोजन से नमूने लेकर उनका विश्लेषण करें तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करें ।

अनुबन्ध-I

वनस्पति में चर्बी के अपमिश्रण के बारे में श्री आर० एल० पी० वर्मा तथा दूसरों द्वारा पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पश्चिम बंगाल :

1. मैसर्स रसोई लि०, रीजेन्ट हाउस, 12, गवर्नमेंट प्लेस, पूर्वी कलकत्ता-700069.
2. मैसर्स कुसुम प्रोडेक्टस लि०, गुरु गार्डन रीच, कलकत्ता ।
3. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०, 63, गार्डन रीच, कलकत्ता ।
4. मैसर्स टाटा ऑयल मिल्स क० लि०, कलकत्ता ।
5. मैसर्स स्वायका ऑयल मिल्स, पो० बा०न० 18-बी, ब्राबोर्न रोड़, कलकत्ता ।
6. मैसर्स वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, नौर्टन बिल्डिंग, कलकत्ता ।

महाराष्ट्र क्षेत्र :

7. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० हिन्दुस्तान लीवर हाउस, बैकवे रेकलेमेशन, बम्बई ।

8. मैसर्स गोदरेज सोप्स (पी) लि० ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विखरौली, बम्बई- 400079.
9. मैसर्स स्वास्तिक हाउसहोल्ड एण्ड, इण्ड. प्रोडक्टस लि०, पो०औ०न० 362, अहमदाबाद हाउस, 13/15, वालचन्द हीराचन्द मार्ग. बालार्ड इस्टेट, बम्बई।
10. मैसर्स बम्बई सोप फैक्टरी, अहमद ओमर स्ट्रीट, 2-टैन्कस, बम्बई।
11. मैसर्स टाटा आयल मिल्स क० लि० बम्बई हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-11
12. मैसर्स बरार ऑयल इन्डस्ट्रीज, बनासडापेट, अकोला।
13. मैसर्स बीप्रो प्रोडक्टस लि०, 5, चोगा स्ट्रीट, बम्बई।
14. मैसर्स मानसिंघा इन्डस्ट्रीज (प्रा) लि०, पचौड़ा, महाराष्ट्र।

तमिलनाडू क्षेत्र :

15. मैसर्स टाटा ऑयल मिल्स क० लि, मद्रास।
16. मैसर्स श्रीकृष्ण वनस्पति लि०, ईरोड (मैसर्स मेटूर कैमिकल एण्ड इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० मेटूरडम)
17. मैसर्स मद्रास वनस्पति लि०, 331-338, थाम्बा चेटी स्ट्रीट, मद्रास।

उत्तर प्रदेश :

18. मैसर्स अमृत वनस्पति क० लि०, जी० टी० रोड़, गाजियाबाद।
19. मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स लि०, पो० बा० न० 32, कानपुर।
20. मैसर्स टाटा आयल मिल्स क० लि०, गाजियाबाद।
21. मैसर्स मोदी सोप वर्क्स, मोदी नगर, जिला मेरठ।

मध्य प्रदेश :

22. मैसर्स मालवा वनस्पति एण्ड कैमिकल क० लि०, इन्दौर।

आन्ध्र प्रदेश :

23. मैसर्स तुंगभद्रा इन्डस्ट्रीज लि०, करनूल।
24. मैसर्स कोआपरेटिव ऑयल इन्डस्ट्रीज़ लि० लातूर (जिला उस्मानाबाद)।

बिहार राज्य :

25. मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर, बिहार।

केरल राज्य :

26. मैसर्स टाटा आयल मिल्स क० लि०, टाटापुरम, एर्नाकुलम, केरल।
27. मैसर्स केरल ऑयल एण्ड सोप लि०, पी०बी० न० 44, कोजिकोड।

कर्नाटक राज्य :

28. मैसर्स ब्रह्मप्पा ट्रावानापानवार लि०, पी०बी०न० 7, दावणगीर।
29. मैसर्स मार्गरीन एण्ड रिफाइन ऑयल क० लि० पी०बी० न० 546, बंगलौर।
30. मैसर्स रावी वैजीटेबल ऑयल इन्डस्ट्रीज, दावणगीर।

दिल्ली क्षेत्र :

32. मैसर्स डी०सी०एम० कैमीकल वर्क्स, पी०बी० न० 1211, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली।
32. मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स क० लि०, पी०बी० न० 1025, दिल्ली।

गुजरात क्षेत्र :

33. मैसर्स मोरवी वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, मोरवी।
34. मैसर्स अश्विन वनस्पति इन्डस्ट्रीज (पी) लि०, प्रीमियर चेम्बर्स, थर्ड फ्लोर, आर०सी० दत्ता रोड़, बड़ोदा।
35. मैसर्स मधुसूदन वैजीटेबल प्रोडक्टस क० लि०, रखियाल स्टेशन, तालुका, देहगाम डिस्ट्रिक, अहमदाबाद।
36. मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लि०, जी०टी० रोड़, शेरपुर, लुधियाना-141003.

भारत सरकार मुद्रणालयों में प्रशिक्षित प्रशिक्षणुओं को रोजगार

2020. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालयों में अब तक व्यवसाय-वार जितने लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ख) इस प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को भारत सरकार मुद्रणालयों में रोजगार दिया गया ;

(ग) जिन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है, उन्हें सम्भवतः कितने समय में रोजगार दे दिया जायेगा ;

(घ) यदि सरकार इन लोगों को रोजगार देने की स्थिति से नहीं है तो उनकी योग्यता का लाभकारी उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) व्यवसायिक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावकारी और उपयोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि सरकार, भारत सरकार मुद्रणालयों में सभी प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के किए बाध्य हो और क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षु ओं के साथ कोई अनुबन्धात्मक करार नहीं है इसलिए सभी प्रशिक्षुओं को रोजगार देने की समय सीमा बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) प्रशिक्षित प्रशिक्षु रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अन्य सरकारी और या प्राइवेट संगठनों में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत श्रय मन्त्रालय द्वारा बताई गई योजना के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालयों में, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	व्यवसाय	प्रशिक्षित	रोजगार दिया गया।
	कम्पोजीटर (हस्त)	1,225	463
1.	जिल्दसाज़	1,843	301
2.	लाइनो आपरेटर	93	48
3.	मोनो आपरेटर	83	43
4.	मोनो कास्टर	125	45
5.	मशीन माइंडर (लेटर प्रेस और आफ		
6.	सेट प्रेस)	458	55
7.	रिटचिंग लिथोग्राफी	9	–
8.	प्रोसेज़ कैमरामेन	8	1
9.	लिपिक (सामान्य)	80	4
10.	इंगरेवर (इचर)	3	1
	योग	3,927	961

दिल्ली में आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई

2021. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी आटा मिलें हैं, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं सप्लाई किया जाता है, इनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मिल वर्ष 1983 में अक्टूबर माह तक की अवधि के दौरान कितना और किस दर पर गेहूं सप्लाई किया गया ;

(ख) प्रत्येक मिलों द्वारा उक्त अवधि के दौरान आटा, मैदा, सूजी चोकर का प्रति मास कितना कितना उत्पादन किया गया और प्रत्येक मिल द्वारा जिन व्यक्तियों को इन उत्पादों की मासिक अथवा साप्ताहिक सप्लाई की गई, उनका ब्यौरा क्या है और यह उत्पाद किस दर पर सप्लाई किए गए ; और

(ग) इन मिलों को सप्लाई किए गए गेहूं की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित माल की मात्रा में कितना अन्तर था तथा इस अन्तर के सविस्तार क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इस समय दिल्ली की 12 रोलर फ्लोर मिलों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं दिया जा रहा है। उनके विवरण तथा 1983 के दौरान अक्टूबर तक उन्हें सप्लाई किए गए गेहूं के मासवार कोटे का ब्यौरा सभा पटल पर रखे विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7164/83]

(ख) विवरण-II जिसमें इन मिलों द्वारा जनवरी से अक्तूबर, 1983 के दौरान तैयार की गई मैदा, सूजा, परिणामी आटा और चोकर तथा होल-मील आटे की मात्रा का ब्यौरा दिया गया है सभापटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-7164/83]

मिलों ने ये उत्पाद निम्नलिखित चार श्रेणियों के उपभोक्ताओं/डीलरों आदि को सप्लाई किए थे :—

(1) उचित दर की दुकानों/सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

(2) पंजीकृत बल्क उपभोक्ता।

(3) दिल्ली में मुक्त बिक्री के लिए।

(4) दिल्ली के बाहर भेजे गए।

इन मिलों द्वारा इन उत्पादों के जो अधिकतम निकासी मूल्य लिए जा सकते हैं, वे दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान ये मूल्य इस प्रकार थे :—

गेहूं के उत्पाद	1.1.83 से 14.4.83 तक	15.4.83 के बाद
मैदा	245	276
सूजी	251	283
परिणामी आटा	165	180
चोकर	110	117

दिल्ली की रोलर फ्लोर मिलों ने इन उत्पादों की सप्लाई उन मूल्यों पर की है जोकि ऊपर उल्लिखित मूल्यों से अधिक नहीं थे। होलमील आटा 3.5.83 तक 200/-रुपया और 4.5.83 के बाद 223/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सप्लाई किया गया।

(ग) मिलों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से विदित होता है कि रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई किए गए समस्त गेहूं का रोलर फ्लोर मिलों द्वारा गेहूं के उत्पाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तथापि, किसी मास विशेष में गेहूं की उठायी गई मात्रा का उनके द्वारा उक्त मास में पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया गया हो सकता है क्योंकि शेष मात्रा को पिसायी करने के उद्देश्य से आगामी मास में दिखाया जा सकता है।

दिल्ली में वृक्षारोपण

2022. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने वन महोत्सव के अवसर पर 1983 के दौरान अपने द्वारा चलाए गए वृक्षारोपण अभियान के दौरान दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में कितने कितने पेड़ लगाए ;

(ख) इनमें से प्रत्येक निकाय ने अब तक प्रति माह कितना धन व्यय किया है ; और

(ग) क्या उक्त निकायों के विभागों द्वारा उक्त कार्य के लिए दिहाड़ी पर मजदूर लगाए गए थे, यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपित क्षेत्र तथा वृक्षों से सम्बन्धित ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

संस्था का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या (लाख)	वृक्षारोपित क्षेत्र
1	2	3
दिल्ली प्रशासन	3.48	शाहदरा, अलीपुर, मांगलोई, नजफगढ़, महरौली ।
दिल्ली विकास प्राधिकरण	11.53	सभी अंचलों में
नई दिल्ली नगर पालिका	0.46	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र
दिल्ली कैन्टोमैंट बोर्ड	0.015	दिल्ली कैंट क्षेत्र
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	5.29	सड़कों के किनारे, स्कूलों में, अस्पतालों में, सरकारी कालोनियों, कार्यालय कम्पलेक्स तथा पार्कों में ।
दिल्ली नगर निगम	7.57	नगर निगम के 15 क्षेत्रों में

(ख) विभिन्न संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यों पर माह-वार किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

(खर्च लाख रुपए में)

संस्था का नाम	1983			
	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
दिल्ली प्रशासन	1.18	1.35	1.59	1.54
दिल्ली विकास प्राधिकरण	31.71	24.31	22.56	1.89
नई दिल्ली नगर पालिका	0.09	0.03	0.06	—
दिल्ली कैन्टोमैंट बोर्ड	—	—	—	—
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	12.35	12.74	7.21	4.11
दिल्ली नगर निगम	1.57	3.65	5.29	2.40

(ग) कार्य पर लगाए दैनिक मजदूरों का माह-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

संस्था का नाम (लगाए गए मजदूरों की संख्या)

1983

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
1. दिल्ली प्रशासन	971	506	468
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण	वर्क चार्ज कर्मचारियों के जरिए		
3. नई दिल्ली नगर निगम	30	10	18
4. दिल्ली कैन्टोमैंट बोर्ड	शून्य	शून्य	शून्य
5. केन्द्रीय लोक निर्माण निगम	जानकारी उपलब्ध नहीं है		
6. दिल्ली नगर निगम	2076	2076	2076

Reporting to nearest port by fishing Vessels

2023. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of AGRICULTURE bepleased to state :

(a) whether Government had received the representation that the stipulation that fishing vessels should report to the nearest port by the 45th day of their departure was not conducive to effective fishing operation ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The stipulation on reporting of chartered vessels at an Indian port on or before the 45th day of the commencement of voyage has been made by the Government in order to prevent any unauthorised trips to foreign port by the chartered vessels. This would safeguard the interests of Indian fishing companies. A similar suggestion by chartering companies was received earlier. After examination, change in this stipulation was not considered necessary.

Domesitic market and fishery Development

2024. SHRIMATI SANYOGITA RANE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state : the steps proposed to be taken to improve and organise domestic market and to develop inland fishery ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Some of the important steps taken to develop domestic market of fish are :

(i) setting up fishermen's cooperative societies ;

(ii) provision of loan and share-capital from the National Cooperative Development Corporation for marketing of fish ; and

(iii) setting up of fish stalls by State Governments.

Important steps taken to develop inland fisheries include puovision of infrastructure for production of quality fish seed ; promotion of intensive culture of fish on scientific lines in ponds and tanks ; raising of productivity of reservoirs ; developing coastal lagoons and saline water areas in inland States for brackish water aquaculture ; ensuring timely flow of institutional finance ; and protecting and conserving fishery resources in the country through suitable legislation.

उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को भूखण्डों का आबंटन

2025. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980-81, 1982-83 के दौरान आवासहीनों को आवासीय भूखण्डों के आबंटन का योजनागत

निर्धारित लक्ष्य क्या था और प्रत्येक वर्ष लक्ष्य के विपरीत कितनी उपलब्धि रही है ;

(ख) वर्तमान योजना के अन्त तक कितने व्यक्ति भूमिहीन रह जायेंगे ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इन सब भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डों का आबंटन करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) देश में भूमिहीनों के लिए केवल एक योजना है अर्थात् भूमिहीन कामगारों की ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना। उत्तर प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल प्रदान करके 3.70 लाख परिवारों को लाभान्वित करना है। इस योजना के अन्तर्गत 1982-83 का लक्ष्य 70, 00 परिवारों को लाभान्वित करना था। परन्तु राज्य सरकार ने 1,51,137 परिवारों का आवास-स्थल प्रदान करके अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है जो लक्ष्य का 215.91 प्र० श० है। इस राज्य का 1980-81 का लक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में सभी भूमिहीन कामगारों को रिहायशी भूखण्ड प्रदान करने पर विचार किया गया है।

लखवाड़ के पास यमुना नदी पर बहु-उद्देशीय बांध का निर्माण

2026. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखवाड़ा के पास यमुना नदी पर बनाया जा रहा बहु-उद्देशीय बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा इस परियोजना पर व्यय करने हेतु कितना धन राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या स्वीकृत समूची धनराशि राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर व्यय की जा चुकी है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस परियोजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कर दिया जाये ; उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लखवार व्यासी बहुप्रयोजनी परियोजना को 1991-92 तक पूरा करना अनुसूचित है।

(ख) से (घ) छठी योजना के दौरान, इस परियोजना के लिए सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत 29 करोड़ रुपए तथा विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत 42 करोड़ रुपए (कुल 71 करोड़ रुपए) के परिव्यय का प्रावधान है। योजना आयोग के कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपए)

वित्तीय वर्ष	सिफारिश किया गया परिव्यय			व्यय		
	सिंचाई	विद्युत	जोड़	सिंचाई	विद्युत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	300	850	1150	301	504	885
1981-82	300	450	750	598	167	765
1982-83	800	200	1000	500	215 (प्रत्याशित)	715
1983-84	700	800	1500	उपलब्ध नहीं		

राज्य सरकारों द्वारा बजट आबंटन, उपलब्ध संसाधनों तथा विभिन्न स्कीमों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए तय किए जाते हैं। भारत सरकार, राज्यों पर चालू परियोजनाओं को अपेक्षित वित्तीय तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर शीघ्र पूरा करने के लिए जोर डाल रही है। 1983-84 के दौरान विद्युत क्षेत्र में परिव्यय को पृथक-रक्षित माना गया है।

टेहरी बांध

2027. **श्री हरीश रावत** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने टेहरी बांध के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और इस पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की आजीविका के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1972 में 197.92 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के टिहरी बहु-प्रयोजनी बांध परियोजना को अनुमादित किया था। राज्य सरकार ने 1979 में 827.30 करोड़ रु० के अनुमानित लागत के साथ इसके आकार में परिवर्तन करके परियोजना को संशोधित किया था। योजना आयोग द्वारा संशोधित स्कीम को अभी अनुमोदित किया किया जाना है। सिंचाई तथा विद्युत सेक्टरों के अन्तर्गत एक साथ छठी योजना में परियोजना के लिए 216 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। मार्च, 1980 तक (छठी योजना के शुरू में) किया गया कुल व्यय 51.27 करोड़ रुपए है। छठी योजना के पहले तीन वर्षों में 66.01 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं तथा राज्य सरकार द्वारा 1983-84 के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पुनर्वास योजना तैयार की है जिसमें टिहरी बांध के निर्माण से स्थापित व्यक्तियों को सड़क, जल-सप्लाई, स्वच्छता, स्कूल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए नए विस्थापित क्षेत्रों में बसाया जाएगा। परियोजना रिपोर्ट में भूमि के लिए मुआवजा दिए जाने के साथ-साथ आवास निर्माण के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी करना, परियोजना को दी गई दरों पर आवास निर्माण सामग्री सप्लाई करने के साथ-साथ घरेलू सामान को शिफ्ट करने के लिए उदारता के आधार पर अन्य अनुदान देने की व्यवस्था है। ग्रामीण परिवारों को भूमि के बदले भूमि दिए जाने के आधार पर 2 एकड़ से कम नहीं और 12½ एकड़ तक प्रति परिवार को कृषि के लिए विकसित भूमि देकर पुनर्वास करने का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि भूमिहीन कृषि-मजदूर परिवारों को भी कम से कम 2 एकड़ भूमि दी जाएगी। वर्तमान टिहरी शहर को सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि की सुविधाएं प्रदान करते हुए एक नए टाउनशिप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसके निर्माण-काल के दौरान इस परियोजना से और अधिक रोजगार के अवसर दिए जाने की संभावना है।

Report by study group on shifting Cultivation and Encroachment

2028. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Study Groups on Shifting Cultivation and Enchroachment have submitted their reports to his Ministry ;

(b) if so, the main recommendations of these Groups therefor, Group-wise,

(c) whether the reports and recommendations have been examined by his Ministry ;

(d) if so, the recommendations so far accepted implemented by Government ; and

(c) the reaction and action of the States for the implementation of these recommendations concerning their States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) to (e) 'Of the' two Task Forces constituted separately on Shifting Cultivation and forest Encroachments. only the Task Force on Shifting Cultivation has submitted its report on 28th October, 1983. The report is under consideration.

Badanalla Medium Irrigation Project

2029. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the World Bank had agreed to provide loan assistance for Badanalla Medium Irrigation Project in Orissa ;

(b) if so, the funds so far released by the World Bank ;

(c) whether Government of Orissa have given the administrative approval to this project soon after the clearance from the Planning Commission as Sixth Plan Project ;

(d) if so, when it was cleared and approved by the State Government for execution ;

(e) funds so far provided and progress made in execution ; and

(f) if it was delayed, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) Yes, Sir ; The Badanalla Medium Irrigation Project was taken up for implementation under the IDA ASSISTED Orissa Irrigation Project II (Cr. No. 740-IN). The credit of US $58.0 million stands fully utilised. It has now been included for completion in the Medium line of credit by the World Bank and the Project has been signed for credit of US $ 105 million in September 1983, which is expected to be declared effective shortly by the Bank.

(c) and (d) Project was cleared by Planning Commission on 7.1.1981 and administratively approved by State Government on 23.10.1982.

(e) (a) above indicates the overall utilization of funds for the World Bank Project. The Progress under individual MIP under the project is within the purview of State Government.

(f) Question does not arise.

Inclusion of States Land Reform Acts in Ninth Schedule of the Constitution

2030. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the names of the States whose Land Reform Acts have been considered by his Ministry for inclusion in Ninth Schedule of the Constitution as suggested by the States ;

(b) whether some States have also suggested to include the Acts relating to Alienation of Tribal Lands in Ninth Schedule along with the Land Reform Acts ;

(c) if so, the names of such States ; and

(d) the steps taken by his Ministry to include these Acts under Ninth Schedule, keeping in view the speedy implementation of land reform measures by the States ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) Certain land laws enacted by Assam, Bihar, Haryana, Tamil Nadu, U. P., West Bengal and Goa, Daman & Diu have been considered and included in the Constitution (Forty-Eighth Amendment) Bill, 1983 for being placed in the Ninth Schedule to the Constitution.

(b) to (d) A number of land laws already included in the Ninth Schedule deal with alienation of tribal lands. Suggestions for inclusion of some more laws have been received from a number of States and examined. These States include Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Manipur, Madhya Pradesh, Orissa and West Bengal. Inclusion of laws in the

Ninth Schedule is to be made keeping such factors into consideration as whether the law has stood the test of time, whether there is any reasonable fear of its being struck down by the court and so on. Some of the proposals received from the States have been examined in the light of this and it has been found that it is not necessary to include them in the Ninth Schedule. Certain other proposals are not, in their present form, adequate for including laws in the Ninth Schedule.

Forest Policy

2031. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether his Ministry has prepared a draft forest policy concerning the country and of the tribals to replace the 1952 forest policy with a new one ;

(b) if so, the main aims and objectives of the new forest policy ;

(c) whether his Ministry is going to discuss the proposed policy on forest and Tiibals with concerned State before finalisation of the draft policy ;

(d) if so, when such a meeting is going to be held ; and

(e) whether the State Ministers incharge of Forest and Tribal Development and the Tribal MPs will be invited to express their views on new national forest policy, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Proposals for the revision of the 1952 National Forest Policy is under consideration.

(b) Final decision on the main aims and objectives of the policy are yet to be taken.

(c) to (e) A draft prepared earlier was discussed by the Central Board of Forestry in its meeting in August, 1982 at New Delhi. Forest Ministers and State representatives were present in the meeting. The Consultative Committee attached to Ministry of Agriculture has also considered the draft policy on 30th Sept., 1982 at New Delhi. In view of the above it is not proposed to call any other meeting.

Production of Cotton

2032. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to lay a statement showing :

(a) the actual production of cotton during the last two years i. e., 1981-82 and 1982-83 seasons ;

(b) the estimated carry over stock at the end of 1981-82 and 1982-83 seasons ; and

(c) the estimated quantity (with value) of cotton which is likely to be exported after meeting the domestic demand ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) The production of cotton during 1981-82 and 1982-83 is estimated respectively at 78.84 and 77.17 lakh bales of 170 kg each.

(b) The year end carry over stocks for 1981-82 and 1982-83 season have been estimated by the Cotton Advisory Board at 27.16 and 23.37 lakh bales respectively.

(c) Government have so far released 2 lakh bales of long staple cotton, 50 thousand bales of Bengal Deshi and 15 thousand bales of yellow pickings for exports during the current cotton season 1983-84.

Allocation of Wheat to Roller Flour Mills in Kerala

2033. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the present monthly allocation of wheat to the roller flour mills of Kerala ;

(b) whether Government of Kerala have requested for the enhancement of the allocation ; and

(c) if so, the details of the request and the action taken by Union Government on the request ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) The Government of Kerala is, at present, allotted 4,000 tonnes of wheat per

month from the Central Pool for the roller flour mills in the State.

(b) and (c) As per the latest demand received from the Government of Kerala, they have requested for increase in the allotment of wheat for roller flour mills to the level of 10,000 tonnes per month.

Allocations of foodgrains from the Central Pool to the various States/Union Territories, including Kerala, are madeon a month to month basis, taking into account the overall availability of stocks in the Central Pool, relative needs of the various States and other related factors. It has, therefore, not been possible to accede to the request of the State Government.

Kerala Government's Drinking Water Supply Schemes

2034. SHRI A. NEELALOHITHA-DASAN NADAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government of Kerala have proposed any water supply schemes to benefit the people living in the coastal villages of Kerala ; and

(b) if so, the details of such schemes and the action taken by Central Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) Since 1977-78, 253 schemes for 724 villages at an estimated cost of Rs. 2557,326 lakhs have been approved under the Centrally Sector Accelerated Rural Water Supply Programme (ARP). These schemes cover coastal villages also. In addition, regional piped water supply schemes have been recently approved for Quilandy and adjoining 16 villages in Calicut District at an estimated cost of Rs. 520.00 lakhs under the new Centrally sponsored Incentive scheme based on performance. Funds provided to Kerala for the Sixth Plan period are :

Minimum Needs
Programme (State Sector) : Rs. 45 crores
ARP (Central Sector) : Rs. 27.22 crores

Easy Availability of Seeds

2035. SHRI A. NEELALOHITHA DASAN NADAR :
SHRI T. S. NEGI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether availability of seeds has become easier (F. E. 24.10.83) as claimed and if so, why this was not possible earlier ; and

(b) whether this easy availability follows banning of clandestine export of seeds and if so, details thereabout ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) The Central and State Governments and institutional agencies have been continously making efforts to increase the availability of certified quality seeds in the country. A number of steps have been taken in this regard. As a result, the distribution of certified/quality seeds increased from 14.09 lakh quinials in 1979-80 to 42.06 lakh quintals in 1982-83 It is estimated that during current year about 56.99 lakh quintals would be distributed. The availability of certified/quality seeds has been increasing every year.

(b) No, Sir.

Unauthorised Occupation of Lodi Colony Quarters by Retired Government Servants

2036. PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refers to the reply given to Unstrarred Question No. 5477 on 4 April, 1983 regarding unauthorised occupation of Lodhi Colony quarters by retired Government servants and lay a statement showing :

(a) the number of Government quarters got vacated till 31 October, 1983 from the unauthorised occupants and reasons foy not evicting the occupants of the remaining quarters, category-wise ;

(b) particulars of persons occupying those Government quarters in Lodhi Colony and the period of unauthorised occupation in each case till 30 November, 1983 ; and

(c) how long will it take Government to get the unauthorised occupants evicted so that these Government quarters are allotted to the eligible Government servants on the waiting list for Lodhi Colony, New Delhi ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) 18 Quarters have already been vacated. The following three quarters are still in unauthorised occupation due to stay orders of the Court/Administrative decision :—

S. No.	Praticulars of retired Governmen servant.	Date of Cancellation
1.	Shri R. R. Handa, B-6/681, Lodi Colony	28.2.80
2.	Shri Shanti Sagar, B-15/295, Lodi Colony.	28.2.82
3.	Shri Durga Prasad, B-7/108, Lodi Colony	31.7.80

(c) Two cases are sub-judice and third is under consideration of the Government.

Central Assistance to Orissa Under Integrated Urban Development Scheme

2037. SHRI K. PRADHANI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Union Government are providing financial assistance to the States regarding Integrated Urban Development Scheme to the States :

(b) if so, the details regarding the amount so far granted by the Ceatral Goverament to Orissa Government in this regard ; and

(c) the amount so far utilized by the State Government for providing water supply to small and medium size towns during last three years, year-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, in respect of certain identified small and medium towns.

(b) The Central Govt. have released so far Rs. 134.64 lakhs to the Orissa Govt. under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns. The Yearwise details are as under :—

1979-80	Rs. 15.00 lakhs
1980-81	Rs. 1.00 lakhs
1981-82	Rs. 32.64 lakhs
1982-83	Rs. 41.00 lakhs
1983-84	Rs. 45.00 lakhs
	Total Rs. 134.64 lakhs

(c) Water supply schemes are not being funded by the Central Govt. under this Scheme. Hence no figures on this account are available with us.

Bringing More Items of Mass Consumption Under the Public Distribution System

2038. SHRI K.PRADHANI :
SHRI LAKSHMAN MALLICK :
SHRI AMAR ROY PRADHAN :
SHRI ANANTHA RAMULU MALLU :
SHRI G. Y. KRISHNAN :
SHRI NAVIN RAVANI :
SHRIMATI MADHURI SINGH :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently Central Government have issued some directions

to the State Governments to bring more ite ms of mass consumption under the Public Distribution System ;

(b) if so, the details in this regard ; and

(c) the details regarding the items that have been added as essentialc ommodities to be supplied to the consumers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) to (c) Under the scheme of public distribution system, the Central Government has assumed responsibility for supplying seven commodities i. e. , whart, rice, sugar imported edible oil, kerosene, soft coke and controlled cloth to States/U. Ts. for distribution to the consumers. The Central Government has advised State Governments/ Union Territory Administrations from time to time to add such other items of mass consumption for distribution through the public distribution system as they deem fit by arranging for the supplies on their own. Thus, a number of Stases are also issuing items such as wheat products, pulses, soap, match box, cycle tyres & tubes etc. A statement showing items at present being distributed by the States/U. Ts. under the public distribution system is attached.

STATEMENT

State-wise break-up of the commodities being supplied through fair price shops.

S. No.	Name of the State/U. T.	Commodities supplied through fair prce shops.
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	Rice, wheat, edible oil, kerosene, and sugar.
2.	Assam	Rice, wheat products, sugar, salt, edible oils, kerosene, controlled cloth.
3.	Bihar	Wheat, rice, sugar, controlled cloth, exercise books.
4.	Gujarat	Wheat, rice, coares grains, sugar.
5.	Haryana	Wheat, atta, sugar, rice and kerosene oil, edible oils, controlled cloth, soft coke.
6.	Himachal Pradesh	Wheat, atta, rice, edible oil, sugar,controlled cloth.
7.	Jammu & Kashmir.	Rice, wheat, atta kerosene oil and sugar.
8.	Karnataka	Sugar, rice wheat, suji, maida, edible oil, kerosene oil.
9.	Kerala	Rice, wheat, sugar, kerosene oil, edible oils, coffee, tea maida, suji, pulses,s pices, sawala onion, jagree.
10.	Madhya Pradesh	Wheat, rice, sugar, edible oil, kerosene oil, controlled cloth, tea, match boxes and soap.
11.	Maharashtra.	Rice, wheat, jowar, edible oils, sugar and kerosene oil.
12.	Manipur.	Rice, sugar, atta, edible oils, kerosene oil.
13.	Meghalaya	Rice, sugar, salt, wheat products, edible oils.
14.	Nagaland	Sugar, salt, rice and wheat products.
15.	Orissa	Rice, wheat, sugar, kerosene oil, edible oils, controlled cloth, cement, pulses, baby food, cycle tubes/tyres, concessional paper, exercise books, soaps, cosemetics, tea.

1	2	3
16.	Punjab	Sugar, wheat/atta, rice, kerosene oil, edible oil, wheat, pulses, controlled cloth.
17.	Rajasthan	Wheat, rice, sugar, edible oils, controlled cloth, kerosene oil, cement, tea, soaps, soda ash, salt, pulses, spices, exercise books, matches, battery cells, bulbs, tyres/tubes.
18.	Sikkim	Rice, sugar, and edible oils.
19.	Tamil Nadu	Rice, wheat, maida, suji, sugar, kerosene oil, edible oils, controlled cloth, chilles. In addition turmeric, jeera, mustard, snuff, pepper, garlic, methi, jaggery, salt, coffee, tea, pulses, edible oils, soap, face powper, baby food, blades, dry cell, match box, nirodh, vicks and amirthanjan are supplied by village fair price shops run by Cooperatives (numbering 38 items).
20.	Tripura	Salt, sugar, rice, wheat, atta controlled cloth, kerosene oil.
21.	Uttar Pradesh	Wheat, rice, sugar, edible oil. In addition 56 items in urban areas & 24 items in rural areas are being distributed through Coops.
22.	West Bengal	Rice, wheat, sugar, wheat products pulses. suji, toilet soap, laundry soap, salt, kerosene, edible oils, soft coke match box, exercise book, candle sticks, spices, controlled janta cloth.
23.	Andaman & Nicobar Islands.	Rice, wheat, sugar, salt, controlled cloth, edible oils, kerosene, matches. soap, exercise books, spices, tea, chillies, vanaspati ghee, butter, coffee, dry cells, paper, maida, onion, potato, pulses.
24.	Arunachal Pradesh	Rice, wheat, sugar, kerosene oil, edible oils, salt, controlled cloth.
25.	Chandigarh	Sugar, rice, wheat, atta, kerosene oil, edible oils, controlled cloth. Improted edible oils are being distributed through consumer cooperatives.
26.	Dadra & Nagar Havali	Sugar, wheat, rice, edible oils.
27.	Delhi	Wheat, resultant atta, maida, suji, sugar, rice, R. B. D. Palm oil, repeseed oil, candles, soft coke. Kerosene oil, cement and controlled cloth is being issued through other retail outlets.
28.	Goa, Daman & Diu.	Rice, wheat, sugar, edible oils and controlled cloth.
29.	Lakshdweep	Rice, wheat, controlled cloth, kerosene oil, soap, edible oils, sugar, salt, tyres/tubes, gram, dalls and chillies, cement, diesel and petrol, white paper, tea, coffee, cheap cloth.

1	2	3
		Edible oils, baby food, dry battery are distributed through cooperatives only.
30.	Mizoram	Rice, sugar, wheat, edible oil, salt and kerosene oil.
31.	Pondicherry.	Rice, wheat, maida, suji, sugar, edible oils, and kerosene oil.

टाइप 'सी' और 'डी' के क्वार्टरों में बरामदों को कवर करना

2039. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोधी रोड, नई दिल्ली के आबंटितियों के अनुरोध पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग टाइप 'सी' और 'डी' के क्वार्टरों में बरामदे को कवर कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1983 से अब तक माह-वार कितने मामलों में बरामदा कवर करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ;

(ग) स्वीकृति दिए जाने के बाद कितनी अवधि में बरामदे कवर किए गए ; और

(घ) इसमें इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां,

(ख)	जनवरी, 1983	7
	फरवरी, 1983	3
	मार्च, 1983	शून्य
	अप्रैल, 1983	3
	मई, 1983	2
	जून, 1983	7
	जुलाई, 1983	3
	अगस्त, 1983	2
	सितम्बर, 1983	शून्य
	अक्टूबर, 1983	2
	नवम्बर, 1983	1
	योग	30

(ग) केवल कुछ छोटे मोटे परिसज्जन कार्यों को छोड़कर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् 1½ से 7½ महीनों के मध्य बरामदों को बन्द किया गया ।

(घ) अनुमोदन देने तथा कार्य को पूर्ण करने के मध्य समय लगता है क्योंकि आंकलनों को तैयार करने तथा स्वीकृति करने, निविदायें आमन्त्रित करने जैसी कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है । निष्पादन में भी समय लगता है क्योंकि ये कार्य छोटे तथा अलग-अलग स्थानों पर है तथा सीमित साधनों से मुख्यत: ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं । कुछ आबंटियों ने इच्छा व्यक्त की कि कार्य उनकी सुविधा के अनुसार किया जाय तथा उन्होंने अपने संशोधन सुझाए ।

बाड़मेर और जैसलमेर में राष्ट्रीय मरू-उद्यान

2040. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी जिलों में राष्ट्रीय मरू उद्यानों की अब तक की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन उद्यानों के निर्माण से रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास में क्या सहायता मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मार्च, 1983 तक उद्यान पर 82.79 लाख रुपए व्यय किए गए हैं । लगभग 4,000 हैक्टेयर क्षेत्र में बाड़ लगाई गई है तथा उसमें सीवन घास तथा अन्य मरूस्थली पौधे लगाए गए हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है । 6 गज़लरों, 4 टैंकों,

2 नलकूपों, 5 नाड़ियों, 11 मरू सुरक्षा चौकियों का निर्माण किया गया है। अकाल में एक बुडफौसिल उद्यान में बाड़ लगाई गई है तथा उसका रख-रखाव किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय मरू-उद्यान का अभिप्राय अपविकसित प्राकृतिक मरूस्थल की पारिस्थितिक पद्धति को पुनः विकसित करना तथा इसके पेड़-पौधों एवं जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करना है। उद्यान अभी भी निर्माणाधीन है। अतः लक्ष्यों की उपलब्धि में इसके प्रभाव का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

Master Plan for Protection of Region Affected by Floods of Luni River

2041. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Master Plan has been framed by Rajasthan Government for protection of the region affected by the floods of Luni River ;

(b) if so, upto what place ; a copy thereof may be laid on the Table of the House ;

(c) whether it is a fact that the area beyond Sindhai to Gunha Gandhav (Barmer District) and area of Sanchore Tehsil (Jalore District) is not covered in the Master Plan ;

(d) if so, will Government propose the master plan for that area ; and

(e) the full details of the works started and completed under the Master Plan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Central Government has not so far received any Master plan for Luni basin from the Rajasthan Government.

(b) to (e) In view of reply to (a) above, replies to (b) to (e) does not arise.

Assistance to Fishing Industry

2042. PROF. P. J. KURIEN :
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the proposals being examined to extend some assistance to the fishing industry, in view of the periodic fluctuations in the prices and catches of shrimp, etc., and

(b) the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) and (b) Small and periodic fluctuations in the prices and catches of shrimp etc. are normal features. There is no proposal at present to extend financial assistance to the fishing industry for such fluctuations.

Utilisation of Funds by the States

2043. SHRI LAKSHMAN MALLICK : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the States could not be able to utilise the fund earmarked by Government during 1982-83 ;

(b) if so, what has been the percentage of the utilised funds and the Punds remained unutilised, State-wise alongwith the reasons thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) to (c) Statements showing State-wise allocations and utilisation of funds to the total allocation under the major programmes of the Ministry of Rural Development are laid on the Table of the House. (Placed in Libray. See No. LT-7165/83.) The reasons for reported shortfalls in expenditure for various schemes vary from State to State. Generally speaking, these could be insufficient infrastructure, delays in preparation and implementation of sub-projects etc.

Amount Earmarked for Providing Employment in Rural Areas

2044. SHRI UTTAM RATHOD : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the finances earmarked for providing employment in rural areas, particularly landless labourers ; and

(b) how many people are expected to be provided employment by the end of the current Five Year Plan ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) and (b) National Rural Employment Programme was included in the Sixth Five Year Plan to provide employment in rural areas. Sixth Plan allocation of Rs. 1620 crores was provided for this programme and an annual target of generation of 300 to 400 million mandays was fixed. The expenditure on this programme is shared on 50:50 percent basis between the Centre and the States. The total expenditure on the programme is likely to exceed the Plan allocation. The Sixth Plan target of generation of mandays is also likely to be achieved.

A new scheme "Rural Landless Employment Gurantee Programme" fully funded by Central Government has also been launched this year. The proposed allocation for this scheme in 1983-84 is Rs. 100 crores. For 1984-85 an allocation of Rs. 500 crores has been suggested. This programme will lead to generation of additional employment of about 360 million mandays during the 2 years 1983-84 and 1984-85.

Survey of Underground Water in Bhiwani and Mohindergarh Districts of Haryana

2045. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether any survey has been made in regard to the under-ground water capacity in the districts of Bhiwani and Mohindergarh of Haryana ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) The Central Ground Water Board has fully covered both the districts under Systematic Hydrogeological surveys. Reappraisal surveys and ground water exploration by drilling have also been undertaken.

(b) Based on the studies so far undertaken, it is seen that ground water in Bhiwani district occurs bath under confined and unconfined conditions on the basis of field pumping tests. Shallow tubewells and dug-cum-bore wells constructed in the depth range of 10 to 54 metres have yielded on an average about 135 cubic metres approximately (35,000 gallons) of water per hour. Similarly Deep tubewells tapping local confined aquifers to a depth of 122 metres have yielded discharge of 20 cubic metres to 57 cubic metres approximately (4500 to 12,500 gallons) per hour. 17 exploratory boreholes have been drilled by the Central Ground Water Board in this district. It had been estimated that as on 1.4.1979, 24591 hectare metres of resource was available for further development and that this could sustain about 13,500 shallow tubewells.

In Mohindergarh district, the Central Ground Water Boar has drilled 68 exploratory boreholes. In the studies so far carried out, in hard rock areas underlain by limestones, the tubewells have yielded about 90 cubic metres approximately (20,000 gallons) per hour, whereas from those drilled in quartzites, the yield was upto 36 cubic metres approximately (8000 gallons) per hour, Wells tapping deeper alluvium yielded 90-135 cubic metres approximately (20,000-30,000 gallons) whereas shallow wells in alluvium yielded 18 to 27 cubic metres approximately (4000-6000 gallons) per hour. The total usable recharge in the distirct has been assessed at 46,407 hectare metres. Of this, 37,914 hectare metres had been developed till 1.4.1979. To tap the remaining resources 1830 shallow tubewells need to be constructed.

Rice Despatch to Gauhati

2046. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of Food and Civil Supplies be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 590 on 11 April, 1983 regarding rice despatched to Gauhati and state :

(a) whether investigations regarding desptch of sub-standard rice to Gauhati by certain officials of Food Corporation of India have been completed ; and

(b) if so, results thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) No, Sir. It is proposed to register a case with C. B. I. for a thorough investigation,

(b) Does not arise.

Abolition of Lease in Delhi and Chandigarh

2047. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: SHRI JAGPAL SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state present stage of the proposal for apolition of lease hold system in Union Territories of Delhi and Chandigarh ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): The question of abolition or modification of the lease hold system relating to residential leases is being examined in all its aspects keeping in view the repercussions of any decision on the system of land tenure in other parts of the country, the experience of some other States and financial and social implications.

Collapse of Water Tank in Delhi

2048. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 324 on 21 March, 1983 regarding collapes of water tank in Delhi and state :

(a) whether enquiry conducted into the collapse of the tank has been completed ; and

(b) if so, the details and result thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking have reported that the enquiry has been completed.

(b) According to the Undertaking, the enquiry report is still undgr examination.

Minimum Cane Price Fixed by States

2049. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state the minimum cane-price fixed, State-wise and the steps taken to ensure instant payment of prices ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : The minimum cane price fixed by the Central Government under the Sugarcane (Control) Order, 1966, for the 1983-84 sugar season, is Rs. 13.50 per quintal linked to a basic recovery of 8.5 per cent. This price is applicable to sugar factories throughout India. Factory-wise prices, however, differ on the bnsis of the recovery achieved by them.

Ensuring payment of cane price dues is the direct responsibility of the State Governments who have the necessary field organisations and powers to enforce such payments. The Central Government, on its part, has taken steps like providing better credit facilities, monitoring the prices of levy free sugar through regulated monthly releases and maintaining a buffer stock of sugar which are aimed at improving the liquidity of the industry in general to enable it to pay the cane price expeditiously. Whenever considered necessary, on excise rebate is also granted. Further, the Industry's financial problems are continually reviewed by the Standing Committee on Co-ordination of Institutional Finance for the Sugar Industry set up by the Reserve Bank of India. The Central Covernment have, only recently impressed upon the State Governments to keep a special watch on the payment of cane price during the 1983-84 season.

Irrigation Master Plan From States

2050. SHRI AMAR ROY PRADHAN : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Governments have submitted their irrigation master plan for security to the Central Government ; and

(b) if so, the details thereof and decision taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) In response to a suggestion made by Government of India to the States, the following plans/reports have been received in the Central Water Commission :—

1. Master Plan of Water Resources, Goa Daman and Diu.
2. Basin-wise Master of Konkan region, Maharastra.
3. Outline plan of some tributaries south of Tapi, Gujarat State.

4. Hyderological data of Major River Basins in Tamil Nadu.

5. Tentative Master Plan of Irrigation Development in Orissa.

6. Perspective plan for Irrigation in Andhra Pradesh.

Considerable further information/details are required to be incorporated in the reports by the State Governments.

Sale of Asiad Flats to Non-Resident Indians

2051. SHRI AMAR ROY PRADHAN :
SHRI HARISH KUMAR GANGWAR :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a whether Government have decided to sell Asian Games Village flats in Siri Fort area of South Delhi to non-resident Indians ;

(b) if so, the details thereof and the number of flats so far sold out to the non-resident Indians ;

(c) wheter Government propose to sell these flats to the citizens of India also on the same terms and conditions as offered to the non-resident Indians ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir. In addition, the following two categories of Indian Nationals are also eligible :—

(1) Indian nationals serving in Internanal Organisations either in India or abroad who can legitimately pay in foreign exchange.

(2) Indian nationals who were employees of International Organisations until recently but have returned to India and would be able to pay in foreign exchange within the permitted period of maintance of foregin account.

(b) The DDA has invited applications for sales of 853 flats in Asiad village complex from the eligible persons by 30-12-83. The cost of dwelling units ranges between Rs. 7,20,000 to Rs. 15,65,600 depending upon the type & size of the dwelling unit including the cost of fixtures & furnishings and also the cost of garages & servents quaters whenever provided. There are, in all 29 type designs. The payment will be received in U.S. dollers only through the following six banks :—

(1) State Bank of India
(2) Central Bank of India
(3) Bank of Baroda.
(4) Indian Overseas Bank.
(5) United Gommercial Bank.
(6) Bank of India.

Efforts are being made by the DDA to complete the sale by 31st March, 1984.

No flat has been sold out as yet.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Suggestions Made for Preventing Use Of Tallow in Vanaspati Oil

2052. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that for prevention of tallow of cow or pig or any other animal being aduelterated with vanaspati oil it has been suggested that ;

(i) immediate chemical analysis of all stocks of vanaspati oil;

(ii) facility of free chemical analysis of vanaspati in any food analysis laboratory if a group of consumers so demand ; and

(iii) by ban on production of indigenous tallow ; and

(b) Government's response to each of these three suggestions ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) The Government are keeping a constant and strict vigil on the quality of the vanaspati produced in the country by carrying out inspections of the factories and

drawing samples from all the vanaspati units regularly to ensure that the product complies with the specifications laid down and only permitted oils are used. The State Governments have also been requested to draw samples from the markets get them analysed and take appropriate action wherever necessary under the P.F.A. Act. The import of tallow has also been banned.

In the view of the action taken by Government to prevent adulteration of vanaspati, the measures suggested are neither considered necessary nor feasible.

उत्तर प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट

2053. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सितम्बर, 1983 के मध्य में देश के उत्तरी भागों में सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी तथा उनके अन्य पड़ोसी जिलों में मूंगफली के उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में मूंगफली के उत्पादन में आई गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण दल भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं,

(ग) मूंगफली की किस्म और उसकी मात्रा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) सीतापुर के प्रमुख विपणन केन्द्र को वर्ष 1983-84 में कुल कितनी मात्रा में मूंगफली लाई गयी थी और वर्ष 1972-73 में लाई गई मूंगफली की तुलना में वह कितनी है और क्या इस समय स्थिति बदतर हो गई है ; और

(ड़) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कृषि मन्त्रालय के एक केन्द्रीय दल ने 18 सितम्बर, 1983 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का दौरा किया ताकि वह इस क्षेत्र में मूंगफली की कीट स्थिति का सामान्यत: और विशेषकर सफेद सूंडी की समस्या का अध्ययन कर सके ।

(ख) और (ग) : इस दल ने मुख्यत: आवश्यकता पर आधारित वनस्पति रक्षण उपाय अपनाने, उन्नत किस्मों के उपयोग उपयुक्त प्राद्योगिकी के माध्यम से तथा विस्तार प्रयासों में तेजी लाकर मूंगफली के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने का सुझाव दिया ।

मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से बीज वितरण, प्रदर्शन आयोजित करने, वनस्पति रक्षण उपाय अपनाने और बीज मिनिकिटों के निशुल्क वितरण संबंधी सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता प्रदान की गई है । इसके अलावा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए समर्थन मूल्य भी घोषित करती है ।

(घ) सीतापुर मण्डी में वर्ष 1972-73 में 38,580 मीटरी टन छिलके वाली मूंगफली आई थी जबकि वर्ष 1983-84 के लिए मण्डी का मौसम हाल में शुरू हुआ है । अत: इस समय मण्डी में 1983-84 के दौरान आने वाले, माल की तुलना 1972-73 के माल से करना संभव नहीं है ।

(ड़) सरकार उन्नत बीजों की आपूर्ति करके, वनस्पति रक्षण उपायों को अपना कर, बीज मिनिकिटों का वितरण करके और समय पर आदानों की व्यवस्था करके, जिनमें किसानों को तकनीकी सलाह देना भी शामिल है, मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के सभी प्रयास कर रही है ।

Central Assistance to Kerala for Ground Water Studies in Coastal areas

2054. SHRI K.A. RAJAN : Will the Minister of IRRGATION be pleased to state :

(a) whether the Union Government have sanctioned Rs. 127.72 lakhs for carrying out ground water studies in the coastal areas ot Kerala ; and

(b) if so, the details of the projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The Union Government has sanctioned Rs. 127, 72,300/—for carrying out Ground Water Studies in Coastal Kerala, in collaboration with Swedish International Development Authority (SIDA), with their contribution being about 16.5 million Swedish Kroner, SIDA would provide a heavy duty drilling rig in addition to geophysical and hydrological equipment as part of its assistance. Under the project, comprehensive multidisciplinary studies for precise assesment of ground water resource potential are envisaged. About 65 Boreholes in an area of 824,000 sq. km. between Ponnani river in North to Attingal (Vamanapuram) in South will be drilled upto a depth of 450 metres to assess the hydrological conditions. Studies on popultion of ground water and its management in coastal areas keeping in view the saline/fresh water interface are also planned. Studies on economic and optimum use of water would be undertaken by Kerala Agriculture University. Assesment of the availability of ground water to meet the irrigation needs in Kunthipuza (Silent Valley) area will be undertaken on priority Basis. The project is expected to be completed in 4 years.

New Rural Landless Employment Guarantee Programme

2056. SHRI B. V. DESAI : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether scope of new Rural Landless Employment Guarantee Programme is to be enlarged and allocation of funds are proposed to be doubled in the Seventh Five Year plan ;

(b) whether during current year provision of Rs. 100 crores has been made for the Programme ;

(c) whether by 1984-85, modalities of operating the scheme at State and district levels would be finalised ;

(d) if so, whether allocation of Rs. 500 crores is being made for the next financial year ;

(e) whether Government are considering the merger of NREP with RLEGP ;

(f) whether his Ministry's opinion is that all projects at State levels should be carried out with Centre's approval ;

(g) if so, the schemes that have been undertaken during the current year ; and

(h) to what extent Rs. 100 crores have been utilised so far ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : (a) to (h) A new scheme of 'Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) has been launched on 15th August, 1983 in addition to NREP. It is proposed to provide an allocation of Rs. 100 crores in 1983-84 and Rs. 500 crores in 1984-85 for this new programme. Guidelines for implementation of this programme have already been issued to the State Governments. The State Governments are expected to propose suitable projects for approval by a Central Committee on NREP/RLEGP. The Projects received from different State Governments were considered by the Committee in its meeting held on 17th November, 1983 and 23 projects have been approved. More proposals are being received for approval by the Central Committee. It is not possible to indicate the position of this programme in the Seventh Plan, which is yet to be formulated. NREP will continue as a separate scheme during the current plan period.

Supply of Safe Drinking Water

2057. SHRI B. V. DESAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has felt that a sizeable number of small towns and villages will continue to be denied safe drinking water even at the end of Sixth Plan due to reluctance on the part of States to raise adequate resources ;

(b) whether Planning Commission has also stated that schemes for improvement of urban sanitation will suffer similarly in view of high cost of construction and maintena-

nce of sewerage schemes and reluctance of local bodies to levy higher taxes ;

(c) if so whether the programmes of rural sanitation is likely to be only partially implemented and towns may get dirtier in view of population increase ;

(d) if so, other steps being taken by Government in this regard ;

(e) to what extent these schemes will suffer ; and

(f) the measures being taken to provide funds for the purpose ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The Planning Commission in the mid-term review document have expressed fears that 100% coverage of all identified problem villages may not be achiveved by the end of the Sixth Plan period. The Planning Commission have estimated that at little over 14000 villages may spill over in the Seventh Plan due to physical and financial constraints.

(b) The Planning Commission have made a recommendation that in view of the high cost of construction and maintenance of severage schemes and the reluctance of the local bodies to levy proportionately higher taxes, most of the towns excepting Class I cities may have to be provided with only low-cost sanitation schemes.

(c) to (f) Water supply and sanitation are State subjects and their progress is monitored by the State Govts. The total outlay during the Sixth Plan for the water supply and sanitation sector is Rs. 3907.80 crores. of this Rs. 600 crores is in the Central sector under the Accelerated Rural Water Supply Scheme and the rest is in the State Sector. State Govts. are being impressed upon during the plan discussions to take all steps for complete coverage of all problem villages by the end of the Sixth Plan period. It has been agreed to release Rs. 75 crores in 1983-84 under a new incentive scheme, to those states who are showing better performance in the coverage of problem villages. The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade envisages a target of 25% coverage of the rural population and 80% coverage of the urban population for sanitation. The Govt. of India has decided, under the Centrally Sponsored Integrated Development of Small and Medium Towns Scheme, to advance Rs. 15 lakhs to the State Govts. Over and above the existing Rs. 40 lakhs, for each town, exclusively for low-cost sanitation. Apart from this, HUDO also gives loans to local bodies for low-cost sanitation schemes.

Meeting on Narmada Project

2058. SHRI B. V. DESAI : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a highlevel meeting on the inter-State Narmada Project was held in November, 1983 ;

(b) if so, whether a full review of the Narmada Project in all its aspects was discussed at the meeting ; and

(c) if so, what were the agreement reached in the meeting and whether any final decision in this regard has been taken ?

THE MINISTFR OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : The Honourable Member of Parliament is presumably referring to the Sardar Sarovar Project being executed by the Government of Gujarat. No high level meeting on Sardar Sarovar Project at the level of State Irrigation Ministers or higher was held in November, 1983. In view of this replies to (b) & (c) do not arise.

Assistance to Victims of Land Slides in North Sikkim

2059. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) how much properties and how many lives were washed away and lost in land slides in North Sikkim ;

(b) how much money was raised for Chief Minister's Relief Fund from different sources ;

(c) how much amount was released from Prime Minister's Fund ;

(d) how much amount was given by the Centre ;

(e) the norms accepted for the distribution of the funds among the victims ; and

(f) whether the State Government are thinking to shift the Head Quarters of North District in view of the above land slides ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) The damages caused by the landslides are as under :

1.	Population affected	: 0.99 lakh
2.	Cropped area affected	: 0.20 lakh ha.
3.	No. of houses/huts damaged	: 284
4.	Human lives lost	: 107
5.	Cattle heads lost	: 3260
6.	Loss of public properties	: Rs. 1957.10 lakhs

(b) State Government has intimated that a sum of Rs. 9.96 lakhs has so far been realised from various sources.

(c) Rs. 2 lakhs.

(d) A Central Team has visited the State from 17th to 21st November, 1983 and its report is awaited. The quantum of Central assistance that may be granted to the Govt. of Sikkim would be decided on receipt of the report of the Central Team. In the meantime the Govt. of India have sanctioned Rs. 50.00 lakhs as Ways & Means advance to enable the State Govt. to undertake urgent relief works. Margin Money with the Govt, of Sikkim is Rs. one lakh.

(e) The Govt. of Sikkim have reported that assistance to the victims have been granted at the following scale :

(i) Rs. 5000/- and Twenty six G. C. I. Sheets to persons in the rural areas whose houses have been completely damaged.

(ii) For the victims of Mangan Town who have lost their houses or whose houses are in danger requiring shifting a Relief Grant of Rs. 10,000/-.

(iii) Tenants (Shop keeper) of big houses Rs. 1000/- and tenants of small shops such as Pan Shop Rs. 500/-.

(iv) Relief grant of Rs. 2000/- to the next of kin of all those who died.

(f) No, Sir.

Opening of more fair price shops

2060. SHRI ARJUN SETHI :
SHRI SGNTOSH MOHAN DEV : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government have planned to open more fair price shops in the country particularly in inaccessible areas ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) The primary responsibility of administering the public distribution system in their respective areas, including the opening of fair price shops, lies with the States/U.Ts. Under the New 20 Point Programme, State Governments have already been asked to take effective steps to expand, strengthen and streamline the public distribution system, including opening of additional fair price shops with particular attention being given to rural, hilly and tribal areas. The States/Union Territories have also been advised to lay special emphasis on the opening of mobile shops for giving coverage to inaccessible areas or hitherto unserved/under-served areas.

Location of Buffalo Research Institute

2061. DR. A. U. AZMI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have seen press report appearing in first week of November, 1983 quoting ICAR Deputy Director General (Animal Sciences), Hissar on location of Buffalo Research Institute in Haryana Agriculture University ;

(b) if so, details of statement and whether Government had approved it and decision had concurrence of ICAR Governing Body ;

(c) State wise population of buffaloes and basis for locating ICAR Institute within Agricultural University, Hissar ;

(d) the particulars of members of site selection committee choosing this site at Hissar and details of farm, its area, irrigation facility and other infrastructural set up ; and

(e) particulars of other ICAR Institutes located in Haryana vis-a-vis other States listing separately new ones started during Sixth Plan period and Plan allocation for each as also for those existing before ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) No such statement regarding setting up of a Central Buffalo Research Institute at the Haryana Agricultural University was made by the Deputy Director General (Animal Sciences) of the Indian Council of Agricultural Research.

(b) In the light of (a) above, the question does not arise.

(c) The State-wise population of buffaloes is persented in Table 1. In the light of the recommendations made by the Task Force appointed by the ICAR to recommend suitable locations for the main campus and the regional stations of the Institute, one of the main campuses of the Central Institute for Research on Buffalo is to be located in the Murrah buffalo breeding tract viz Haryana. The recommendations have been accepted by the Council and it has been decided with the approval of the competent authority and keeping in view the requirements of land and its availability at different sites proposed by the Haryana State to locate the Institute at Hissar. It will be independent and not a part of the Haryana Agricultural University.

(d) The I. C. A. R. had constituted a Task Force for suggesting suitable locations for the Buffalo Research Institute which consisted of the following members :

1. Dr. P. Bhattacharya	Ex Animal Husbandry Commissioner & Member National Commission on Agriculture Chairman.
2. Dr. A. C Mathur	.....,Retd. Asstt, Director General (Animal Health)...Member.
3. Dr. B. D. Patil	Director, Indiau Grassland & Fodder Research Institute—Member
4. Dr. R. Nagarcenkar	Director, Central Sheep & Wool Research Institute & Former PC (Baffalo) and Head, Dairy Cattle Genetics, National Dairy Research Institute, Karnal—Member Secretary.

The site selected at Hissar meets the requirements suggested by the Task Force for setting up the Central Institute for Research on Buffalo.

(e) The following are the other ICAR Institute that are located in the State of Haryana :

1. National Dairy Research Institute, Karnal.

2. Central Soil Salinity Research Institute, Karnal.

There are a number of crop and livestock researeh Institutes of ICAR which are located in different States of the Country (Table 2). The Central Institute for Research on Buffalo is the only Animal Sciences Research Institute of the ICAR to be set up in Haryana during the Sixth Five Year Plan. Two Animal Sciences Research Institutes viz Central Avian Research Institue and Centrla Institute for Research on Goats located in Uttar Pradesh were established during the 6th Five Year Plan. Two Agricultural Research Institutes viz Soil Research Institute and Indian Institutes of Agricultural Economics are also to be set up during the 6th Five Year Plan. The locations for these two Research Institutes are yet to be decided. The plan allocation for the existing and new Institutes is given in Table 3.

TABLE 1

Statewise breedable Buffalo population according to 1977 Live-stock Census

Name of the State	Above 3 years of age (thousands) Buffalo	
	Male	Female
1	2	3
Andhra Pradesh	1275	3573
Assam*	201	142
Bihar	779	1999
Gujarat	35	2085
Haryana	94	1525
Himachal Pradesh	12	383
Jammu & Kashmir	45	298

1	2	3
Karnataka	297	1883
Kerala	219	151
Madhya Pradesh	1149	2591
Maharashtra	320	2127
Manipur*	16	11
Meghalaya	11	16
Nagaland	2	2
Orissa	594	415
Punjab*	268	1910
Rajasthan	190	2776
Sikkim	5	3
Tamil Nadu	384	1532
Tripura	6	4
Uttar Pradesh	1840	7271
West Bengal*	522	189
Andeman Nicobar Islands	3	3
Arunachal Pradesh	2	5
Chandigarh	5	8
Dadar & Nagar Haveli	1	1
Delhi	3	66
Goa Daman & Diu	11	18
Lakshadweep	—	—
Mizoram	1	1
Pondicherry	1	6

* Reference dates for these four States are 1972 since no enumeration was conducted in 1977-78.

TABLE 2

I. C. A. R. RESEARCH INSTITUTES

(i) Agricultural Institutes

1. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
2. Central Rice Research Institute, Cuttack, Orissa.
3. Central Potato Research Institute, Simla, Himachal Pradesh.
4. Jute Agricultural Research Institute, Barrackpore, West Bengal.
5. Central Tobacco Research Institute, Rajahmundry, Andhra Pradesh.
6. Central Tuber Grops Research Institute, Trivandrum, Kerala.
7. Indian Grassland & Fodder Research, Institute, Jhansi, U. P.
8. Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore, Karnataka.
9. Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, U. P.
10. Sugarcane Breeding Institute, Coimpatore, Tamil Nadu.
11. Central Plantation Crops Research, Institute, Kasargod, Tamil Nadu.
12. Indian Lac Research Institute, Ranchi, Bihar.
13. National Bureau of Plant Genetic Resourees, New Delhi.
14. Central Institute of Cotton Research, Nagpur, Maharashtra.
15. Vivekananda Parvatiry Krishi Anusandhan Shala, Almore, U. P.
16. Jute Technological Research Laboratory, Calcutta, West Bengal.
17. Cotton Technological Research Laboratory, Bombay, Maharashtra.
18. Research Complex, NEH Region, Shillong, Meghalaya.
19. Central Institute of Agricultural Engineering, Bhopal, Madhya Pradesh.
20. National Bereau of Soil Survey and Land Use Planning, Nagpur, Maharashtra.
21. Central Soil and Water Conservation Research and Training Instt. Dehradun. U. P.
22. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, Rajasthan.
23. Central Soil Salinity Research Institute, Karnal, Haryana.
24. Central Agricultural Research Institute for Andaman & Nicobar Islands, Portblair, Andaman.

(ii) Animal Sciences Institutes

25. Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, U. P.
26. National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana.
27. Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar, Rajasthan.

28. Central Institute for Research on Goat. Makhdoom, U. P.
29. Central Avian Research Institute, Izatnagar U. P.
30. Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, West Bengal.
31. Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin, Kerala.
32. Central Institute of Fisheries Technology, Cochin, Kerala.
33. Central Institute of Fisheries Education, Bombay, Maharashtra.
34. Indian Agricultural Statistics Research, Institute, New Delhi.
35. National Academy of Agricultural Research Management, Hyderabad, Andhra Pradesh.

TABLE 3

APPROVED PLAN OUTLAY (1980-85) FOR THE ICAR RESEARCH INSTITUTES

(i) **Agricultural Institutes**

	Approved plan outlay 1980-85 (Rs. in lakhs)
1. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.	1125.00
2. Central Rice Research Institute, Cuttack, Orissa.	462.00
3. Centrat Potato Research Institute. Simla, H. P.	260.00
4. Jute Agricultural Research Instt., Barrackpore, West Bengal.	91.31
5. Central Tabacco Research Institute, Rajahmundry, Andhra Pradesh.	185.64
6. Central Tuber Crops Research Instt., Trivandrum, Kerala.	111.54
7. Indian Grassland & Fodder Research Institute, Jhansi, U. P.	157.89
8. Indian Institute of Horticultural Research, Bangalore, Karnataka,	530.55
9. Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow U.P.	157.80
10. Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, Tamil Nadu.	125.00
11. Central Plantation Crops Research Instt., Kasargod, Tamil Nadu.	479.85
12. Indian Lac Research Institute, Ranchi, Bihar.	82.37
13. National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi.	353.00
14. Central Instt. of Cotton Research, Nagpur, Maharashtra.	215.76
15. Vivekananda Parvatiya Krishi Anusandhan Shala, Almora, U. P.	90.00
16. Jute Technological Research Laboratory, Calcutta, West Bengal.	79.08
17. Cotton Technological Research Laboratory, Bombay, Maharashtra.	189.00
18. Research Complex, NEH Region, Shillong, Meghalaya.	797.02
19. Central Instt. of Agricultural Engineering, Bhopal Madhya Pradesh.	310.00
20. National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, Nagpur, Maharashtra.	250.00
21. Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute, Dehradun, U. P.	271.49
22. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, Rajasthan.	282.00
23. Central Soil Salinity Research Institute, Karnal, Haryana.	276.00
24. Central Agril. Research Institute for Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, Andaman.	200.00
(ii) **Animal Sciences Institutes**	
25. Indian Veterinery Research Institute, Izatnagar, U. P.	850.00
26. National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana.	700.00
27. Central Sheep & Wool Research Institute, Avikanagar, Rajasthan.	210.00

28.	Central Instt. for Research on Goat, Mukhdoom, U. P.	150.00
29.	Central Avian Research Institute, Izatnagar, U. P.	152.00
30.	Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore, West Bengal.	334.00
31.	Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin, Kerala.	592.00
32.	Central Instt. of Fisheries Technology, Cochin, Kerala.	250.00
33.	Central Institute of Fisheries Education, Bombay, Maharashtra.	534.14
34.	Indian Agril. Statistics Research Institute, New Delhi.	197.25
35.	National Academy of Agricultural Research Management, Hyderabad, Andhra Pradesh.	370.02

Denundation of Himalayas

2062. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the threat posed to the country from large scale denundation of the Himalayas which has accelerated landslides, floods, sedimentations in the dams and rivers ; and

(b) if so, the steps being taken to check the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes, Sir.

(b) Following are the important steps being taken to check forest denundation :—

(1) The Forest (Conservation) Act 1980 was enacted to enable the Central Government to regulate the diversion of forest area to non-forest purposes.

(2) State Governments who are primarily concerned with protection of forests have tightened protection against illicit felling of trees.

(3) The following forestry and soil-conservation schemes are being implemented :

(i) Soil Conservation in the Catchments of River Valley Projects.

(ii) Integrated Watershed Management in the Catchments of Flood-prone Rivers of the Indo-Gangetic Basin.

(iii) Soil Water and tree conservation in the Himalayas.

(iv) Social Forestry including Rural Fuel Wood Plantation.

(v) State Social Forestry Schemes.

(vi) State Soil Conservation Schemes.

(vii) Himalayan Watershed Management Project in Uttar Pradesh.

Utilisation of Irrigation Potential of Halali Dam in Vidisha and Raisen Districts

2063. SHRI PRATAP BHANU SHARMA: Will be Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that irrigation potential of Halali Dam in Vidisha and Raisen districts is not being fully utilized for want of additional funds and slow progress in construction of its major canals ; and

(b) if so, what effective steps Central Government are taking to complete the remaining work immediately wilh a view to create full irrigational potential ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The estimated cost of Halali project is Rs. 13.06 crores and while an expenditure of Rs. 11.56 crores has been incurred upto March 1983, an amount of Rs. 80 lakhs is anticipated to be spent during 1983-84. The State Govt. have proposed an outlay of Rs. 60 lakhs during 1984-85 for completing the balance work. Full potential of 37.200 hectares is expected to be created by end of 1984-85. No constraint imposed by financial resouces has come in the way of the completion of thls project, which had been scheduled for the end of the current Plan period.

Booth Halali and Barna projects are included, from August 1979, as tne charge of the Command Area Development Authority implementing the Command Area Development Programme, under the Centrally

Sponsored Scheme. Under this programme, till the end of September 1983, field channels have been constructed to cover an arer of 15,000 hectares. However, the the anticipated utilisation of potential during the current year 1983-84 is only 10,000 hectares. It is expected that with further completion of on-farm Development works under this Programme, utilisation will further improve.

Demand for Addditional Funds From M. P. for Irrigation Purposes

2064. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh Government have demanded additional funds for major and medium irrigation project to create additional potential during 1983-84 and 1984-85 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reaction of Central Government ; and

(d) how much extra irrigation potential shall be created after that assistance ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) Yes Sir. The Government of Madhya-Pradesh had asked for an additional requirement of funds to the tune of Rs. 39.00 crores for Major & Medium Irrigation project to create additional Irrigation potential during 1983-84 and 1984-85.

(c) An amount of Rs. 99.35 crores have since been allotted to the State Government as additional overall plan assistance for the years 1983-84 and 1984-85. It is for the State Government to allocate a sizeable portion of the additional assistance to the Irrigation Projects in this State :

(d) The State Government reported that with the additional assistance of Rs. 39.00 crores, an extra irrigational potential of 74.5 thousand ha. could be created.

Fifth Self Financing Scheme of DDA

2065. SHRI PRATAP BHANU SHARMA :
SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of applications which were registered under Fifth Financing Housing Scheme of Delhi Development Authority during the period from 14 May 1982 to 14 August, 1982 for different categories ;

(b) the full detail s thereof ;

(c) wheter site selection and preliminary work has been completed for this scheme ; and

(d) if so, the cetails thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) The DDA has reported that 34335 persons were registered under the Financing the period under reference.

(b) The DDA has reported thot 15450 and 18885 persons were registered under category II and category III respectively.

(c) Yes, Sir.

(d) The DDA reported that appilcations for allocation of flats have already been inveted from the persons registered under this scheme along with those registered under lst, 2nd, 3rd and 4th Self Financing Scheme. The DDA have further reported that the areas where these houses wiil be constructed are Vasant Kunj Sarita Vihar, Trilokpuri, Nand Nagri, East of Mukerjee Nagar, Vasant Vihar and Vikas puri.

Improvement in Well-Being of Small and Marginal Farmers and Share Croppers

2066. SHRI MANOHAR LAL SAINI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact thet during the Sixth Five Year Plan it was proposed to improve the well-being of small and marginal farmers and share croppers ;

(b) if so, the details of the progress made ; and

(c) how many farmers have been benefited thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Yes, Sir. Integrated Rural Development Programme is being implemented by Ministry

of Rural Development to improve the well-being of small and marginal farmers and share croppers. In addition, a Centraliy Sponsored Scheme for assisting the small and margainal farmers for increasing agricultural produclion is being implemented in all the States and Union Territories except Rajasthan in 1983-84.

(b) The details of the progress made in respect of Integrated Rural Development programme is as under :—

Item	1980-81	1981-82	1982-83
1. No. of beneficiaries (in lakh)	27.27	27.13	34.55
2. Total expenditure (Rs. in lakh)	15863.68	26464.92	35959.01
3. Term credit mobilised (Rs. in lakh)	28904.97	36759.01	71398.20

Under the Centrally Sponsorad scheme of assistance to small and marginal farmers for increasing agricultural prodution an amount or Rs. 67.2198 crore as central share has alerady been released to various States and Union Territories. Dadra & Nagar Haveli do not, however, need any funds for this scheme.

Many State Governments have reported that State Level Coordination Committees have worked out district-wise and block-wise targets and funds for each component of the scheme and communicated to the concerned implementing agencies. For Minor Irrigation work the beneficiaries are being identified by the States for construction of dug-wells and installation of pump sets/ tube-wells. Some States have identified beneficiaries and have started forwarding applications of the beneficiaries to financial institutions for credit and utilising the subsidy available under the scheme. Certain components like minikit distribution and plantation of fuel and fruit trees have been implemented by a number of States.

(c) Under Integrated Rural Development Programme, 88.95 lakh beneficiaries have been assisted from 1980-81 to 1982-83. Under the programmme of assistance to small and marginal farmers about 600 farming families of the small and marginal farmers per block, depending upon the availability of the funds, have been planned to be benefitted.

गैर सरकारी क्षेत्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का प्रस्ताव

2067. **श्री मनोहर लाल सैनी :**
श्रीमती प्रमिला दंडवते :
श्री राम स्वरूप राम :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को भी सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर विचार करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वियन तथा उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी, जिसमें उचित दर की दुकानों का आबंटन करना भी शामिल है, मुख्यत: राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की है ; इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानें

सहकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना में सहकारी क्षेत्र को ज्यादा भूमिका दी जाये।

Adoption of Villages by Organisation

2068. SHRI G. NARSINHA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has written to the Chief Secretaries of all States Governments and Union Territories suggesting that District Magistrate should see that at least one village in a block should be adopted by one oganisation out of various organisations which include Public Sector Undertaking, Universities, Research Institutions, Voluntary Organisations etc., for intensive implemention of programmes for improved agricultural productivity ;

(b) if so, the details of the programme ;

(c) the number of villages adopted so far State-wise ; and

(d) whether this programme has given any positive results ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The adoption of villages primarily aims (i) to bring about a general increase in agricultural production and thereby to raise the income of the rural community and (ii) to ensure optimum possible development of the villages so that they become models of development for the neighbouring areas. The villages to be adopted should have a population ranging from 100-200 farm families with a percentage of small and marginal farmers and should have preferably, in operation, some Central of State Government programmes on crops, animal husbandry, fisheries or irrigation.

(c) More than 5000 villages have been adopted in different States by various agencies as detailed below :—

Name of the States/UT	No. of villages adopted by various agencies
1. Assam	247
2. Andaman & Nicobar Administration	5
3. Andhra Pradesh	392
4. Bihar	36
5. Chandigarh	2
6. Delhi	10
7. Dadra & Nagar Haveli	2
8. Goa	1
9. Gujarat	588
10. Himachal Pradesh	303
11. Haryana	463
12. Jammn & Kashmir	3
13. Karnataka	433
14. Kerala	187
15. Lakshadweep	5
16. Mizoram	32
17. Maharashtra	599
18. Madhya Pradesh	310
19. Orissa	24
20- Punjab	132
21. Pondicherry	3
22. Rajasthan	30
23. Tamil Nadu	611
24. Uttar Pradesh	130
25. West Bengal	168
26. No. of villages adopted by public Sector Undertakings (Names of States not given).	464
Total No: of villages adopted.	5180

(d) Reports received from the adopting agencies indicated encouraging results. Various programmes for increasing agricultural production (including dryland farming oil-seed and pulses programme) providing credit facilities, agricultural implements, fertilizer promotion, bio-gas development, Social Forestry, Marketing, Transfer of Technology through Minikit Demonstrations, distribution of inputs, Soil Testing, digging of wells, horticulture development

etc., have been taken up by different agencies in the several adopted villages.

Release of Central Assistance for Flood Relief

2069. SHRI T. S. NEGI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some State Minister have sought his help for early release of Ceutral assistance asked for to launch relief works in flood-revished area and if so, the details and results thereof ;

(b) whether it is also a fact that there have been inordinate delays due to Central Teams 'visits to the States affected by cyclones/floods/droughts etc ; and

(c) if so, the corrective steps proposed to overcome these delays leading to human misery and delay in agricultural production due to late supply of relief and inputs ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Yes, Sir. The Chief Ministers/Other Ministers of the States of Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh had written for expediting the Central assistance. Immediate action has been taken to process the Memorandum for purposes of sanction of the Central assistance.

(b) and (c) No Sir, Immediately on receipt of Memorandum, a Central Team representing the concerned Ministries is constitured and deputed to the State. On receipt of report of the Team, the High Level Committee on Relief considers it at the earliest. The Ministry of Finance, taking into consideration the reommendations of the High Level Committee on Relief sanction the Central assistance. This procedure is being adopted as per recommendations of the VII Finance Commission.

Every State has been allocated Annual margin money to meet the emergent expenditure at the time of occurrence of the natural calamities.

However, pending the visit and report of the Central Team and recommendations of the Hlgh Level Committee on Relief, the affected States are sanctioned Ways & Means advance to take up emergent relief meassure pending sanctions of ceiling of Central assistance after the visit of the Team.

Priority to Scientific Management of Irrigation Resources

2070. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister to IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the suggestions made by the Director of the Indian Agricultural Research Institute (IAIR), that the foremost priority at this stage should be given to the scientific management of irrigation resources rather than to making addition to it ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) At the recently held symposium on An Integrated Approach to Management of Irrigation Water in the Command Areas, the Director, IARI, had suggested that the foremost priority at this stage should be the scientific management of the irrigation resources created ;

(b) The Government is aware of the need for improving water management and has taken steps to introduce scientific management of irrigation resources through measures such as

(a) modernisation of irrigation systems ;

(b) introduction of warabandi ; and

(c) provision of multi-disciplinary inputs through Command Area Development Programme. Further, the Government is of the view, that while improvement of water management is to be given due importance in existing projects, the creation of additional irrigation facilities is of equal importance to extend the benefits to areas and population henceforth not receiving this benefit.

Price rise of Vegetables and Vanaspati Ghee

2071. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of vegetables and vanaspati ghee have been rising steadily despite good rains in the various parts of the country ;

(b) if so, to what extent the prices of the major vegetable like tomatoes, onions, potatoes and various vanaspati and edible oils have increased during the past three months indicating the comparative prices in August and October 1983 ; and

(c) steps taken or being taken to keep these prices under check ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) There has been some increase in the prices of vegetables during the past few months but the price of Vanaspati has remained more or less steady.

(b) The index number of wholesale prices of tomatoes onions, potatoes and various edible oils including vanaspati for the months of August, September and October, 1983 are indicated in a statement.

(c) For making essential commodities available to the consumers at reasonable prices, the main thrust of the Government policy is to increase the production oft various commodities. The Public Distribution System is being expanded. Some commodities are being imported. The export of essential commodities is regulated. The State Government and Union Territory Administrations are enforcing the provisions of the Essential Commodities Act and similar legislations.

STATEMENT

Statement showing the Wholesale Price Index Numbers of selected commodities in August, September, and October, 1983.

(Base yeas 1970-71 = 100)

	August	September (P)	October (P)
Potatoes	246.5	274.2	258.3
Onions	461.8	541.8	535.6
Tomatoes	322.8	306.6	328.0
Vanaspati	256.2	256.5	254.5
Groundnut Oil	342.9	352.0	335.4
Mustard Oil	281.1	286.7	294.2
Coconut Oil	302.6	315.8	336.5
Gingelly Oil	291.1	286.6	276.7
Kardi Oil	354.4	351.9	357.5
Cottonseed Oil	321.1	318.7	307.4

(P) = Provisional

Land Covered by Irrigation, Rainfall, River and Canal Waters and by Well Water

2072. SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state the latest assessed estimate about the extent of land in the country (State-wise) covered by (1) assured rainfall (2) by adequate irrigation by means of river and canal waters and (3) by well water irrigation and (4) with no irrigation at all ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Land us Statistics are published by the Ministry of Agriculture and the latest published figures and for the year 1978-79. Statewise figures for that year relating to cultivable area with assured rainfall, area irrigated by surface water, area irrigation are shown in the statement enclosed.

STATEMENT

STATEMENT SHOWING DETAILS OF CULTIVABLE AREA, IRRIGATED AREA BY SURFACE WATERS, WELLS AND TUBEWELLS AMD CULTIVABLE AREA WITH NO IRRIGATION

(Area in ,000' ha.)

Sl. No.	State/Union Territories	+Cultivable area more or less getting assured rainfalll for one crop.	Area irrigated by Surface waters (net.)	Area irrigated by wells & tubewells.	Cultivale area with no irrgation
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	8629	2930	725	12132
2.	Assam	3288	572	—	2716
3.	Bihar	9439	1943	1017	8800
4.	Gujarat	3823	369	1346	10734
5.	Haryana	2176	1123	795	1882
6.	Himachal Pradesh	797	87	2	708
7.	Jammu & Kashmir	433	302	3	764
8.	Karnataka	2047	1052	357	11343
9.	Kerala	2463	186	42	2235
10.	Madhya Pradesh	17597	1372	943	20316
11.	Maharashtra	11592	795	1101	19223
12.	Manipur	164	65	—	99
13.	Meghalaya	1105	48	—	1067
14.	Nagaland	705	54	—	651
15.	Orissa	6699	1001	147	6367
16.	Punjab	4284	1419	1843	1052
17.	Rajasthan	11176	1165	1730	23523
18.	Sikkim	67	10	—	57
19.	Tamil Nadu	3610	1804	1069	5648
20.	Tripura	350	29	—	321
21.	Uttar Pradesh	17473	3670	5222	12146
22.	West Bengal	4489	1472	17	4793
23.	Andaman & Nicobar Islands	72	—	—	72
24.	Arunachal Pradesh	377	24	—	353
25.	Dadra & Nagar Haveli	23	—	1	22
26.	Delhi	99	22	39	38
27.	Goa, Daman & Diu	228	13	—	215
28.	Lakshadweep	3	—	—	3
29.	Mizoram	584	8	—	576
30.	Pondicherry	36	16	11	9
	GRAND TOTAL	113828	21551	16410	147825

(*) Area under assured rainfall has been worked out as total cultivable *minus* area assured culturable area in drought prone districts.

NDMC, s Policy for Granting Licences for Shops in Garages of Residential Building

2073. SHRI RAM PRASAD AHIRWAR : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the NDMC's policy for granting licences for sale of food/edible items and whether such licences are granted/renewed for shops located in garages of residential buildings in residential colonies in violation of the DDA Act for non-conforming use and lease agreements of President of India and if so the details and procedure thereof ; and

(b) whether no-objection certificates of residential building owners and/or L.&D.O. are asked for before granting renewing such licences and if so, whether such no-objection certificates were obtained in respect of shops running in garages of residential buildings in in Golf Links alone with details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

खेतिहर मजदूरों और छोटे तथा सीमांत किसानों के आंकडे

2074. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेतिहर मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) राजस्थान में खेतिहर मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों संबंधी जिलावार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) राजस्थान में उत्तम श्रेणियां निर्धारित करने के लिए कितनी भूमि को मानदण्ड माना गया है और इस संबंध में सिंचित और असिंचित भूमि संबंधी जिलावार आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) उत्तम भूमि निर्धारण के मानदण्ड क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार खेतिहर मजदूरों से संबंधित राज्यवार आंकड़े विवरण-I में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7166/83] 1976-77 के लिए सीमांत और छोटे किसानों से संबंधित आंकड़े विकरण-II में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7166/83]

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित जिलावार आंकड़े विवरण-III म तथा राजस्थान के सीमांत और छोटे किसानों के लिए आंकड़े विवरण 4 में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7166/83]

(ग) और (घ) कृषि संगणना के प्रयोजन के लिए एक हैक्टेयर से कम भूमि पर फसल उगाने वाले किसानों को सीमांत किसान और 1 से 2 हैक्टेयर भूमि पर फसल उगाने वाले किसानों को छोटे किसान कहा जाता है। राजस्थान के सिंचित और गैरसिंचित क्षेत्र से संबंधित जिलावार आंकड़े विवरण-5 में दिये गए हैं।

Plan Budget for Govt. Institute

2075. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the plan budget for 1983-84 of Goat Institute and actual expenditure till 1 November, 1983 with reasons for any dis-proportionality ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Plan Budget for 1983-84 and actual expenditure upto 1.11.83 in respect of the central Institute for Research on Goats, Makhdoom are given below :

Budget allocation for 1983-84 — Rs. 40,000,00

Progressive expenditure up till 1.11.83 — Rs.3005279.12

From the proportionality point of view the excess expenditure incurred during the first seven months of the year is due to inerease

in the cost of labour for land development, scrub forest clearning and making arrangements for drinking water, telephone, & electric connections for the Institute which had been set up only a few years back, because the purchase of equipments materialised earlier than the expected period, & also because advance payment had to be made for works.

Selection of Dircetor of ICAR Goat Institute

2076. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR. Will the Minister of AGRICULTURE be pleaesd to state :

(a) whether ICAR while selecting Institute Directors take into account the confidential reports of its own candidates and if so, the details thereof ;

(b) whether the policy of taking into account the coufidential reports has been implemented for selecting Director of ICAR Goat Institute and his confidential reports from mid seventies were shown to selection board ; if not, the reasons therefor ;

(c) whether enquries against him have have been made for high mortality in sheep at IVRI and in loss of imported frozen semen at IVRI and if so, the composition of enquiring committees, their findings and dates of enquiries with the action taken so far ; and

(d) whether Government are aware of allegations of irregularities committed by him since joining Goat Institute and if so, the details of each with findings and action taken if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE : (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Confidential Reports are taken into account when candidates are departmentaly promoted. There is no practice however of considering Confidential Reports of candidates while selecting through Direct Recruitment as in direct recruitment candidates are adjudged purely no merit. This practice is followed by the Agricultrural Scientsts Recruitment Board on the pattern of the practice followed by the Union Public Service Commission while selecting all candidates includiug Directors of the Institutes.

(b) Does not arise, in view of what has been stated at (above).

(c) and (d) No, Sir.

Agriculture Growth

2077. DR. A.U. AZMI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the Sixth Plan highest priority was given to bridge the gap between actual and potential farm growth and the untapped growth reservior was to be tapped so as to be a source of optimism ;

(b) if so, what are the details of the progress made ; and

(c) what steps have been taken to become self-sufficient in foodgrains ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI (ARIF MOHAMMED KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) As a results of the special efforts made by the Centre and State Governments and the incentives given to farmers through subsidies on various agricultural inputs, foodgrains production has been going up since 1980-81, beginning of the Sixth Plan except during 1982-83 when there was a set-back to production caused by the unprecedented drought compounded by floods, cyclones, etc. The highlights of achievements are as follows :—

(i) Foodgrains production reached a record level of 133.3 million tonnes in 1981-82 as against 129.6 million tonnes in 1980-81.

(ii) Although there was a decline in total foodgrains production to 128.4 million tonnes during 1982-83 due to drought and other natural calamities, the performance during the rabi season of that year was impressive. Production of rabi foodgrains reached a record level of 58.9 million tonnes during 1982-83 as compared to 53.9 million tonnes in the previous year. Similarly, production of rabi oilseeds reached a record level of 51.3 lakh tonnes as against 50.4 lakh tonnes in 1981-82. Production of rabi pulses also went up from 71.8 lakh tonnes in 1981-82 to 76.5 lakh tonnes in 1982-83.

(iii) During 1983-84, as a results of the Production Campaigns mounted through-

out the country during the kharif and rabi seasons and National Agricultural inputs Fornight organised before each crop season, and thanks to the favourable monsoon this year, the country hopes to reap a bumper harvest. Total production of foodgrains during this year is expected to reach or even exceed the targetted level of 142 million tonnes.

(iv) The annual growth rate of foodgrians production during the first four years (1980-84) of the Sixth Plan works out to 2.65% as against 2.31% over the 13 year period (1967-80).

(c) The following measures have been taken to increase the production of foodgrains :

(i) Expansion of area under irrigation ;

(ii) Larger and efficient use of fertiliseres ;

(iii) Increased distribution of quality seeds ;

(iv) Adoption of integrated pest management ;

(v) Expansion of area underhigh yielding varieties ;

(vi) Intensification of Central Sector Schemes of Establishment of Community Nurseries of Rice and distribution of seed minikits ;

(vii) Greater emphasis on soil and water conservation measures and improved dryland farming practies ;

(iii) Transfer of technology through reorganised extension network based on Training and Visit System ;

(ix) Training of farmers and extension workers ;

(x) Intensification of research ; and

(xi) Adoption of appropriate pricing policies.

To supplement the efforts of the State Governments, various development schemes are being implemented to improve the production of cereals and pulses through the Central Sector and Centrally Sponsored Schemes.

Proposal to Build New Godowns by Food Corporatoin of India in Gujarat

2078. SHRI R.P. GAEKWAD : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether, keeping in view the increased foodgrains demand, Food Corporation of India proposes to build new godowns in Gujarat ;

(b) if so, the locations/where the proposed to godowns are likely to built ; and

(c) The total capacity of the proposed godowns as well as existing godowns ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) and (b) The Food Corporation of India propose to construct additonal godowns at Gandhidham and Godhra, besides augmenting the capacity of the existing godowns at Palanpur, Mehsana, Viramgam, Baroda and Godhra in Gujarat.

(c) The total capacity of the existing godowns, constructed and hired taken together, with the Food Corporation of India in Gujarat is 5.06 lakh tonnes. The additional capacity proposed to be built by the Food Corporation of India in Gujarat is 71,720 tonnes.

गुरु सिंह सभा को डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली में भूमि का आबंटन

2080. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में वेलफेयर एसोसिएसन के बच्चों के लिए पार्क के रूप में विकसित किए जाने के लिए आबंटित भूमि को जब गुरु सिंह सभा को सौंप दिया गया है और मन्त्रालय अपने पहले के करार से मुकर गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिफेन्स कालोनी की मूल योजना में किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई षड्यंत्र किया गया है और यदि हां, तो इसमें सम्मिलित समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं। पार्क के रूप में विकास करने के लिए प्रश्नगत भूमि का आबंटन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं किया गया। तथापि, डिफेन्स कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन और विश्व अहिंसा संघ को आबंटित भूमि के बीच की भूमि का टुकड़ा श्री गुरु सिंह सभा डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली को 6 महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप दिया गया है।

(ख) डिफेन्स कालोनी के मूल नक्शे के अनुसार, इस प्रकार से कोई भूखण्ड धार्मिक संस्थाओं के लिए उदिष्ट नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

Proposal to Import Coconut Oil

2081. SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the rising prices of coconut oil which is sold at about Rs. 30 a kilogram ;

(b) whether Government propose to import coconut oil from the Philippines, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka etc ; and

(c) the measures Government propose to take to provide relief to consumers of coconut oil which is the popular cooking medium in South India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Government is allocating imported palmolein to the Southern States which has been progressively increasing for issue to consumers through bublic distribution system at reasonable prices. This oil has been accepted by the consumers in those States.

Correcting Statement

Statement Correcting reply to USQ No. 4495. dt. 22.8.83 re, Bogus certificates Furnished by the Employee of Shri Keshoraipatan Sugar Miils Ltd.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : In the reply given in the Lok Sabha on 22nd August, 1983 to Unstarred Question No. 4495 asked by Shri Virdhi Chander Jain regarding Bogus certificates furnished by employees of Shri Keshoraipatan Sugar Mill Ltd., the information furnished, as received from the Custodian, Keshoarai-Patan Sugar Mill, who gave hls figures on the basis of the Mill's records built up and maintained by the earthwhile management, was unfortunately defective. On the Custodian's re-verification of the position, in consultation with the Revenue Authorities of the Rajasthan Government, the figures have been revised. A revised and corrected statement is placed on the Table of the Sabha.

(a) the catogory-wise number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in Shri Keshoraipatan Sugar Mill Ltd., District Bundi (Rajasthan) ;

(b) whether this mill has employed people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe against reservation made for them in pursuance of the New 20 — Point Programme ;

(a) and (b) Out of 838 employees, 63 (7.5%) belong to Scheduled Castes and 20 (3.3 %) belong to Scheduled Tribes.

The management af the Mill was taken over by the Central Government temporarily on 13.12.1978 and, after an extension the take over by three years, is due to returned to the owners/erst-while management on 13.12.1984 Recruifment was made before the take over. The present management is giving preference to S.Cs and S.Ts for apperentice training and also for jobs where such skill is not required.

12.00 hrs.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I have given a very important notice regarding question of security.

MR. SPEAKER : I have allowed Shri Satish Agarwal.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Something concerning the security of this country has appeared in the newspapers. You are very much concerned with that. We are very much concerned with this the leakages of secret documents of air force to the U.S. Government. You should kindly direct the Minister to make a statement.

MR. SPEAKER : It is under my consideration.

SHRI SATISH AGARWAL : Even the Vice Marshals are involved.

MR. SPEAKER : I will see. Let me get facts.

PROF. MADHU DANDAVATE : I have submitted certain documentary evidence. Officers of the Army of the rank of Major General, Air Vice Marshals Lt. Col., are involved. They have supplied the secret of our Defence deal with the Soviet Russia to the Amercian Government. It is a very serious matter. Like Bhindrawala matter it is a matter that effects both the sides.

MR. SPEAKER : I Will get the facts and then we will see.

PROF. MADHU DANDAVATE : Why do you not direct the Minister to make a Statement ?

MR. SPEAKER : I will direct the Minister, when it is necessary. That is what I am trying to do, I will deal with it.

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : It has appear in the press. What has been the Government/ doing so far ?

(*Interruuptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : I have given yon the documentary evidence.

MR. SPEAKER : I am as much interested as you are. Security of the country is our joint concern and for that I will get the facts and then we shall

(*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : What proof do you want ? I have submitted to you the news that has appeared in the name of correspondent Hindustan of yesterday.

MR. SPEAKER. It is not so sacrosanct. They are not going to run away.

PROF. MADHU DANDAVATE : Did you ascertain the facts of Bhindrawala already ? You expressed your right sentiments.

SHRI SATISH AGARWAL : It is a cross party barrier. You must give direction.

PROF. MADHU DANDAVATE : Even the ruling party Members contributed to the matter of Bhindrawala.

अध्यक्ष महोदय : उनको भी चिन्ता होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह चिन्ता वाला सवाल नहीं है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : He should come forward and make a statement.

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं, मैंने इन्कार नहीं किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बहुत गम्भीर मसला है–मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चिन्ता नहीं है।

Our information is that ceratin officers have been arrested.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न कीजिए। आप को आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? मुझे फैक्टस मालूम कर लेने दीजिए।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : The news appeared on the 4th of December. The Government talks of.....(*Interruptions*) They should have contradicted that it is not true.

PROF. MADHU DANDAVATE : There is a *Prima Facie* fact. (*Interruptions*) Will you please listen to one information ? The papers say that ex-Army Officers are under judicial custody.

अध्यक्ष महोदय : मैं सारा देखकर बतलाऊंगा। आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप को चिन्ता है, लेकिन हमको भी चिन्ता है.....

DR. SABRAMANIAM SWAMY : Statement must be made to-day.

अध्यक्ष महोदय : आप इसको पूरे फैक्ट्स के साथ करवाना चाहते हैं या अधूरी बात करवाना चाहते हैं ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You direct them to make the statement to-day. (*Interruptions*). Every day they make allegations. Why do you not come out ? They must statement to-day. It is a matter of national security.

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास फैक्ट्स आने दो।

SHRI CHANDRAJIT YADAV : This is a very important national sensitive issue. When notices were sent to you, at least the Defence Minister should have been present in the House to-day. It is a very important matter.

PROF. MADHU DANDAVATE : He ought to have been present in the House in a way to respect the notices of the Members.

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है। ये नोटिस आज ही मेरे पास आये हैं और मैंने आज ही एक्शन ले लिया है।

PROF. MADHU DANDAVATE : He should have been present in the House. (*Interruptions*). If you yourself take so lightly, we have nothing to say.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज ही भेजा है।

PROF. MADHU DANDAVATE : On such an urgent important matter, notices are sent to you but the Defence Minister is not present here.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज ही भेजा है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You could have called the Defence Minister on telephone and asked if it was true or false. If he says "No", You say "No" and if he says "Yes". you say "Yes".

अध्यक्ष महोदय : जरा सुनिये, मैं आपको बताऊं। मेरे ख्याल में ठीक 11 बजे से आधा सेकिंड पहले सीरियन डैलीगेशन को लेकर मैं आप के पास यहां हाउस में पहुंचा। मैं सेक्रेटरी को कह कर आया कि इसको फौरन भेजो।

That is what I am trying to do and finding oat things.

मैं एक मिनट की देरी नहीं करता। जो नेशनल इशूज हैं, उन पर हम में से कोई नहीं चाहता कि देरी हो। जहां तक सिक्योरिटी की बात है उस पर तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। अब परसों के मुतल्लिक आपने कह दिया। अब जहर तो कहीं भी हो, चाहे काली बोतल में हो, चाहे हरी बोतल में हो, चाहे छोटी बोतल में हो, जहर तो जहर ही है।

PROF. MADHU DANDAVATE : Let me point out the procedure. You might have come at about 11 O'clock in the chamber. But notices were given at 10 O'clock. Directly the copy goes to the Defence Minister. Before you got the copy, the Defence Minister must have got it.

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि टेलीफोन पर कहो, इसलिए मैंने टेलीफोन पर कहा।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You must tell them that by 5 O'clock to-day they must make a statement. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, You ask the Government to make a statement on the CIA activities in our country including that of Defence because this is part of the CIA activities.

MR. SPEAKER : Unnecessarily, why are you professor.....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : What about KGB ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : The entire activities of CIA in our Defence should be.....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Not only CIA but all foreign intelligence.

MR. SPEAKER : Whatever it is, intelligence or espionage is everything.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार): राष्ट्र के सवाल पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप

सारी बात को खुद ध्यान से देखें कि किस तरह से हवाई जहाज टूटे हैं, गिरे हैं, खरीदे गये हैं। किस तरह से अपने ये मीर जाफर काम कर रहे हैं। यह सारा आप देख लीजिए। ये जो सारे एयर फोर्स के हवाई जहाज गिरे हैं इन पर मैंने शार्ट नोटिस भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं करवा रहा हूं। मैं देख लूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी : आप कब देख लोगे ?

अध्यक्ष महोदय : हरेक चीज में टाइम लगता है। मैं कोई मशीन थोड़े ही हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : मशीन को तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, स्पीकर को सारे काम करने पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां आपकी नौकरी है, सारे ही काम करने पड़ते हैं।

Even hurry takes time. I am not a machine. I have to find out the facts and come to you.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You are not a machine but *Devta* as far as we are comcerned. Like Lord Krishna, you should be everywhere.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : This is a very serious matter. The Minister should make a statement today itself. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : अब बात हो गई है। अब इसमें बाकी क्या रह गया। हरिकेश जी इसमें से अब और क्या आप निकालना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : आप को शार्ट नोटिस दिये हुए बहुत दिन हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : हरेक चीज का टाइम होता है। There is a procedure for everything, Mr. Bagriji. I have to follow that.

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आप को इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : काहे का ?

श्री मंगल राम प्रेमी : एक हरिजन एम० पी० को कोई भी अधिकारी.....

अध्यक्ष महोदय : आप गलत बात करते हैं। जायज बात नहीं करते हैं। मैंने आप को समझा दिया और अच्छी तरह से समझा दिया था।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Not allowed.

12.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications under the Essential Commodities Act, 1955

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to lay on the table :—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commoditles Act, 1955 :—

(i) The Fertiliser (Control) Second Amendment Order, 1983 published in Notification No. G. S. R. 749 (E) in Gazette of India dated the 26th September, 1983.

(ii) G. S. R. 750 (E) published in Gazette of India dated the 26th September, 1983, regarding fixation of prices of Anhydrous Ammonia under clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957.

(iii) G.S.R. 751 (E) published in Gazette of India dated the 27th September, 1983 regarding fixation of prices of area and Diammonium Phosphate stored for mere than two years under 'Special Rebate Scheme' under sub-clause (2) of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1957.

[Placed in Library. *See* No. LT 7132/83]

(2) A copy of Notification No, G.S.R. 711 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 19th September, 1983 specifying the Fertiliser (Control) Order, 1957 as special Order for purpose of summary trial under section 12A of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library. *See* No. LT 7133/83)

Notification under Requistioning and Acquisition of Immovable Property Act, Punjab Municipal Corporation Services (Recuritment and conditions of services) (First Amendment) Rules, etc. Audited Accounts of Delhi Urban Act. Commission New Delhi and Building Bye-laws of Union Territory of Delhi, 1983 etc.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : I beg to lay on the table :—

(1) A copy of Notification No. S. O. 3571 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 17th September, 1983 directing that the powers exercisable by the Central Goverement under section 6, 7, 8, (b), 8 (c), 8 (d), 10 and 13 of the Requistioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 shall also be exercisable by Secretary/Additional Secretary/Special Secretary to the Government of India in the administrative Ministry/Department for whose use the property in question in requisitioned, under sub-section (2) of section 17 of the said Act.

(Placed in Library. *See* No. LT—7134/83)

(2) A copy of the Punjab Municipal Corporation Services, (Recruitment and Conditions of Services) (First Amendment) Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 38/P, A. 42/76/S, 71/Amd. (2)/83 in Punjab Gazette dated the 8th April, 1983 under sub-section (2) of section 397 of the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 read with clause (c) (iv) of the Proclamationdated the 26th October, 1983 issued by the President in relation to the State of Punjab.

[Placed in Library. *See* No. LT—7135/83]

(3) A copy of the Punjab Water Supply and Sewerage Board (Conduct of Business) (First Amendment) Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 24/P. A. 28/76/S. 71/Amd. (1)/83 in Punjab Gazette dated the 8th March, 1983 under sub-section (2) of section 71 of the Punjab water supply and Sewerage Board Act, 1976 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 6th October, 1983 issued by the President in relation to the State of Punjab.

(4) A copy of the Punjab Water Supply and Sewerage Board (Conditions of Service of Directors) (First Amendment) Rules, 1983 (Hindi and English versions) Published in Notification No. G. S. R. 25/P,A. 28/76/S. 71/Amd. (1)/83 in Punjab Gazette dated the 8th March, 1983 together with Corrigendum thereto under sub-section (3) of section 71 of the Punjab Wates Supply and Sewerage Board Act, 1976 readwith clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 6th October, 1983 issued by the President in relation to the State of Punjab.

[Placed in Library. *See* No. LT—7136/83]

(5) (i) A copy of the Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 1982-83 under sub-section (4) of section 20 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973.

(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Government on the Accounts of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 1982-83.

[Placed in Library. *See* No. LT—7137/83]

(6) A copy of the Building Bye-laws for Union Territory of Delhi, 1983, under jurisdiction of Delhi Development Authority (Hindi and English versions) published in Notification No. S. O. 140 in Delhi Gazette dated the 23rd June, 1983 under seation 58 of Delhi Development Act, 1957.

(7) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the notification mentioned at (6) above.

[Placed in Library. *See* No. LT 7138/83]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनका मैं क्या जवाब दूं । आप पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं ।

I have not allowed a single word.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए । सदस्यों की बात यहां उठाई जाती है लेकिन

मंगल राम जी जो सवाल उठाना चाहते हैं उसके लिए मैंने स्वयं लिखा है। ये जानते हैं कि मैंने लिखा है, लेकिन वह कार्यक्षेत्र हमारा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनाधिकार चेष्टा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : तो क्या कार्यवाही नहीं होती ?

अध्यक्ष महोदय : यह वहां की सरकार जाने। जितना हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूं, उतना मैंने कर दिया है।

श्री मंगल राम प्रेमी : आपकी चिट्ठी भेजने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पदोन्नत किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह चीफ मिनिस्टर जाने, वहां की सरकार जाने। मैं सरकार को डिसमिस तो नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

You do not know what is your responsibility ; you do not know what this House can do.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप हमको हरिजन नहीं मानते हैं ? क्या आप हमको सबके समान मानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको बराबर मानता हूं। जो आदमी मजहब के नाम पर या दूसरे ढंग से इन्सान-इन्सान में फर्क समझता है, वह ज़लील किस्म का आदमी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जहां पर किसी जो जलील किया जाय, नीच कहा जा रहा है, उसके लिए क्या होगा ? (व्यवधान)

अयध्यक्ष महोदय : मेरी बात आप सुनते नहीं हैं, अपनी बात करते रहते हैं। बिना वजह हाउस का समय ले रहे हैं। इनकी मान हानि हुई तो कह सकते हैं, लेकिन जब एक चीज इसके साथ संबंधित नहीं है, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इनकी मानहानि का सवाल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कैसे कर सकता हूं, मुझे बताइए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए। जब तक सुबूत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता।

You are uunecessarily agitated : What can I do about it ?

अध्यक्ष महोदय : यहां सारा कुछ कर दिया गया है। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं भेजी है। अगर प्रिवलेज कमेटी कर सकती है तो ठीक है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या यह फिजूल वक्त जाया हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

(व्यवधान)

Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (Seventh Amendment) Regulation. 1983

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : I beg to lay on the Table a copy of the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (Seventh Amendment) Regulations, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. 26/F. No. 39-2/82-EP (Pt) in Gazette of India dated the 5th November, 1983 under sub-section (5) of section 45 of the Food Corporation Act, 1964.

[Placed in Library. *See* No. LT 7139/83]

Annual Report and Audited Accounts of Bihar State Agro Industries Development Corporation Limited, Patna etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : Sir, on behalf of Shri Arif Mohd. Khan. I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under

section 619 A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the Bihar State Agro Industries Development Corporation Limited, Patna, for the year 1976-77.

(ii) Annual Report of the Bihar State Agro Industries Development Corporation Limited Patna, for the year 1976-77 along with Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. LT—7140/83]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, हम नियमों के अन्तर्गत खड़े रहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ उंगली नहीं उठाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी तरफ उंगली कैसे उठा सकता हू, आप इतने भले आदमी हैं ।

श्री राम लाल राही : मैं दो बातें कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय में ?

श्री राम लाल राही : एक वीकली में छपा है, वाइस आफ दि. वीक जो दिल्ली में छपता है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है ।

श्री राम लाल राही : इसमें हरिजन अधिकारियों के साथ, हरिजन पुलिस कर्मचारियों के साथ रेलवे पुलिस फोर्स..... ।

MR. SPEAKER : Not like this ; this is irrelevant. Not allowed.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं । विधि के अनुसार हुआ तो मैं एडमिट कर सकता हूं । इस तरीके से कुछ नहीं कर सकता ।

श्रीराम लाल राही: दूसरी बात मेरी यह है कि आप ने देखा कि शाहजहांपुर एटा जिला, उत्तर प्रदेश में हजारों लोग नए किस्म के बुखार से, बीमारी से मर रहे हैं । सरकार स्वास्थ मन्त्रालय इन बीमारियों का पता लगाने, रोकने में असफल है । इस पर रिसर्च होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं । स्टेट गवर्नमेंन्ट देखेगी ।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : State Government. No. Not allowed.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Last Thursday you said you were looking into the facts of the case when I raised the matter regarding Shri Dhirendra Brahmachari.

MR. SPEAKER : It is under investigation. Nothing has come up.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Is it under investigation by you ?

MR. SPEAKER : By the authority. Not allowed. I cannot interfere in any investigation.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Government can make a statement. He is not a special citizen of India.

MR. SPEAKER : No. Not allowed. Irrelevant.

Betwa River Board (Amendment) Rules 1980 Annual Report and Audited Accounts etc. of the Rational Water Development Agency, New Delhi and the Central Board of Irrigation and Power, New Delhi

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Betwa River Board (Amendment) Rules, 1980 (Hindi and English versions) publised in Notification No. G. S. R. 719 in Gazette of India dated the 5th July, 1980 under section 24 of the Betwa River Board Act, 1976 ;

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the notification mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-7141/83]

(3) (i) A copy of Annual Report (Hindi and English versions) of the National water Development Agency, New Delhi, for the year 1982-83 alongwith Audited Accounts.

(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Govrenment on the working of the National Water Development Agency, New Delhi, for the year 1982-83.

[Placed in Library. *See* No. LT-7142/83]

(4) A copy of Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Board of Irrigation and Power, New Delhi, for the year 1982-83 along with Audited Accounts.

[Placed in Library. *See* No. LT-7143/83]

Annual Report and Audited Accounts of the Central Warehousing Corporation, New Delhi and Review by the Government

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M. S. SANJEEVI RAO) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 1982-83 along with Audited Accounts under sub-section (11) of section 31 of the Warehousing Corporations Act 1960.

(2) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the years 1982-83.

[Placed in Library. *See* No. LT-7144/83]

12.13 hrs.

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Reports of Study Tours

SHRI A. C. DAS (Jaipur) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports (Hindi and English versions) of the Study Tours of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :—

(i) Report of the Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Srinagar, Chandigarh, Nangal and Simla during October, 1983.

(ii) Report of the Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Calcurta Kharagpur, Darjeeling and and Gangtok during October, 1983.

12.14 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of rule III of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Indian Railways (Amendment) Bill, 1983, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st December, 1983."

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 1983

As Passed by Rajya Sabha.

SECRETARY : Sir, I lay on the Table of the House the Indian Railways (Amendment) Bill, 1983, as passed by Rajya Sabha.

STATEMENT RE. REPORTED THREAT TO HINDUS IN PUNJAB BY SHRI JARNAIL SINGH BHINDRANWALE, ON DECEMBER 1, 1983 AT AMRITSAR

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : Sir, On 2nd Deecmber, 1983, the Hon'ble Chair and the members of this August House had expressed deep concern over the reported statement made by Shri Jarnail Singh Bhindranwale on 1st December, 1983 containing serious threat to one community.

2. Hon'ble Members are aware that Shri Bhindranwale has been making provocative and inflammatory statements from the sanctuary of Guru Nanak Niwas. It has been reported that on lst December, 1983 Shri Bhindranwale made a statement that he wanted to make it clear to Hindus, especially in Punjab, that if Sikhs living in any other part of the country were uprooted, the Hindus should also be ready to face death. Such a threat naturally caeated consternation in the country and has been unanimously condemned by Hon'ble Members. It is unfortunate that despite this Shri Bhindranwale has chosen to justify his objectionable remarks through another statement.

3. Shri Bhindranwale has referred to the recent incident at Churu in this connection. According to the State Government a small portion of one of the doors of a building under construction had been damaged. The Police is investigating the matter. It has been further reported by the State Government that there is no organisation as Jai Hindu Sangh in the State. Such incidents and attempts at mischief deserve unequivocal condemnation.

4. It is most unfortunate and deplorable that this incident should have been made a pretext for ventilating communal hatred and inciting mass murder and violence by a person who has tried to seek protection for himself within the sanctuary of a holy shirine in the hope that he can thereby escape all consequences of his acts. The Government will take all necessary steps to deal with crime and investigation of crime wherever and by whomsoever it may be committted.

5. According to information received trom the Government of Punjab cases have already been registered against Shri Bhindranwale.

6. Government have consistently maintained that all citizens of India irreospective of caste, community or religion will have full and equal protection under the law and all opporunities of participation in civic life in any part of the country. Government condemn and feel equally pained at any attempt to harass or disturb Sikh, Hindu or any other community.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपके स्टेटमेंन्ट के बाद पंजाब में लार्ड जगन्नाथ का मन्दिर जलाया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में दिल्ली के पुलिस अफसरों के बारे में कहा गया है, कि उनको देख लिया जायेगा। (व्यवधान)

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : It is a very unsatisfactory statement. Did you expect this kind of statement ? It is a very unexpected and unsatisfactory statement.

श्री मनी राम बागड़ी : जो मन्दिर या गुरुद्वारे को जलाता है वह देश को जलाता है। जो इस किस्म के लोग हैं उनकी कौमियत को खत्म कर दिया जाए, उनकी राष्ट्रीयता को खत्म कर दिया जाए। भिंडरावाले की राष्ट्रीयता को खत्म किया जाना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक तरफ तो गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी मैम्बर कहते हैं कि वहां कोई मुजरिम नहीं है और दूसरी तरफ आप कहते हैं, वहां मुजरिम है और उसका नाम है भिंडरावाला जो कत्लेआम करवाना चाहता है। जो सिख हिन्दुओं के मन्दिर जलाता है वह गुरुद्वारे को भी जलाता है और जो हिन्दू गुरुद्वारे को जलाता है वह मन्दिर को भी जलाता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस स्टेटमेंट से कोई बात जाहिर नहीं होती है। सरकार क्या कर रही है ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Are you

happy with the statement, Sir ? The Home Minister should do something. (*Interruptions*) We wanted action from the Government.

श्री मनी राम बागड़ी : जगन्नाथ मन्दिर जला दिया ।

SHRI STAYASADHAN CHAKRABORTY : You should ask the Government to do something. Are you happy with the statement ?

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South) : You had directed the Government to take action. The entire House had spoken with one voice and directed them to take action. But the Home Minister's statement is most unsatisfactory.

अध्यक्ष महोदय : मेरी डायरेक्शन का प्रश्न नहीं आता । मैं, आपकी जो बात होती है उसको कहने का माध्यम हूं । जो हाउस ने चाहा, जो हाउस की मंशा थी, वही मैंने किया । जब सारा हाउस इकट्ठा था और सभी ने कहा था तभी मैंने कहा था । गवर्नमेंट आगे जो करना चाहे करे । एक बात और । हाउस ने यह बात समझ कर कही थी कि कम्युनलिज्म का जो जहर है यह कोई करे, हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान कोई करे वह एक जघन्य अपराध करता है । उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है । इसीलिए कहा था कि जहर कहीं भी हो, किसी बोतल में हो बराबर होता है चाहे वह बोतल छोटी हो या बड़ी हो । आप नोटिस दे दीजिए और मैं बात कर लेता हूं ।

SHRI BHIKU RAM JAIN (Chandni Chowk) ; Sir, I have to draw your attention to anotther statement of Mr. Bhindranwale in connection with what happened in Delhi the day befoce yesterday. I only wish to repeat those words.

अध्यक्ष महोदय : आपने सुने और मैंने उसको पढ़ लिया ।

SHRI BHIKU RAM JAIN : It has created a great stir in Delhi and the peoble of Delhi are feeling very unsafe, with your permission I would say only one thing : a challenge has been given even to the police people and I would want that this should not remain. The police people are feeling very insecure.

(*Interruptions*)

श्री मनी राम बागड़ी : हिन्दू हो सिख, हो मुसलमान हो जो भी राष्ट्र के खिलाफ बयान देता है उसकी राष्ट्रीयता को खत्म कर दिया जाना चाहिये और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए । ऐसे कौमी गद्दारों को कैसे बाहर रहने दिया जा सकता है फिर चाहे वह हिन्दू हो, सिख हो या मुसलमान या ईसाई हो ।

SHRI RATANSINH RAJDA : The times are extraordinary demanding extraordinary measures from the Home Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Short of Emergency.

SHRI RATANSINH RAJDA : Short of Emergency.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Government should deal sternly with all communal elements. But what is the action taken. And what do you propose to take ? There is no indication about it. You are silent about the future course of action.

अध्यक्ष महोदय : फिरकापरस्ती किसी की भी हो बुरी है। यह तो नालायकी है । कोई भला आदमी, धार्मिक आदमी न मंदिर गिराएगा, न गुरुद्वारा गिराएगा । भगवान की तो बेईज्जती होती नहीं, ऐसा आदमी अपना गिरापन दिखाता है । ऐसे काम करने वालों के खिलाफ जो भी सख्त कारंवाई की जाए मेरा खयाल है कि आप सब उसके हक में हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : वक्तव्य ही देंगे या कुछ करेंगे भी ?

श्री मनी राम बागड़ी : रंगा जी से पूछो । आप चुप क्यों बैठे हो, रंगा जी ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी आदमी किसी को बुरा नहीं कह सकता है ।

Communalist is a communalist. He has got no religion... (*Interruptions*) They are the worst enemies of the nation,

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY : All communalists should be dealt with firmly.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : The Government is repeating only what has appeared in the newspapers. what is the use ? The House very much exercised over this matter. You ask the Government to make a statement and the Home Minister comes out ony with what has appeared in the Press. The government has not said what course of action they are going to take. That they have nat indicated. This is very serious.

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : गृह मंत्री का स्टेटमेंट कोई जानदार नहीं आया, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री भीकू राम जैन : भिंडरावाले ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका उसने स्पष्टीकरण नहीं किया और आज फिर उसका स्टेटमेंट आ गया दिल्ली में हुई घटना के बारे में ।...(व्यवधान)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : On the one side the Members ask for action and on they other side, they do nothing. They are playing both sides.

AN HON. MEMBER ; You people have some personal axe to grind in this.

SHRI BHIKU RAM JAIN : I am very much pained about what has been said by Sant Bhindranwale about the recent incidents in Gurudwara Sisganj. He has unnecessarily threatened those involved in the incident and has said that they will not be pardoned. He has also said that even the Police personnel will not be excused and that the Sikhs never excuse anybody for the sacrilege of the Gurudwaras. This has posed a threat to Delhi and now even the Police is unsafe. (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Sir, you asked, 'What action you have taken ?' and he has come back with nothing. ...(*Interruptions*) We have been used as pawns in the Punjab game.

श्री मनी राम बागड़ी : पंजाब के अन्दर जगन्नाथ मंदिर जलाया गया यह ऐक्शन हुआ ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : They want to use the Opposition as the pawns in the political game. Peopld want action on the part of the Government. We want action, but we are abused.

SHRI RATANSINH RAJDA : The House has expressed its sentiments. But they sit idle. It is an affront to the entire House. This statement of inaction is an affront to the entire House....(*Interruptions*)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : क्या गृह मंत्री जी कोई ऐसा कानून लाना चाहते है कि जो मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर जलाने आदि ऐसा जघन्य अपराध करते है उनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके ? आप इसका जवाब दिला दीजिए । आपने कहा था कि सोमवार को जवाब दिलायेंगे, लेकिन जो जवाब गृह मंत्री जी ने दिया है सदन उससे संतुष्ट नहीं है किसी तरीके से । इसलिए उन बातों को स्पष्ट करें जो सदन जानना चाहता है ।

SHRI BHIKU RAM JAIN : Sir, Delhi is the capital of India. For the safety of the/people of the capital, it is necessary the Government must act firmly so that people can move about freely.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur) : The hon Minister has come out with a statement and the whole House, I think will dgree with me that euerrone's sentiments were that the Government must take firm and definite steps towards that. Also everyone is agreed that these anti-social elements should be firmly dealt with. Sant Bhindranwale has been associated with the Akali Dal. I want an assurance from the Government and the hon. Opposition Parties must act now. It is not enough that we condemn them. We have been condemning these things for the last three years. We should take action against these people. First let rhese people who sit next to Akali Dal say that they will not support them anymore.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उसको गिरफ्तार करना चाहिए । That is the only solution.

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : आप होम मिनिस्टर से कहलवा दें...(व्यवधान) अगर कोई पागल

चलने के काबिल नहीं है (व्यवधान) आज पंजाब में जोदिमाग गुरुद्वारा जलाता है तो मन्दिर पहले जलता है, मस्जिद पहले जलती है। सब एक साथ जलते हैं। इस एक्शन के रिएक्शन बड़े खतरनाक होते हैं। इससे देश डूबेगा, आग लगेगी। फिर आप कहेंगे कि बुझाओ तो कैसे बुझेगी ? अब वक्त है, वक्त से पहले बचाओ। यह बचाने की बात क्यों नहीं करते ? इनसे कहिये कि ये विश्वास दिलायें कि यह बात नहीं होगी।... (व्यवधान) सरकार है क्या ? सरकार कोई प्रेस रिपोर्टर तो नहीं है ?

(व्यवधान)

SHRI RATANSINH RAJDA : Sir, the Home Minister must take action beyond what has been taken.

श्री चन्द्रजीत यादव : जो मनीराम जी कह रहे हैं, वह स्पष्ट तो कराइये।

श्री मनी राम बागड़ी : आप इसको बन्द करवाइये। एक मीटिंग बुलाइये, मीटिंग बुलाकर कुछ कीजिये। (व्यवधान)

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Sir, they are worried about their votes. (*Interruptions*) Shri Bhindranwale should be arrested. (*Interruptions*) He is your own creation. (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER (Delhi Sadar) : You gave an undertaking that you won't align with the Akalis. Now you are the people sitting in Vijayawada aligning with this group who is creating all this.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : I am speaking about Shri Bhindranwale only (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Now, all of you please sit down. (*Interruptions*)

श्री जगदीश टाइटलर : बैठ जाइए।

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : Mr. Speaker, Sir, you will kindly agree with us that the entire House expressed their indignation and anger and anguish was expressed on 2nd December in this very House from all sections of the House including your goodself also. We were expecting some storn action again and again than what has already been taken by the Government during the last three days. It is unfortunated that Government seems to have surrendered before Shri Bhindranwale. I think no action has been taken. This sort of statement was not expected in the House. Indignation was expressed by all sections of the House over the reported statement by Shri Bhindranwale. He has only come out with a cyclostyled statement which does not meet the demands. You also directed the Government to make a statement on what specific steps have been taken by Government. (*Interruptions*)

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY (Puri) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Member, Shri Jain was on his legs. Please allow him to complete it.

SHRI BHIKU RAM JAIN : I only want to point out. (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : What action has he taken ? He has come out with a pious statement before the House. We have been used to meet their own political ends. (*Interruptions*)

SHRI BHIKU RAM JAIN : Mr. Speaker, Sir, let me complete what I said about Delhi.

आज मैं तीन प्वाइन्ट्स आपसे कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइन्ट नहीं है।

This is not a debate. This is a question about the sentiments of the House.

श्री भीकू राम जैन : सारी दिल्ली में बड़ी परेशानी है।

MR. SPEAKER ; It does not matter what he has said. We have all read about it.

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर बैठे हैं। उन्होंने सारे हाउस के सेन्टीमेंट्स को उस दिन भी देख लिया था और आज भी देख लिया है। सारी बात उनके सामने है। वह देखेंगे और अपने आप कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कृपया उनको डायरेक्ट करें।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : यह पार्लियामेन्ट

हालत है, उसको देख कर सारी जनता यह समझती है कि यह जिन्दा सरकार नहीं है, यह मुर्दा सरकार है—यह मुर्दा लाश है। (व्यवधान) यह मरी हुई लाश है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। बात करेंगे।

(व्यवधान)

SHRI BHIKU RAM JAIN : Probably the Opposition wants Bhindranwale to be arrested from within the gurudwara. Let them say so.

(Interruptions)

SHRI SATISH AGARWAL : Sir, the entire Opposition had expressed its anguish and anger over the statement made by Bhindranwale and your goodself also directed the Government to come before the House with a statement on the action taken. Action should have been taken. No action has been taken. The Home Minister has made a routine cyclostyled statement. Sir, there is President's rule in Punjab and it is the direct reponsibility of the Central Government. This statement does not meet our requirements and your expectations also. *(Interruptions)*

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, is it possible that the Prime Minister should come and make a statement since... *(Interruptions* Will you request the Prime Minister to make a statement ? The entire Opposition demands that the Prime Minister should make a statement in this connection tomorrow. We want the House to be informed unequically and categorically the policy of the Government.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्राईम मिनिस्टर को आ कर इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : I am representing the Government. It is not necessary for her to intervene in this matter.

(Interruptions)

SHRI RATANSINH RAJDA : What are you doing ? What action have you taken ? *(Interruptions)*

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप क्या कर रहे हैं ? सारे सदन की मांग है कि भिंडरावाले को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

SHRI RAJESH PILOT : Let the Opposition parties pass a resolution to this effect.

(Interruptions)

SOME HON. MEMBERS : No resolution. We want action.

SHRI RATANSINH RAJDA : Sir, strong sentiments of the entire House have been expressed. Government has not taken any action. This attitude of inaction on the past of the Government is an affront to the entire House because strong sentiments were expressed by the entire House. *(Interruptions)* Today the country needs leaders like Sardar Patel. Instead Lilliputian Home Minister is there doing nothing. These are extra-ordinary times demanding extra ordinary measures and Government is not taking any action. When the entire House speaks with one voice what prevents the Government from taking action ? What is the mystery ? I would like to ask the Home Minister what is the mystery. Will he give an explanation to the House ? This is my submission.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, are you satisfied ? Are you yourself satisfied ?

MR. SPEAKER : It is for the House, not me.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : There are strong sentiments of the House. Is it not an insult to the House ? Our strong reaction has not been taken note of.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : विरोधी पार्टी की ओर से जो आवाज उठायी जा रही है भिंडरांवाले के विरोध में, मैं समझता हूं अब तो यह स्थिति बन गई है कि इनके विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि सीसगंज गुरुद्वारे में जब पुलिस एन्टर हो सकती है तो वहां भी ठोस कदम उठाना चाहिए और हमें उसमें पूरी तरह से अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन करना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए इस मुल्क में इस हाउस के जरिए कि हम इस राय के हैं कि गुरुद्वारों में पुलिस जानी चाहिए... (व्यवधान)...This impression should not go.

कि गुरुद्वारे में पुलिस जानी चाहिए । (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप क्या बात करते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : It is a statement of helplessness.

भिन्डरांवाले को और दूसरे केस को साथ में न मिलाया जाय । मैंने इस बात पर कहा जो जैन साहब ने कहा कि सीसगंज गुरुद्वारे में चूंकि पुलिस गई इसलिए वहां भी जानी चाहिए ।

मैं गृह मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं कि इन्होंने आज क्या बताया कि केस रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं उनके खिलाफ । यह हम दो साल से सुन रहे हैं । दो साल से केस रजिस्टर्ड हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । हाउस जानना चाहता है कि दो साल से जब केस रजिस्टर्ड है तो आप कोई ऐक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं ? न तो वारंट इश्यू होता है, न गिरफ्तारी होती है, न मुकदमा चलता है । तो आप ने नई बात क्या कही है ? एक आदमी किसी घर में या गुरुद्वारे में बैठ कर इंस्टीगेशन करता रहे और आप ने कह दिया कि केस रजिस्टर्ड कर दिया है...(व्यवधान)... क्या आपने गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को कोई नोटिस दिया है कि उन्हें हैंड ओवर किया जाय ?... (व्यवधान)...

SHRI P. C. SETHI : I would like to make it clear that as far as the Sisganj Gurdwara is concerned the Police has not entered there ; they had gone to the DGPC Office which is situated in an adjacent building.

(Interruptions)

SHRI JAGDISH TYTLER : Sir, Bhindranwalle is getting protection from the Akalis and these excited friends are helping the Akalis who are giving protection to Bhindranwalle. What kind of people you are ? You are helping the Akalis who are giving protection to Bhindranwalle.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : चाहे मन्दिर हो, चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, अगर कोई अपराधी वहां पर सुरक्षा लेता हो तो उसे जरूर एन्टर करना चाहिए । (व्यवधान)

SHRI CHANDRAJIT YADAV : They must find a political solution. Only political soultion is the solution for this, it is not merely a law and order problem. Let them take a political solution.

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल सालव्यूशन क्या है ?...(व्यवधान)...

SHRI JAGDISH TYTLER : Mr. Bhindranwale is seeking protection from the Akalis. He is now sitting in the Akalis Office.

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में अपराधी को पकड़ने के लिए सहमत नहीं है, तो वह उसका अपना विचार हो सकता है । लेकिन हम सबका विचार है कि चाहे मन्दिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा या गिरजाघर—यदि अपराधी कहीं भी शरण लेता है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए । इसी संदर्भ में आपने कहा है कि हम आप लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं । हम आप लोगों की सारी की सारी बातें सम्बन्धित व्यक्ति को पहुंचाते रहते हैं । हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप गृह मन्त्री जी से कहें और भिंडरावाले के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी कल इस सदन में आकर वक्तव्य दें और तुरन्त भडरावाले को गिरफ्तार करें । इस हाऊस में आज उनकी घोषणा करें ।...(व्यवधान)

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is your responsibility. We are not running the Government. You are running the Government and it is your responsibility.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां से ?

श्री मनी राम बागड़ी : जिम्मेदारी आपकी है, कैसे और कहां गिरफ्तार करें । यह विरोध पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है । आप उसको पकड़िए ।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पहले प्रधान मन्त्री कल वक्तव्य दें और दूसरी बात

यह है कि तुरन्त भिंडरांवाले को गिरफ्तार करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी सहमति है, मेरी सहमति इसमें क्या है। मैंने तो आपकी बात बता दी है। कल भी बता दी और आज भी बता दी।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि 35 साल की आजादी के बाद भी मैं देख रहा हूं कि देश की व्यवस्था को चलाने का सिस्टम कैसे और क्या है। जब आजादी मिली तो हरिजनों को मदद करने का बहाना किया गया। उसके बाद जब देखा कि जनता व हरिजन खिलाफ जा रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। जब उसमें भी सरकार असफल रही तो आज क्या हो रहा है कि देश के चारों तरफ साम्प्रदायिकता फैलाने का कार्य हो रहा है। सवाल भिंडरांवाले को बन्द करने का नहीं है, सवाल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का है। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भिंडरांवाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। सरकार उसको संरक्षण दे रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे, तो काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ जितने जोर से सारे हाउस में कहा, होम मिनिस्टर साहब शायद परसों नहीं थे, वे आज तो आपके सामने बैठे हुए हैं। सारी बात बता दी है। सवाल सिक्योरिटी का है, उसमें सारे हाउस ने एक ही बात कही है कि देश की सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की अपनी एन्टीटी का सवाल है, भाई-चारे का सवाल है। इसमें भी हाउस की दो राय नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं भी किसी रूप में भी किसी प्रकार से भी, किसी मजहब से, किसी रंगभेद से कुछ करने वाला आदमी हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह आप की अभिव्यक्ति है, जैसा कि आपने बताया है। एक काम करना है, किस प्रकार से करना है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसके मुताल्लिक बैठ कर एक मीटिंग बुला लें और आप सब ग्रुप लीडरों से अलग बात कर लें और बात करके फिर विचार कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो हाउस चलाना है, डिसकशन के लिए मैं तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : क्या फायदा है इस हाउस को चलाने का ?

अध्यक्ष महोदय : हाउस अगर नहीं चलता तो यह अभिव्यक्ति कैसे होती, यह संसद कैसे बनती, आप सबका एक मत कैसे होता ? इन सारी बातों का असर पड़ता है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I seek a clarification, Mr. Speaker, Sir. Last time on Friday, the House was completely unanimous and then you expressed it. And you, in fact, asked : Come back and report what action you have taken. You go through the records, it is there. Now, his Statement is that of helplessness. Don't you think it is morally right either the Home Minister should be able to take action or he should come and tender his resignation if he cannot do it ? How can you have the whole House telling him something and then he comes and says no, nothing is going to be done. Just see what is his moral position ? What is the meaning of this House ? Or if you have got cases against Mr. Bhinderanwale and if you cannot prosecute him, withdraw the cases and treat him as a national monument, who cannot be touched. Take one of these positions.

The whole House, with the Opposition united with the Government, was complaining about that with one voice and you said : To back and report what action you

have taken. And the Home Minister comes back with no action taken. This means either he should resign or he should say that I will not accept what the House says. He cannot function in this vacuum . There is a vacuum.

(*Interruptions*)

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur) : Of course, the House was unanimous and spoke with one voice, but he was not given any suggestion,

(*Interruptions*)

SHRI BHIKU RAM JAIN : Sir, I would like to quote what an Hon. Member referred in his statement on 2nd of September. He said that the Government should not enter the Gurudwaras. Then it was said that the Governmen was ineffective to take action. But I ask what is your suggestions. Now, you are also telling that the Government by its inaction is taking political advantage.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : I did not say that. I said that he should be arrested without taking such an action. (*Interruptions*) Just saying that does not mean that you should not take any action. Let the Home Minister deny it. I said the impression should not go that you are not solving the problem-without entering the Gurudwaras ; you enter one Gurudwara and take another action. I did not say that. I said cases have been registerted against him and action must be taken. A person who is making inflammatory statements...

AN HON. MEMBER : How ?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : How ? Let the Government come out. (*Interruptions*) Has he asked the management of the Gurudwara ? Guru Nank Niwas is not the Golden Temple. Now, it is for them to decide how they take action. It is for them to decide. Let the Government fuoction how will they take action. It is not our job to tell them how to take action. What for are they sitting there ?

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : If they are running the Government they should gnd out the way. The entire House said they should take action.

(*Interruptions*)

In the present political system there is no other body which is more important than the Lok sabha. The entire Parliament says one thing and the Government does not want to obey that.

SHRI RAJESH PILOT : Mr. Speaker, Sir, none of us is against firm action. We are supporting firm action. But what is their connection, what is their function ? In democracy what is their function ?

(*Interruptions*)

SHRI HARIKESH BAHADUR : It is the incompetence of the Government that the Government does not want to take any action and this Statement of the Home Minister is a statement of inaction.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I say either they should take a decisive action or they should resign. They cannot do both.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Let the Prime Minister clarify the situation. You can direct the Government, at least the Prime Minister should come and make a statement.

(*Interruptions*)

SHRI RAJESH PILOT : Sir, they are also elected Members of the Lok Sabha. But what we see is that they come out with different version in Amritsar and something else in Praliament. They take a different stand in Srinagar, they discuss something else with Mrs. Gandhi. They go and join them in Vijaywada.

(*Interruptions*)

श्री मनी राम बागड़ी : प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार फेल हो गई है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, परसों की बात कुछ राष्ट्र के हित की बात थी। उससे राष्ट्र की जनता का मन कुछ टिका था। मैं एक सवाल आपसे पूछना चहता हूं—हम लोगों को कहते हैं कि बहादुर बनो, विदेशों का मुकाबला करो। लेकिन माननीय सदस्य कहता है—मैं दिल्ली आते हुए डरता हूं, ऐसे में यह देश विदेश का क्या मुकाबला करेगा। क्या नाम है उसका—

भिंडरा—एक मुल्जिम है और एक मुलाजिम है, दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष जी कोई रास्ता निकाला जाए। आज कितने ही ऐसे सिख हैं जो दूसरी स्टेट्स में हैं, डरे हुए हैं, उनके दिलों में डर बैठा हुआ है। अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर साहब कोई रास्ता निकालो। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है बल्कि राष्ट्र के सब लोगों के दिलों से डर निकालना हमारा काम है। हम जब एक बदमाश का मुकाबला नहीं कर सकते तो विदेशी हुकूमत का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। जिस देश में जयचन्द और मीर जाफर जैसे व्यक्ति हों, वह देश पाकिस्तान का या अमेरिका का कैसे मुकाबला कर सकेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी, मजबूती से काम करें और बात को आगे नहीं बढ़ने दें।

एक अन्याय के साथ दूसरा अन्याय होता है। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि दस मन्दिर जल गये या एक गुरुद्वारा जल गया। जब एक गुरुद्वारा जलेगा तो दस मन्दिर भी जलेंगे और जब कोई मन्दिर जलाता है तो वह पहले गुरुद्वारा जलाता है, जब कोई गुरुद्वारा जलाता है तो वह मन्दिर पहले जलाता है। दोनों ही बदमाश है। उन दोनों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं हैं। ये दोनों ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्म के सामने सब लोग समान हैं। लेकिन कुछ लोग धर्म का नाम लेकर कुकर्म करते हैं। वे कुकर्मी हैं। इन दोनों ही कुकर्मियों को आप पकड़ो। इस काम को तो आप करो। (व्यवधान) सेठी जी को भी डर लगता है।

(व्यवधान)

श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला (संगरूर) : स्पीकर साहब, आपके जरिये मेरी दरख्वास्त सारे हाऊस से यह है कि नानक निवास या कोई और जगह गुरुद्वारे में है। उनका कस्टोडियन प्रेजीडेंट, एस० जी० पी० सी० या अकाली दल का प्रेजीडेंट लोंगोवाल है। उनकी मर्जी के बगैर वहां कोई नहीं ठहर सकता है।

अभी कल परसों एक बयान में अकाली दल के प्रेजीडेंट लोंगोवाल ने अफसोस जाहिर किया था कि यह गलत बात हुई है। मैं अपने अपोजिशन के साथियों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने साथी अकालियों से कहें...

(व्यवधान)

स्पीकर साहब, मैं होम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि इनको कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए और प्रेजीडेंट, एस० जी० पी० सी० और अकाली दल के प्रेजीडेंट को कहना चाहिए कि वे हर किस्म के आदमी को वहां ठहरने न दें। अपोजिशन वालों को भी कहना चाहिए। वे आपके साथी होते हैं। उनसे कहो कि इनको बाहर निकालो।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सरकार किस लिए है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएंगे तो काम आगे चलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, कह दिया है। Don't record'.

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। बिना बात पर रेक्रिमिनेशन हो रहा है, अननेसेसरी कम्पटीशन कर रहे हैं। It is not a healthy No. I don't like it. Mr. Tytler, don't get agitated. Please sit down. I don't want this.

(*Interruptions*)**

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए। Don't record without my permission whatever these gentlemen say.

(*Interruptions*)**

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है यह, बैठिए। बैठ जाइए।

देखिए कंसेसन इस बात पर है कि देश में कानून का राज रहे, सबको संरक्षण मिले।

** Not recorded.

कोई बिला लिहाज मजहबो मिल्लत के, बिना रंगभेद के सब बराबर हैं। सबको बराबर अधिकार है। चाहे सिक्ख, हिन्दू, मुसलमान हो या कुछ और हो, सभी को बराबर अधिकार है। रत्तीभर भी फर्क नहीं है। जो फर्क करने वाला है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह सीधी सी बात है। जो कुछ है नहीं, न परमात्मा का आदमी है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था—मानस जात एकबे जानिब, जो एक जात मानव को नहीं समझता वह कोई संत नहीं है, कोई पीर नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। मैं एक बात समझता हूं कि इन्सान-इन्सान है, हर जाति की रक्षा होनी चाहिए, यह सीधी सी बात है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बात तो आपने कई बार कही है।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाउस की राय इसी बात पर है, बीच में रेक्रिमिनेशन कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। फिर देख लेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी: इससे क्या फायदा है।

अध्यक्ष महोदय : फायदा होता है, आप बैठ जाइए। हर बात में जिद नहीं करनी चाहिए। हां, श्री योगेन्द्र मकवाना।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मकवाना जी के प्रस्ताव के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हो नहीं सकता, आप लिख दें।

13.03 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE
Animal Welfare Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : I beg to move :

"That in pursuance of Section 5(1) (i) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the members of this House do to elect, in such manner as the proceed Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the Animal Welfare Board, subject to the other provisions of the said Act, vice Shri Satish Prasad Singh resigned."

MR. SPEAKER : The question is : "That in pursurance of Section 5(1) (i) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the members of this House do proceedto elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the Animal Welfare Board, subject to the other provisions of the said Act, vice Shri Satish Prasad Singh regigned."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : If the House permits we can forego lunch recess today.

MR. SPEAKER : Is it the pleasure of the House to forego lunch recess today ?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

13.05 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
Fifty Third Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : I beg to move :

"That this House do agree with the Fifty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd December, 1983."

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That this House do agree with the Fifty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd December, 1983."

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : (Jadavpur) : I have given an amendment.

MR. SPEAKER: That is not according to the rules.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Then you assure me that you will allow it.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"इस रूपभेद के अध्याधीन सिफारिश किये गये समय को—

(एक) लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) विधेयक 1983 के लिए 2 घण्टे से बढ़ा कर 5 घण्टे कर दिया जाए;

(दो) छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85—मध्यावधि मूल्यांकन पर विचार के लिए 5 घण्टे से बढ़ा कर 8 घण्टे कर दिया जाये; और

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए 5 घण्टे से बढ़ा कर आठ घण्टे कर दिया जाये।"

13.07 hrs.

[MR. SOMANTH CHATTERJEE *in the Chair*.]

पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का समय बढ़ाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज के युग में उद्योग प्रतिष्ठानों पर निजी घरानों का दस प्रतिशत पूंजी निवेश होने पर भी कब्जा रहता है जबकि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का लगभग पचास प्रतिशत तक पूंजी निवेश होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल पर विशेष रूप से चर्चा हो और इसका समय दो घण्टे से बढ़ाकर पाँच घण्टे रखा जाए।

मेरा दूसरा संशोधन पंचवर्षीय योजना के बारे में हैं। हमारी योजना के मूल्यांकन का मापदण्ड खर्च मूलक रखा गया है जबकि परिणाम मूलक होना चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं। इस पर विचार करने के लिए पाँच घण्टे का समय बहुत कम है इसलिए आठ घण्टे का समय किया जाए।

मेरा तीसरा संशोधन इंटरनेशनल सिचुएशन पर है। हम अपनी वैदेशिक नीति में बहुत असफल रहे हैं। पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि पड़ौसी देश पाकिस्तान को कुछ हथियार मिले हैं, उसकी वजह से हमारे देश में तहलका मचा हुआ है। इसका मतलब है, हमारे सम्बन्ध पड़ौसियों से ठीक नहीं हैं इसलिए इस पर विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसका समय भी आठ घण्टे किया जाये। अभी हमने देखा कि "चोगम" हुआ। इसमें हम अपनी नीतियो पर कोई कलीअर-कट सपोर्ट लेने में असफल रहे। मैं समझता हूं कि इस विषय पर विस्तार से बहस मुबाहिसे की आवश्यकता है।

हम नान एलाइनमेंट की नीति अपना रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमारी नीति कभी उस बड़े राष्ट्र के पक्ष में झुक जाती है और कभी उस बड़े राष्ट्र के पक्ष में। सही नान-एलाइनमेंट की नीति हम को अपनानी चाहिए और इस पहलू पर भी विचार करने के लिए पांच घण्टे का समय कम प्रतीत होता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इसको बढ़ा कर आठ घण्टे कर दिया जाना चाहिए।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat) : I have also an amendment. Now you are in the Chair, will you look into that, I have given the notice for amendments on this.

MR. CHAIRMAN : But that has been disallowed.

SHRI BUTA SINGH : Sir, I have seen the amendments moved by the hon. Member Shri Ajit Kumar Mehta. As you will notice from the Business Advisory Committee's Report just now adopted by the House, we have realised that the issues mentioned theein are quite important and that is why the time has been allotted. The time originally allotted was somewhat leaser but the Business Advisory Committee increased the time.

As the issues are taken up before the House, the time is not rigidly followed. Sometimes if the House takes more than five hours, we do not mind. Therefore, let the issues come and then the House can sit longer. I do not mind sitting beyond usual

hours and prolonging the session because the issues are very important. We will try to accommodate as best as possible.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) But you agree with this point that your foreign policy has failed.

SHRI BUTA SINGH : I will reply when the issue is taken up.

MR. CHAIRMAN : Now, Prof. Mehta do you wish to press your amendment or withdraw it ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह कहा गया हैं कि सभी दलों की सहमति से समय निर्धारित हुआ है और एमेंडमैंट नहीं दिया जाना चाहिए। इसको देखते हुए में अपनी एमेंडमेंट्स को वापिस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Ajit Kumar Mehta be withdrawn ?

The amendment was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : The question is "That this House do agree with the Fifty third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 2nd December, 1983."

The motion was adopted.

13.09 hrs.

PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS (OBLIGATION AS TO FIDELITY AND SECRECY) BILL

MR. CHAIRMAN : Now legislative business. Bill to be introduced. Shri Pranab Mukherjee.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OE FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the obligation of public financial institutions as to fidelity and secrecy

MR. CHAIRMAN : The Question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the obligation of public financial institutions as to fidelity and secrecy."

The motion was adopted.

SHRI JANARDHANA POOJARY : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN : Now matters under Rule 377.

13.10 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to give alternative House sites to Scheduled caste families living in Chakdeo village in Distt. Satara, Maharashtra

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Under the 20-Point Programme, Scheduled Caste persons who do not have house sites in the rural areas are to be provided one by the authorities. I am constrained to bring to notice that this policy unfortunately is not being consistently followed. To site an instance in district Satara taluka Jawli in Maharashtra, there is a village called Chakdeo consisting of 30 families. These are all Scheduled Caste families.

These families have been agitating since 1962 to be given alternative house sites which will make it easier to conduct agriculture and to live a life of less hardship.

At present, they live 6,500 feet up on a mountain plateau which is mostly rock and hard pebbles. There is no road leading up to the mountain top, and the climb up is hazardous. It takes four hours walking from the nearest road. The path is narrow, at some places only six inches wide, and the drop at these points is easily 2,000 feet. In the rainy seasons it is nearly impossible to averse this path.

The villagers have no radio as they are too poor to buy one, no medical facilities and no school.

In 1973, the Satara Zila Parishad Rehabilitation Consultative Committee under Chairmanship of the Collector passed a resolution to give alternative house sites on flat ground (below the mountain) to these villagers. But this has not been implemented.

Since the Government have decided to give house sites to the rural poor, it should move immediately in the matter and see that the Chakdeo villagers do not have to suffer any more.

(ii) Need for a Committee to consider the problems arising out of the closure of brick kilns

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, देश में ईंट निर्माताओं ने उत्पादन करना बन्द कर दिया है। गत वर्षों में निर्मित किया गया ईंट बहुत महंगा पड़ रहा है। कुछ दिनों में सम्भवत: ईंट मिलेगा ही नहीं और सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के बन्द हो जाने की सम्भावना है और ईंट का संकट आसन्न है। ईंट उद्योग एक लघु और कुटीर उद्योग है। इस उद्योग को बड़ा उद्योग या फैक्ट्री समझना और फैक्ट्री में लागू होने वाले कानूनों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। इस उद्योग में जो कानून लागू किए जा रहे हैं वे अव्यावहारिक हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ईंट उद्योग की जानकारी रखने वालों की एक समिति तत्काल बनाई जाये और इस उद्योग के प्रतिनिधियों से वार्ता करके शीघ्र समाधान निकाला जावे। जिससे ईंट उद्योग पूर्ववत् चालू हो जावे तथा लाखों लोग बेरोजगार होने से बचें और निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो।

(iii) Unsatisfactory working of Communications facilities in Amreli District, Gujarat

SHRI NAVIN NAVANI (Amreli) : Amreli district is a big business centre with poor telecommunication facilities. The present trunk circuits are inadequate to meet the flow of trunk traffic to various important stations like Rajkot, Ahmedabad etc.

According to an official source, the installation of wide band microwave system for Rajkot-Amerli-Bhavanagar route will be completed by December 1983 and is likely to be commissioned by the end of March 1984. Meanwhile, it is necessary to take action for satisfactory working of present trunk circuits.

At present the trunk line remains in non-working condition from 10 A.M. to 6 P.M. Consequently, the trading community face lot of hardship.

With commissioning of wide band microwave station at Amreli by the end of March 1984, there will be a lot of microwave channels available between the important stations. It is, therefore, most important that STD facility is provided between Amreli-Rajkot, Amreli-Bhavnagar, Amreli-Ahmedabad and Amreli-Savarkundle.

Similarly, with the commissioning of wide band and microwave station at Amreli, additional trunk circuits from Amreli to other important stations on microwave route may also be given.

The performance of Dhan-Chalala and Dhari Amreli lines is very poor. As a result, Dhari is frequently cut off from the district town. To eliminate this difficulty, channel carrier system be immediately commissioned between Dhari and Amreli.

(iv) Non-payment of sugareane arrears to cane growers in Eastern U. P.

श्री हरिकेश बहादुर: सभापति जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अनेक चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पैसा बकाया है जिससे गन्ना किसानों के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गए हैं। जब कभी यह बकाया किसानों को दिया भी जाता है तो वह भी सूद के साथ नहीं दिया जाता जो भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम के विपरीत है। इस प्रकार गन्ना किसान सरकार की उदासीनता के कारण शोषण के शिकार हो गए हैं। किसानों से सरकारी कर्जे की वसूली भी बेरहमी के साथ की जा रही है जबकि किसानों का पैसा मिलों पर पहले से ही बकाया है। अत: सरकार से मेरी मांग है कि गन्ना किसानों का पैसा शीघ्र भुगतान कराया जाये और उन्हें उस पैसे पर सूद भी दिया जाय तथा जब तक किसानों का पैसा उन्हें मिल न जाये तब तक सरकारी विभागों द्वारा किसानों को दिये गये कर्ज की वसूली तत्काल बन्द कर दी जाय। जो चीनी मिलें, मिल मालिकों की लापरवाही के कारण

किसानों को पैसा न दे सकी है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना भी अति आवश्यक है।

(v) Industrialisation of Saidpur constituency of Uttar Pradesh.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री का ध्यान संसदीय क्षेत्र सैदपुर की वर्तमान गरीबी और भुखमरी की ओर ले जाना चाहता हूं। यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी का ग्रामीण पिछड़ा इलाका है। यहां आठ लाख मतदाता हैं। इनमें पच्चीस प्रतिशत लोग खेती करते हैं। शेष लोग खेतों और मजदूरी पर निर्भर हैं। कृषि योग्य भूमि जनसंख्या की तुलना में यहां कम हैं। इसी कारण 45 प्रतिशत लोग बेकारी तथा असमर्थता की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। 20 प्रतिशत लोग आज एक वक्त खाना खाते हैं। कोई उद्योग यहां नहीं है। जौनपुर जनपद में केराकत और ब्यालमी नामक दो विधान सभायें तीन लाख मतदाताओं से बनी हैं। गोमती और राई नदी इसके बीच से गुजरती हैं। इसके भयानक बाढ़ से लाखों रुपये की फसल बर्बाद प्रतिवर्ष होती है।

मान्यवर, जक्खनियां और सादात गाजीपुर की दो विधान-सभाएं हैं। यदि यहां कोई केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से बड़ा तीन-चार औद्योगिक कारखाना नहीं खोला गया तो स्थिति बड़ी गम्भीर हो जायेगी। यहां कागज, खाद, अल्युमिनियम आदि का कारखाना सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। दुग्ध और खोए के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए गुजरात के अमूल जैसा भी कारखाना स्थापित किया जा सकता है। ईंट के भट्टे के साथ ही बुनकरों को सहायता देकर हैंडलूम एवं अन्य इसी प्रकार के लघु उद्योगों को भी यहां विकसित किया जा सकता है।

अतः मैं उद्योग मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे तुरन्त सैदपुर के गरीबों की मुक्ति के लिए यहां के औद्योगिकरण के सम्बन्ध में सक्रिय हों।

(vi) Need for Improving the working conditions of Medical representatives.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : There are about 20,000 medical respresentatives all over India engaged in the Organised and unorganised Drugs & Pharmaceutical Industry. Their services are terminated without assigning any reasons, They are transferred on whims and fancies of the Management, and without minimum bonus. Normally, a medical representative has to work for 14 to 16 hours daily. But, no over-time is allowed to them. All the companies in this industry should be categorised according to the sales turnover. The fair wages committee has suggested that the minimum wages of an employee should be somewhere between the needbased wage and living wage as envisaged in the Constitution of India. The 15th Labour Conference recommended a formula for the need based wage. While deciding the minimum wages of the sales promotion employees including the medical respresentatives, these two points should be taken into consideration. When the charter of demands submitted in in 1978 by the medical respresentatives failed they agitated. Then, the Government of India constituted in 1980 a National Triparty Committee. There were negotiations in 1982 and a report was submitted to the Government of India. Even after a lapse of about 14 months, the report has not been published and no action taken on it for the betterment of these Medical Representatives. I, therefore, request the Central Government to immediately publish the report and take effective follow up action to implement its recommendations.

(vii) Demands of ticket checking staff of Indian Railways.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Today, the ticket checking staff working in Indian Railways are sitting on 24 hours mass fasting...

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, आज शास्त्री जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य हमको बराबर उपदेश देते रहे हैं कि हिन्दी में बोलो, क्या आज उनके लिए जरूरी हो गया है कि अंग्रेजी में बोलें ? उन्हें तो हिन्दी में बोलना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : I leave it to him to decided.

श्री राम प्यारे पनिका : वह चाहे किसी भी भाषा में बोलें, मुझे एतराज नहीं, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : कभी-कभी दोनों भाषाओं में बोलते हैं ।

MR. CHAIRMAN : Shastriji, if you want to speak while sitting, you can do so.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Thank you.

Today, the ticket checking staff working in Indian Railways are sitting on 24 hours mass fasting before the residence of Railway Minister, New Delhi, for redressal of their most genuine long pending demands like-

(1) Restoration of running allowance.

(2) Promotion on Seniority basis.

(3) 80% upgradation having Rs. 330-560 as initial pay extending to Rs. 840-1040.

(4) Fair accommodaiion for conductors and TTEs in all Mail and Express trains.

(5) Withdrawal of all victimisation orders and so on.

To treat them as 'Running Staff' Justice Rajadhyaksha has said : "The travelling ticket examiners habitually work on running trains and their hours of employment was continuous and no roster is possible to frame for them."

According to Acharya J.B. Karipalani, Chairman, Corruption Enquiry Committee—

> "The TTE has today become part and parcel of the train and his importance in running train is nothing less than that of a guard and a driver."

The Industrial Tribunal, Pakastan, in the year 1962 restored payment of running allowance for ticket checking staff.

In view of their just demanns and assurances given by the then Railway Minister late Kedar Pandey, the Railway Administration should come to a settlement without any further delay.

I hope, the Railway Minister will show good gesture and do the needful.

(viii) Need for resolving the deadlock between managements and staff of Canara Bank

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Under Rule 377, I make the followiug statement :

The management of Canara Bank entered into a settelment with Canara Bank Staff Union in 1980 in the Office of the Labour Commissioner (Central) on various demands of the Union. It has, however, advoided implementation of the various agreed item of the settlement.

The Union submitted a Charter of Demands to the management in December, 1982. The management instead of accepting even certain minor demands of the Union like maternity leave for lady employees, clock and toilet facilities at all the branches of the Bank and subsidised canteen, has imposed a struggle on the employees. The members of the Union have been agitating since January, 1983 for redressal of their legitimate demands. The management has resorted to repressive measures and has issued charge-sheets to employees, and resorted to harassment, resulting in imposed wage cuts and has further restored to transfers. Even basic trade union rights like pasting of posters of the Union has been denied as the management has suspended several employees.

I, therefore, urge upon the Government to intervence in the matter and instruct the management of Canara Bank to resolve the deadlock by implementing the various agreed items of the settlement.

(ix) Need for financial assistance to complete on going irrigation projects in Mirzapur

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के किसानों के लिए यह गम्भीर चिन्ता की बात हो गई है । केन्द्रीय सरकार द्वारा पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा स्वीकृत समस्त सिंचाई की परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष से धनाभाव के कारण बन्द कर दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस जनपद की विशेष सूखा एवं बाढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए सिंचाई की महत्वपूर्ण परियोजनाएं तैयार करा कर उनको स्वीकृति दी थी । इनमें कनहर परियोजना, सोन

लिफ्ट परियोजना, बकहर बेलन डाइवर्शन, बाणसागर, शारदा नहर परियोजना आदि है। यही नहीं, डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत बहुत सी सिंचाई की योजनाएं बनी थीं, जिनमें 34 बंधियां निर्मित भी हो गई हैं, परन्तु धनाभाव के कारण मांड एरिया नहीं सृजित किया जा रहा है। आश्चर्य यह है कि उपर्युक्त कुछ परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है, किन्तु उनके कार्य भी धनाभाव के कारण बन्द हो गए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनाभाव के कारण आई रुकावट को तत्काल समाप्त किया जाए, जिससे सर्वदा सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने वाले जनपद का विकास हो जाए।

(x) Need for financial assistance and employment to people of Ghazipur of in view of famine and floods in recent years

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का जिला बहुत ही पिछड़ा है। वहां की जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग खेती पर आधारित है। भूमिहीन, सीमान्त तथा लघु कृषकों की संख्या 75 प्रतिशत से ऊपर है। इस वर्ष यह जिला अकाल और बाढ़ की चपेट में रहा। ये प्राकृतिक विपदाएं पिछले पांच वर्षों से लगातार आ रही हैं। सन् 1978 में भयंकर बाढ़ आई थी। सन् 1979-80 के देश-व्यापी अकाल में भी यह जिला प्रभावित हुआ। सन् 1982 में पुन: बहुत बड़ी बाढ़ आई और इस वर्ष अकाल और बाढ़ दोनों ही।

ऐसी दशा में वहां के लोगों की आर्थिक कमर ही टूट गई है। अभी मैं वहां से लौटा हूं और वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। लोगों का रोजी-रोटी चलना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ काम हो रहा है, लेकिन बेरोजगारों की एक बड़ी फौज को देखते हुए ये काम भी बहुत कम हैं—विशेषकर ऐसे समय में, जबकि खरीफ की फसल नहीं के बराबर हुई है और रबी की फसल भी अच्छी होने की संभावना नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां की विकट स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक धन गाजीपुर को दिया जाए, ताकि वहां रोजगार-परक योजनाओं पर काम शुरू हो। इस मामले में बहुत ही शीघ्रता किए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो वहां के लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे।

MR. CHAIRMAN : Now we come to items 15 and 16. They may be discussed together. Shri Krishna Kumar Goyal may move the Resolution.

---

13 30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF TEA (AMENDMENT) ORDINANCE AND TEA (AMENDMENT) BILL

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota) : I beg to move :

> "This House disapproves of the Tea (Amendment) ordinance, 1983 (Ordinance No. 7 of 1983) promulgated by the Presidenton the 7th October, 1983."

सभापति महोदय, जहां तक अध्यादेश की भावना का सवाल है मैं किसी सीमा तक उस भावना को स्वीकार करने को तैयार हूं परन्तु जिस प्रकार से बार-बार इस सदन के माध्यम से सरकार की ताड़ना की गई है कि जब सरकार यह समझती है कि किसी भी वस्तु के लिए कानून बनाना आवश्यक है और उसके लिए विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है तो सरकार को विधेयक का ही सहारा लेना चाहिए, अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए और इस आधार पर ही मैं यह कहना चाहता हूं कि चाय कानून में संशोधन के लिए जो अध्यादेश निकाला गया, जैसा कि सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया उससे पता लगता है कि 10 अक्तूबर, 1983 को जो बीमार चाय बागान थे जिनका मैनेजमेंट सरकार ने अपने हाथ में

लिया था प्रारम्भ में पांच साल के लिए और जैसा कि कानून के अन्दर अधिकार है कि अधिक से अधिक सात साल तक चाय बागान का मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले सकती है, एक साल पहले बढ़ाया और उसके बाद एक साल और बढ़ाया, अब सात साल का जो मैक्सिमम अधिकार है आपको वह समाप्त हो रहा है इसलिए आप यह अध्यादेश लेकर आए हैं। मेरा यह कहना है कि ये जो चाय बागान बीमार चल रहे हैं जिनका मैनेजमेंट आप ने लिया क्या 10 अक्तूबर 1983 को जब आर्डिनेंस निकाला इसके पहले सरकार को पता नहीं था या यह पता नहीं किया जा सकता था कि ये चाय बागान अभी भी बीमार हैं और अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं, इनका मैनेजमेंट कुछ समय तक और सरकार के हाथ में रहे, क्या यह पहले मालूम नहीं किया जा सकता था ? मेरा कहना है कि मालूम किया जा सकता था और सरकार को मालूम था कि इनके मैनेजमैंट का समय बढ़ाना पड़ेगा। जब यह पहले से मालूम था तो कोई कारण नहीं था कि अक्तूबर 1983 में ही इसके लिए अध्यादेश निकालते। इससे पहले जो हमारा मानसून सेशन था या उसके पहले जो बजट सेशन था, मैं तो यह कहूंगा कि उस समय भी सरकार को पता था कि इसके मैनेजमेंट को हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो उस समय आसानी से इसके लिए विधेयक लाया जा सकता था। सरकार की इस मनोवृत्ति का कि जो बार-बार सदन की उपेक्षा करने की उसकी आदत पड़ गई है और सदन की पीठ के पीछे यह बहाना लेकर कि चूंकि आवश्यक हो गया था और सदन नहीं चल रहा था इसलिए हमें अध्यादेश निकालना पड़ा, इस मनोवृत्ति की मैं घोर निन्दा करता हूं और इसीलिए मैंने इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए अपना संशोधन दिया है।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार की स्वयं की उद्घोषित नीति क्या है ? जिन चाय बागान को बीमार मान कर या यह केवल चाय बागान का नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री एज सब का सवाल है, जो उद्योग बीमार हैं भविष्य में उनके बारे में सरकार की नीति क्या है ? मैं यह कैटेगोरिकली, स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि भविष्य के अन्दर भी जो चाय बागान बीमार हैं उनके मैनेजमैंट को सरकार अपने हाथ में लेगी या सरकार यह तय करेगी कि भविष्य के अन्दर कोई चाय बागान जो बीमार होंगे उनको सरकार अपने हाथ में लेने वाली नहीं है ? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनेक बार पश्चिम बंगाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने और यहां तक कि आसाम के प्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाया है कि हमारे क्षेत्रों के अन्दर अनेक चाय बागान बीमार पड़े हैं और उनके बीमार होने की वजह से मजदूर घर बैठे हुए हैं।

देश को नुकसान हो रहा है। सरकार बराबर घोषणा करती रही है कि केन्द्रीय सरकार की कोई नीति नहीं है। जिन चाय-बागान के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिया है या जो कुछ करना है, वह राज्य सरकारें करें। तो फिर क्या कारण है कि जो मैनेजमेंट आपके पास अभी तक हैं, जो बीमार चाय-बागान की है और जो उनका मैनेजमेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सात साल के बजाए आप ग्यारह साल की अवधि लेना चाहते हैं—यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जिन मैनेजमेंट को बीमार मानकर सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उसके संबंध में भविष्य के लिए सरकार की क्या नीति है। जिस किसी भी चाय-बागान के उद्योग को बीमार मानकर सरकार ने उसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिया है, तो क्या उन चाय-बागान को फिर से सरकार ठीक करके उन मालिकों को देना चाहती है या नहीं—इस बारे में भी मैं सरकार की स्पष्ट नीति जानना चाहता हूं।

मेरी तो स्वयं की मान्यता यह है कि चाय बागान के मालिक बदनियती के कारण ही मिल को बीमार करते हैं। जिस किसी भी उद्योग को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उसको

सुधारने के बाद किसी भी कीमत पर मालिक को वापिस नहीं लौटाना चाहिए। इस बारे में भी मैं सरकार की नीति के बारे में जानना चाहता हूं। सभापति जी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार इस बात को कहने में शायद डरे, लेकिन वह भी यही कहेगी जो चाय-बागान बीमार हुए हैं, उनको अपने हाथ में लेकर सुधारने के बाद मालिकों को वापिस नहीं लौटाएगी। इसलिए मेरी मांग है कि बराबर संशोधन लाकर अवधि बढ़ाने के बजाए, सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करे। उनको अपने हाथ में लेकर उनकी इकानामिक स्थिति में सुधार करे—इस बारे में भी मैं सरकार की नीति के बारे में जानना चाहता हूं। एक बात मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन चाय-बागान को आपने अपने हाथ में लिया, जिनको सात साल हो गए हैं, क्या आज वे मुनाफे की स्थिति में आ गए हैं? क्या कोई चाय बागान का मालिक सात साल तक इनवेस्टमेंट करने के बाद इन्तजार कर सकता है? इतना पैसा लगाने के बावजूद भी क्या आप नाप्राफिट ना लास की स्थिति में आ गए हैं; यदि नहीं; तो क्या इसके लिए आपने कोई प्लान तय किया है? अगर सरकार इन चाय-बागान को अपने हाथ में लेकर नुकसान के अन्दर चल रही है, तो कहा जा सकता है कि पब्लिक सैक्टर की तरह वे भी जनता के पैसे को खा रहे हैं। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जो प्लान्ट पुराने हो गए हैं, उन को बदल कर नए प्लाट लगाए जायें, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। ऐशो-आराम की जिन्दगी जिस प्रकार से चाय बागान में बिताई जा सकती है, जिस प्रकार से ब्रिटिश पीरीयड के अन्दर मैनेजर्स बिताया करते थे, उसी प्रकार से अब भी हो रहा है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार ने टडन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है? क्या उस रिपोर्ट के आधार पर चाय के कानून में कोई परिवर्तन किया गया है? ऑक्शन सैन्टर में चाय के अन्दर जिस प्रकार से मनमानी की जाती थी, वही आज भी विद्यमान है। मन्त्री महोदया-चाय जबकि कोई लग्जरी आइटम नहीं है, वह आज के जीवन के लिए नैसेसिटी हो गई है, लेकिन उस की कीमत आज 40 रु० प्रति किलो हो गई है। बच्चों को आज दूध नहीं दिया जा सकता है, घी नहीं दिया जा सकता है, चाय जरूर पिलाई जा सकती है, लेकिन आज उसकी कीमत 40 रु० प्रति किलो है। मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि इन बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए आप ने क्या कदम उठाए हैं?

क्या आप ने मालिकों को मजबूर किया कि जितना चाय का उत्पादन होता है, वे आक्शन सैन्टर में ले कर आयें? आज वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइज की चोरी होती है, लूज टी के नाम पर चाय बाला-बाला चाय-बागान से बिक जाती है और पता नहीं चलता है। यह ठीक है कि आप का फारन-मार्केट बहुत अच्छा है और मैं भी यही चाहूंगा कि फारन-मार्केट खत्म न हो, लेकिन चाय-बागान के मालिकों से सांठगाठ करके 40 रुपए किलो पर चाय पीने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर किया जाय, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है? 40 रुपये किलो की चाय आज कौन पी सकता है, क्या हमारा जनसाधारण पी सकता है और वह भी बाजार में धूल जैसी चाय पीने को मिल रही है, कोई स्टेण्डड की चाय नहीं है। इस सम्बन्ध में आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? जो मुद्दे मैंने इस समय उठाये हैं, उनके बारे में सरकार की नीति क्या है—इस सम्बन्ध में आप अपने जवाब में बतलायें?

MR. CHAIRMAN : Resolution moved :

"This House disapproves of the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 7 of 1983) promulgated by the President on the 7th October, 1983".

Now, Shrimati Ram Dulari Sinha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : I beg tomove :

"That the Bill further to amend the Tea Act, 1953, be taken into consideration."

I would like to say that I have heard with great patience the speech delivered by Shri Krishna Kumar Goyal. In the first instance, I would like to say that Chapter III-A of the Tea Act, 1953 provides for the take over of the management of sick tea undertakings or tea units by the Central Government under certain circumstances. This was inserted in the Tea Act in 1976. These provisions are based on the corresponding provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in respect of sick industrial undertakings or units.

In terms of the provisions of the Tea Act under Sections 16D and 16E, the Central Government is empowered under certain circumstances to take over the management and control of the whole or part of tea undertakings or units for a period of five years, which may be extended by a further period of one year at a time, subject to a maximum of two years. Thus, the total period of takeover prescribed was seven years.

However, the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 provides that the total period for which an industrial undertaking can be taken over is seventeen years, that is, five years in the first instance and thereafter by extensions of two years at a time for a further twelve years. On the basis of the experience of the tea units taken over in 1976 under the provisions of the Act, Government is of the considered view that the period of seven years provided for the continuance of management of sick tea gardens is not adequate to provide effectively for all the managerial and developmental inputs necessary to ensure the gardens back to health. A long gestation period is required for the rejuvenation and rehabilitation of tea bushes. Tea cultivation is an agricultural operation and nature cannot be compelled to conform to our schedules. We must adjust our own schedules according to the course of nature.

Hon. Members will be glad to know that despite all legal hurdles created by the owners of the taken-over gardens which made implementation of rehabilitation programme difficult, significant improvements in productivity, have been made. After takeover, conditions in the tea factories have been improved by the provision of controlled withering facilities installation of generating sets, repair of irrigation and drainage facilities etc. Large-scale rejuvenation, pruning inter-planting etc have also been undertaken. Modern methods of cultivation have been adopted scientific inputs such as fertilisers, pesticides, weedicides etc have been regularly applied.

Labour welfare measures which as hon. Member Shri Goyal was mentioning in his speech, had fallen into disuse have been reintroduced and construction of pucca labour houses undertaken on a phased basis. Labour from these gardens welcomed the take-over of the management and they have represented against handing them back to the owners who had been responsible for mismanagement and neglect.

I would like to inform hon. Member Shri Goyal that, in view of considerable efforts made by the Government to revitalise these gardens, extension of take-over period is necessary to improve their viability, Then only the socio-economic objectives of the take-over will be served.

Hon. Member Shri Goyal has asked as to why we issued an Ordinance on 7th October. I shall now reply to that. It became imperative to issue the Ordinance on 7th October, 1983, because the maximum period for the take-over allowed in certain cases was coming to an end on 11th October, 1983, and Parliament was not insession at that time. I want to remind you of that. We are now seeking to amend the existing provisions relating to the period of takeover so that the maximum period for which a tea unit is taken over will now be eleven years, that is, for a further period of six years, one year at a time, beyond the initial period of five years.

The hon. Member has made many suggestions and I will reply to all those at the concluding stage.

Now I move for consideration of this Bill.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Tea Act, 1943, be taken into consideration."

Shri Ananda Pathak.

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the two items together, one is the Statutory Resolution moved by Shri Krishna Kumar Goyal seeking disapproval of the Tea (Amendment) Ordinance, 1983, and the second is the Tea (Amendment) Bill.

As far as the Resolution is concerned, we generally do not support promulgation of Ordinances just a few days before Parliament is to meet. Hon. Member Shri Goyal has rightly pointed out that the Government was very much callous and unconcerned about the take-over of tea gardens, not only take-over of the tea gardens, but also of the tea industry as a whole. On the eve of the expiry of the period of takeover of the tea gardens they hurriedly came forward with this Ordinance. We do not support the practice of bringing Ordinances in each and every case, every now and then. But in this particular case, maybe, it is due to the Government's callousness or whatever it may be that this had to be done. Had the Ordinance not been promulgated on 7th October, 1983 when Parliament was not in Session, a difficult situation would have arisen because the extended period was due to expire on 10th October, 1983.; a very difficult situation would have arisen as regards the four or five tea gardens involving more than 2,000 workers. As a matter of fact, the workers of the tea gardens were very much restive when they came to know that the extended period was going to expire and were afraid that the gardens might be returned to the owners. They submitted a very strong representation to the Prime Minister and the Commerce Minister as far back as May urging upon them not to return these gardens to those owners who had made these units sick. I also made a strong plea to the Prime Minister and the Commerce Minister urging upon them not to return these tea-gardens to the previous owners.

Now, coming to the Bill, though I do not oppose the amending Bill, yet I feel that the proposed period of extension to 11 years still falls short of the requirements. Because the tea industry is an agro-industry, it requires more time to bring it back to health from its sickness. More so, it requires more time especially in the high altitude like Darjeeling hills where the topographical and climatic conditions are different and where most of the lovely tea gardens are located and have been closed and abandoned now for yeaar together. Therefore, I have proposed to make it 15 years instead of 11 years as proposed by the Government, in my amendment which I hope the hon Minister would seriously consider and accept.

I had already made this suggestion in the course of the discussion on the last Tea (Amendment) Bill in the year 1980, but unfortunately, at that time, they have not accepted it. Now, I find in the Statement of Objects the Government has also realised the gravity of the situation and felt the necessity of extending the period of taking over. The purpose of this Bill being very limited, I have no scope to discuss about the whole matter regarding the tea industry. Therefore, I have made my suggestion in a very limited way. But I feel even this 15 years or even 18 years, whatever it is, may not be sufficient and it is not the solution. The only solution will be outright nationalisation of these tea gardens. How long and how many times do you go on extending the period of taking over in this piecemeal fashion ?

Another pertinent question is : what are you going to do after the expirty of the extended period of taking over ? Are you going to return these taken over tea gardens to he same owners who mismanaged and ruined them ?

The Government have invested and sunk huge amount of money from the public exchequer for bringing these sick tea gardens to health. For what purpose ? Just to help these unindustrialist traders and unscrupulous managements who have no sympathy, no love for the workers, for the industry and for the country ? They have love only for the money. Sir, this is the unique pattern of our socialism !

However, may I be permitted, Sir, to refer here to the assurance given by the then Minister of State in the Ministry of Commerce, Shri Khursheed Alam Khan, on the floor of this House in the course of his reply to the discussion on the last Tea (Amendment) Bill on 19th December, 1980. What he stated then, I quote ;

"...I want to assure him that there is no idea of taking over these gardens, investing and sinking money in them and giving them back to the owners."

Further on he has said :

"We do not want to function as a hospital where a patient is restored to health and then handed over to the relatives so that they can again make the unit sick or run it to destruction."

Quite Excellent. I think the Government stands committed by this assurance. So why do you not outright nationalise these taken-over tea-gradens immediately on the expiry of the period of taking over as you have done in the case of some of the jute companies, textile mills; the Bird Co. and some other taken-over under-takings ?

Another thing is : when you take over any sick tea garden, yon do so being satisfied that the production is falling, tea bushes are dying and machineries are getting rotten and outdated and the workers are being deprived of their wages and other statutory benefits.

So, you have to spend a lot of money. You have to makc capital investment for there juvenation and revamping of such sick tea gardens.

But, there is no such provision in the Tea Act. Then, how do you expect to bring such sick unit to health ? So instead of bringing occasional amendments in a piecemeal manner, why is the Government not bringing forward a comprehensive Bill to nationalise such units and remove the lacunae and weaknesses in the existing Act ?

Sir, the tea industry is one of the vital industries. It earns the muchneeded foreign exchange worth more than Rs. 400 crores annually ; it pays more than Rs. 150 crores per annum to the Government Exchequer in the form of taxes and duties and it provides direct employment to more than 10 lakhs of people But, such a vital industry is getting sick due to mismanagement. In Dajreeling, which produces the worldfamous flavoury and finest tea, more than 12 tea gardens are still closed and abandened and many more are getting sick. What are you going to do about these tea gardens ? I urge upon the Government to take over these closed tea gardens under the previsions of the Tea Act and save thousands of workers and their family members from the verge of starvation and also save this vital industry from ruination.

Before I conclude, I would like to draw your attention to the very disturbing report appearing in the *Statesmen* (Calcutta edition) of 24th November, 1983, wherein it is stated that some of the producers of Tea in North East India have misappropriated more than Rs. 150 crores by underinvoicing the private sales either at ex-factory level or by withdrawing from the auction sales.

The Chief Commissioner of Income-tax West Bengal has revealed the above fact after a series of raids conducted by his department simultaneously in Calcutta, Jalpaiguri, Siliguri and and also in Madras, Ahmedabad, Delhi and other places. This shows that when the prices come down, these companies close down and abandon the tea gardens. But, when the prices go up, they resort to all sorts of malpractices but they do not care for the development and proper maintenance of tea gardens and thus make them sick.

Transactions are recorded at a price much lower than what they get and the differences are being taken as 'one money' thereby they are cheating not only the shareholders but are also depriving the Government, depriving the industry and also the workers.

So, all the more it is necessary to nationalise these questionable units before it is too late. With these words, I conclude my speech.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV. Mr. Chairman, Sir, this amendment to the Tea Act which has been brought before ihe House again proves the Government's casual attitude towards tea industry which is one of the most important ndustries of the country from the point of view of earning foreign exchange and also from the point of view of employment.

Sir, in our country, there are about 13,345 tea estates and, roughly, we produce now six million K. Gs of tea. The target for our country by 2,080 is of the production of 19 million K. Gs of tea. To achieve this, we have to nourish these huge number of tea gardens. And, at the same time, we have also to look after the labour who are employed there. They are mostly

from the harijan classes or Scheduled Tribes some of whom come from the areas of the hon. Minister, Shrimati Ram Dulari Sinha, namely, Bihar, and some of them come from Orissa while some of them come from U. P. So they have all gone to Assam, West Bengal as well as in certain parts of Kerala. Now, unfortunately, the Government does not give as much importance as they should have given to the tea industry.

14.01 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

My point is that Government has come forward with different legislation for the welfare of the tea eastates. Government has given various conveniences to the tea estates but I personally feel that the facilities which have been extend to the tea eastates have not been properly utilised and this is why these ad hoc measures are being taken by the Government.

This Tea Act which was introduced long before the idea was to take over the gardens not only from the commercial point of view but from socio-economic point of view as well. As it is a labour orinted industry Government wanted to take care of the huge number of labours appointed there but in doing so the Government is wasting the national exchequer's money in these tea gardens. They have so long taken over five tea gardens. If the Government themselves are to run them in a proper manner in the course of five to seven years-at present the amendment is for 14 years—I think, they are living in a fool's paradise. Tea gardens which cannot be run properly by the management for years together if Government by putting some organisation there tries to improve them in the courase of 14 years, I think, they are wrong. Even if they want to improve they are not allowed to improve them because these garden are run by the Government as per existing rules and regulations which are governing the other tea gardens in the country. What happens is—I am saying from my experience—when the Government wants to make any capital expenditure there they are not allowed by the proprietors because the proprietors take order from the court and stop them from doing any development work. Not only that the TTCI which is doing good work in the tea industry for exporting tea they are also not allowed to buy tea from the gardens. They have to buy tea from the auctions and again sell it. The idea of TTCI taking over or Government taking over is to run them for a particular period and give them back to the industrialists who originally owned the gardens. I think it is basically wrong. Government should be forthrignt and nationalise these gardens so that these gardens are run properly and efficiently.

Sir, the Tea Board has been fed with certain information by certain association in regard to various schemes which the Tea Board is implementing. Now, all this information which comes before the Tea Board is fictitious and these fictitious reports are the base through which you are giving various grants.

I propose that Government if they do not want to totally nationalise the industry —I am not a supporter of it—if they can manage these gardens properly in the question of development, expermenting and labour welfare that can be the guideline for Government to look after the tea industry and give them help. That can be the guidelines for the Government and also the Finance Ministry to know what is the actual loss and what is the actual gain which the industry is getting.

Now Sir, at the same time I would say that It is high time now that the Govt. of India should consider the tea industry as a priorty industry which is very essential. Why it is very essential ? It is because the tea industry needs very many inputs like coal, fuel, manure and various other things. Tea industry is there concentrated mostly in the North eastern areas, in West Bengal and in other areas. Their sources of supply are from remote areas and remote places. Now to bring all these inputs extra cost is involved. They can't get all the permission which they will get if they are considered as a priority in dustry. They have to bring all these things either by road or even sometimes by road-cum-steamer-cum-rail. Therefore the cost of production goes up. Same is the case of fuel. Same is the case of other inputs ; it is the same problem everywhere. Many of the tea gardens are in

remote areas ; and they are getting their products by tanks and lorries. Here another problem is this. The petrol pumps are in the main cities and main towns. So, these problems are arising there. Therefore, tea industry must be considered as a priority industry. If it is considered as a priority industry they will get more facilities in 'Inward' and 'outward' movement of thier inputs as well as their finished products.

Secondly, Sir, if the tea industry is considered as priority industry they will get more benefits from financial institutions. Now what is happening is this : The financial instituions are not forthcoming to help tea industry in times when they are in dire necessity. I you go into the history of the tea industry you will mind that there have been periods of 'boom' and periods of 'slump'. Now, at present, tea industry is having a boom period. It is being said that the tea industry was earning so much. The other day when they Minister was replying to a question Mr. Somnath Chatterjee was saying that the tea industry was earning so much, earning huge profits and so on, and they must spend more money on modernisation and all that. But at the same time we should also consider the huge backlog and the huge loss which they have to sustain in the last 10 or 15 years. When it is said that they are having huge profits, Government is also gettiug part of that money by way of incometax and excise duties which they are paying to the Government Exchequer.

Now, Sir, Let me say, the Tea industry needs development ; tea industry needs a fresh look there should be fresh thinking bestowed to capture foreign market. It is time we come out with novel ideas to attract foreign buyers. The folly done by the Janata Government was levying excise duty of Rs. 5. But it is ultimately withdrawn. But it took a long time for them to recapture the international market. Sir, it always takes a long time to capture foreign markets, to develop the foreign market; to but in one minute, by one decision, you can lose that market. The Janata Government's decision has created havoc in the tea industry about which I have already made a mention. Slr, they have been able to capture the market because of the present situation in Sri Lanka,— not as politics, but for tea industry, it is a good thing : The present situation in Sri Lanka is a plus point for the tea industry and we have to take steps to contain the markets, I ask the Government : What steps have the Government. taken in this regard ? I request the Government that it is high time that they should caputer more foreign markets even if it is at loss of some money to our exchequer because foreign exchange is more important than earning money within the country. Government must have dialogue with tea board, with tea manates and tea associations to find out methods by whice we can capture foreign market. We must capture that market by taking all necessary steps, Sir, I am a member of the tea Board. If you go to the meeting you will find that there are 45 items. Out of those, 43 items will be only on transfer, posting, promotion, house allowance etc. Nothing about development of tea industry. Even if you ask, let us have some discussion on development, they will say it is coming in next meeting, next meeting, etc. But nothing comes up.

The Tea Board has got a function to do If it is, considered to be a body to appease certain officials who are in the good books of the Government or the Minister, then I am sure it is not doing good work. But if it is for the cause of the industry and if it is to do good, work then it has really to do good work for the industry. The Tea Board, for the last four years or so has not done a bit for the cause of the tea industry because there has been no scope for discussion for the promotion of tea industry in the meetings held during these years. Therefore, I would request the hon. Minister to be courteous and forthright. I am glad that Shrimati Ram Dulari Sinha has moved this Bill and I would request that she should have a motherly attitude towards the tea industry. A child who is sick needs nursing of a lady. The lady Minister can nurse it better than Mr. Viswanath Pratap Singh. I hope the present Minister is taking a lot of interest in the industry and with his magnanimity and his team consisting of Mrs. Ram Dulari Sinha and Mr. Sharma would cefinitely look after the tea industry and this Bill should not be taken as an *ad hoc* measure. They should think now the tea industry can be revitalised keeping in view this industry which is earning 2/3rds of our foreign exchange which needs better care from the financial institutions and from the Govern-

four such investment companies. The ment at the same time. It is high time the Government stopped siphoning off the money from the industry and misusing it for some other purposes. Once the hon. Finance Minister said "the tea industry has become sick, but the industrialists do not become sick". is That the correct picture and the industrialists are becoming richer and richer day by day at the expense of the industry. With these words, I support the Bill and I hope the suggestions which I have given will be considered by the hon. Minister. Thank you.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let us compete with Sri Lanka and capture the tea market in the world when normal conditions exist in Sri Lanka beeause Government of India wants that normal conditions should prevail there. We will not compete with them when they are weak. We will compete with them when they are strong.

* SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Hon. Mr. Deputy, Speaker, Sir, I rise to make a few suggestions on The Tea (Amendment) Bill, 1983; which seeks to replace the Ordinance promulgated by the President on 7th October, 1983. Sir, at the very outset I would like to say that I am seriously opposed to the recourse being taken by the Government for amending the parent acts through Presidential Ordinances.

As the seven-year period in respect of those tea undertakings, whose managements were acquired by the Government on the ground of mismanagement, is due to expire, the Government has suddenly woken up and realised the need for extending the period to II years so that these undertakings could be restored back to heatlh. At the last moment the Government has felt that this seven period has not proved be adequate for restoring them to normalcy. I am surprised that that the highly paid officials in the Tea board and in the Ministry could not foresee the need for extending this period sufficiently in advance so that there would have been no compelling circumstances for issuing Presidential proclamation. All I want to emphasise is that the Government should not resort to proclamation of Presidential Ordinances even for amending parent Acts, like the one under reference. I would like to stress that this authority should be sparingly used.

If the Government takes recourse to Presidential Ordinances so requently, it is in fact denigrating the authority of the President. It also highlights the ineptitude of the Government. These tea undertakings were over in 1976 and till 7th October 1983 the Government did not realise the need for extending the period of nurturing them back to health. This also does not speak well of the Government.

Sir, the total period for which the management of an industrial undertaking can be taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, I951 is seventeen years. I refer to this because the Government should not again proclaim a Presidential Ordinance just befor the expiry of 11 year period extending it to I7 years. I would go to the extent of saying that even now this period of nursing sick tea units can be extended to 17 years through this amending legislation.

I would like to refer to another import issue relevant to this amending Bill. I would like to know the intentions of the Government as to whether after nursing such tea undertakings for 11 years they will be handed over to the same managements which had fleeced them to marrows. The tax-payers' money is invested in these undertakings. The Government have restored them to normal health. After that, in no circumstances they should be given back to the erstwhile managements, whose callousness compelled the Government to acquire them. If they are handed over to the erswhile managements then the Government is playing foul with public money. The people are done injustice by the Government. I would suggest that the Government should create a public sector organisation to run such tea undertakings.

Under the caption "Tea raids unearth black money hoard", a news item has appeared in BUSSINESS STANDARD of 28th November 1983. The recent raids of the Incometax Department have revealed massive tax evasion on the part of tea garden owners in Calcutta, Siliguri, Cochin, Ahmedabad, Surat, Amritsar and New Delhi. The various modes of laundering black money through investment companies have come to notice. In Assam and Darjeeling investmen of Rs. 2.5 crores has been made in[t]

*English translation of the speech delivered in Tamil.

Directors of tea companies have diverted corporate funds amounting to Rs. 3.75 crores into their personal accounts. Such mismanagements of tea gardens led to the acquisition by the Government. If after nurturing them back to normaley they are to be handed over to the very same people, then the Government is placating these plunderers and is giving fiilip to these fleecers. That is, why I suggest that a public sector organisation should be created for running these units.

I will now come to another important aspect. In Udhagamandalam, formerly known as The Nilgiris and in Anamalai Hills, there are very fine tea gardens. In fact the whole of the Nilgiris is covered with tea gardens. They were all established by the Britishers. There were thick intractable jungles here. But the Britishers converted them into very good tea gardens. In these places there are small tea garden owners who require financial assistance for their working. All these tea gardens are very old now. The tea plants are not yielding the same quantum of tea, as they were in the intial stages. There is urgent need for undertaking replantation on a wide scale. This has been brought to the notice at the Ministry several times. Here I have to point out the owners of tea gardens. Udhagamandalam and in Amamalai Hills are not getting adequate financial assistance from the Tea Replantation Finance Scheme being implemented by the Government. This neglect of tea gardens in South appears grave consequence when it is found that the replantation financial assistance being given to tea gardens in North-east parts is comparatively large. Tea is the largest foreign exchange earner for our country. The Government should not only give protection to the existing tea gardens but also ensure substantial replantation programme so that the future of tea estates is not jeopardised. The foreign exchange earnings of our country should not get depleted due to neglect of such replantation programme. In addition, we have to ensure that the workers are not thrown out of employment because of the continuous neglect of tea gardens. I would like to appeal to the hon. Minister that adequate replantation financial assistance should be extended to tea gardens in Udhagamandalam and Anamalai Hills.

The hon. Member, Shri Sontosh Mohan Dev, who preceded me, referred to the competition from Sri Lankan tea. At that time, the hon. Deputy Speaker intervented to say that we should compete with Sri Lankan tea after normalcy is restored in Sri Lanka and we should not take advantage of the present position in Sri Lanka. I honour the sentiments of our Deputy Speaker. We should make an all-out effort in compering with Sri Lankan tea only after Sri Lanka achieves peace and tranquillity. Here I have to refer to the plight of refugees from Sri Lanka, who take shelter in India. We know that they are the hapless victims of racial conflagrations in Sri Lanka. We also know that they have given their blood and sweat in the tea gardens of Sri Lanka for generations together. They are export tea pluckers in the world. Their expertise is not being utilised by the Government of India, More tea gardens shauld be set up in Udhagamandalam and Anamalai Hills, where there is ample opportunity for this, These refugees from Sri Lanka can be rehabilitated in these gardens. We will be able to augment our tea production.

While concluding, I would urge npon the Government not to hand over the restored and revived tea gardens to the former managements, as that will preve an incentive for further mismanagement and it will also be doing injustice to the people whose taxes have been invested in the sick tea gardens. There should be replantation of tea plants, expansion of tea gardens and also nursing of sick gardens. With these words I conclude my speech.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Era Mohan, You have not said whether you are supporting or opposing it. It is left to you.

Now. Mr. Xavier Arakal.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): This short Bill aims at extending the management of the sick tea industries which are taken over by Government. Nevertheless, the scops of the Bill is much larger, going deep into the causes and effect, as also the problems and their solutions of the tea industry as a whole.

I would like to emphasise on the prenentive measures which the government ought to take if they want to protect, encourage and promote the tea industry as a whole in India. I have been drawing the attention of the government for a long time

through 377 matter and supplementaries on various a specfs of the tea industry. If you refer to the 6th Five Year Plan, you will see that the Sixth Five Year Plan aims at 5 per cent growth rate in the tea production ; and it has a target of 705 million kgs., out of which 438 million kgs are for domestic consumption and 216 million kgs are for export. On page 125, it says, "Development of these crops is handled by the respective commodities boards under the Ministry of Commerce." Therefore, the question arises what the Board has done in this matter to achieve the target of 5 per cent growth rate ? Have they handled effectimely the problem of drought and allied problems ? Have they given any substantial assistance to them ? The Board has assessed that 52,250 cash croppers will be available in north for new plantation and 15,350 hectares of land in south for new cultivation. Now, I would like to ask the hon. Minister what the Board has done in this matter ? Further, 2,600 hectares of land will be cultivated in non-traditional areas of north eastern region. Therefore, is the takidg over the manegement, the answer to the problem or the implementation of the 6th Five Year Plan ? I would like to know from the hon. Minister what they have done about it, ? The basis measure to solve this problem according to me is to declare it as a priority sector because of the land and labour involved, SC & ST and weaker sections are largely employed there in remote hilly and other areas. More over, 500 of the labour force is women.

MR. DEPUTY SPEAKER : It seems that the labour is exploited. To a great extent, labour is also being exploited in these areas.

SHRI XAVIER ARAKAL : We have been repeatedly saying that. If it is declared as a priority sector, many of the ailments, sickness can be reduced to a larger extens. I have been asking since 20th July, 1982, that the rebate or reduction of the excise duty and central excise should be done or the amount collected should be converted into soft loan purpose. I would like to know what they have done about it ? The government has enunciated three things ; full rebate on excise duty and the tea exported ; rebate on excise duty of 44 paise per kg. by marchant exported ; draw back custom/excise duty paid on packing material, etc. in the export of tea. May I ask the hon. Minister who is benefiting by this ? Is it the producer or the exporter ? What is the policy of the government ? Is it to protect, encourage and patronise exporters or the producers ? When you answer the points, you please answer these points also.

The cost of production of tea is very high in India Rs. 11.05 per kg, whereas in Sri Lanka, it is Rs. 6.86 ; in Bengladesh, it is Rs. 7.92 ; in Indonesia, it is Rs. 9.05 and in Kenya, it is Rs. 8.38. Recently, China has come in the world market in a larger way. So, the production, prices, distribution and export are adversely affected. What is the government doing in this matter ? Now, the world competition is very keen.

London is the market for the determination of the prices for all these crop commodities. Now, I'would like to suggest that for the developing countries, it is high time we have a world market of commodities, for different commedities of crops of onsoun. Will the Government take an initiative in this matter ? Instead of London, for determining the prices of crop commodities, for cash crops of the developing countries, can we not first have our own world market ? Forty per cent of the commodity produced is exported. There is lot of money involved in this. Have we got a control over the world market ? Naturally this can be thoughtabout. We can determine what the world price will be. If you examine the industry, there are various sources of financing it, like IDBI, IRCI, IFCI, ICICI, so many agencies are there. A large extent of finance is diverted to the industrial sector. May I ask, what is the percentage given to the agricultural sector ? Therefore, my second submission is that there should be a special banking facility for commodity crops. Then only we can accelerate giving impetus to the agricultural production and give financial assistance to the farmers. Therefore, will the Government take an initiative in that matter also ?

Another basic problem is, there are dual policies and procedures so for as taxation is concerned. There is the Central Government excise duty, income-tax, the State Government's sales tax, plantation tax and what not. Can anyone take it lightly ? She is taking is lightly.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Who is taking it lightly ? At least not ?

SHRI XAVIER ARAKAL : We are discussing very seriously.

Can we not have a rational taxation policy in this matter ? You come to think about it. The State Sales Tax is a matter of hurdle. Plantation tax is another hurdle. There are so many other taxes in this sector. So also the Central Government excise duty, central sales tax duty any other taxes also are there. Therefore, there should be a rational, reasonable taxation policy and procedure. They are given some rebater. I am told that it is very difficult to get a rebate or any concession given by the Central Government. It is rather impossible to get the money refunded. Therefore, there should be a proper arrangement to reduce problem in this matter.

This industry is a regional industry, as it is in some regions only, like north-eastern region, Western Ghats ; To solve their problems there should be a regional autonomous bodies with full authority of finance. All the cultivators and producers have now to come from Cochin to Calcutta for sanction of any amount or assistance. It is very difficult. We have experienced a severe drought in the Tea Estates in Kerala. What have you done for that ? What assistance has the Board given ? You say everything will be channelised by the Board which is located at Calcutta. Why cannot me have an autonomous regional body with full authority in Kerala or anywhere according to the region, for that matter ? I am not parochial. There should be bifurcation of funds. This will be one more point to be brought to your notice. Of course, I am not very keen to say that all the industries should he nationalised. Whatever action the Government has taken is welcome. But it should not be at the cost of the tax payers. It should be implemented and managed properly now. Any expert will now say that to have a proper crop it does not require 14 years ; what I understand is three to four is maximum period for yield. Even if you should start with a new plant, it will also yield results in two or three years.

This Bill is seeking to have 14 years. Anyway, they may have their own reasons. But I take this occasion to say something about the industry as a whole. I hope, my suggestions will be taken note of and something will be done in this matter urgently.

With these words, I support the Bill.

श्री राम लाल राही (मिसरिख) उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे इस बिल का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन बिल को देखने और पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निजी किन्हीं उद्योगों के अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया चल पड़ी है हमारे देश में रुग्ण उद्योगों की, वह बड़ी खतरनाक है। श्रीमन, चाय उद्योग पहले प्राइवेट सैक्टर में था, अच्छा खाता उद्योग चलता था, इसके मालिकान अच्छा मुनाफा कमाते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि मालिक मुनाफा कमाते थे और काम करने वाले मजदूरों को उस मुनाफे का समुचित लाभ नहीं मिल पाता था। कमाई के लालच में उद्योगपति मालामाल होता चला गया लेकिन मजदूर भूखों मरता चला गया और जब देखा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी या पब्लिक इसमें हस्तक्षेप करेगी या मजदूर यूनियन इसमें हस्तक्षेप करेगी तो अधिग्रहण का सवाल सामने आ गया।

आजकल उद्यमी बड़े होशियार हो गए हैं। चाहे चाय उद्योग में हो, चीनी उद्योग में हो या मारुति उद्योग में लगे हों, इन सब का काम एक हो गया है कि उद्योगों में जो पूंजी इन्होंने लगाई है उससे कहीं अधिक पूंजी सरकार से मिलती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं ताकि सरकार के सर यानि जनता के सर यह बोझ चला जाए और जो इन्होंने कमाई की है वह तो की है और सरकार के खजाने से अधिक एंठ लें। मान्यवर यह पूंजीपति का, उद्योगपति का उद्देश्य है जिसको यह सरकार या तो समझ पाने में समर्थ नहीं है या समझता है और समझने के बावजूद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सही कह रहे थे कि मैं काफी पीता हूं या चाय। हम तो ऐसे व्यक्त हैं कि जो मिलता है वही पी लेते हैं।

मैं तो मजदूर परिवार का हूं। मजदूर को जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से अपनी क्षुधा शांत करता है। अगर आप अशोका होटल में ले जाएंगे तो वहां जो मिलेगा वह भी खा लेंगे और खेत में चलें तो गुड़ का शरबत भी पी लूंगा।

मैं चाय पीता हूं इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ बातें इस बिल के सम्बन्ध में कहूं। पहली बात तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपने अधिग्रहण कर लिया और ऐसी स्थिति आ गई एक अध्यादेश लाना पड़ा क्योंकि अधिग्रहण की मियाद समाप्त हो रही है और उसके आधार पर बिल लाए हैं।

माननीय सदस्य गोयल साहब बता रहे थे कि इस चाय की कीमत 40 रुपये किलो हो गई है। मेरी समझ में तो शायद गोयल साहब जानते ही नहीं। अब तो आधे पौण्ड का डिब्बा 40 रुपए में मिलता है। उसमें भी गारन्टी नहीं है कि चाय की पत्ती, चाय के पेड़ की पत्ती है या किसी पेड़ की पत्ती का बुरादा या लकड़ी का बुरादा होगा। जब इतनी ऊंची कीमत वाली चाय की यह हालत है तो बाजारों में साधारण आदमी को जो चाय मिलती है, उसकी क्या हालत होगी? मैं दावे के साथ कहता हूं और मंत्री जी चाहें तो मंत्री के रूप में नहीं नागरिक के भेष में चलें। मैं बता सकता हूं कि पचास फीसदी चाय के तरीके की पत्ती अथवा बुरादा चाय में मिलाया जाता है और बेचा जाता है। इस विधेयक में यह प्रोविजन नहीं रखा कि जो इस तरह की चोर बाजारी या मिलावट करेंगे, उन पर रोक लगायी जायेगी। इसलिए, मैंने सोचा कि मैं मंत्री जी से कहूं कि इस तरफ भी इनका ध्यान जाना चाहिए। जो प्राईवेट मिल-मालिक थे, मुनाफा तो मजदूर का पेट काट कर कमाते थे पर गनीमत थी, उनसे चाय शुद्ध मिल जाती थी। आपने जब इस उद्योग का खुद चलाना शुरू कर दिया और खुद ही मिलावट करने लगे। इसका मतलब साफ है कि निजी उद्यमी पवित्र है और आपके उद्योग में मिलावट है। आपके सरकारी अधिकारी गड़बड़ करते हैं और आप चैक नहीं कर पाते। निजी क्षेत्र का उद्यमी चैक करता है। जिससे मिलावट नहीं हो पाती। इसका राज जानते हैं साफ है। जबसे आजादी आयी है तब से यह मांग हो रही है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि उद्योगों का अधिग्रहण करें जिससे अधिक मिलावट व गड़बड़ हो ताकि जनता का रुझान इस तरफ राष्ट्रीयकरण की मांग से हटे कि यह उद्योग प्राईवेट सैक्टर में रहना चाहिये और पब्लिक सैक्टर में न आए यह सरकार की नियत में है। इस विचार को आपको बदलना होगा अन्यथा आप को समाजवाद का नारा भी बदलना पड़ेगा। आप अपने आपको पूंजीवादी न कहकर समाजवादी कहते हैं। यह सरकार पक्ष का कोरा झूठा जनता को भ्रमित करने वाला है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Say some words about the amendment also.

श्री राम लाल राही : हमारे देश में चाय की पैदावार बढ़ाने के बहुत से क्षेत्र हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद भी मंत्री जी ने कह दिया कि हम कुछ नए बाग लगा रहे है और कुछ पुराने उखाड़ रहे हैं और कुछ नयी व्यवस्था कर रहे है। मैं पूछना चाहता हूं कि

उत्पादन बढ़ाने पर भी दाम ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? कुमायूं क्षेत्र में सन् 1841 में चाय पैदा होती थी उसके बाद सन् 1864 में अंग्रेजों ने चाय पैदा करने की कोशिश की। लेकिन, आपके प्रयास जो इस आजादी के बाद हुए, वह सफल नहीं हो सके। मैंने एक रिपोर्ट "नवभारत टाइम्स" 23 जनवरी 1983 में पढ़ी है। इसमें शीर्षक लिखा है, कुमायुं नी चाय बागानों में अंधेरा।

इसमें लिखा है मौजूदा चाय बागानों में भी कई स्थानों पर चीड़ के पेड़ों के नीचे चाय के पौधे लगे हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीड़ के जंगलो में चाय नहीं लगाई जा सकती है। क्या यह जानकारी प्राप्त करने के

प्रयास किए गए हैं कि चीड़ के जंगलों में दोहरी फसलें पैदा की जा सकती हैं ? बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार सोचे और इस तरह की दोहरी फसलें पैदा करने के लिए अनुसन्धान करवाए और पता लगवाए कि चीड़ के जंगलों में दोहरी आपकी फसल पैदा हो सकती है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में आपने कोई प्रयास किया है ? कुमायुं गढ़ वाले क्षेत्र की तरफ भी आप ध्यान न दें, वहीं जांच न करवाएं बल्कि जहां-जहां चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के जंगल हैं वहां-वहां चाय पैदा हो सकती हो तो करवाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि यह बिल आपका निरर्थक है। चाय उद्योग का आप अधिग्रहण करें। और भी जितने निजी उद्योग हैं उनका आप अधिग्रहण करें, उनका राष्ट्रीकरण करें। लेकिन डर आप को टाटा का है, बिड़ला का है, दूसरे बड़े-बड़े उद्योगपतियों का है कि अगर कल को कहीं चुनाव हो जाते हैं तो उनके ही पास आपको हाथ पसारने के लिये जाना पड़ेगा। इस वास्ते नीति और नियत साफ होनी चाहिए। ऐसे काम आप करें जिन का लाभ देश की गरीब आम जनता पाए। तब देश के लोग निश्चित रूप से आपके गुण गाएंगे। आपने ही नहीं सारे देश ने समझ लिया है कि आप कुछ करने वाले नहीं हैं, आपसे कुछ हो नहीं सकता है।

आप देखें कि आप कौन कौन से वाद चलाते रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। जब देश में संवैधानिक सरकार बनी। तब आपने हरिजनवाद का नारा चलाया, कहा कि हरिजनों का उद्धार करो, उनका कल्याण करो। खूब वोट पाये। 35 साल बीत गए, हरिजन बेचारा आज भी अछूत है, हरिजन है, उसका उद्धार नहीं हुआ। उसमें आप फैले हुए। तब आपने बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया। सन 1971 में दिया। उसमें भी आप फेल हुए। अब आप साम्प्रदायिकता की बात सारे देश में फैला रहे हैं और उसका नाना दे रहे हैं। यह पुन सत्ता में आने का अपना षड्यंत्र है, साजिश है और उसमें भी आप फेल होंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं दो तीन बातें ही कहना चाहता हूं। जब भी आप कोई बिल लाते हैं उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि कभी कभी आप उसके बारे में सोचते नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते...

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : बराबर सोचते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : ज्यादा सोचने से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इस बिल में आपने कहा है :

> "Experience with respect to certain tea undertakings the management whereof had been taken over in 1976 has revealed that for nursing of a sick tea unit or tea undertaking back to health, the maximum period of seven years would not be adequate."

1976 में भी आप एक अमैंडमेंट लेकर आये। आपके एक्सपर्टस ने यह सोचा कि यह ठीक नहीं है। अगर आपको यह मालूम होता है कि टी का डैवलपमेंट इतने पीरियड में होता है, एक छोटे से परपज के लिए, एक लाइन के लिये—

> "As the seven-year period in respect of these tea undertakings was due to expire, the President promulgated the Tea (Amendment) Ordinance on the 7th October, 1983, to increase the maximum period for which the mangement of a tea undertaking or a tea unit can be retained by the Government to eleven years.

इससे मालूम होता है कि आपका डिपार्टमेंट इस तरह से काम करता है। आप इस अमैंडमेंट को कितनी बार करेंगे, आपको अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि टी का विकास कितने समय में हो सकता है।

अभी टी बोर्ड के एक सदस्य श्री संतोष मोहन देव बोल रहे थे। उन्होंने बताया था कि कोई किस प्रकार फंक्शन कर रहा है। उन्होंने बताया कि बोर्ड केवल अपनी प्रमोशन और

सर्विसेज का काम करता है। यही कारण है जिससे हमारी टी का एक्सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है। 22 अप्रैल, 1983 को आपने जवाब दिया था कि 1981 में हमारी टी एक्सपोर्ट की क्वान्टिटी 231,74 मिलियन किलोग्राम थी और वैल्यु 435.27 करोड़ रु० थी। 81-82 में कहा गया कि एक्सपोर्ट 223.09 मि० किलोग्राम हो गई और वैल्यु हो गई 404.61 करोड़।

हिन्दुस्तान एक्सपोर्ट में बहुत आगे था, लेकिन अब स्टेगनेशन हो गया है। हमारे माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि हमारा बोर्ड बिल्कुल ठीक से फंक्शन नहीं करता है। कलकत्ता में इनका बोर्ड रखा गया है।

इन्होंने सोचा था कि एक बोर्ड आसाम में रहेगा और दक्षिण में रखेंगे और दोनों जगह वाइस चेयरमैन रखे जायेंगे। मैनेजमेंट का यह परपज था कि दक्षिण में भी एक फुल फ्लैज्ड चेयरमैन काम करता रहे एक और असम में करता रहे। क्या कारण है कि आप कलकत्त में ही बोर्ड रखे हुए हैं? शिलांग में बोर्ड होना चाहिए जहां कि चाय का उत्पादन होता है, लेकिन आप वहां रख नहीं रहे हैं।

आज टी का डैवलपमैंट नहीं हो रहा है, कारण यही है कि मंत्री जी कुछ नहीं कर पाते। कामर्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स की मिनिस्ट्री है। मंत्री जी फ्री हैं, इनको कुछ काम नहीं करना। गवर्नमेंट की तरफ से ये आटोनामस बोर्ड बना दिये जाते हैं, कहीं भी इनका इंटरफीयरेंस नहीं होता। अगर कहीं होता भी है तो ये कुछ नहीं कर पाते। इनकी डायरेक्शन मानने वाला कोई नहीं है। हजारों बोर्ड बन गये, खर्चा करोड़ों का और वे सर्विस व प्रमोशन की बातें करते हैं इसीलिए आज टी का यह हालत हो गई है।

हमारा टी का डोमैस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है और इतना कि इसे बाहर नहीं भेजा जा सकता है। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हम टी की तरह का और कोई तरीका निकालें जिससे लोगों को उसकी आदत पड़े और वह आदत बदलें।

आज गांव गांव में टी के होटल बन गए हैं और टी का डामेस्टिक कनजम्प्शन बहुत बढ़ गया है। वैस्ट बंगाल वाले बड़ी क्रान्ति की बात करते हैं, लेकिन वे मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उससे उनकी गरदन नीची हो जानी चाहिए। जब मजदूरों ने बोनस मांगा, तो उनको गोली मिली और दो मजदूर मारे गये। उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : कहां ?

श्री मूलचन्द डागा : सरकार पहले इंडस्ट्री को ले लेती हैं, मगर वह उसको रिटर्न क्यों करती है ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Daga can make a reference to the workers. There is no harm. But it is a rare thing that Shri Daga speaks on behalf of the workers. I think, it is the first occasion. You must appreciate it.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Minister, in reply to the question said :

> "15 Tea Estates have so far come under the purview of the Tea Act and out of this the Government have taken over the management of only 5 Tea Estates. Management of other Tea states which was taken over under these provisions had to be handed over back to the owners due to legal difficulties."

सरकार टी एस्टेट को ले लेती है और जब उनका डैवेलपमेंट हो जाता है, तो वह उसे मालिक को वापस कर देती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि लीगल डिफीकल्टीज की वजह से टी एस्टेट्स वापस की गईं। वे लीगल डिफीकल्टीज क्या थीं, यह एक्सप्लेन नहीं किया गया है।

कहा गया है कि स्टेट मिनिस्टर थोड़े दिन के लिए टी गार्डन में जाएं और स्थिति को देखें।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : और हम लोगों को भी साथ ले जाएं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले हम लोगों को अच्छी टी उपलब्ध कराएं । मेम्बरों को बताएं कि टी कैसे बनती है और टी गार्डन्ज में किस तरह काम हो रहा है । सरकार को माडल टी गार्डन बनाने चाहिए ।

MR. DEPUTY SPEAKER : More of the ladies work in the tea garden. Therefore, the hon. lady Minister is the fittest person to work in the Ministery of Commerce.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : टी बोर्ड माननीय सदस्य के और सुझावों को माने या न माने, लेकिन वह इस सुझाव को जरूर मान लेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : चाय हिन्दुस्तान का पेय बन चुका है । टी के क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है । उसका काफी विकास किया जा सकता है । और हमें उससे काफी फारेन एक्सचेंज मिल सकता है ।

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Bihar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, tea industry is a vital industry in our country and it earns about Rs. 300 crores of foreign money every year. But regarding the proclamation, I must say it is the callousness and indifference of the Government. But yet I am supporting this Bill because there is no other alternative. I don't think this Bill is the best. But what I think is, it is good rather than worse.

I do not have the same view as hon. Mr. Santosh Mohan Dev. I could have lent my best support to the hon, Minister had she come forward with a Bill to nationalise all the tea gardens. The present Bill simply contains the taking over the management of the sick and uneconomic tea indurtries under the provisions contained in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. But I would like to know from the hon. Minister whether she is at all serious about the development of tea. I would like to know from the hon. Minister whether she is at all serious about the world market for the tea and foreign money. I would like to know from the hon. Minister whether she is at all serious about the tea trade in the world market. I would like to ask whether the hon. Minister is aware of the fact of mismanagement in the private tea gardens. I would like to ask from the hon. Minister she is aware how the workers are being exploited in the tea gardens.

15.01 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

It is a matter of great regret and shame to say that after 37 years of our independence, we are still in those days which remind us of the novel of renowned writer Mulek Raj Anand *Two leafs and a bud*. We are in the same category as before. If you visit those tea gardens, you will come to know about this. But the hon. Minister and your Government will not do anything for the development of the tea industry and for the improvement of the workers because of the fact that you are committed to capitalistic socialism. (*Interruptions*). You should have explained it to your people because you have given so many calls in those days, socialistic pattern of society and all that. After that, your great leader Mrs. Indira Gandhi gave a clarion call for socialism and all these things. (*Interruptions*). So, it is not possible for you to do all these things.

Mr. Chairman, Sir, it is a matter of great regret and shame to say that the time is not far away when they will have to set some memorial stone with the heading. "There was a tea garden here –the golden tea leaves which brought gold from foreign countries". This is the sad and miserable plight of the workers,

Those who are supporting for the private entrepreneurs must know what amount the Government has spent since March, 1981 to September, 1982. How much money the Government has spent for the development of tea gardens, rather say for the development of tea owners ? I am reading few lines from the report of the Ministry of Commerce under the heading Comprehensive paper on Government Assistance to Tea Industry-October, 1982. I do not like to read all this. In brief, I would like to quote some figures.

Loans and subsidies for Tea Plantation and Manufacture : (Loan at the rate of interest maximum 10.2%).

Loan

Plantation	— Rs. 7.79 crores
Hire purchase for tea machinery	— Rs. 38.34 crores

Subsidy

Tea Replantation — Rs. 3.96 crores
Tea Rejuvenation — Rs. 49.16 lakhs

It is also notable that this is not assessable to central Income-tax. Mr. Sontosh Mohan Dev, you are advocating for the private entrepreneurs. You should know that A. R. D. C. (Agriculture Refinance and Development Corporation) has sanctioned Rs. 103,79 crores with rate of interest not exceeding 12.5%.

He should know that the Industrial Development Bank has sanctioned Rs. 139 crores at the rate of 10 per cent and out of that, the assistance money is Rs. 8.61 crores. The Government have spent Rs. 14.61 crores for Tea Development in non-traditional areas—Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Tamil Nadu, etc.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Are you speaking on behalf of the Government ?

SHRI AMAR ROY PRADHAN : I am not speaking on behalf of the Government. I am saying what the Government has done and how you are advocating for the private entrepreneurs.

The total outlay on Tea Rejuvination Scheme in Darjeeling is Rs. 43 crores....

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Out of Rs. 43 crores, how much money has been given ?

SHRI AMAR ROY PRADHAN : Special assistance to nine clonal nurseries (Tamil Nadu and Kerala) in the order of Rs. 9 lakhs each (Rs. 4.5 lakhs as loan and Rs. 4.5 lakhs as subsidy).

What are the fiscal reliefs granted by the Central Government with effect from 1st April, 1981 ? The Development Allowance under the Central Income-tax Act is as follows :

1. Tea gardens in plains — Rs. 15,000 per hectare
2. Tea gardens in hills — Rs. 17,500 ,, ,,
3. Tea gardens in Darjeeling — Ks. 20,000 ,, ,,

The Surcharge on Central Income-tax in respect of companies has been reduced from 7.5 per cent to 2.5 per cent.

There is lesser excise duty at the production point, that is, 25 paise in place of 40 paise per kg.

With the abolition of excise duty, the revenue loss on account of this measure has been of the order of Rs. 100 crores.

With all this, after so much loan, assistance, subsidy, abolition of excise duty, etc., the hon. Minister must explain to the public what is the net result because it is the public money that is involved. After all this, what is the tea development ?

What about the tea bushes ? It is known to us that after 3 years. the leaves begin to come out—two leaves and one bud. That is the plucking point. From 5 years to 20 years is the best period for a tea bush, in quality as well as in quantity. A tea bush can live upto 80 years and even more, upto 100 years. But what is the average age of our tea bushes in India ? Let the hon. Members who are advocating for the private entrepreneurs know that. What is the condition of tea plantation in our country ? Upto 5 years, it is 4.9 per cent ; from 5 to 20 years, it is 19.7 per cent only ; from 20 to 50 years, it is 22.9 per cent and above 50 years, it is 52.5 per cent. That is, above 20 years, it is 75.4 per cent which means 3/4th of the total tea plantation. So, one can easily imagine what is the future of our tea industry ? What will be the quality and quantity of our tea ? Can you tell us that when all the tea garden owners are fleecing money ? Can you tell us whether our tea industry will be able to compete in the world market and whether, at the same time, it will be able to meet the country's consumer demand ?

Again, we should know that except six cooperatives in the south and five tea gardens (Peshok, Vantukvar, Polong, Looksan and Chargola) under Central Government management and four tea gardens in West Bengal under State Government management, all the tea gardens are in the hands of private entrepreneurs who are looting and bungling with tea gardens. This is the state of affairs.

In this connection, I would like to draw the attention of the House fact which has been drawn by my comrade friend Mr. Ananda Pathak, I have got the newspaper.

We are all opposing you.

(Interruptions)

Revenue of about Rs. 150 crores has gone underground in North-Eastern India in the last six months as a result of the evasion of auction system of tea companies, brokers and exporters, according to an estimate of the Income Tax Department. The Income Tax Department has.....

(Interruptions)

Yes, yes. I am coming to the fact. What you are doing to the private enterpreneur, to the private owner of the tea gardens, to the tea industries and how you are squeezing the tea gardens and tea labourers.

(Interruptions)

That should be examined.

To curb this malpractice, Income-tax Officers swung into action today in Calcutta, Siliguri, Jalpaiguri and other places.

Till this evening in Calcutta, the IT officials detected that an executive of a reputed tea company had a deposit of 35,000 pounds with a London bank. Another 1030 dollars and travellers' cheques for 70 pounds were found in his place. Altogether 16 lockers of different account-holders were seized. In Siliguri, jewellery worth Rs. 2.5 lakh were seized from a tea trader's house.

You just imagine the total money. How you are squeezing. After all, this.....

(Interruptions)

I am asking all these questions through. Chairman to the Hon. Minister.

Through I may support this Bill. I must say, that it will not Serve the purpose. The only purpose can be served only by nationalisation and that should be done and I hope that within a short time, you will bring that Bill in the House.

(Interruptions)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस चाय संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। इस बिल के सम्बन्ध में अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पहले इसकी मियाद 7 साल थी और अब 11 साल की व्यवस्था की गई है—मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले सात सालों में आपने इन चाय बागानों की जो व्यवस्था की है उससे क्या प्राप्ति हुई है ? आपको क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है और अब आने वाले चार सालों के लिए आपका क्या प्रोग्राम है ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या 11 सालों के बाद जब आप का करोड़ों रुपया इसमें इन्वेस्ट हो जायगा, क्या इसको पूंजीपतियों को लौटा देंगे, जिसकी वजह से सरकार का करोड़ों रुपया इसमें इन्वेल्ट हो जाय और उसके बाद इसका फायदा पूंजीपति उठायें ? इसी तरह की व्यवस्था पहले भी इस कामर्स डिपार्टमेन्ट द्वारा कई दफा की गई है, जो कि निश्चित तरीके से नहीं होनी चाहिये थी। जब किसी इण्डस्ट्री को आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका मैनेजमेन्ट खराब है, वह लेबर के इन्टरेस्ट को नहीं देख सकती है, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को पूंजीपति ठीक तरीके से नहीं कर सकता है, उसको बराबर फेल करता जा रहा है, तब सरकार उसको टेक-ओवर करती है। मगर टेक ओवर करने की ही हमारी मंशा नहीं होना चाहिए। टेक ओवर करने के बाद आप वापस मालिक को हैंड ओवर कर देते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि किसी मरीज का आपने इलाज कर दिया और उस पर लाखों रुपया खर्च कर दिया फिर उसे खुला छोड़ दिया। इससे आपकी इण्डस्ट्रीज की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है।

सरकार की धारणा यह होनी चाहिए कि टेक ओवर करने के बाद वह अपने हाथ में ही रखे जिससे कि ऐसी इंडस्ट्री का सारा लाभ राष्ट्र को मिले, उस इण्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मिले उपभोक्ताओं को मिले। अगर किसी इण्डस्ट्री का माल विदेशों में भेजा जाता है और उससे फोरेन एक्सचेंज कमाया जाता है तो उस फोरन एक्सचेंज का लाभ भी देश को मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था आपको निश्चित तरीके से करनी चाहिए।

ये जो चाय बागान आपने टेक ओवर किए हैं इन चाय बागान का 11 साल के बाद निश्चित तरीके से नेशनेलाइजेशन किया जाना चाहिए जिससे कि उनका लाभ देश को मिल सके।

मेरा एक यह भी कहना है कि टी बोर्ड के बारे में एक माननीय सदस्य ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। ये जो बोर्ड बनते हैं—चाहे टी बोर्ड हो, चाहे सिल्क बोर्ड हो, चाहे ओपियम बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो इनमें जो अधिकारी मुकर्रर किए जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का ही ये बोर्ड काम करते हैं। क्या आप बतायेंगे कि आपका टी बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है? उसने टी प्लान्टेशन का विकास करने के लिए क्या क्या काम किए हैं? वहां भी बड़े-बड़े अधिकारी बैठ गए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को भत्ते या दूसरी फैसिलिटीज देने पर इन बोर्डों में लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इन अधिकारियों को कार देने पर, बंगला देने पर और बहुत सी दूसरी सुविधाओं को देने पर ही ये बोर्ड लगे रहते हैं। जब बोर्ड स्थापित हो जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें आटोनोमस बना दिया जाता है। फिर तो वे मालिक बन जाते हैं, जितना चाहे पैसा खर्च करें, कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार की स्थिति इन बोर्डों में है। इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने से देश का कोई भला नहीं होगा। होना तो यह चाहिए था कि इनसे मजदूरों को और इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो यह टी बोर्ड है, इसने टी-प्लान्टेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से इसने प्रोडक्शन से बढ़ोत्तरी की है? आगे यह क्या काम करने वाला है जिससे कि देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो? ऐसी व्यवस्था आपको निश्चित तरीके से करनी चाहिए।

आज मैनेजमेंट की क्या हालत है? जितना जितना भी वहां पर मेनेजमेंट हैं...

15.19 hrs.

[MR. SPEAKER *in the chair.*]

MR. SPEAKER : There is no quorum in the House, Let the quorum bell be rung. ...Now there is quorum in the House.

15.20 hrs.

WELCOME TO SYRIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

MR. SPEAKER : Hon'ble Members, I have to make an announcement. On my own behalf and on behalf of the Hon'ble Members of the House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Mohmoud Al-Zoabi, Speaker of the People's Council of the Syrian Arab Republic and the Hon'ble Members of the Syrian Parliamentary Delegation who are on a visit to India as our honoured guests.

The other Hon'ble Members of the delegation are :—

1. Mr. Nazir Doweidary, M.P.
2. Mrs. Hajar Sadeq, M.P.
3. Mr. Mahoude Nasif, M.P.
4. Mr. Ahmed Dasho, M.P.
5. Mr. Ibrahim Alouzy, M.P.
6. Mr. Abdo Hoddad, M.P.

The delegation arrived here this morning They are now seated in the Special Box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them we convey our greetings and best wishes to the People's Council, Government and the friendly people of the Syrian Arab Republic.

15.23 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF TEA (AMENDMENT) ORDINANCE AND TEA (AMENDMENT) BILL

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Sir, we hear that the President of Syria, Mr. Assad, is not well. so, we send him good wishes for speedy recovery and that should be conveyed.

MR. SPEAKER : The good wishes will be conveyed. Now, Mr. Girdhari Lal Vyas will continue with his speech.

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाय बागानों के बारे में जो यह बिल है, जिनको इन्होंने अधिग्रहण किया है, उनके माडर्नाइजेशन के संबंध में इन्होंने क्या

व्यवस्था की है। कोई नए प्लांटेशन लगाए गए हैं, आमदनी बढ़ी है या नहीं। इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है, इसका कोई जिक्र नहीं आया। यह जिक्र आवश्यक था। जब तक यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक भविष्य में भी जो चाय बागान टेक ओवर किए जाएंगे, टेक ओवर करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा।

इसी तरीके से मजदूर के संबंध में आपने क्या व्यवस्था की है। यह सबसे ज्यादा लेबर ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री है। लेबर इन्डस्ट्री होने के बाद जिन मालिकों के जमाने में यह उद्योग आपने ले लिया था, उसके इ०एस०आई० प्रोविडेण्ट फण्ड और ग्रेच्युटी आदि के बारे में आपने क्या किया ? सारे मजदूरों को इससे लाभान्वित किया या नहीं ? वैस्ट बंगाल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वहां पर कोयले के साथ-साथ चाय की भी स्मगलिंग होती है। उसको रोकने में आपने क्या व्यवस्था की है जिससे आपका फारेन एक्सचेंज बढ़े।

मेरा दूसरा निवेदन खासतौर से प्राइसेज के बारे में है। इस संबंध में सभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। इसकी प्राइसेज बराबर बढ़ती जा रही है। आज यह गरीब आदमी का पेय हो गया है। बाहर से आप जितनी मर्जी चाहे कीमत वसूल करें लेकिन डोमेस्टीक परपज के लिए कीमत कम कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसको एग्रीकल्चर की तरह प्रायोरिटी सैक्ट में लिया जाना चाहिए क्योंकि लाखों मजदूर जो इस पर पलते हैं और शेड्यूल्ट कास्ट्स, शेड्यूल्ट ट्राइब्स तथा वीकर सैकशन्स के लोग, जिनकी रोजी-रोटी इस पर चलती है, उनकी व्यवस्था करने के लिए आप इसे प्रायोरिटी सैक्टर में लें। कम इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है जिससे यह इन्डस्ट्री फलती-फूलती रहे। कल भी मैंने प्राईवेट इन्डस्ट्रीज के बारे में कहा था कि ऐसी इन्डस्ट्रीज को जान-बूझकर सिक बना दिया जाता है और वे लोग इसके असेट्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं। आपने इनके असेट्स को ट्रांसफर न होने देने के लिए और गलत तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से पैसा लेकर जो दुरुपयोग करते आ रहे हैं, इसको रोकने की क्या व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सारी इन्स्ट्री को नेशनलाइज किया जाए जिससे मजदूर और सारे देश को फायदा पहुंच सकता है।

MR. SPEAKER : Now, the Minister.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Mr. Speaker, Sir, I like to thank all the hon Members who have participated in the discussion.

MR. SPEAKER : The hon. Minister may continue later.

Now, the Minister of External Affairs will make a statement.

15.30 hrs.

STATEMENT COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING HELD IN NEW DELHI FROM 23rd TO 29th NOVEMBER, 1983

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : Mr. Speaker, Sir, Hon'ble Members would have seen the texts of all the various documents issued at the end of the Commonwealth Heads of Government Meeting in New Delhi from 23 to 29 November. These are the Goa Declaration on International Security ; the New Delhi Statement on Economic Action and the Final Communique. (Copies have since been kept in the Parliament Library). 42 out of 44 full members of the Commonwealth participated in the meeting ; 34 at the level of President or Prime Minister. It was the largest sumit meeting in Commonwealth history. The majority of Commonwealth members are nonaligned nations. A few belong to the industrial North and military alliances. There is great diversity in their size, population and stages of development. Nearly half the countries are small states with less than 600,000 population. It was thererfore, natural that this gathering should represent

a kaleidoscope of the world's concerns and probelms. But they all had also a common purpose in meeting to seek answers to some of the most difficult political and economic issues of the day.

Unlike the nonaligned summits, where issues are openly debated by leaders and communiques prepared on the basis of drafts submitted by the host country, Commonwealth meetings are more confidential and informal in character and the drafts are initially prepared by the Commonwealth Secretariat. There were nevertheless some very frank and candid exchanges of view on important issues even though the style was different. The dialogue among Heads of Government without aids was continued during the Goa retreat.

Coming as it did after the Nonaligned Summit in New Delhi and the leaders' consultations in New York during the 38th session of the U.N. General Assembly, the Commonwealth Summit provided a useful and timely opportunity to discuss the urgent issues related to peace, disarmament and development.

The Summit's attention was focussed on a few important issues ; the tense world political scene and the nuclear threat, the difficult global economic situation, and the need for North-South Dialogue and specific issues such as the independence of Namibia, and the developments in Grenada and Cyprus.

In her opening statement at CHOGM, the Prime Minister outlined the major problems of peace and security, disarmament and development and called upon the Commonwealth to be clear in its objectives but responsive to changing stuations in dealing with the world problems through dialogue.

For India, the threat to humanity posed by the ever increasing stocks of nuclear weapons, the issue of general and complete disarmament, the growing trend towards interference and intervention in the affairs of small nations, illegal recourse to force and disregard for the norms of international behaviour and problems affecting developing nations are matters of deep concern. Consistent with our support for decolonisation, we have vigorously compaigned for Namibia's independence and I am glad that the Meeting considered the linkage, so-called, between the withdrawal of Cuban troops from Angola and the independence of Namibia irrelevant and asked for the full activation of the U. N.'s role in terms of Resolution 435 of the Security Council. The Summit expressed itself in a forthright manner on Cyprus, Palestine, Grenada, the situation in Central America, militarisation of the Indian Ocean. Equally, the leaders put forward their views on the lack of progress in the North-South dialogue, protectionism and decline in multilateral concessional assistance.

What was the outcome of a great assembly of nations held in India's capital, for the second time this year ? Did they succeed in providing some of the solutions to the problems of security and development or finding ways to reduce tensions and restore confidence about the future ?

A large measure of agreement was achieved on many of the issues that I have mentioned above. There was consensus on the problems of Cyprus, Namibia, the Indian Ocean nnd Central America There was a large measure of agreement on the West Asian situation which poses to world peace as on the lnalienable rights of the Palestinians. Thete was a general understanding on Kampuchea and Afghanistan which had in the past proved very contentious issues.

As Prime Minister said in her opening speech at the inaugural session, we cannot agree on all matters but we try to find some common ground. And this is precisely what happened. Indian's views on important issues were adequately reflected in the CHOGM documents. Prime Minister had felt that the Commonwealth must urge the United States and the Soviet Union to exert themselves with greater determination to break the stalemate in the negotiations on disarmament. The Goa Declaration on international security stated : "As Prime Minister Indira Gandhi has so consistently emphasised, the central issue in securing wider progress on disarmament is the stopping of the nuclear arms race". It called for the resumption of a genuine political dialogue to reduce tensions and achieve progress on disarmament in order to lift the menace of nuclear weapons from the world.

Prime Minister had also spoken about the pressures to which small countries

following independent policies were subjected. The Goa Declaration expresses concern at the vulnerability of small states to external attack and interference in their affairs. It states that these countries are members of the international community which must respect their independence and at the very least have a moral obligation to provide effectively for their territorial intergrity.

The Commonwealth has come a long way from a small club of affluent nations to a large multi-racial organisation with a world-wide membership and a deep interest in the world's political and economic problems. India has played its part in the evolution of this new Commonwealth and in making it relevant to the concerns of the nonaligned and other nations who share some of these goals. The decisions taken at New Delhi on Southern Africa should contribute to the Namibian people's struggle for independence and the black Africans' struggle against apartheid and racism. The condemnation of the Unilateral Declaration of Independence by the Turkish Cypriot authorities and the Commonwealth's pledge of support for the independence, sovereignty, territorial integrity, unity and nonalignment of the Republic of Cyprus will reinforce the Commonwealth's call to all States not to countenance the illegal secessionist entity. A special Commonwealth Action Group on Cyprus has been set up at a high level to assist in securing compliance with the Security Council Resolution 541. The Group which consists of Australia, Guyana, India, Nigeria, Zambia together with the Secretary-General has already held its first meeting.

Our principled and forthright position on the West Asia has not in any way been weakened by the paragraphs in the Joint Communique relating to this subject. On the contrary, the Commonwealth meeting appreciated the successful efforts of the Nonaligned Mission in securing the ceasefire in northern Lebanon. Even on Grenada which was a hotly debated issue during the Conference, the Commonweath leaders called for the strict observance of the principles of independence, sovereignty and territorial integrity. They looked forward to the functioning of the interim civilian administration in Grenada, free of external interference, pressureor the presence of foreign military forces. It is our hope that foreign troops will be withdrawn from Grenada without further delay.

The New Delhi statement on Economic Action is on the whole good even though it does not meet our expectations. It does open the door, even if slightly, to further progress in the direction of reforming the international economic system. It calls for a comprehensive review of the international monetary, financial and relevant trade issues. It underlines the urgency of the process of preparatory consultations to indentify areas of agreement, potential agreement and areas requiring further consideration. It is our expectation that this would eventually lead to the international conference with universal participation on money and finance for development which the Nonaligned Summit had called for.

The call for prompt and substantial additional resources for international financial institutions and the emphasis on progressive relaxation of protectionist measures are positive gains. To stimulate a dialogue on long-term issues between developed and developing countries and to promote consensus, the Commonwealth meeting established a consultative group of eight nations. The group will consist of official representatives from Britain Canada, Fiji, India, New Zealand, Tanzania, Trinidad and Tobago Zimbabwe together with the Secretary-General. It will submit its report to Finance Ministers before their meeting next year in Toronto.

I should like to stress that a world-wide dialogue in absolutely necessary to pull the world away from nuclear catastrophe and to tackle urgent political and economic problems. India has all along called for such an approach, not just for super powers but at all levels in order to create a climate of mutual understanding and confidence which alone can make a forward movement possible on a host of outstanding issues. Prime Minister said at the Summit meeting at the United Nations recently that there is no alternative to negotiations and dialogue in our inter-dependent world. In fact, we need a series of dialogues on East-West relations, on disarmament and arms control, on North-South issues as well as on such common prob-

lems as preservation of the environment, care of the young and protection of the weak. Issues of particular concern to non-aligned countries must remain high on the international agenda. For security and progress are not just for the powerful or the rich ; they may be important for them but for the weak and the poor they are materts of life and death.

Apart from the issues on the agenda of the Commonwealth meeting, we discussed with various visiting dignitaries, issues of bilateral interest and ways and means of promoting cooperation between India and these countries. It was gratifying to note that many Commonwealth leaders visiting India for the first time or after a lapse of several years, expressed keen interest in strengthening relations with us especially in scientific and sicklogical cooperation, education, education, culture, and so on. The Commonwealth leaders sojourn to Goa and the visits by their Ministers and senior officials to Jodhpur, Jaipur and Agra gave them a glimpse of India's rich cultural heritage and her traditions of hospitality and tolerance.

In the course of the last 12 months, New Delhi has played host to three major events of world importance—the Ninth Asian Games, the Nonaligned Summit and now the Commonwealth Heads of Government Meeting. These events have raised the country's prestige abroad and in the comity of nations.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF TEA (AMENDMENT) ORDINANCE-*CONTD.*
AND
TEA (AMENDMENT) BILL-*CONTD.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : Sir, at the outset I would like to thank the Hon. Members, who participated in today's discussion. I would like to mention their names : Shri Goyal, Shri Pathak, Shri Sontosh Mohan Dev, Shri Murugian, Shri Arakal, Shri Rahi, Shri Daga, Shri Pradhan and Shri Girdhari Lal Vyas. It shows how much interest they have for preservation and growth of this industry and for the welfare of the workers.

Sir, some of the Hon. Members have shown their tempers against the Government's measures and the Government's policies in this regard and I would like to say that it is but natural for them. But some have also appreciations for the steps taken bp the Government to improve production and also the lot and conditions of the workers engaged in tea industry.

Sir, the scope of his amendment is very much limited and hence it is not possible for me to reply to all of their suggestions made here. But I assure the Hon. Members that I have that I have taken note of all their suggestions and steps can be taken in this regard as and when found necessary. We will also try our best to come to the expectations expressed by my Hon. Friend, Shri Sontosn Mohan Dev.

As regards Shri Arakal's suggestion, the Government is very much seized of all the problems raised by him here. His indepth study to this industry shows his keen interest and the intelligence he has shown in this regard is a matter for appreciation.

Sir, I would like to mention only a word about the Hon. Member of the Opposition, Shri Rahi. He is always in the habit of expressing something or other against our Government and the Government's policies. He said :

आजादी के 35 वर्ष बीत गये लेकिन चाय बागान के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे इतना ही कहना चाहती हूं कि दुनिया के नक्शे पर, शांति और सहयोग के क्षेत्र में, उत्पादन उत्पादकता के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नालाजी के क्षेत्र में, गरीबी मिटाने के क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष ने क्या कुछ किया है और दुनिया के मानचित्र पर भारत का नेतृत्व कितना आगे बढ़कर चमक रहा है, माननीय श्री रामलाल राही को इसका पता ही नहीं है।

जब अंग्रेजों से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कहा करते थे;

उन्हें यह फिक्र है हरदम
नयी तर्जे जफा क्या है,
हमें भी शौक है देखें
सितम की इन्तहा क्या है।

15.41 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : कन्टेनर और क्लोजर फैक्ट्री में बंगाल में आपने 900 आदमियों को बेकार कर दिया।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : किन्तु मैं राही जी को यही कहना चाहती हू: "नमक छिड़को, नमक छिड़को मजा ही इसमें आता है, कसम ले लो, नहीं आदत कभी घावों की भी मलहम लगाने की।"

I would like to say a few words to Mr. Roy Pradhan. He has made some wrong statement regarding some of the tea gardens. (*Interruptions*) Please have some patience.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Bihar) : Then your Department is in the worng. All these records are from the department concerned.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : As regards his statement, I would like to say that only one tea garden, i. e. Kuhai tea estate was returned after take-over, under court orders. This garden was managed by West Bengal Tea Development Corporation. It is not a fact that 15 gardens were returned.

जहां तक डाया जी को अच्छी अच्छी चाय पिलाने का सवाल है, सैन्ट्रल हाल में वे पी ही गहे हैं यदि वे मेरे दफ्तर में आधेरी तो उनको अच्छी चाय में पिलाऊंगी।

The sustained development of the tea industry which provides employment to over two million people, has been and continue to be a vital concern of the Government in view of India's position as the largest producer, consumer and exporter of tea. The industry has registered considerable progress since Independence, the production having gone up from 227 million Kgs. to 585 million Kgs., and yields from 900 kgs. per hectare to 1500 kgs, per hectare.

During this period like other agricultural commodities, the tea industry had spells of boom and stagnation. Instances of sickness and periods of stagnation are common features in all sectors of economic activity all over the world and are not unique to the tea industry.

श्री मोहम्मद इस्माइल : मंत्री महोदया क्या बोल रहीं हैं या पढ़ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माइक्रोफोन लगाकर सुनिए।

श्री मोहम्मद इस्माइल : माइक्रोफोन नहीं चल रहा है।

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Stagnation and sickness in agaricultural commodities like tea may be the result of agro-climatic factors, depressed marketing conditions on account of over-supply, lowering of real prices accompanied by inrceased cost of production.

मुझे उम्मीद है, इस्माइल साहब अब ठीक से सुन रहे होंगे।

In recent years, the tea industry in India has had to face intense competition from the newly emerging tea growing countries equipped with the latest machinery and producing tea in virgin areas from young. bushes.

Prevention is better than cure, Government. on the basis of continuous dialogue with industry, has attempted to anticipate difficulties and take appropriate measures for constant improvements and increased yields, to keep pace with rising costs. New areas need to be planted, and old areas subjected to rejuvenation and re-planting, in order to increase production to meet the increasing requirements within the country as well as to maintain our position abroad. The effects of fluctuation in international markets are sought to be mitigated by intensive promotional campaigns, as well as efforts to arrive at an international tea agreement.

It is obvious that for an agricultural commodity like tea, sickness may not only result on account of mirmanagement. By and large, the industry has been doing well. However, Government of India did note with increasing concern cases of mismanagement, neglect and over-exploitation of tea estates that were brought to its notice. There have been complaints of neglect of tea gardens, by unscrupulous owners resorting to short term measures to increase production by over-exploitation, without any inten-

tion of investing money to maintain the tea gardens. Essential measures like application of fertilizers and pesticides, re-planting and maintenance activities were being neglected.

There were even complaints of felling of trees for use as fire-wood and disregard for labour welfare measures, including non-payment of labour dues for 7 to 8 years. Certain tea gardens had defaulted in making payments to banks and financial institutions. Yields had come down' drastically.

It was necessary to arm government with powers, to prevent over-exploitation and reckles mismanagement as well as to be able to take measures for restoring the gardens to health.

Chapter 3(A) of the Tea Act was introduced in 1976 with this objective. The provisions are along the lines of similar provisions (Development & Regulation) Act, for take-over of management and control of schedule industries, for a specified period. These amendments provide for a takeover period of five years extendable by another two years. The total period of takeover is now proposed to be increased from 7 years to 11 years.

At present, 5 sick tea gardens are being managed under the provisions of the Tea Act. The revival of these gardens has not been on easy task. The gardens have arrived at their present stage of sickness as a result of years of neglect and over exploitation. Large investments are now needed to restore them to health. Mismanagement had also created discontent and unrest among labour. This situation can be improved only gradually, some cases, owners of the taken-over gardens have involved the authorised persons in litigations. This has delayed implementation of necessary programmes for restoration and revival of such gardens. More or less coinciding with the period of take-over, the tea industry has been passing through a period of stagnation and this has made the task of restoring these gardens to financial viability even more difficult.

The tea industry has recently started picking up and with rising demand for tea, both at home and abroad, it is expected that this trend will continue. It is hoped that the extension of management take-over period will help to improve the financial viability of the taken over gardens and enable a proper assessment of their long-term potential.

Despite various difficulties, the taken-over gardens have registered the following improvements since the date of take over :—

(a) By and large, the statutory liabilities for wages and other dues to labour have been discharged by the authorised persons.

(b) The productivity and output have registered increase after take over.

(c) Essential maintenance and repairs have been carried out in spite of difficulties relating to litigation and finance.

(d) The very fact of take over of management of some tea gardens has served to warn unscrupulous garden owners from reckless mismanagement of the gardens.

While it would be pointless to continue to extend the period of take-over of gardens which are assessed to be patently non-viable the Government must fully satisfy itself that such gardens have gone beyond the stage of recovery and revival. In case the gardens are denotified without such efforts, the socioeconomic objectives of take-over to help the the revlival of the gardens and prevent unemployment will be defeated.

De-notification on a large scale may also encourage every unscrupulous owner to resort to seeking quick profits through over-exploitation and then abandon the gardens to their fate. This may also have a snow-balling effect on the the tea industry.

In line with the guidelines, issued by government relating to the policy on sick industries, the Tea Board is in constant touch with the banking and financial institutions in order to be able to monitor sickness and take timely corrective action. There may be cases where policy initiatives are required in order to prevent sickness. A flexible approach has to be adopted.

For instance, fiscal measures whitch seem perfectly reasonable during a period of boom may start acting as a drag in a period of stagnation. An existing development scheme may become unworkable, with the

change in the economics of production and may need revision. Here, I may quote the examble of the Darjeeling Tea Industry. Drajeeling tea has become a legend and has been considered synonymous with premium quality fetching fancy prices. However, market conditions and consumptton patterns have changed. The demand is small as compared to other types of tea and real prices have remained stagnant. Productivity increase has been low, on account of special topographical and agro-climatic factors. At the same time, the cost of production has risen on account of the increase in cost of labour and other inputs.

In order to tackle this problem, a three fold strategy is being evolved. Special marketing efforts are needed to obtain premium prices for Darjeeling tea. Research and development efforts have to be concentrated to increase productivity and reduce the cost of cultivation. Fiscal levies will have to be reviewed to ensure that production of Darjeeling tea does not remain unremunerative and incentives have to be provided to encourage investment and rejuvenation. Work on preparation of appraisal reports for Darjeeling tea gardens has been started by Tea Board in consultation with the banks, so that the interest-subsidy scheme can be successfully implemented.

As I have already mentioned, there may be cases where in spite of efforts by the Tea Board, banks and necessary policy initiatives by the Governments, problems of sickness still remain. Wherever mismanagement is identified, as the primary cause, the solution would lie in management takeover, followed by attempts at revitalisation. After an initial period of takeover there are various options available to Government. The gardens may be sold as a going concern, after initiating liquidation proceedings of the owning company, which has mismanaged the gardens. Alternatively, attempts can be made for merger of such units with healthy units. Nationalisation will have to be considered if other means fail and the tea gardens are assessed to be potentially viable. There may however be cases where the tea gardens are assessed to be potentially non-viable, in which case, nationalisation would serve no purpose and would simply be a permanent drain on the exchequer In such cases, the decision of management takeover, may be the only course left.

In view of the socio-economic implications of closure, every effort has to be made to examine the possibilities for revival. The management takeover period may have to be rather long, in view of the long gestation period, before a proper assessment can be made.

It would not be out of place to mention here that under the ID & R Act, 1951, the provision for management taken over period is five years, extendable by a maximum of 12 years. The Tea Act provides for takeover for five years, extendable by another two years. On the basis of the experience of taken over gardens, Government is of the considered view that a period of seven years is not adequate in all cases, to provide effectively for all the management and developmental inputs necessary to restore the gardens back to health. Some time is lost in initial litigation, regarding takeover. The tea plant has a gestation period of about six years. Appraisal of the economics of the estate and a phased programme of rehabilitation would therefore require another eight to nine years. I have not proposed an open ended or unduly prolonged take over period. At the same time the take over period should be sufficient to allow for rehabilitation or to come to a conclusive finding that the garden is patently non-viable. I am therefore unable to agree to a longer take over period, as suggested by some Honourable Members.

To sum up, I would like to reassure the House that Government is fully seized of the problems of the tea industry. Efforts are constantly being made in consultation with the tea industry, to ensure increased production, to meet the rising domestic demand as well as to retain our primaey in the export market. The Governmenr is fully alive to the needs of market promotion for maintaining our exports in the face of increasing competition and increased foreign exchange earnings required by increasing the export of value-added teas. Consultations are being held with the State Governments to extend tea production to non-traditional areas. Schemes to revitalise the existing plantations are under constant review and new schemes are being evolved. Government is closely monitoring the

industry in order to take appropriate measures on signs of sickness and stagnation.

I would urge the House to pass the Tea Amendment Bill which has been submitted for consideration. A period of extended management take-over is necessray for tea in view of the agricultural nature of operations with a long gestation periods to ensure effective action for improvement of management of tea gardens which may have to be taken over by Government from time to time.

16.00 hrs.

STATEMENT RE. NEW OIL STRIKE IN GODAVARI OFFSHORE

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PETROLEUM IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA) : Sir, I am happy to announce the discovery of oil in well G-1-6 drilled on G-1 structure in Godavari offshore by the ONGC.

Flow of oil has been obtained on conventional testing of G-1-6 well, which is a step-out well on the G-1 structure in Godavari offshore. This well located at about 2 kilometers South West of discovery well G-1-1 was spudded on 8th August, 1983 at a water depth of 248 meters and drilled down to 3208 meters. The 5th object perforated in the interval of 2150-2152 meters and 2154-2156 meters has produced oil and gas at the rate of 876 barrels per day with the GDR of 131 through 1/4" choke during the initial testing carried out on 1.12.1983. and 2-12-1983. Further testing of zone is in progress. One more object will be tested in this well. The well is located about 75 kilometers South West of Kakinada and 25 kilometers from the coast.

The first well on the structure, G-1-1, located at the water depth of 250 meters, produced 33° API oil at 500 barrels a day through 32/64" choke from a Neogene sand. In this a hisher sand produced significant quantity of gas with condensate on commercial testing.

G-1-6 is the second hydro carbon bearing well on this structure. G-1-6 well establishes the continuity of the accumulation. Further testing of this well and the drilling of more delineation wells will indicate the commercial viability of the accumulation. It may be recalled that oil and gas were also struck in the adjoining structure G-2 in February, 1983 also in Neogene sands. It confirms the petroliferous nature of the sediments of Krishna Godavari basin and thus significant for continuing offshore exploration in this basin where 3 exploratory wells out of 14 drilled in the offshore part of the basin have been found to be hydro-carbon bearing.

Present plans call for the drilling of two more step-out wells on the G-1 structure to assess the extent of accumulation.

MR. CHAIRMAN : We were to take up further discussion under Rule 193 at 4 O' Clock but the discussion on the Tea (Amendment) Bill will not take much. Is it the pleasure of the House that we conclude the Bill and then take up further discussion ? It will not take much time, it will take only 5-10 minutes.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : पहले यह बताया जाए कि पंजाब का क्या होगा ?

सभापति महोदय : इसके बाद ही होगा ।

श्री मनी राम बागड़ी : अगर रात को पंजाब चलेगा तो क्या फायदा होगा ? कैसे छपेगा ?

MR. CHAIRMAN : What is the sense of the House, let me know ?

SOME HON. MEMBERS : We oppose.

MR. CHAIRMAN : Then we take up further discussion under Rule 193 Shri Harish Rawat...(*Interruption*). We shall take it up later on.

श्री राम लाल राही : माननीय मन्त्री जी ने मेरा नाम लिया है ।...(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN : We will do it. We have taken up the other important subject. You reserve your right or take it up tomorrow or later on when the Bill is taken up....

(*Interruptions*)

Why don't you listen to me it will be

taken up after this discussion, then you can make your point if you like.

Now Shri Harish Rawat.

16.08 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the chair*]

16.08 hrs.

DISCUSSION ON THE STUATION ARISING OUT OF REPORTED TRAINING CAMPS FOR TRAINING OF EXTREMISTS OF PUNJAB IN NEIGHBOURING AREAS OF THE STATE-*CONTD*

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, आज जो जम्मू-काश्मीर से हुक्मरान हैं, वह इस देश की एक महान परम्परा की कड़ी हैं। मैं समझता हूं, जो प्रश्न यहां पर डिसकस किया जा रहा है, उसके संदर्भ में उनको भावुकता से या राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। मुझसे लेकर डॉ० स्वामी तक किसी भी व्यक्ति की यह दिली ख्वाहिश होगी कि इन कैम्पस के विषय में जो कुछ अखबारों या मैगजीन में साया आ रहा है, वह सत्य न हो। कोई भी राष्ट्र-भक्त इस बात को सहन नहीं कर पायेगा कि उग्रवादियों के कैम्प आयोजित किए जाएं और उन कैम्पों में लोगों को जाति विद्वेश और धार्मिक विद्वेश तथा ऐसी उग्रवादी कार्यवाहियों की ट्रेनिंग दी जाए जिससे राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ सकती है। कोई भी इस बात को सहन नहीं करेगा कि इन कैम्पों में भारत के झण्डे या परम्परा की अवहेलना करने की छूट दी जाये। वह चाहे वरक ग्राम उधमपुर, पुंछ, पुलवाना, बारामुला या दिगाना आश्रम की कैंप हो या वह कैम्प हो जिसको एक दो दिन पहले जम्मू-काश्मीर के मुख्यमन्त्री जी ने सम्बोधित किया है। हम चाहते हैं कि इन समाचारों को यकीन न करें। हकीकत कुछ और ही बताती है। नए मुख्य मन्त्री के द्वारा इन कैम्पों को अटेन्ड किया जा रहा है और उनकी प्रेजेन्स में लोगों के द्वारा खालिस्तान आदि के नारे भी बुलन्द किए जा रहे हैं। ए० आइ० एस० एस० एफ० एक उग्रवादी संगठन है जिसकी गतिविधियां भी अवांछनीय हैं। उस संगठन के निमंत्रण पर एक मुख्य मन्त्री अमृतसर भी जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश या बीमार पड़ जाने के कारण वे जा नहीं पाए। यह भी एक हकीकत है।

चाहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच हो चाहे मीर वायज फारूख के साथ श्रीनगर में चुनाव के समय किया गया समझौता हो या उसके बाद मीर वायज फारूख के साथ दोहराई गई यह बात हो कि हम जिहाद के लिए तैयार रहें, ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जो अपने आप में जुड़ी हुई हैं।

आज मुख्य मन्त्री बार-बार एक बात दोहराते हैं। यह कहा जाता है कि राज्य के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू काश्मीर के मुख्य मन्त्री इस तरह की बात दोहराते हैं तो उससे सारे देश को नुक्सान होता है। वहां जो उग्रवादी संगठन हैं जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करते हैं, जमायते तुलबा हैं, इस्लामी मुहाजे आजादी है, उनको बढ़ावा मिलता है। आप तो जानते ही हैं कि श्रीनगर में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मुख्य मन्त्री की उपस्थिति में हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, हिन्दुस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए।

आज जम्मू काश्मीर में अपने राजनीति विरोधियों का दमन करने के लिए पुलिस एक्ट 1925 का सहारा लिया जा रहा है। एक नौजवान का एक बयान शाया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको मुख्य मन्त्री को कंट्रैडिक्ट करना चाहिये था, उनका प्रतिवाद करना चाहिये था लेकिन नहीं किया। यह गम्भीर आरोप है। उससे किसी भी व्यक्ति का दिल शंका से भरे बिना नहीं रह सकता है।

जो कुछ भी आज इन ट्रेनिंग कैम्पों में हो रहा है, या पंजाब में जो घटनाएं हो रही हैं उस

संदर्भ में हम पड़ोसी मुल्कों को भी नहीं भूल सकते हैं। जनरल जिया के द्वारा जिस प्रकार गंगा सिंह ढिल्लों को आमंत्रित किया गया, जिस प्रकार का बयान उनका एक मैगजीन में छपा है, उसको देखकर अफसोस ही होता है। साथ-साथ पाकिस्तान के विदेश मन्त्री कहते हैं :

Kashmir is not a forgotten issue.

गिलगित में डिनर देकर भारत को प्रोवोक करने की कोशिश हो रही हैं, हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है।

ये सब घटनाएं चिन्ता का विषय हैं। जम्मू काश्मीर में या पंजाब में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर हमें पैनी नजर रखनी चाहिये, उनका बारीकी से अध्ययन करना चाहिये। एक और गम्भीर खबर अखबारों में छपी है। यह कहा गया है कि इन कैम्पों को एक अरब शेख द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। राज्य सभा में कहा गया कि सी आई ए के द्वारा जनरल जिया के नेतृत्व में पाकिस्तान में उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के मामले में डा० स्वामी विशेषज्ञ हैं और वही इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। लेकिन पंजाब में जो घटनाएं घटित हो रही हैं चाहे भिंडरांवाले की धमकी हो अकाली दल द्वारा उनको राजनीतिक संरक्षण देने की बात हो या युनाइटिड फ्रंट के द्वारा दिया जा रहा समर्थन हो, इस सब पर से हम आंख और कान बन्द करके बैठे नहीं रह सकते हैं। सदन को भी इन सब कड़ियों पर गहराई से विचार करना चाहिये और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये। निश्चय ही पंजाब की ये सारी घटनाएं ट्रेनिंग कैम्पों के साथ जुड़ी हुई हैं।

अकाल तख्त द्वारा बार-बार लोगों द्वारा निवेदन करने के बावजूद भी इन्कार किया जा रहा है कि हिंसा के खिलाफ वह हुकमनामा जारी करे। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लोगों को और पार्लियामैंट को एक मत से अकाली दल को कहना चाहिये कि हुकमनामा जारी करवा कर इस प्रकार की हिंसक वारदातों को रोकने की उसको कोशिश करनी चाहिये। साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिये कि जब तक अकाली मोर्चा कायम रहेगा तब तक पंजाब में किसी प्रकार की शान्ति नहीं हो सकती है और मोर्चे को समाप्त करके प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री ने जो वार्ता का उनको निमंत्रण दिया है उसको उनको स्वीकार कर लेना चाहिये और वार्ता के लिए आ जाना चाहिये।

माननीय प्रधान मन्त्री ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सीमा-विवाद के समाधान का काम एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाए। किसी को भी इससे मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन अकाली दल इसको मानने से इन्कार करता है। लोंगोवाल के नेतृत्व में अकाली दल इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के बजाए इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। लोंगोवाल ने एक बयान में कहा है कि कामनवेल्थ कन्ट्रीज के हैडज को इस मामले पर विचार करना चाहिए। जो राजनैतिक दल भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता है और भारत के संविधान के अन्तर्गत एक राजनैतिक दल के रूप में कायम है, उसको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए और हर भारतवासी को उस पर एतराज होना स्वाभाविक है।

अकाली दल और ए आई एस एस एफ के लोगों ने अमृतसर में बसें जलाईं। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि निरंकारी चीफ के हत्यारे, रंजीत सिंह, को रिहा किया जाए। यदि कोई राजनैतिक दल किसी हत्यारे को रिहा करने की मांग करे, कानून का मुजरिम है, तो कोई भी सरकार उसको नहीं मान सकती। विरोधी पक्ष को और युनाइटिड फ्रंट के लीडर साहबान को – उसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग व्यूज हैं, इसलिए वास्तव में वह डिसयुनाइटिड फ्रंट है— इस समस्या पर इस व्यूपायंट से विचार करना चाहिए।

मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इन व्यक्तियों और दलों के नाम लेना चाहें या न चाहें, मगर

ये सब घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जम्मू-काश्मीर या पंजाब या राष्ट्रीय स्तर पर जिन दलों के नाम मैंने लिए हैं, वे सब इन घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग कैंप हो या अकाली मोर्चा, ये सब एक षड्यंत्र की कड़ियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह तो टिप आफ दि आइसबर्ग है—एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है, जिसमें कई गंभीर चीजें छिपी हुई हैं। गृह मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह टाइम रहते देश को इस षड्यंत्र से वाकिफ कराने की कोशिश करें और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं।

हिन्दुस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा करना केन्द्र का सबसे पहला फर्ज है। जिन राज्यों में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, केन्द्र को उन राज्य सरकारों को सख्त हिदायत देनी चाहिए, उन्हें निर्देश जारी करना चाहिए कि वे अपने राज्यों की सीमाओं में ऐसे ट्रेनिंग कैम्प न लगने दें, जिनके बारे में सारे देश में शंकाएं व्याप्त हैं। जिन लोगों ने इन कैंपों से ट्रेनिंग ली है, उनकी लिस्ट बनाकर उनके नाम प्रकाशित करने चाहिए और उन्हें एरेस्ट करना चाहिए। उन लोगों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। जो लोग इन ट्रेनिंग कैंपों से ट्रेनिंग लेकर निकल रहे हैं, उनमें केवल हिन्दुस्तान के लोग ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाबी भाषा-भाषी लोग भी हैं, जो पंजाब में गड़बड़ फैला रहे हैं। यह और भी खतरनाक बात है। पाकिस्तान के कई लोग धार्मिक भावना से प्रेरित होकर पंजाब आते हैं। एक सैंट्रल इनवेस्टिगेटिंग एजेन्सी को क्वाट करते हुए अखबारों में कहा गया है कि वे लोग यहां ओवरस्टे करते हैं। गृह मन्त्रालय को उनके यहां पर रुकने के बारे में विस्तार से जांच करनी चाहिए।

मुझे आशा है कि गृह मन्त्री इन सारे पायंट्स पर ध्यान देंगे। मैं विरोध पक्ष से, और विशेषकर डा० स्वामी से, निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर दलगत दृष्टिकोण से न बोलें, बल्कि श्री बहुगुणा के व्हिप में न आकर और श्री चन्द्रशेखर से न डर कर, अपनी आत्मा को साक्षी बना कर बोलें और इन घटनाओं की निन्दा करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, गृह मन्त्री का वक्तव्य मैंने देखा है। 14 प्रशिक्षण शिविर जो उग्रवादियों के लिये लगाये गये हैं उनमें से, उन्होंने कहा है, 6 कश्मीर में, 2 हिमाचल प्रदेश में लगाये गये। बाकी 6 के बारे में मौन हैं। एक शायद उत्तर प्रदेश में लगा, राज्य सभा में कहा है शायद। ठीक है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होता है कि कहीं भी इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगे जिससे बिखराव की भावना मजबूत हो तो उस पर केन्द्र का ध्यान जाना चाहिये।

असल में यह वक्तव्य बिल्कुल निर्दोष होता यदि वास्तव में मंशा निर्दोष होती। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में वक्तव्य हुआ उसके बाद 15 सांसदों के नाम से एक वक्तव्य निकला है जिसमें कश्मीर के मुख्य मंत्री को दोषी ठहराया गया है, और इस सदन में भी जो भाषण हुआ है उसका अर्थ भी यही है कि कश्मीर के मुख्य मंत्री की जानकारी में यह शिविर लगाये गये और गृह मन्त्री के वक्तव्य से भी पता चलता है कि कश्मीर के मुख्य मन्त्री कम से कम एक प्रशिक्षिण शिवर में प्रशिक्षार्थियों से वह मिले। गृह मन्त्री जी पंजाब पर तो आपका शासन है और पंजाब में धार्मिक स्थल कह कर के जिन स्थानों से सरकार विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्यवाही हो गई है उस पर आप क्या कर रहे हैं? कश्मीर में जो प्रशिक्षण शिविर लगाये गये थे वह क्या कह कर लगाये गये थे? कहा गया यह शिविर धार्मिक उद्देश्य के लिये लगाये गये हैं। अब जब धार्मिक प्रशिक्षण के लिये शिविर लगाने का ठप्पा उन पर लग गया तब जब पंजाब में जहां आपका सीधा शासन है, वहां धर्म का ठप्पा लग गया वहां आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कश्मीर के मुख्य मंत्री से क्यों यह अपेक्षा करते हैं और क्यों यह धारणा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का

मुख्य मंत्री बिखराव का समर्थक है ? ऐसा आपके वक्तव्य से लगता है कि देखो उस राज्य में प्रशिक्षण शिविर लगता है जो बिखराव को बढ़ावा देता है और वहां का मुख्य मन्त्री कुछ नहीं करता है। जब आप स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को क्यों दोषी ठहराते हैं ? इतनी बातें कही गयीं कश्मीर के मुख्य मन्त्री के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने क्या किया ? वहां भी दो शिविर लगे हैं। जो दोष कश्मीर के मुख्य मन्त्री पर लगाना चाहते हैं, जो आपकी मंशा है, वही दोष हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री पर भी लगाना चाहिये। लेकिन उसके बारे में चुप्पी साधेंगे क्योंकि वह आपके दल का मुख्य मन्त्री है।

सभापति महोदय : थोड़ा जरा अपने टाइम का भी ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इस वास्ते जो पाइंट्स हैं वही कहिये।

प्रो० अजित कुमार मेहता : गृह मंत्री जी...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज अपोजीशन में बड़े-बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं क्या कम हूं ? नेता का काम समाज को नेतृत्व देना है भले ही उसका कोई साथ दे या न दे। रास्ता दिखाना उसका काम है, और मैं समझ रहा हूं कि वह कर रहे हैं। गृह मन्त्री जी कहते हैं कि प्रशिक्षण शिविर में आए हुए लोग कश्मीर मुख्य मन्त्री जी से मिले हैं। अभी कोई धार्मिक के नाम पर प्रशिक्षण शिविर लगाए और जिस राज्य में लगाए, उस राज्य के मुख्य मंत्री से उस प्रशिक्षण शिविर के लोग मिलना चाहें तो क्या मुख्य मन्त्री को मिलने से इन्कार कर देना चाहिए।

श्री हरीश रावत : खालिस्तान का नारा लगायें, तो मुख्य मन्त्री उनके साथ नाचें।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : पिछले होम मिनिस्टर उनके साथ क्या करते रहे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं सन् 1981 की एक घटना की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुंछ में एक बंगला साहिब गुरुद्वारा है, जहां पर एक शिविर लगाया गया था। जिसको आर्गेनाइज ए आई-सी सी के सैक्रेटरी श्री प्रदुभन सिंह के पुत्र ने किया और उसमें श्री अमरीक सिंह भी आए थे। उसका उद्घाटन एक गोली चलाकर किया गया। उसमें एक सिख की मौत भी हो गई थी। आपने उस व्यक्ति को अपने दल का सैक्रेटरी बना कर पुरुस्तार दिया। इसी से आपकी मंशा का दृष्टिगोचर होता है कि आपकी वास्तविक मंशा क्या है।

बार-बार कहा जाता है कि इस चीज को पैदा करने में बाहरी हाथ है। बाहरी हाथ तो प्रकट हुआ, जब अभी आपने काश्मीर में छापा मारा, जहाँ दो गन फैक्ट्रियों में बाहरी हथियार पकड़े गए हैं। क्या आप उनको सजा देना चाहते हैं ? मैं तो यह समझता हूं कि आप यह सारी परिस्थिति काश्मीर की सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए पैदा कर रहे हैं। जो गन फैक्ट्री का अपराधी है, उसको छोड़ दिया जाए। मुझे उम्मीद है, इस पर भी आप स्पष्टीकरण देंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या को हल करने का क्या आपका विचार है, मन है ? महोदय, पूर्वांचल में आग लगी हुई है। असम जल रहा है, पश्चिम में पंजाब की भी वही स्थिति है और अब इन सब कामों से काश्मीर को भी लपेटना चाहते हैं। यह किसी तरह से वांछनीय नहीं है। यह बिल्कुल भी राष्ट्रीय हित में नहीं है। अभी अभी हमारे एक सहयोगी ने सुझाव दिया कि इन बातों पर हमें दल की सीमाओं को तोड़ कर चलें, मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। सुझाव उनका बड़ा सुन्दर है आप स्वयं दल की सीमा को तोड़कर विचार कीजिए। आपकी मंशा सिर्फ इतनी है कि पंजाब में इस प्रकार का आतंक कायम हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि पंजाब हिन्दू समझे कि उनके

रक्षक केवल आप हैं, जिस तरह की भावना आप काश्मीर में जगा रहे हैं। काश्मीर में भी अल्पसंख्यक हिन्दू हैं और उनकी रक्षक श्रीमती इंदिरा गांधी है। उसी तरह की भावना आप पंजाब में जगाना चाहते हैं। पंजाब में भी अल्पसंख्यक हिन्दू हैं और उनकी रक्षक श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस तरह केवल वोट बटोरने की राजनीति से काम लेना उचित नहीं है। यह राष्ट्रीय हित में घातक हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने कामों पर पुनर्विचार करें, तो अच्छा रहेगा।

पंजाब में तरह-तरह के आपत्तिजनक भाषण दिए जा रहे हैं। भिंडरांवाले के बारे में काफी चर्चा हुई है। मुझे याद है पिछले शुक्रवार को इस बहस को इसलिए रोक दिया गया था कि सब लोग समझें, सारा सदन समझे कि आप इस बीच में गम्भीर कार्यवाही करने वाले हैं। और सोमवार को पूरी तैयारी से इस पर बहस होगी। लेकिन आप का आज का वक्तव्य केवल खानापूरी वाला वक्तव्य था। जिस तरह से एक कहानी कही जाती है उस तरह से आपने कह दिया, राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी, भिण्डरावाले ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया ···

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : आपने भी कोई नई बात नहीं कही है। ये सब बातें तो आप बहुत दफा कह चुके हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप इस तरह का बहाना क्यों ढूँढ़ रहे हैं ? भिंडरावाला कोई हमारा समर्थक नहीं है। उसको किसने बनाया था ? जब वह दिल्ली में आया तो किस ने उसके पांव छूए थे ? उसने अपने हरबे-हथियार के साथ दिल्ली में प्रवेश किया था, जिनमें कुछ लाइसेंस वाले होंगे और कुछ बगैर लाइसेंस वाले होंगे। क्या यह बात सही नहीं है कि तत्कालीन गृह मन्त्री ज्ञानी जैलसिंह ने उसके पांव छूए थे ? यदि यह सच है तो आप कैसे यह सोच रहे हैं कि भिंडरावाला हमारा समर्थक है या हमारा दोस्त है ? वह आपकी उत्पत्ति है, यह आपको मानना चाहिये। जब यह मान लेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का काम भी आपका है। आप कहते हैं कि भिंडरावाले को कैसे गिरफ्तार करें ? क्या यह जिम्मेदारी हमारी है ? आप शासन से अलग बैठकर देखिये कि हम क्या करते हैं। हमारे समय में तो पंजाब में कोई समस्या नहीं थी। पंजाब की समस्या आप के समय में उत्पन्न हुई है, लेकिन आप आज बहानेबाजी करते हैं, यह कहते हैं कि उसका गिरफ्तार करना मुश्किल है, क्योंकि वह धार्मिक स्थान में छुपा हुआ है। क्या कोई क्रिमनल धार्मिक स्थान में छुप जाय तो उसको छोड़ देंगे ? जिस तरह से और जगह कार्यवाही करते हैं उसी तरह से वहां भी कार्यवाही कीजिये।

एक अजीब बात यह है—आपने एक अजीब भावना सारे भारत में फैला दी है कि सारे भारत का सिख अकाली है और सारे अकाली देशद्रोही हैं।

श्री हरीश रावत : गलत बात है। आपकी तरफ एक भी सिख नहीं है। हमारी तरफ देखिये—क्या ये मेडम सिख नहीं हैं ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : उनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है। क्या भिण्डरावाला अकाली दल का सदस्य है ? फिर भी आप कहते हैं कि भिण्डरावाले ने जो किया उसकी जिम्मेदारी अकाली दल पर है।

श्री हरीश रावत : इसीलिये कि लोंगोवाल-तोहरा-भिण्डरावाले की मीटिंग होती है। पेपर्स में भी निकलता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : पंजाब के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं भूल नहीं पाता हूं—पंजाब के मसले पर त्रिपक्षीय वार्ता यहां पर शुरू हुई थी, जिसमें मतभेदों का दायरा बहुत सीमित हो गया था। उस त्रिपक्षीय वार्ता से कौन हटा ? आप कहते हैं कि अकाली अपनी डिमाण्ड्स पर स्थिर नहीं रहते हैं, अपना स्टेंड शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है—शुरू-शुरू में अकाली अपनी 45

मांगें लेकर आये थे, उन्होंने जो मैमोरेण्डम सबमिट किया था उसमें 45 मांगें थीं, लेकिन बाद में उसको घटा कर उन्होंने 10 कर दिया। आप बतलाइये कैसे उन्होंने अपने स्टैंड से शिफ्ट किया ? उन 10 मांगों में भी 6 मांगें धार्मिक थीं, जिनको सरकार ने बाद में मान लिया था, लेकिन उस समय नहीं माना। अगर उस समय मान लेते तो उससे अण्डरस्टैण्डिंग का वातावरण पैदा होता और बाकी के मतभेद भी समाप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके पीछे एक राज था, एक राजनीतिक कारण था—आप वोट बटोरना चाहते थे, इसलिये आपने नहीं माना। त्रिपक्षीय वार्ता की सफलता आप नहीं चाहते थे, समझौता वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान आप बिलकुल नहीं चाहते हैं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मंत्री जी ने बीसियों बार इस सदन में वार्ता के लिये कहा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : लेकिन कभी भी अकालियों को निमन्त्रित नहीं किया—समझौता वार्ता करने के लिये। मंत्री जी ने कंसल्टेटिव कमेटी में जो कुछ कहा—बाद में उसका इन्टरप्रेटेशन दूसरा दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा।

हमारे कहने का मतलब है कि कभी आप अपने मंत्री जी से पूछिये कि क्या उन्होंने अकालियों को समझौता वार्ता के लिए निमंत्रित किया है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि भिंडरावाला पर तो समझौता वार्ता करने के लिए तैयार हैं लेकिन आज तक जितनी बातें हुई, समझौता वार्ताएं हुईं, और बहुत-सी बातों में मतभेद भी सीमित हो गये हैं क्या इन सारी बातों का आप एक श्वेत पत्र निकालने के लिए तैयार हैं ? आप एक श्वेतपत्र क्यों नहीं निकालते हैं जिससे कि सारे देश को जानकारी मिले कि इतना काम हो चुका है ? इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि पंजाब के ऊपर आप एक श्वेत पत्र निकालें कि इतनी मांगें पेश की गई थीं, इतनी मांगें मान ली गई हैं और इतनी मांगों पर मतभेद है। कौन-सी मांगें मान ली गई हैं, कौन-सी मांगों पर वार्ता हो सकती है, इन सबके बारे में आप एक श्वेत पत्र निकालें।

अब मैं आपसे दो-चार प्रश्न करना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में परिणत कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार को यह कब जानकारी मिली कि कश्मीर में उग्रवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे हैं और कब सरकार ने कश्मीर सरकार को इसके बारे में लिखा ? यदि प्रशिक्षण शिविर धार्मिक स्थानों में लगाये जाते हैं और सरकार उनको रोकना चाहती है तो उनको रोकने का सरकार के पास क्या उपाय है ?

दूसरे राज्य सभा में इस विषय पर बहस के बाद राज्य सभा के एक माननीय सदस्य श्री गुलाम रसूल ने एक पत्र लिखा था जिसमें तीन सवाल उठाये गये थे जिनमें से दो मैं अभी उठा चुका हूं, वह पत्र अभी तक अनुत्तरित रहा है, वह अभी तक अनुत्तरित क्यों है ?

मेरा अन्तिम सवाल यह है कि क्या यह सही है कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में असमर्थ होकर देश में बेसिर पैर की अफवाहें फैला कर राष्ट्र का ध्यान मुख्य समस्या से हटाने का प्रयास सत्तारूढ़ दल और विशेष कर प्रधान मंत्री कर रही हैं ?

सभापति जी, मैंने आपका थोड़ा ही समय लिया है, अधिक समय नहीं लिया है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, आज हम जिस समस्या पर विचार कर रहे हैं वह समस्या आज पूरे देश को परेशान किये हुए

है। पंजाब की समस्या को केवल पंजाब तक सीमित रखने से काम नहीं चलेगा। आज समाचार पत्रों में हमने देखा है कि बहुत से रिटायर्ड सेना के, एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका की जासूसी करने के इल्जाम में पकड़े गये हैं। पंजाब के उग्रवादियों को कश्मीर में और दूसरों में राज्यों में ट्रेनिंग काम हुआ है। हमारे पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान में छापामार लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग देने का काम भी चल रहा है।

पाकिस्तान में आज क्या हालत है? वहां की जनता वहाँ जनतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है और जो हमारा पिछला तजुर्बा पाकिस्तान के साथ रहा है कि ऐसे समय में पाकिस्तानी फौजी शासक वहां की जनता का ध्यान हटाने के लिये इस के साथ लड़ाई-झगड़ा ठान लेते हैं कहीं वे ऐसी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों को मिलाकर अगर हम देखें तो आज हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में दिखाई पड़ती है। हमें बाहर से भी खतरा है और अन्दर से भी खतरा पैदा होता जा रहा है। मैं तो सभापति जी इस राय पर पहुंचा हूं कि पिछले तीस वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति इतनी खतरनाक कभी नहीं थी जितनी खतरनाक आज पैदा हो गई है। हमने बाहर के देशों से लड़ाई लड़ी, चीन के साथ लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन उस समय पूरा देश एक साथ होकर लड़ाई लड़ा था। लेकिन अब जो स्थिति है वह बड़ी गंभीर होती जा रही है और हमारी सरकार जिस तरह से स्थिति का मुकाबला कर रही है, उससे सभापति जी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। बार-बार यह कहा जा रहा है कि सरकार सतर्क है और हम कार्यवाही कर रहे हैं और आज यहां संसद में घोषणा की जाती है और कल पंजाब में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है। लोगों की भावनाए उबल रही हैं, तलवारें तन रही हैं, पूरा देश कब खून खराबे की स्थिति में आ जाए, कहा नहीं जा सकता और मैं समझता हूं कि जब सरकार कार्यवाही करने पर उतरेगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और देश आग की लपटों में झुलस रहा होगा। अगर सरकार को कार्यवाही करनी है, अगर उसकी मंशा ठीक है, अगर देशहित में काम करना है तो यह कार्यवाही आज बल्कि अभी शुरू होनी चाहिए। अगर इस मामले में देर कर दी गई तो इसका नतीजा इस देश को बड़ा गंभीर भुगतान पड़ेगा।

सभापति जी, अगर गृह मंत्री और उनका मंत्रालय यह समझता है कि पंजाब आसाम है तो वह भयंकर भूल कर रहा है। बंटवारे के जमाने में पंजाब में जो खून-खराबा हुआ, उसकी याद अभी लोगों को भूली नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर इस मामले में देर कर दी गई तो बंटवारे से भी ज्यादा भयंकर खूनखराबा न केवल पंजाब में बल्कि देश के दूसरे भागों में भी फैल सकता है। इस लिए जो कार्यवाही करनी है शीघ्र करनी चाहिए।

होम मिनिस्टर ने अपने बयान में यह माना है कि कश्मीर में उग्रावादियों के द्वारा ट्रैनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 नवंबर की खबर का पूरा ब्यौरा दिया गया है—"एक्स्ट्रीमिस्ट्स ट्रेनिंग इन जम्मू-कश्मीर", हिमाचल प्रदेश में भी कैंप लगाए गए, हो सकता है कहीं और भी कैंप लगाए गए हों। गृह मंत्री ने एक पत्र मुख्य मंत्री को लिखा-आप इसको देखें। जिसका उत्तर भी उनको प्राप्त नहीं हुआ है। आखिर देश की अखंडता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी कश्मीर के मुख्य मंत्री की है या यह जिम्मेदारी भारत के गृहमत्री और भारत सरकार की है? आपने तुरंत कार्यवाही क्यों नहीं की। लेकिन आप कश्मीर के खिलाफ कार्यवाही कर भी कैसे सकते हैं। जैसा कि अभी प्रा० मेहता ने कहा कि पंजाब आपके नीचे है, सेंट्रल रूल वहां, है जब वहाँ कार्यवाही करते हुए आप डगमगा रहे हैं तो कश्मीर में किस हौसले से आप कार्यवाही करेंगे।

अब यह भिंडरावाला कौन है। यह भिंडरावाला एक व्यक्ति जो पूरे देश को चुनौती दे रहा

है। जो इस माननीय संसद को चुनौती दे रहा है, वह भारत सरकार को चुनौती दे रहा है और उसके खिलाफ आप असहाय हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसके विरुद्ध 4-4 मुकदमें दर्ज हैं और उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाय, मैं भाग जाऊं, पकड़ा न जा सकूं तो मेरी कुड़की होगी, वारंट होगा। दरवाजा, खिड़की, चारपाई, सब कुछ पुलिस लादकर थाने में लाकर रख देगी। भिंडरावाला के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है। क्यों पुलिस 87-88 की कार्यवाही नहीं करता ? आप किस मुंह से दूसरों के लिए यह बात कहेंगे।

सभापति महोदय, यह भिंडरांवाला मेरे खयाल से कोई सही दिमाग का आदमी नहीं है। वह सही दिमाग का आदमी नहीं है। क्योंकि कोई भी सही दिमाग का आदमी ऐसा नहीं कर सकता जैसा भिंडरावाला कर रहा है। भिंडरावाले पूरे सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री निहाल सिंह वाला ने अपने भाषण में कहा कि पंजाब में जो आतंक की स्थति है, यदि सरकार वहां कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो बड़ी संख्या में जो सिख हैं, उनकी भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती। वह भी डरते हैं और भारत सरकार भी डरती है। भिंडरावाले से पंजाब का सिख क्यों नहीं डरेगा ? आज हिन्दुओं को पकड़कर मार रहे हैं, कल सिखों को पकड़ कर मारेंगे। मेरी सूचना के अनुसार वह सिख उनकी हिट लिस्ट में हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। हिन्दू से बड़ा वह दुश्मन है जो उन उग्रवादियों के खिलाफ बोलता है। आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और न उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अकाली दल के लोगों ने भिंडरावाले को क्यों रखा हुआ है ? क्यों अपने गुरु नानक निवास में छिपाया हुआ है ? आप लोग जो उधर बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों से कहिए और उनको निकालिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : सरकार हमें दे दीजिए।

श्री जैनुल बशर : सरकार क्यों दें ? आप नहीं निकाल सकते। असलियत यह है कि अकाली दल भी भिंडरावाले से डरता है। जब हमारी भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो पूरे पंजाब में लोग उससे डर रहे हैं। आज इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वह प्रोवोक नहीं हुआ है। भिंडरावाले ने जो ब्यान दिया है और जो बातें कही हैं, उसका प्रोवोकेशन होता है तो कल से हिन्दुस्तान जल रहा होता और हम सब लोग संसद में बैठे हुए तमाशा देख रहे होते। मैं, भारत सरकार और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कार्यवाही शुरू कीजिये। पूरे देश में यह धारणा पैदा हो गई है कि सरकार भिण्डरावाले के खिलाफ कमजोरी दिखा रही है और डटकर मुकाबला नहीं कर रही है। अगर, यह इम्प्रैशन पूरे देश में घर कर गया कि सरकार कमजोर हो गई है तो इसका बड़ा भयंकर परिणाम निकलेगा। हमें उधर बैठे हुए लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे तो ऐसा चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो। आज इस देश की एकता और सुरक्षा को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी की है। काश्मीर के संबंध में हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि ये लोग क्या कहते हैं ? काश्मीर के संबंध में इन्होंने बहुत बातें कीं। राज्य और केन्द्र के संबंध में बहुत बातें कही गई। अगर, केन्द्र को कमजोर कर लिया जाए तो इस देश में एकता कायम नहीं रह पायेगी। केन्द्र सरकार इस मामले ढिलाई करेगी तो इसका बहुत बुरा नतीजा होगा। काश्मीर में जहां इस प्रकार के कैंप लग रहे हैं, वहां की सरकार यदि कुछ नहीं करती है तो उसको बरखास्त करने में क्या हर्ज है ? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जब कांग्रेस आई दल की सरकार बर्खास्त कर सकते हैं तो वहाँ की सरकार को क्यों नहीं कर सकते ? यही नहीं, आज देश के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर एमरजेंसी लगाए जाने की आवश्यकता है। काश्मीर की स्थति बहुत विकट है। आज तीस साल से काश्मीर एक समस्या बना हुआ है। काश्मीर में देश-द्रोही

ताकतों की कमी नहीं है। आज काश्मीर में ऐसे एलीमेंट मौजूद हैं जो काश्मीर को भारत में मिलाए जाने के विरुद्ध हैं। उनमें उग्रवादी भी हैं। काश्मीर और पंजाब बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर दोनों उग्रवादियों में तालमेल हो गया और पंजाब की तरह काश्मीर में भी उग्रवाद फैलता चला गया तो ये दोनों मिल कर देश के लिये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे। काश्मीर और पंजाब की समस्याओं को अलग अलग नहीं देखना चाहिये, हाथ मिला कर देखना चाहिये। काश्मीर में कुछ हो गया तो पंजाब में भी होगा और पूरे देश में जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, हैं, सिख हैं, उनका क्या होगा ? अगर पंजाब में कुछ होता है तो उत्तर-प्रदेश, बिहार, मद्रास आदि दूसरे राज्यों में उसका रिएक्शन और फिर काउंटर रिएक्शन होगा और तब पार्टिशन जब देश का हुआ था, जिस प्रकार की स्थिति तब बनी थी, उस बार की स्थिति अगर पैदा हो गई और बाहर की ताकतें जो हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं उन्होंने हमारे लिए खतरा पैदा कर दिया तो जो भयानक स्थिति बनेगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस वास्ते मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त कार्रवाई करे, भिंडरांवाले को गिरफ्तार करे। कैसे गिरफ्तार करेगी, गुरुनानक निवास में जाकर करेगी या न जाकर करेगी, यह मैं सरकार पर छोड़ता हूं, यह निर्णय सरकार स्वयं करे। लेकिन देश की 95 प्रतिशत जनता को हम यह समझा नहीं पा रहे हैं कि गुरुद्वारों में पुलिस क्यों नहीं जा सकती है। मैं मुसलमान हूं। मेरी मस्जिद में पुलिस जा सकती है, दरगाहों में जा सकती है, विश्वनाथ मंदिर में जा सकती है, गिरजाघरों में जा सकती है, बौद्ध विहारों में जा सकती है तो गुरुद्वारों में क्यों नहीं जा सकती है। गुरुद्वारों की पवित्रता पुलिस के जाने से नहीं बल्कि क्रिमिनल्ज को वहां पनाह देने से समाप्त होती है, उनको छिपाने से समाप्त होती है, उनको वहां शरण देने से समाप्त होती है। मेरी जोरदार मांग है कि अभी आप कार्रवाई शुरू करें। थोड़ी और देर आप करेंगे तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी और यह देश आग में जलता हुआ नजर आएगा।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : (Bombay North East) : Sir, the ruling party member, Shri Zainul Basher's speech today reminded me of the very speech Shri Morarji Desai had delivered very recently in one of our party conclaves. This just shows that ultimately the ruling party will have to realise that it was only during the Janata party rule that we were able to keep peace in the country. Although our party being new we could not keep peace within the party yet we kept peace within the country.

Sir, the discussion today is on the topic of the situation arising out of reported training camps for training of extremists of Punjab in its neighbouring areas. Now, what is the meaning of neighbouring areas ? I was surprised to read the statement because I had expected some specific evidence being presented about the involvement of neighbouring areas. There is no mention about Pakistan in this entire statement. This may indicate a change in government's attitude. Maybe now they want to play down the Pakistani factor because, perhaps, it is not being credible. I do not know. Jammu and Kashmir has been brought up into focus. There is only one indirect to Pakistan and I do not know whether he means—

> "According to some reports with the Government consignment of arms brought from a neighbouring country has reached some organisers of these camps in Guru Nanak Niwas, Amritsar."

Brought by whom ? sent by whom ? It could be smug gled. Was it sumggled ? Therefore, Sir, I am sorry that in this Parliament we are being consistently innuendoes about the whole situation. We want to know in specific terms what is happening in Punjab. You say, foreign hands in one place ; you say Pakistan, you say, Jammu and Kashmir,- all these you say. These are all innuendoes. What is the concrete evidence ? What is it that you want to place before the House ? If you want the support of the entire House you will have to take the House into confidence- Sir, all of a sudden, this Jammu and

Kashmir has come into focus. I really don't know how this has happened. I went through all the Press Cuttings and I found that the first reference to Jammu and Kashmir being involved in what is happening in Punjab was a statement by the ruling party's General Secretary Mr. Rajiv Gandhi, who, according to UNI. told Vichar Vibag of the Congress-I. Now, Sir, I do not know that Congress-I had any Vichar, but they have a Vichar Vibag. There was this Seminar in Delhi on the 12th November and he said.....

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS, AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : You are not supposed to know the inside functioning of the party.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Well, it has come in the Press. I am sorry to say. He must have leaked it out to the Press and it says like this :

> 'Mr Rajiv Gandhi told a conference of the Vichar Vibag of Congress-I in Delhi that extremists in Punjab are being trained in Pakistan and Jammu and Kashmir'.

Now Mr. Rajiv Gandhi is not here. He is a Member of Parliament. We hardly see him here. (*Interruptions*) There are some Members of Parliament who are permanently absent. But, anyway, he should have made the statement in the House but he made it in the Vichar Vibag.

16.56 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *In the Chair*]. He said :

> 'Extremists in Punjab are being trained in Pakistan and Jammu and Kashmir'

—and then it adds in quotes—

> "Recalling the harassment and arrests of Congress-I workers in connection with the Kashmir Bandh on the 7th of November, Mr. Gandhi said that these were examples of unabashed interference of big powers in the affairs of small nations."

Sir, I do not understand and how the arrest of Congress-I workers in connection with Kashmir Bandh establishes an example of unabashed interference of big powers in the affairs of small nations.

SHRI BUTA SINGH : Bad reporting.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Now, may be bad reporting, but he should have corrected it. He has a big Secretariat and you are ruling party...

SHRI BUTA SINGH : You people rely so much on the Press unfortunately. Everything that you say here is based on Press Report. It is incoherent, it is baseless ; and unfortunately you have a bad case.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : All right. I will now rely on the information suppied by you. So far I relied on information supplied by newspapers which he rejects. They should have at least contradicted it.

Now, Sir, I will go to the information supplied by the Minister in Parliament-I hope that that at least is unadulterated. (*Interruptions*) There is Question No. 458. Now, on foreign hands, you know, Sir, how much has been said. What is this foreign hand ? Is there ans evidence ?

The other day I mentioned this,-about the Governor's statement, which was made on 15 November in Jullundar about there not being any foreign hand in Punjab. The prime Minister reacted violently and ultimately the Governor was given**

(*Interruptions*)

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : What a word :

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I withdraw it, if that word is unparliamentary. He was pulled up. I want this word off the record...

MR.DEPUTY SPEAKER : You can say, Prime Minister pulled up the Governor,

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Strongly pulled up the Governor...

SHRI HARIKESH BAHADUR : That word is not unparliamentary, Sir.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Later on he said, well, he did not really mean what he said, etc.

**Not recorded.

Now, however, the Governor has given a taped interview to the Indian Express sometime earlier. This was on the 6th of November. And it appeared in the Sunday Indian Express. The question was put squarely to Mr. Pande. Well, he is your officer, that is, Governor under Central rule ; he is directly under you, a man working under your instructions and the question was put by Indian Express :

'Do you see a foreign hand in the latest happenings in Punjab ?' And Mr. Governor replies :

> 'I have not been able to discern anything yet. Different people who have met me have expressed their suspicions about foreign elements in the incidents in Punjab. No such information or facts have come to my knowledge.'

This is what Mr. Pande, the Governor of Punjab, says in a taped interview to the *Indian Express* published on the 6th November. Now, the hon. Minister asks whether I rely on the newspaper report. I am relying on the Governor.

Then, Sir, a question was asked in the Rajya Sabha on 17th November 1983. Question No. 458. This is for Mr. Buta Singh's benefit who generally does not follow what is going on in Parliament. Otherwise, he would not say what he said. Now, the question is regarding Crimes in Punjab. This question is like this—

> "458 (c) whether Government have investigated into the alleged role of Pakistanis masquerading as Indians causing disturbances in Punjab."

This was the allegation made by Mr. Zainul Basher, a minute ago in a breezing manner about the involvement of foreign powers. The reply given by the Minister is like this.

> "(c) & (d) : Government have come across some reports in this regard for which enquiries are being made."

When you say the Government has come across the report, it means that the Government has seen some newspaper reports, But somebody came and told them "it is not based on authentic information. It is not the internal intelligence report. Some report they may have heard from the radio broadcasts and they are investigating and making enquiries". I want the Minister to tell us whether has completed his enquiries and whether he has something specific to say. Now, there is another question, that is, Q. No. 1112 was put in the Rajya Sabha on 1st December 1983. This question reads like this.

> "(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in *Hindustan Times* of 19th October, 1983, to the effect that. CIA was training Sikh terrorists to Pakistan ; and
>
> (b) if so, what are the details in this regard ?"

Here the reply has been given by Nihar Ranjan Laskar.

> "(a) & (b) Government have come across some reports in this regard. The authorities are keeping a close watch in this regard."

Sir, what is this answer ? Is it a fact ? It is not a fact. Mr. Zainul Basher was quoting the *Hindustan Times*. The *Hindustan-Times* had this report. But here what the Government is saying is that he is keeping a close watch. Is it true ! Is it what you confirmed or do you deny it ?

Now, coming to the Unstarred Question No. 243 in the Lok Sabha, what did the Government say ? The question is like this.

> "(a) whether it is a fact that Pakistani agents are helping in making bombs and some people are being trained in sabotage there and there is a sustained compaigning and rumour-mongering to create panic ?"

The reply given by Mr. Nihar Ranjan Laskar, is as like this.

> "(a) Government have come across some reports in this regard for which enquiries are being made.
>
> (b) There is no confirmed evidence at present in this regard."

Again Unstarred Question No. 279 put in the Lok Sabha, dated 16th November 1983, reads like this.

> "(a) whether during current year six explosions took place in Delhi.

(d) whether any foreign hand has been found ?"

The answer given by Mr. Venkatasubbaiah, reads like this.

"(a) & (b) : During the current year upto 31st October 1983, 12 explosions have taken place at the following places in Delhi....."

(c) Investigations conducted so far do not show any evidence of involvement of any foreign hand in these cases."

Now, I can give you some more information. He talks of criminals, criminals in the Golden Temple and they should be handed over. Now, I paid a visit to the Golden Temple some time ago. They said that Room No. 32 was Khalistan headquarters. The passport is being issued and the currency is being issued and so on from there. Mr. Balbir Singh Sandhu is sitting there handling the whole thing and the Government of Khalistan is functioning from there Now, I made a surprise visit to Room No. 32 there. They took me there and opened the door. There were two 'charpayees' lying there and two little boys were sleeping. That is all and there was nothing else. Then I asked the newspaper men "how did you say that the room No. 32 was the Khalistan's heaquarters ?". If it is a headquarters, it means telephone facilities, a cabinet for keeping files, some furniture, some printing press, all these things, should be there. At least something should be there. All these things cannot be removed within five minutes before I went there. Suppose, tomorrow in Maurya Hotel, somebody pays Rs. 600 for room rent and calls a press conference and says-for instance some Tamilians can go there and say-that this is the headquarters of the Eelam.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : why not yourself ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I want the whole of Sri Lanka, not a part of Sri Lanka.

Then I asked them that criminals are hiding in the Golden Temple, why don't they hand them over to the Government. They said : Where are they ? I told them that they had got a list of forty persons sent by the Chief Minister, Shri Darbara Singh. They said that forty-member list is ridiculous, because out of those forty persons, eighteen cannot be in the Golden Temple. I asked them why. They said : Six are in Germany, six are in Canada. two of them have been let out on bail, and two of them have already died. Like that they eliminated eighteen names. I asked Sethi, if it was a fact, and he told me—now he may deny,-that it was a fact : those eighteen people cannot be in the Golden Temple. And that list was sent by Darbara Singh by registered post to the Golden Temple I do not know, why he did not sent it by a messenger. I say again today ; that time when I went, I said to Longowal also that you must do something about these crniminals. He set up a screening committee. Naturally, that screening committee cannot include any representative of the Government, because Government and they have got a bad blood, but they had included some independent people from Amritsar, whom I know. They went from room to room and took the names, and they did not find any criminals. Criminals come and go ..... (*Interruptions*). Yes, there were some people of my party, sympathisers, they were also there. Unless the Government gives a list of names, the charges against them, their photographs, and their addresses, how can you expect the Akali Dal or the SGPC to hand over the criminals. Everytime I ask Mr Longowal about this, he says that they are not there. You tell them where they are, where they are hiding, their names and give them their photographs. In this regard, again loose talk has been going on.

Again Rajya Sabha, Shri Sethi answered Question No. 41 on 17th November, 1983. The question was :

"...the number of terrorists and extremists so far arrested in Punjab ;

(b) the number amongst them who have been chargesheeted ;

(c) the names and particulars of criminals who are alleged to have been taken shelter in Gurdwaras ;

(d) whether those criminals have been proclaimed as absconding ;

(e) whether the names and particulars of such absconders have been conveyed to the Gurdwara authorities ; and

(f) if so, the response thereof : "

And the answer of the Minister was :

"A list of persons who are so far reported to be hiding in Golden Temple complex laid on the Table of the House. Most of these persons have been declared proclaimed offenders."

Then, there is a list of names ; Just a list of names. This was a Starred question, naturally some questioning took place and in the questioning we found very strange things to be said by the Minister. The Minister was asked, why he did not give the particulars, and if he had given the particulars. No particulars have been given. He was asked, if he had given what charges those people were guilty of, and for what they had been charged The Minister said No : from time to time we have sent a list.

Now, there are forty five names. Harminder Singh everyboody knows that there can be thousands of Harminder Singhs, as there can be thousands of Subramaniams. Tomorrow, someone can say that Subramaniam is hiding in the Meenakshi temple.....(*Interruptions*). There could be so many persons of these common names.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record it·

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Now let us take** But that does not mean a particular person. Generally speaking, the Sikh names are common names. All the names given here in the list common names, and no particulars are given. Shri Sethi thinks that he can get away with it.

The Government, according to Unstarred Question No. 1054, in the Rajya Sabha, have arrested 5351 persons in the mopping operation in the State. During the period from 18-10-1983 to 24-11-1983 i. e. since the President's Rule, Now, how many of them are known to be spies or agents of foreign powers or trained in Jammu and Kaskmir ? Answer is none. 5,351 persons they have arrested and they have not caught even one person to establish that foreign hand is involved. This way, I am sorry to say, the Government goes on alleging and alleging, but the Parliament is not told what is this solid evidence.

Now, Sir Mr. Pande, the Governor of Punjab in Gurdaspur on llth November said, and it is reported in The Statesman on 13th November the following. He was asked a question about the criminals hiding in the Golden Temple and whether any list has been supplied ? And what does Mr. Pande say ? According to the Statesman, he said he was not aware of any list of criminals taking shelter in the religious places that has been supplied to the SGPC President.

Now, here the Governor says he does not know of any list which has been supplied and Mr. Sethi says there is a list supplied to the SGPC. President. But in the Rajya Sabha when questioned by my colleague, Mr. Shahabuddin and others,...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I am finishing. I have such a solid material and even Minister has not given such a solid material to Parliament. I am Just concluding.

The question is according to the Governor there is no list, but according to the Minister there is a list supplied. When my colleague, Mr. Shahabuddin asked in Parliament what are the names, somebody called Talvinder Singh and somebody called Harminder Singh. Now, which village does he belong to ? What is the charge ? Have you got the photograph. None of that. So, how have we to believe the Government ?

They say arms. Everyday we hear about arms. Well, here again is a question No. 327 of the Lok Sabha :

"Whether it is a fact that during raids in certain villages in Punjab, a big haul of arms was made ? If so, please give details.

The answer was :

"227 weapons have been recovered during the raids since October 18" i. e. since the President's Rule."

**Not recorded.

227 guns have been recovered.

Now Unstarred Question No. 340 is :

"Whether it is a fact that 'made in Pakistan' marks have been found in arms seized in violence incidents in Punjab ?"

The answer is that "the Government of Punjab have informed that only one Sten-gun and one revolver of Pakistani markings was recovered in Amritsar."

That is, out of 227 guns recovered, only two guns have Pakistani markings 225 have had what markings-Spanish, markings, Dhirendra Bramhachari markings ? So, this is the question. He hasto answer to us. They want our support, but we want unadulterated information. We want solid information. We do not want all these innuendoes. We do not want all these cover-ups. When you say foreign hands, what is your evidence ? Give it in writing. Give it in form where we can analyse. Though they are there in Prime Minister's speeches or in Rajiv Gandhi's speeches or is anybody's speeches have no value. What in stated in Parliament is important here. We come across reports government have not found any evidence, government is looking into the matter. All this is told here to us.

We are asked condemn the Akali Dal on the basis of such frivolous innuendoes. We are not prepared to do that. We consider Akali Dal as our brother party. They were with us in the Government. They are in agitation, there is no doubt about that. If they do something wrong, we are prepared to tell them. I told them that you-have got criminals in the Golden temple ; everybody says that. They say, no. You tell us where it is ? We will open the sereaning committee. You come with us. Tell us which room and we will take you to every room. This is what they say to us. What do we do ?

Sir, in conclusion I would say.....

MR. DEPUTY- SPEAKER ; After all, concluding.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : ...I don,t want this Government to bluff us. The Government should take us into confidence. If the Government does not want to do it openly, you call a small meeting or you call, what is called, secret session. There is a provision for it under the Parliamentary rules where there is no press, nothing. Do something, but don't do this allegation. Don't create this general impression. Already in the country there is an impresssion that all Sardars are wanting Khalistan. It is not true. There may be all kinds of organisations that have come up as a reaction.

I do not at all approve of Mr. Bhindranwala making the Statement that he did. I did meet him when I went last time to Amritsar. When I meet him next, I will certainly tell him. If some child. a Hindu's son makes a statement and says : 'We will kill all Sardars' — we have never heard it that he even exists —— the answer Bhindranwale should give is : "We all Hindus and Sikhs, will join together to defend ourselves against these extremist elements" and not say. "We will take revenge,,. But he is only 40 years old ; and he is an immature person in these matters. In fact, he would not have got this prominence but for these people.

I would be happy to help the Government ; but they must take us into confidence.

MR. DEPUTY SPEAKER : Is he younger to you, or older ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : He is a little younger to me, but a little older than you.

MR. DEPUTY SPEAKER: But I am 60.

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : So, I would like Government to treat us like Members of Parliament, and us the truth at least.

I may draw your attention to "The Telegraph" issue of 28th November which speaks about Ranjit Singh, the prime suspect in the case of murder of the Nirankari chief. When he entered the SGPC office, according to this report :

> "....the SGPC authorities asked Ranjit Singh to vacate the Golden Temple premises so that it would not cause any embarrassment to them."

There are plenty of reports that when they come to know that somebody who is a criminal has come there, the Akali Dal, Shri Longowal and his group which is a moderate group, take steps.But the Government is trying to get political advantage and to but them in the wrong. This is the feeling which they have.

PROF. N.G RANGA : No.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You may not know. Their feeling is that you are trying to suppress them ; you are trying to get electoral advantage over them. You are trying to blacken their name.

The Sikhs are a an emotional people. They have this feeling : "Look ; there is no public sector in Punjab. There is nothing. We have to fight. We are only 3% ; but we produce 75% of the procurement of wheat." They are prosperous by their hard work. They are emotional people. They fight. They bear the brunt of any attack. And you go on caricaturing them as anti-nationals in this kind of loose talk involving Pakistan, Kashmir etc. So, what the Government should do is this : if they want to take action against criminals, we will help them. Let them take action. But they must not suspend negotiations.

The only thing left now in the Punjab agitation is Akali's one demand. viz. Chandigarh —— because the water issue which was pending, has gone to Supreme Court. It was the demand of the Akalis that Supreme Court should take it up. The Chandigarh issue remains. They promised Chandigarh to Punjab in 1970. And about giving Fazilka and other areas to Haryana, they can appoint a Boundary Commission, and work out contiguous areas ; and Chandigarh need not be transferred till the Boundary Commission completes its work. They can give Rs. 100 crores to Haryana to build a new capital.

PROF. N.G. RANGA : Is it so simple ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Yes; it is so simple. You are complicating it. I say today with complete confidence : if the Government announces its decision to hand over Chandigarh to Punjab with all these supplementary things added to it, about boundary commission, the Akalis would withdraw the agitation. They would call it off, because they would consider their agitation to have been successful.

PROF. N.G. RANGA : Let them say so.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Why should they say so ? I am convinced about what happened in the tripartite discussion. You have enough material in the tripartite discussions. They are not any longer going to tell you that they would do this and that. You are the Government. You take these steps. If you don't negotiate with them, then I think you are doing it for political reasons. In that case, I would say that they have a point. After all, many Akalis tell me : Look at this ; they are talking about Bhindranwala.' Many Akalis—there sober elements ——are not happy about the way Bhindranwale is behaving. But they say : 'What about Dhirendra Brahmachari ? But for Farooq Abdullah, he would have been carrying on with all the Apsaras and carrying guns there, and bringing them back here. (*Interruptions*) Yes ; he would have been still flying there, and flying back He has been carrying guns without licence. His import licence is a forgery. They say : 'Look at this. There is a difference in treatment. Because one happens to be a Yoga teacher in high places, nothing is being done.

But for Dr. Farooq Abdullah this Brahmachari, this scandalous swami would not have come before the public eye, So, they say, why are they treating two persons differently ? Why Bhindranwale is being singled out every day ? No discussion. Every day, in Parliament, there is *hullah* on Bhindranwale but no hullah on Brahamachari. So, even these things are utilized. You show your even handedness and we will help you. All the material I have placed will show that government have no shred of evidence to talk of foreign hand about weapons from abroad or about 11 the camps in various places and they are using all these. This is a great bluff, manifestly imaginary. They are trying to create a case ; they are trying to blacken the Akalis' name. They want our support. We cannot give our support to them. But if they come forward with genuine information and take us into confidence, we would be happy to help them.

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो कालिंग अटेंशन दिया था ट्रेनिंग कैंपों के बारे में, उसको आपने 193 में चेंज कर के हम सब लोगों को मौका दिया है इस पर बात करने का। अभी-अभी हमारे कुलीग इस पर बोल चुके हैं। होम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा है कि 14 कैंप हुए, जिसमें से 6 कश्मीर में हुए। एक बात और नोट करने की है कि 1981 और 1983 के बीच ये कैंप वहां लगाए गए। पहले कभी कोई ऐसा कैंप वहां नहीं लगा। और यह जो पुंछ एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है और यह वह लाइन है जहां से आक्यूपाइड कश्मीर को लोग जाते-आते हैं। उनकी एंट्री होती है और इधर आते हैं। फिर इस सबका क्या मतलब है। "डेली रिकार्डर" और 'कश्मीर टाइम्स" में वहां पर इन्होंने कहा है कि एक कैंप देरा बंडा बहादुर, नियर रियासत ऊधमपुर में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 1981 को लगा। दूसरा··· (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ये अखबार हैं, इन पर आप विश्वास कर रहे हैं ?

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार : तो फिर सारे अखबार बंद कर दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उस दिन बूटा सिंह जी कह रहे थे···।

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार : ठीक है, आपको पता है चुरू की खबर का क्या हुआ। भिंडरावाला ने जो स्टेटमेंट दिया वह भी गलत दिया कि सब हिन्दुओं को पंजाब से निकलना पड़ेगा। प्रेस की भी जिम्मेदारी है। प्रेस को जिम्मेदार होना चाहिए। यह कोई बात नहीं है। पंजाब में जो हालत पैदा हुई है, उसको संभालना सबकी जिम्मेदारी है। चाहे अपोजीशन के लोग हों या रूलिंग पार्टी के लोग हों या प्रेस वाले हों। इसके साथ इस तरह से खेलना नहीं चाहिए, सबको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सबको पार्टी और रिलीजन से ऊपर उठकर और नेशन का खयाल करते हुए इस जिम्मेदारी को निभाना है। यह मेरी आप सबसे अपील है। करना तो बाद में चाहती थी लेकिन आपने पहले ही करवा दी।

ये जो कैंप लगे हैं, इन कैंपों का क्या मतलब है। (व्यवधान)

आप मुझे बात करने दीजिए। आप तो बड़े हम दर्द हैं सिक्खों के, कैंप लगवा रहे हैं, जो वहां जाकर स्पीच दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फारुख साहब को बोलिए कि इसकी इन्क्वारी कराकर बताएं कि क्या गलत है और क्या ठीक है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे।

इण्डिया टू डे निकलता है। उन्होंने भी पुंछ का जिक्र किया है।

इण्डिया टू डे में पुंछ के कैंप के बारे में छपा है। फारूक साहब भिंडरावाले की तस्वीर रखते हैं। यह कहां तक सच है क्योंकि यह तो प्यार-मोहब्बत की बात है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी की तस्वीर है।

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार (श्रीनगर) : शुरू से ही गुरुमत प्रचार के लिए कैंप लगते थे। इसमें बच्चों को बताया जाता था कि सिखी क्या है ? इसलिए, यह कोई बुरी बात नहीं है, शुरू से ही लगते आए हैं। ऐसे ही कैंप और जगहों पर भी लगते रहे हैं। रिसेन्टली जो कैंप हुए हैं और वहां जो स्पीचेज हुई हैं, उनको निकलवाइए। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि पुंछ और पाकिस्तान ओक्युपाइड काश्मीर के बारे में कुछ न कुछ अवश्य करें। आपको पता होगा कि पंजाब में पहले कैनाल वाटर की जगह से मोर्चा शुरू हुआ। अमरीक सिंह और तारा सिंह ने कहा कि हम मोर्चा लगायेंगे। अमृतसर में गोल्डन-टेंपल है। वहां रामदास सराय है और गुरु का लगर है। वहां रहने को जगह मिल जाती है। इसलिए, वहां कोई तकलीफ नहीं है। वहां मोर्चा कभी फेल नहीं होता। शुरू-शुरू में एक्सट्री-

मीस्ट्स ने प्रैशर दिखाया। मैं स्वामी जी से इस बात पर सहमत नहीं कि इसको ठीक करने का सरकार का मन नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूं कि लॉ एण्ड आर्डर को फर्मली डील किया जाए। यह सबके लिए अच्छा होगा तभी कुछ हो सकता है। पंजाब में ही नहीं बल्कि किसी भी जगह ऐसी बात हो जाती है तो हर किस्म के लोग सिर उठाना शुरू कर देते हैं। पंजाब में एन्टी सोशल एलीमेंट्स भी हैं। दल खालसा, बब्बर अकाली दल, नैक्सलाइट्स और स्मगलर्स हैं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बार्डर पर स्मगलर्स खास रोल प्ले कर रहे हैं। इससे एन्टी सोशल एलीमेंट्स को मौका मिल जाता है। हैदराबाद के रायट्स के बारे में वहां मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि दो आदमी स्कूटर पर आते थे। उनके पास छुरा होता था। वे एक ही जगह पर छुरा लगाते थे।

पेट में मारते तो एक ही जगह और ऐसी दबाई लगी होती थी कि इन्सान मर जाता था, बचता नहीं था। इसी तरह से पंजाब में स्कूटर पर लोग आते हैं और यही काम करते हैं। वहां बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल होता है। मैं समझती हूं कि इसके पीछे बड़ी भारी फोर्स है जो चाहती है कि इस एरिया में डिसटरबैंसिस हों और न सिर्फ इस एरिया में बल्कि सारे भारत में हो और उस दशा में जैसे मच्छरों के लिए गंदगी ब्रीडिंग ग्राउण्ड बन जाता है वैसे ही इन लोगों के लिए बन जाए और गड़बड़ और अनरेस्ट में इनको अपना काम करने का मौका मिले। एक चीज आप करें। जो नक्सलाइट हैं उनके साथ आप उस तरह से बरताव करें, नक्सलाइट का करें और दूसरे के साथ दूसरा करें। पट्टी के नजदीक जो घटना हुई यह मेरा इलाका है। यहीं मेरी पैदाइश हुई थी। वहां पर चार हिंदुओं को निकाल कर मारा गया है। मेरा मन नहीं मानता है कि किसी सिख ने ऐसा किया होगा। यह कहा गया है कि बाहर उनको निकाला गया तो किसी ने कहा कि मैं मोची हूं, हिंदू नहीं हूं, किसी ने कहा कि मैं गोल्डस्मिथ हूं, हिंदू नहीं हूं। किस सिख को पता नहीं मोची या गोल्डस्मिथ हिंदू होता है या नहीं। कोई इस वजह से उनको छोड़ देता। यह फिजूल की बात थी। यह सोचने वाली बात है। आप यह भी जानते हैं कि एक ही फैमिली से पैदा हुआ हिंदू फैमिली का पहला लड़का सिख बनता है। यह आज की बात नहीं है, सदियों से चलती आई है। ऐसे काम वही लोग कर सकते हैं जो यह चाहते हैं कि गड़बड़ हो। मैं जैनुल बशर साहब से एक बात कहना चाहती हूं। हम हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे नहीं। इक्का दुक्का जो घटनाएं हो रही हैं इनको हमें बन्द करना है। जब छः को मारा गया कपूरथला के पास और बाद में चार को मारा गया तो सभी ने अक्लमन्दी से काम किया, सभी पार्टियों ने कहा कि हम ऐसी शरारत नहीं होने देंगे, सिविल वार जैसी चीज नहीं होने देंगे। हमारे विरोधी भाइयों ने तथा दूसरों ने जब्त से काम लिया। लोंगोवाल ने तथा दूसरों ने भी इसको कंडेम किया। इस मसले को आप अच्छी तरह समझें। क्या यह नक्सलाइट्स का काम है, स्मगलर्ज का है या किसका है। स्मगलर तो उधर से बंदूकें लाते हैं और इधर से दूसरी चीजें उधर ले जाते हैं। स्मगलर्ज तो गुंडे ही होते हैं। उनके साथ निपटना हो तो पूरी तरह से उनके साथ आप निपटें। जो इस तरह के काम करते हैं उनका तो उद्देश्य यह है कि कम्युनल रायट्स हों और फिर वे उसमें फयूल लगाएं ताकि सीसैशनिस्ट टैंडीस बढ़ें। बाहर की बहुत सी एजेंसीस हो सकती हैं जिनका इस सबके पीछे हाथ हो।

अमृतसर के नजदीक चाटीविंड के पास उन्होंने बस को रोका, अपना काम किया और भाग गए। यह अफसोस की बात है कि वे पकड़ नहीं गए। लेकिन इण्डिया टूडे में जो निकला है और श्री प्रीतम सिंह भिंडर ने जो कहा है वह मैं कोट करना चाहती हूं :

> "The criminal today is far ahead of the police ; Yet things will improve. We are trying to modernise, re-equip and re-orient the police force."

हम यह तो नहीं कह सकते कि पंजाब में पुलिस बड़े हौसले से काम कर रही है। वह डीमारेलाइज्ड है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्रिमिनल्ज फार ऐ हेड हैं, तो हम क्यों नहीं होते। यह एक जिम्मेदार इन्सान का स्टेटमेंट है। मिनिस्टर साहब देखें कि क्रिमिनल्ज किस बात में ऐहेड हैं और हममें क्या कमी है, ताकि उसको दूर किया जाए।

उन लोगों का मेजर आब्जेक्टिव यह है कि हिंदू और सिख कम्युनिटीज में डिसट्रस्ट पैदा किया जाए। वे पूरी ताकत से इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम कोशिश कर के हिन्दुओं और सिखों के आपसी डिसट्रस्ट को दूर करें। थोड़े से यंग लड़कों का ब्रेन-वाश भी किया जा रहा है। अगर ज्यादा देर न करके उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, तो पंजाब और ज्यादा तरक्की करेगा। पंजाब हमारे देश का एक इम्पार्टेन्ट बाजू है। यहां पर गेहूं और बहुत सी दूसरी चीजें पैदा होती हैं।

आज की खबर है कि कल रामतीर्थ मंदिर के, जो एक बड़ा तीर्थ-स्थान है, लार्ड जगन्नाथ, उनके भाई और सुभद्रा बहन के आइडल्ज को जलाया गया। लेकिन अभी तक वहां पर शांति है। होम मिनिस्टर साहब बताएं कि इसके क्या रीएक्शन और रिपरकशन्ज हुए हैं। इन बातों से जाहिर होता है कि वे लोग हिन्दुओं और सिखों को लड़ाना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वे दोनों आपस में लड़ें। लेकिन अभी तक वे बिल्कुल अमन-चैन और शांति से रह रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ला एंड आर्डर को फर्म हैंड से कंट्रोल करें और अकालियों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर पोलीटिकल सेटलमेंट करें। अकाली भाइयों से मेरी अपील है कि वे आकर प्राइम मिनिस्टर से बात करें। अगर और पार्टियों को भी बीच में लाना है, तो उन्हें बुला कर इस मामले को निपटाया जाए। श्री जैनुल बशर ने कहा है कि सरकार कमजोर है। सरकार बिल्कुल कमजोर नहीं है। सरकार अपना टाइम देखती है कि हमने किस टाइम पर क्या करना है। क्या वह पंजाब में आग लगा दे? सरकार को सोच समझ कर काम करना होता है। ऐसी बातें हमारी जुबान पर नहीं आनी चाहिए। न ही आग लगेगी और न ही सरकार कमजोर है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, now we have got to take up Half-an-Hour discussion and the Goevrnment has told us that this Bill also which was stopped in the middle, must be passed today as it has got to go to Rajya Sabha. This discussion also should be concluded. Half-an-our discussion we are going to start, then we take up the Bill. In five minutes the Bill will be passed and then we come to This discussion and complete it today. Going on postponing becomes every stale, therefore, we must conclude it today. Now Mr. Paswan. He must definitely take only half-an-hour. Half-an-Hour discussion should not go beyond half-an-hour.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : He is prepared to take the Bill first and then Half-an-hour.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : If the Parliamentary Minister desires I have no objection.

MR. DEPUTY SPEAKER : We will take the Bill first, then Half-an-Hour discussion, then we will complete Punjab discussion today.

17.40 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF TEA (AMENDMENT) ORDINANCE AND TEA AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put the statutory resolution moved by Shri Krishna Kumar Goyal to the vote. The question is :

> "This House disapproves of the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 7 of 1983) promulgated by the President on the 7th October, 1983."

The motion was negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Tea Act, 1953, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up clause by clause consideration.

Clause-2

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling) : I bag to move :

1 Page 1, line 8,—

for "six Years" *substitute* "ten Years"

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put amendment No. 1, moved by Shri Ananda Pathak, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. DFPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : I beg to move

"That the Bill be passed"

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill be passed"

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हू कि मन्त्री जी ने अपने भाषण में कुछ इस तरीके के शब्द कहे जिनको सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। सम्भवत: उन्होंने कहा है आपकी आदत है सहने की, तुम्हें आदत है कहने की नमक छिड़को, नमक छिड़को, नमक छिड़को। मैं मतलब नहीं समझ पाया क्या इनकी आदत है सहने की, गहने की ? मेरी आदत तो कहने की है। मैंने तो सुझाव दिया था और कहा था कि आप बताइये उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में जहां चाय पैदा की जा सकती है उसके बारे में क्या कर रही हैं ? आपने एक शब्द भी उस बारे में नहीं कहा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी जब बोलें तो जवाब दें कि कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में चाय पैदा हो सकती है और यही नहीं चीड़ के बागान में पेड़ों के नीचे चाय पैदा की जा सकती है और ऊपर पेड़ हो सकते हैं, तो इसके बारे में रिसर्च वगैरह के लिये आपने कुछ किया है ? मूल्य वृद्धि चाय में निरन्तर क्यों हो रही है ?

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling) : I have pointedly asked the hon. Minister to clarify the position as to what they are going to do with regard to the gardens whicn were taken over, once the period is over. Will they be handed over to the same managnment which mismanaged them earlier and brought them to this condition ? Secondly, the hon. Minister referred to the ailement of tea industry in Darjeeling allotment of Rs. 43 crores for rejuination of this industry. But she has not explained as to when the project will be implemented.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि डि-नोटिफाई करने से पहले हम हर काम को पूरा कर लेते हैं। 28 अक्टूबर को नैशनलाइज्ड बैंक ने दो करोड़ रुपए के लिए पैटीशन देकर लिक्वीडेशन के लिए डिमांड किया। वर्कर्स और मैनेजमेंट को कोई जानकारी नहीं। नोटिस भी नहीं दिया। कन्टेनर और एन्कलोजर इतनी बड़ी कम्पनी के 900 वर्कर्स की डिमांड का क्या होगा। आई आर सी को वहां बोलने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, चीफ राज्य सरकार को जानकारी नहीं मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं। बैंक के दो करोड़ रुपए के लिए कारखाना लिक्वीडेशन में चला गया। 900 वर्कर्स बैठे हुए हैं। मैं आपकी पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री राम लाल राही : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चाय की कीमत को कम करने

और मिलावट को रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister will reply.

(*Interruptions*)

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Sir, I had dealt with each and every point raised by the hon. Members either from this side or from that side. Regarding one of the points which has just now been mentioned by Mr. Rahi, I want to inform him and all the hon. Members of the House that all steps are taken to explore the possibility just to see what the Government can do for that area about which he is interested. About the other points, I am not in a habit to repeat every time all that I have said.

Sir, the purpose of the Amendment is very much limited, i.e., extending the period from two years to six years. That is the only amendment and there is nothing more to add.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, this is an important Bill. The Policy of the Government is involved in it. The Government should declare the policy before the Parliament. That is what you have failed to do.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.48 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Free Medical Help to Poor

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह डिस्कशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह आधे घण्टे की चर्चा 17 नवम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न सं० 41 से उत्पन्न होती है। उस प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया था यदि आप उसको देखें तो उसमें मंत्री जी ने दो-तीन बातें कही हैं। मैं सर्व प्रथम मन्त्री जी का ध्यान इस बात पर खींचना चाहता हूं—उन्होंने इस बात की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि वे उस बात पर अडिग हैं कि सन् 2000 तक "हैल्थ-फार-आल" के टारगेट को पूरा करेंगे, लेकिन इधर जो जवाब मंत्री जी ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में दिये हैं उनसे ऐसा नहीं लगता है कि मंत्री जी उस दिशा में कोई कारगर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने दो-तीन बातें बतलाई हैं—गांव से ऊपर तक का जो लेवल है उसमें एक हजार की पापुलेशन पर हैल्थ गाइड होता है, 5000 की पीपुलेशन पर सब-सेन्टर का प्रावीजन है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में 20 हजार और सामान्य क्षेत्रों में 20 हजार की पापुलेशन पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर होता है, उसके बाद 1 लाख से ऊपर की पापुलेशन पर कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर चला रहे हैं।

इन्हीं के जवाब के मुताबिक पूरे देश में सब-सेन्टर्स की संख्या 65643 है जो कुल मिला कर 30 करोड़ 81 लाख 15 हजार की पापुलेशन को कवर करते हैं। आप प्रश्न सं० 1387—1 दिसम्बर, 1983 के उत्तर को देखें—जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 5955 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स हैं वे 14 करोड़ 88 लाख 555 लोगों को कवर करते हैं। इस तरह से कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर्स की संख्या 471 है जो 4 करोड़ 71 लाख की जनसंख्या को कवर करते हैं। इसी तरह से उन्होंने अतारांकित प्रश्न सं० 1747 के जवाब में 14 अक्तूबर, 1982 को बतलाया था कि हम प्रत्येक गांव में कम से कम एक ट्रेण्ड दाई की व्यवस्था कर रहे हैं। एक साल से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक उस दिशा में क्या कार्यवाही हुई है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जवाब देते हुए इस सम्बन्ध में हमें बतलायेंगे। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि हमारे गांवों में सबसे बुनियादी चीज है—बच्चों को देखना, बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखना। किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है—हम लोग गांवों से आते हैं—

आज भी जब कि विज्ञान इतनी चरम सीमा पर है, गांवों में मां अपने बच्चों की नाभी खुर्पी से काटती है। हमारे अधिकांश माननीय सदस्य जो गांवों से आते हैं, उनकी माताओं ने भी उनकी नाभी खुर्पी से ही काटी होगी। वहां पर न कोई ब्लेड या दूसरे औजार मिलते हैं। नतीजा क्या होता है—आधे से अधिक अनुपात में बच्चे मरते हैं, कोई डिपथीरिया से, कोई पोलियो से मरता है, कोई टेटिनस से मरता है और कोई हूपिंग-कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, उस से मरता है। सरकार कहती है कि हमने वहां फ्री-मैडिसिन की व्यवस्था की हुई है, लेकिन क्या, मन्त्री महोदय, आप नहीं जानते कि आज भी गरीब को दवाई कहां मिलती है। एक-एक पुड़िया के लिये, एक-एक टिकिया के लिये गरीब जान गंवा देता है। आज अब आप 2000 ईस्वी तक "हैल्थ-फार-आल" का नारा दे रहे हैं तो कम से कम उसके लिये शुरूआत तो करें। आज गांवों में जो बच्चे पैदा होते हैं—कम से कम गांवों से ही इस काम को शुरू करें तो उसके कुछ परिणाम निकल सकते हैं। आप गांवों के बच्चों के लिये ऐसा कर सकते हैं कि सबके लिये आइडेन्टिटी कार्ड बनवायें, कम से कम जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके लिये कार्ड की व्यवस्था करें और निश्चित रूप से देखा जाय कि कम से कम साल में एक बार बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाय। देखा जाय कि उनके कानों में कोई बीमारी नहीं है, नाक में कोई बीमारी नहीं है, आंख में कोई बीमारी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं— 1977 के बाद अब 1984 तक 7 साल हो गये—क्या इस बीच में उन्होंने देश का कोई सर्वे कराया है कि देश में कितने लोग अन्धे हैं? मेरे पास जो रिकार्ड है—वह 1977 का है और जहां तक मेरी जानकारी है 1977 के बाद आपने कोई सर्वे नहीं करवाया। 1977 के सर्वे के मुताबिक इस देश में 1 करोड़ लोग अन्धे थे और उसका कारण यह बतलाया गया है कि आदमी में विटामिन ए की कमी है, अच्छा खाना मां को नहीं मिलता है। जो गर्भवती मां हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनको काम अधिक करना पड़ता है, इसलिए उनके पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं वे लंगड़े, अंधे या अपाहिज पैदा होते हैं। हमारे देश में एक करोड़ लोग अन्धे हैं और दो करोड़ लोग टी० बी० से बीमार हैं।

टी० बी० क्यों होती है? इसलिए होती है कि आदमी को काम करना पड़ता है और एक मजदूर को पूरा भोजन और पौष्टिक भोजन नहीं नहीं मिलता है, नतीजा यह होता है कि टी०बी० हो जाती है। क्या आप कह सकते हैं कि सब को टी० बी० की दवाई मुफ्त मिल रही है? नहीं मिल रही है। एक टेबलेट होता है जो कि गर्भवती महिला को देने से बहुत कुछ रोगों की रोकथाम हो सकती है। वह टेबलेट हमारी मां-बहिनों को नहीं मिल पाती है।

आप अगर चाहें तो यह सारी चीजें गांवों से शुरू कर सकते हैं। आपके गांवों में जितने भी सेन्टर या सब सेन्टर हैं ये किसी काम के नहीं हैं। हमको पता है कि आपके प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों की किस प्रकार की हालत है। वहां कोई डाक्टर नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि आपका कोई डाक्टर वहां जाना नहीं चाहता है। बहुत कहा जाता है कि ट्राइबल एरियाज में लोग विदेशी धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि विदेशी डाक्टर आदिवासी क्षेत्रों में डेडीकेशन के साथ काम करते हैं, लोगों की अच्छी सेवा करते हैं, बीमारी में उनको दवाई देते हैं। लेकिन हमारे डाक्टर गाँव तो क्या, प्रखण्ड हैडक्वार्टर तक में जाने को तैयार नहीं हैं। अगर किसी डाक्टर को वहां भेजा भी जाता है तो वह सौ पैरवी करा कर अपना ट्रांस्फर रुकवा देता है।

आज गांवों में कीड़े-मकोड़े की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजादी के 36 साल के बाद भी हम लोगों को गांवों में शुद्ध पानी नहीं दे सके हैं। गाँवों के लोग अभी भी कीटाणुओं से भरा जल पीते हैं। आप मध्यप्रदेश के इलाके में चले जाइये। आज भी यहां के लोग पोखर का पानी पीते हैं। उसी पोखर में जानवर भी पानी पीते हैं और वहाँ के लोग भी पानी पीते हैं।

पोखर में जो कीड़े-मकोड़ होते हैं वे वहां के लोगों के पेट में पानी के साथ चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद वे बीमारी के रूप में उनके शरीर से बाहर निकलते हैं।

आपने जो यह नारा दिया है कि सन् दो हजार तक आप सबको स्वास्थ्य सुविधाएं, उपलब्ध करायेंगे, वह आप कैसे उपलब्ध कराने जा रहे हैं कैसे इस योजना को आप पूरा करने जा रहे हैं,यह बताइये। हमारे देश में 5,76,917 गाँव हैं। इनमें से 50 परसेंट गांवों में आज तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आप नहीं कर सके हैं। फिर आप कैसे यह नारा देने के लिए सक्षम हैं? आप भी कैबिनेट के मंत्री हैं। आप कहेंगे कि पेय जल की व्यवस्था आपके पास नहीं है। लेकिन जिस केबिनेट मंत्री के पास में इसकी व्यवस्था करने का भार है उससे कह कर आप क्यों नहीं यह व्यवस्था करा पाये हैं। आप अपने मंत्रालयों के बीच में कोआरडिनेशन कर के कम से कम शुद्ध पेय जल की व्यवस्था तो गांवों में कर दें। आज कम से कम इसकी ही घोषणा कर दें कि एक साल में देश में जितने भी गाँव हैं, उनमें शुद्ध पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी। इसको तो आप आज अश्योर कर सकते हैं।

जो बच्चे प्रथम क्लास में दाखिल होते हैं, उसी समय से उनको कार्ड दे दिया जाए, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके पैदा होने के बाद से उनके माँ-बाप उनके कार्ड बनाकर देने की व्यवस्था कर दी जाय और उनके दस-ग्यारह साल का होने तक उनके स्वास्थ्य की हर साल चेकिंग होती रहे तो उनको कोई भयंकर रोग तो नहीं हो। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दे तो इससे भी आप भयंकर रोगों की रोकथाम कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यहाँ जोशी जी भी बैठी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालाँकि मंत्री जी भी हमारी मदद करते हैं। हम नहीं जानते कि कितने मरीजों को लेकर जिनकी हालत खराब होती है, हम मदद के लिए उनके पास जाते हैं। हम नहीं चाहते कि मरीजों की मदद के लिए हम उनके पास जाएं लेकिन बहुत से मरीजों की हालत इतनी खतरनाक होती है कि हमें जाना पड़ता है।

हमारे यहाँ जो मरीज मदद के लिए आते हैं उनमें से 80 परसेंट मरीज हार्ट के रोगी होते है। हार्ट की बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। हमें डाक्टर ने बताया है कि एक तरह का बुखार होता है, अगर किसी को वह हो जाता है और उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है तो 15 से 21 साल तक की आयु तक जाते-जाते उस आदमी के हार्ट का बल्ब खराब हो जाता है। अभी मैंने पिछले साल पढ़ा था कि आपके आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसिज में 75 हजार लोग हार्ट का बल्ब बदलवाने के लिए रजिस्टर्ड हैं। आपके वहां कैपेसिटी कितनी है, मुश्किल से 400 साढ़े चार सौ के बीच में सालाना केपीसिटी है। पूरे देश में इस तरह के 28 इंस्टीट्यूशन हैं और हार्ट आपरेशन का काम सिर्फ 8 जगहों पर हो रहा है। पिछले साल आल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट में 150 लोगों के वाल्व बदले गए, कैपेसिटी 450 की है। लिस्ट में 28 हजार हैं जिनका आपरेशन होना है। बाकी 28 केन्द्रों को छोड़ दें तब भी आल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट में इस काम को निपटाने में 100 साल लग जाएंगे। मरीज समझता है उसका आपरेश होगा, उसका वाल्व बदला जाएगा, हम जिन्दा रह जाएंगे। लेकिन आज वह घुट घुट कर मर रहा है। वह सोचता है कि आज जिंदगी का एक दिन खत्म हो गया, आज दो दिन खत्म हो गए।

आपने कहा है कि मुफ्त दवा की व्यवस्था की है। जहां मुफ्त दवा की व्यवस्था है वहां सारे का सारा ब्लैक में चला जाता है। प्रश्न पूछने पर आप क्या कहेंगे कि स्वास्थ्य राज्य सरकार का मामला है। डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह हमारे बल-बूते के बाहर की चीज है। आपने बताया कि एक सब सेंटर पर 30 हजार की पापुलेशन पर 90 हजार का बजट होता है। एक आदमी पर

3 रुपया बजट होता है। तीन रुपया तो क्या तीन पैसा भी किसी को नहीं मिल पाता। सारे का सारा ब्लेक में चला जाता है। कोई डाक्टर वहां नहीं जाता है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह सूचना सही नहीं है कि 3 रुपया पर आदमी मिलता है।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय के जवाब के मुताबिक बतला रहा हूं। नतीजा यह हो रहा है कि जब कभी भी हम आल इंडिया मेडीकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि हम किसी डाक्टर को डीफेम करने के लिए करते हैं या इंस्टीट्यूट को डीफेम करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लोगों के सामने लोग आते हैं और हम उनको घुट घुट कर मरता हुआ देखते हैं तो आंखों से आंसू गिर जाता है। किसी का भाई, किसी का बेटा ...।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) : आप मंत्री महोदय के लिए इस तरह की बात नहीं कह सकते।

श्री राम विलास पासवान : मैं मंत्री महोदय के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। आप उधर बात करते हैं और जवाब मुझे देते हैं।

आपने कहा है कि एड देते हैं, कितनी देते हैं ? मेंबर आफ पार्लियामेंट की सिफारिश पर 2000 रुपए एड देंगे। लगता कितना है ? एक आपरेशन करने में 20 हजार रुपया लगता है। 5000 तो सिर्फ दवाई के लिए लिया जाता है। बाल्व का दाम 12 से लेकर 15 हजार तक लिया जाता है। कोई गरीब इसको कैसे सहन कर सकता है। क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि सबसिडाइज्ड रेट पर या मुफ्त में गरीबों के लिए व्यवस्था हो सके। या कम से कम दाम पर व्यवस्था की जाए जिससे उसका आपरेशन हो सके। इसलिए कि यह बुनियादी सवाल है। आठ बोतल खून मांगा जाता है। आपको मालूम नहीं है कि आठ बोतल खून इंस्टीट्यूट में कितना महंगा पड़ता है। आपके बगल में सफदरजंग अस्पताल है। वहां डाक्टर हैं। आप सिर्फ साधनों की व्यवस्था कर दें, वहां भी हार्ट आपरेशन हो सकते हैं। वी आई पीज के लिए तो आल इण्डिया मेडीकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है लेकिन गरीब के लिए अभिशाप है। हम सब चाहते हैं कि इसको रैफरल हास्पीटल बनाएं लेकिन नहीं बनाते हैं।

जब तक गांवों में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक देश के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सकता। आपने कहा है कि एक सेंटर पर एक्स-रे की व्यवस्था कर देंगे, आपरेशन की व्यवस्था कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। हमें तो यह सब दिवास्वप्न लगता है। 2000 ईस्वी तो क्या 4000 ईस्वी तक भी यह सब हो सकेगा इसमें हमको शंका है। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास चारों तरफ का जो एरिया है, यहां पर बड़े-बड़े अस्पतालों की व्यवस्था कर दें। गांव में कम से कम लोगों के लिए बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था कर दें।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : He has covered all the points. Now he must give a reply for two to three hours because all points have been covered by him.

MR. DUPUTY SPEAKER : Yoy know why Mr. Mool Chand Daga said like that. He wants that you must stop now and the Minister to reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : You placed before him whatever subjects that you can make as far as Central Government is concerned.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I am within the purview of the subject.

मैं वही बात उठाता हूं जो केन्द्रीय मंत्री से सम्बद्ध मामला है। आपने दो हजार ईसवी तक "हैल्थ फार आल" की व्यवस्था करने की बात की है। आप कहते हैं कि इतने सब-सेन्टर हैं। वे, यह काम करेंगे और वह करेंगे। मैं मंत्री महोदय से करैक्ट जवाब चाहता हूं। क्या आप

प्रत्येक गांव में एक साल के अन्दर ट्रेंड दाई की व्यवस्था करेंगे जो गर्भवती महिलाओं की देख-भाल करे ? गाँव में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सस्टेन एज तक छोटी-छोटी भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए चैक-अप करायेंगे ? क्या गांव में शुद्ध जल की व्यवस्था करा देंगे ? जिन इंस्टीट्यूट्स में हार्ट की आपरेशन होता है और जिसमें रोगी को पता है कि मरने की सम्भावता है तो क्या उनका मुफ्त में ऑपरेशन और सबसिडाइज्ड रेट पर दवाई की व्यवस्था करायेंगे ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : Within how much time I have to reply ?

MR. DEPUTY SPEAKER : The whole thing is in Half-an-Hour. He has taken 20 minutes, minus my intervention is 2 minutes. His last point is an important point, about "Health Centres". I think I have followed you. Health Centres is an important subject.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Free aid to poor.

MR. DEPUTY SPEAKER : You raised some point with regard to Health Centres. I told him it is an important point.

MR. DEPUTY SPEAKER : I only appreciate all the points have been covered within the short time.

SHRI B. SHANKARANAND : The Hon. Member has raised various issues which are basic for the consideration of the entire health policy and I have already requested this House that the health policy document of the Ministry of Health and Family Welfare should be considered by this House.

I am awaiting from Session to Session and I hope that the Health Policy Document would be considered during this Session. I am saying this because the Hon. Member has raised many issues which are relevant and which need detailed consideration by the House and it is all right on the part of the House to expect to know from us as to what we have been doing, what have been our achievements in the field of health.

MR. DEPUTY SPEAKER : Because Health is Wealth. I am helping you.

SHRI B. SHANKARANAND : No doubt. we have committed under the Alma Ata Declaration that we will have a level of health by the end of 2,000 AD which will be productive and which will give a state of health.

(*Interruptions*)

SHRI B. SHANKARANAND : We have established the necessary infrastructure to provide Health Care Services to the rural people where the poor live.

The hon. Member has already given the figures which I have given to the House regarding the number of Primary Health Centres, Sub-Centres and the Community Health Centres and the figures for the tribal areas, hilly areas and other places. The shift in the health policy has been this. We are not merely on the curative aspect of health, but we are emphasizing on the aspects of promotive and rehabilitative aspects of health ; that has been the main shift in the health policy.

AN HON. MEMBER : What do you mean by that ?

SHRI B. SHANKARANAND : The hon. Member may not be knowing. It is right for him to expect from me to enlighten him on this point. Given the time, I can. That is why I am requesting the House to discuss the health policy document so that we can consider in detail all these aspects.

Coming to the limited point of the debate regarding provision of medicines for the rural poor. Under the Minimum Needs Programme provided by the States, Rs. 12,000 to Rs. 25,000 worth of medicines are provided per.

Primary Health Centre and on an average of 11 Sub-Centres at a rate of Rs. 2,000 it comes to Rs. 22,000. Under the Health Guide scheme—about 75 per cent of the Primary Health Centres are covered under this scheme—the provision is Rs. 6,000 because each Health Guide is provided certain medicines so that the rural poor may not rush to the hospitals leaving their hearth and home. This Health Guide is expected to give, just like oral rehydration powder, some such common medicines ; he is provided with such medicines to the extent of Rs. 6,000/- per year.

Besides providing medicines with the Health Guide, with the Primary Health Centres and Sub-Centres, we have also been

spending money for the control of diseases at the national level like the Malaria Control Programme, the T. B. Control Programme, the Leprosy Control Programme and Control of Blindness. If I can give the figures for 1983-84, for tuberculosis we have Provided Rs. 365 lakhs, for leprosy Rs. 1, 100 lakhs, for malaria Rs. 556 lakhs, vaccines Rs. 657 lakhs and for vitamin A and iron and folic acid Rs. 347 lakhs which come to, if I can give in terms of crores of rupees, about Rs. 30.25 crores per year ; and the figure of medicines that we purchase every year at the various levels, Village Health Guide, Primary Health Centre, Sub-Centre, etc., etc., is about Rs. 50 crores.

These medicines, I would submit to the House, are meant for the rural poor only-the poor people—for those who suffer from T. B., leprosy, diarrhoeal disease of the children and their mothers. Provision for the folic acid, tablets to their mothers and vitamin A to their children-these are meant for the poor people. That is what I say. We are hoping to do that. It is not that we have not been doing it. About Rs. 80 crores worth of medicines besides other things we have been spending on them under the goitre control, guinea worm control and other national programme. I am speaking here about the medicine only—not the other infrastructure. The money goes to the poor people it is true, though we have not been able to serve the whole lot of people. We do not want to claim that. The hon. Member said that it is not reaching the poor. It is here that we want the hon. Members' active cooperation as also the active cooperation of the social workers, leaders like hon. M. Ps. I want their cooperation in this regard so that their active cooperation definitely helps the Government efforts to see that these medicines reach the rural poor. Regarding heart patients, the hon. Member spoke. It is true that we have not been able to cater to the needs of the heart patients who come from the rural areas because the capacity to treat such patients in the Medical Institute is limited ; we cannot admit patients there. We have been trying to help the poor people and we do not make any distinction between rich and the poor and between 'haves and have-nots'. I have a little money which I can rant in my discretion to the poor who needs a little money for his heart operation in the Medical Institute. It is our endeavour to help the poor and we have been doing it. I shall see that there is no discrimination between the rich and the poor as far as treatment is concerned.

श्री राम विलास पासवान : डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं, मैंने कहा कि अमीर लोग अपना इलाज करा सकते हैं लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है कि वह इलाज करवा सके तो कम कीमत पर या मुफ्त में उसके लिए दवा और इलाज की व्यवस्था करें ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Rich people alone get the heart disease.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, 90% of the poor people get the heart disease. Heart attack is another thing and heart disease is another thing.

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, I can assure the House that we will do our best to help the poor people as for as their disease or as far as the medical aid is concerned whether it be a heart operation or whatever it is. Sir, the hon. Member has rightly stressed that if we can provide safe drinking water to the People of this country, perhaps, half of the diarrhoeal disease will be over and the poor people can be saved of this disease. It is our endeavour—the endeavour of the Government to provide safe drinking water to the poor people.

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा था कि जो बच्चे गांवों के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए कार्ड की व्यवस्था हो और उनका रेगुलर चैकअप हो ।

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, we have decided to take up a scheme under the School Health Programme. We have requested the State Governments to accept the scheme. The children at the primary schools level will be examined by the doctor and a regular health card will be maintained by the doctor to detect the disease at the early stage and the child can be treated for it.

MR. DEPUTY SPEAKER : After this we can take up the Puujab discussion. We shall then ask the hon. Minister to reply.

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh) : We may take up the Punjab discussion tomorrow.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : Agreed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. We are now in the half-an-hour discussion. Now, Mr. Harikesh Bahadur.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : This half-an-hour discussion becomes ane hour discussion.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Sir, millions of our people are dying every year due to lack of medicines and proper care. In our districts especially we find that when poor people go to the hospital they are not properly looked after. Most of the people who are working in the hospitals including doctors misbehave with the poor people.

As the hon. Minister is aware in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital doctors did not behave properly even with a Member of of Parliament. From this illustration itself the hon. Minister can understand what is the behaviour of our doctors and other staff members in the hospital with the poor people. Nobody listens to them. Unless money is paid doctors do not attend to the poor patients. These things are regularly happening in almost all the hospitals in the country except in a few hospitals which are very important hospitals.

Sir, in several districts of Uttar Pradesh people died because of malaria as it was not properly and timely detected. Such things are happening throughout the country. As far as medicines are concerned although Government is giving money yet the medicines are not reaching the poor people. Government does not have any machinery to monitor whether the benefit is reaching the poor people. Drugs are sold in the market. The poor are neither getting good treatment nor anybody is listening to them. Poor people are being forced to buy medicines from the open market. Since they are very poor, it becomes difficult for them to purchase medicines from the market.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Sir, a word obout drinking water. My friend had raised the question but the hon. Minister did not reply. I would like to know whether Government is having any proposal to provide drinking water in all the villages. If so, when will the Government be able to provide drinking water to all the villages ? I would also like to know whether Government is having any proposal to increase the number of primary health centres which are at present only six thousand in number. This small number of primary health centres cannot provide medicine even according to Government data to more than 14 to 15 crores of people.

This is from the 'Indian Express' of 4th December 1983, that is yesterday. The news item is that harmful aruge are being used in India. It was said by an expert. I would like to quote here the relevant portion.

> "Certain harmful drugs which have been banned in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka Pakistan and Malaysia are still being administered to patients in India, according to a medical expert from Bangladesh".

Further I quote—

> "Citing the example of analgin, Dr. Zafrullah Choudhury Director of Gonoshasthya Kendra (People's health centre) Dhaka, recorded that India, emerging as a leader in third world, is still permitting the use of this".
>
> "He said drugs banned in Bangladesh are still being marketed in India by multinationals."

Sir, this is a very serious matter. I do not know whether the attention of the Government was drawn to this news item. The Government must take care of such a serious information. This medicine is specially being used by the poor people in our country. The doctors are prescribing these cheap medicines and they are distributed in the hospitals. The costly medicines are not provided in the hospitals. Only rich and resourceful people are able to get such costly medicines which are not harmful to health. But these cheap medicines which are dangerous and harmful to health are given to the poor people in the hospitals. I would request the hon, Minister to look into this. I would also like to know whether he has seen this news item and if he has seen, I would like to know what he has done in this regard.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, नारों से सरकार बनाई तो जाती है, लेकिन चलाई नहीं जा सकती। हैल्थ मिनिस्टर अगर झूठ बोलता है, तो उसकी हैल्थ घट जाती है।** बोलने से तंदुरुस्ती गिरती है, इन बात का पूरा बेस है। मेरी भी गिरेगी, अगर मैं** कहूंगा और** बात वह भी नहीं कहेंगे।

SHRI B. SHANKARANAND : He has used the word **. This is unparliamentary. This should not go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the records.

AN HON. MEMBER : It is not unparliamentary.

MR. DEPUTY SPEAKER : You leave it to the Chair. We will decide it.

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री महोदय ने कहा है कि 2000 तक सब को स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाएंगी। यह अच्छा नारा है। आज हिन्दुस्तान में 52 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये गवर्नमेंट के फिगर्ज हैं। मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब बताएं कि जो लोग गांवों में रहते हैं, उनमें एक आदमी पर सरकार स्वास्थ्य के लिए ऐवेरेज कितना खर्च करती है। वह यह भी बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर कितना है और दवाइयों पर कितना खर्च होता है। 30,000 आदमियों पर एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, ट्राइबल एरिया में 20,000 आदमियों पर एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर है और 5,000 आदमियों पर एक सब-सेंटर है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है 17,000 रुपए और दवाइयों पर खर्चा है 5,000 रुपए। वे दवाइयां 20,000 लोगों पर बांटी जाती हैं। 5,000 रुपए की दवाइयों में से 1,000 रुपए की दवाइयां डाक्टर साहब और उनके सम्बन्धियों के घरों में, एम०एल०ए० और एम०पी० के पास जाती हैं। और वह जाती है गांव के मुखियों के पास। 1,000 रु० की दवा जाती है गांव के बड़े-बड़े लोगों के पास। और जो दवा बचती है उसमें से कुछ कम्पाउन्डर ले जाता है, कुछ नर्स ले जाती है। आप बतायें कितने रु० की दवाइयां 30,000 लोगों में बांटते हैं? इसलिए यह न कहिए कि 2000 ए०डी० तक सब तक स्वास्थ्य की सुविधायें पहुंच जायेंगी। गांवों में तो डाक्टर ही नहीं हैं। लेकिन आपने कह दिया कि डाक्टर हैं। मेरा कहना है कि कोई गांवों में डाक्टर जाना ही नहीं चाहता। राज्यों में शहरों में सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कभी आपने कहा है कि जो नौकरी करेगा उसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाऊ नहीं करेंगे? आज 27,000 डाक्टर बेकार हैं, लेकिन गांव में कोई जाना नहीं चाहता। बड़े-बड़े अस्पतालों में जैसे आल इंडिया इंस्टीट्यूट या राम मनोहर लोहिया में जो रूम्स हैं वह एम० पीज० एम. एल. एज. और गण्यमान्य लोगों के लिए ही हैं। उनमें गरीब आदमी नहीं रखा जाता है। कैसे आप कहते हैं कि किसी के साथ डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा? एक एक बिस्तर पर 5, 5 बीमार पड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप डायरेक्टर को भेज पर दिखवाते? मैं देखी हुई बात कह रहा हू एक एक बिस्तर पर 4, 4 बीमार पड़े हुए हैं, और जमीन पर पड़े हैं। कभी आपने यह रूल बनाया है कि क्यू में खड़े होइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड रूल लागू होगा? इसलिए हैल्थ फार आल बाई 2000 ए०डी० कभी नहीं होगा। दिल्ली में 5,000 आदमी पर एक डाक्टर है, और गांवों में 40,000 पर है।

अब आपने हैल्थ वालन्टीयर्स बनाये हैं 3 लाख 60 हजार जो कुछ नहीं जानते हैं। क्या यह लोग 3 महीने में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर डाक्टर बन गये? पता नहीं किसने सोचा है? राजनारायण जी की बुद्धि थी या जनता पार्टी के दिमाग में आया हैल्थ फार आल की बात। यह वालेन्टीयर्स कुछ नहीं समझते हैं दवाओं के बारे में।

मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ता, आप यह बताइए कि आपकी बेसिक पौलिसी क्या है? क्या आपने स्टेट्स को गाइड लाइन्स दी हैं कि

** Expunged as ordered by the Chair.

स्टेट्स के अन्दर सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा ? स्टेट्स में इतने लोगों पर इतनी दवाओं का खर्चा है। आप ये दवायें हास्पिटल से ले सकते हैं और ये बाहर से आप खरीद सकते हैं। वहां तो डाक्टर ये काम करते हैं कि कि जाओ ये दवाई भी और वह दवाई भी बाजार से ले आओ। हर दवाई को बाजार के लिए कह देते हैं। आपके छठे पंचवर्षीय प्लान में लिखा है कि 2000 ई० तक सब का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। किसी स्थान के लिए बजट में प्रोवीजन है कि 12 लाख रुपया खर्च करना है, तो उसको डाइवर्सिफाई करके चार लाख रुपया काट दिया जाता है। आप देश के नागरिक हैं, आप देश को चलाते हैं और हम आपको सहयोग देते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप सीरियासली इस बात पर विचार कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन स्थानों पर कम से कम साल में छः बार जाइए। उस समय आप जाइए, जब आप अपनी आखों से वहां की स्थिति का जायजा ले सकें। सूट पहन कर नहीं एक साधारण आदमी बनकर, एक पेसेंट के रूप में आप वहां जायें वहां की स्थिति को देखें। जैसा आप वहां की स्थिति के बारे में लिखेंगे, हम मान लेंगे। लेकिन आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो इन्कम टैक्स देने वाले हैं, जिनको दो हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, वे लोग हास्पिटल में नहीं जायेंगे। हम लोग थोड़ा फायदा उठाते हैं, लेकिन गरीब को कोई फायदा नहीं हैं। यदि इनडिस्क्रिमेंशन हटाना है तो आप आर्डर निकालिए और इनकलाब पैदा कीजिए।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास जी ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि यदि पांच बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक पैसा होते ही कुछ देर के बाद मर जाता है। चार बच्चों में दो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक चलता रहता है और दो का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं आपसे दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूं। छोटे बच्चों को आप टीके लगाते हैं, जो कि पैदा होने के कुछ दिनों बाद शुरू हो जाते हैं। आप पोलिया, काली खांसी और चेचक आदि के टीके लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं डा० राम मनोहर लोहिया होस्पिटल में से ठीक नहीं उपलब्ध होते हैं। गांव की बात तो बहुत दूर रह गई, यहां दिल्ली में भी बच्चों को टीके उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या आपने कभी राज्य सरकारों से पूछा है कि आपके काम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर्स में टीके लगाने की कोई व्यवस्था है या कोई गाइड लाइन्स आपने वहां की सरकारों को दी है ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आगरा जिले में एन्टी-रेबिट का टीका भी उपलब्ध नहीं है।

गांव में अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो वह वहीं गांव के किसी जादूगर के पास या नीम-हकीम के पास जाकर अपनी जिंदगी गवां देता है, लेकिन एन्टी रैबिट्स के इन्जैक्शन वहां नहीं मिलते हैं। मैं यह बात उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं, दिल्ली के बारे में मुझे मालूम नहीं है। यहां तो शायद यहां की नगर पालिका या नगर निगम कुत्तों को मरवा देती होंगी। लेकिन गांवों में या तो कलैक्टर से लिखवा कर लाओ या किसी को 10 रुपए देकर इन्जैक्शन लगवाओ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब बच्चे की स्वास्थ्य की व्यवस्था शुरू में ही नहीं होगी तो जब वह बच्चा स्कूल में पढ़ने जायगा, तब आप उसको क्या हैल्थ देंगे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खसरे तक के टीके नहीं हैं।

अभी आपने 2000 रुपए की मदद की चर्चा की थी। हार्ट-सर्जरी के लिए मंत्रालय 2000 रुपये की मदद करता है। मेरे सामने केश आया था जिसमें 9 हजार रुपये की संतुति की गई थी लेकिन फाइनेन्स विभाग ने क्या आब्जैक्शन लगाया कि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बेटा है। मुझे इस बात को जानकर बहुत आश्चर्य हुआ—वह

एक सरकारी कर्मचारी हो सकता है, लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का कितना मासिक वेतन होता है, क्या वह उतना पैसा उपलब्ध करा सकता है ? 18000 रुपए की डिमान्ड थी, उसमें से 9000 रुपए के लिए उस गरीब का बाप आपके पास घूमता रहा लेकिन दुर्भाग्य से आप से सम्पर्क नहीं हो पाया। वह सरकारी कर्मचारी है, लेकिन किस क्लास का कर्मचारी है यह नहीं बतलाया गया—नतीजा यह हुआ कि उसकी मदद नहीं की जा सकी। मुझे यह निवेदन करना है कि 2000 की राशि बहुत कम है, ऐसे केसेज में उसको बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए, जिससे कम से कम ऐसे केसेज में जो असहाय हैं, जिन का आपरेशन के लिए वर्षों तक इन्तजार करने के बाद नम्बर आता है जब तक ए०आई०आई०एम०एस० में हार्ट सर्जरी के लिए बुलाया जाता है और उनको जब यह मालूम होता है कि कुल 2000 रुपया सैंक्शन हुआ, 18000 रुपया उनको देना है तब उनकी क्या स्थिति होती है आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस राशि में वृद्धि का प्रयास करें तथा राज्य सरकारों को निर्देश दें कि एन्टी-रेबिट्स के सेन्टर कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर में खोलें और बच्चों को जो टीके लगाये जाते हैं, जिनका 3 महीने और 6 महीने का कोर्स होता है, उनकी व्यवस्था वहां होनी चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : You can reply to all the three Members.

SHRI B. SHANKARANAND : The hon. Members have complained in general about shortage of drugs and their pilferages, unwillingness of the doctors to go to the rural areas and the not so proper a behaviour—I don't say improper but absence of respectful behaviour—towards Members of Parliament by some doctors.

MR. DEPUTY SPEAKER : And private practice by doctors.

SHRI B. SHANKARANAND : Regarding discrimination and indiscrimination, I have already replied ; and I do not want to repeat it. But I would advise the hon. Member—or I should say I can request him—to try to develop an attitude towards life i.e., to see the brighter aspects of life, and not always of looking to the dark aspects and having tension in his mind that life is not worth living. I don't think this sort of an attitude will help either or the parliament.

Having heard in detail, what the Government has been doing for the welfare of poor people regarding their health, if they stills that nothing is being done, I have nothing to say.

Regarding private practice by government doctors, may I quote the health policy that is pending before the House for consideration. It says as follows :

> "It is desirable for the States to take steps to phase out the system of private practice by medical personnel in government service, providing at the same time for payment of appropriate compensatory non-practising allowance. The States would require to carefully review the existing situation, with special reference to the availability and dispersal of private practitioners, and take timely decisions in regard to this vital issue."

This year, the Central Council of Health which is constituted by the Health Ministers of the States, and Union Territories they have passed a resolution. It states as follows :

> "All States/UTs. should consider the desirability of taking immediate steps to phase out the system of private practice by medical personnel in Government service, providing at the same time for-payment of appropriate compenastory non-practising allowance not imposing any ceiling on Pay plus N. P. A. The upper limit of NPA of Rs. 600 is 2 decades old and needs revision."

This is the recommendation of the Central Council of Health.

The government isin the right direction.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : It only betrays the ignorance of the government regarding re-arming of the private practitioners.

SHRI B. SHANKARANAND : Regarding availability of drugs and vaccines, the

hon. member from Uttar Pradesh has brought to my notice about the shortage of rabi vaccine in U.P. If any specific instance is brought to my notice, we will take prompt action. To my knowledge, so far, we have not received and report of shortage in this regard.

18.50 hrs.

DISCUSSION ON THE STATEMENT RE : SITUATION ARISING OUT OF REPORTED TRAINING CAMPS OF EXTREMISTS OF PUNJAB IN NEIGHBOURING AREAS OF THE STATE-CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up.....

(Interruptions)

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh) : Postpone it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You please wait.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, please wait. Please. Mr. Namgyal, if you want to postpone it, tomorrow we are taking up at 2 P. M. on the request of all the Members, the international situation. Supposing we postpone it, if we could not take up this then you should not blame the Chair. Therefore, you suggest to me now. Many Membres have Spoken, *(Interruptions)*

SHRI P. NAMGYAL : Postpone it to day-after-tomrrrow.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is not like that. You cannot postpone it to day after tomorrow or the 14th and so on. Take, for instance, the international : situation, is it not an important subject ? We have to take it up at 2 P. M. Therefore, Dr. Subramaniam Swamy suggests because he was one of the movers of this Calling Attention Motion.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : What is it you are talking ?

SHRI P. NAMGYAL : We may postpone it.

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : From our party no one has spoken.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is wanting postponement. If you want to continue I have no objection.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : All right. What is the sense of the House ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : I have to reply in the other House tomorrow. I would therefore appeal to hon. Members, and also to the Chair that it may be finished today.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister wants that we should finish it today. I would therefore appeal to hon. Members not to take much time, not to repeat what the other hon. Members have said, and not to go around Punjab, Chandigarh and other places and all that, but to come to the point. The Minister will reply and then only we will adjourn. You also assure me that any Member, after he speaks, does not leave the House.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : The *raga* and *tala* should be new.

MR. DEPUTY SPEAKER : You must know that the Press also have criticised that at times there are not sufficient Members in the House. You would have also seen. When important matters are discussed, all the Members should be present, both the sides must organise so many Members and if the discussion is there, then only it will be good. Therefore, please, *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER : We are therefore continuing the discussion and I will appeal to hon. Members not to take more time.

Till what time we should sit, you please tell me. We will sit till you finish. Who is to speak now.

Mr. Rajesh Kumar Singh.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Some *ragas*, same *talas*, and the tune also is the same.

MR. DEPUTY SPEAKER : What can I do ? If it is postponed it will never come up ; we are takingup the Five-Year Plan, then the international situation is there.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : All the failures of the Government we are going to discuss.

MR. DEPUTY SPEAKER : I am fixing the time. Each hon. Member will not take more than ten minutes. Mr. Rajesh Kumar Singh.

SHRI G. L. DOGRA (Jammu) : It is not possible. It is impossible.

MR. DEPUTY SPEAKER : You leave it to the Chair. I am very sorry.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Kashmir Members have to speak a lot,

MR. DEPUTY SPEAKER : That is all right. I am only appealing to the hon. Members that they should finish their speeches within ten minutes· Why do you object Some Members may finish it before ten minutes. If you want to takemore time, you can take Mr. Rajesh Kumar Singh.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : A good suggestion has not been accepted.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : पंजाब की समस्या काफी गंभीर समस्या है और इस सदन में बार-बार इस बारे में चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। हमें लगता है कि हम कुछ दिन बाद आदी हो जाएंगे और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह होता रहेगा। कभी कभी ऐसा अहसास होता है कि पंजाब में सरकार है या नहीं।

मान्यवर एक बात कभी कभी लगती है कि सरकार एक पक्ष अख्तियार करना चाहती है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ अन्य लोग जिम्मेदार हैं। सरकार जिम्मेदार नहीं है। नहीं तो प्रशिक्षण शिविर वाली बात का जो जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि 6 प्रशिक्षण शिविर जम्मू-कश्मीर में लगे, दो हिमाचल प्रदेश में लगे और बाकी के पता नहीं है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाकी क्या जिन राज्यों में आप की ही सरकार है क्या वहां ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब जम्मू कश्मीर से हथियार सप्लाई होते हैं और फैक्ट्री पकड़ी जाती है और किसी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आता है तो सरकार मौन हो जाती है। सरकार क्यों मौन रहती है। जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना हो रही है तो जम्मू कश्मीर की सरकार की जिम्मेदारी है। सही मायने में वह सिर्फ मनगढ़न्त बात है या यह मंशा है कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की स्पेनिश बंदूकें पकड़ी गई हैं, उसी पृष्ठभूमि में यह बात आ गई है और सरकार ने कहा कि वहां कुछ अरसे से ऐसा चल रहा है। मान्यवर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। सभी जानते हैं कि श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाला को प्रोत्साहन देने वाले लोग कौन हैं। वे छिपे नहीं हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने भी बड़ी चिंता व्यक्त की है। जो कुछ हो रहा है, बड़ा दुखद और दर्दनाक है। सरकार ने आज तक इसके सोल्यूशन के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया है ? क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू या शासन को सख्त करके इस समस्या का समाधान करना चाहेगी या सरकार पोलिटिकल सोल्यूशन के हक में है। मेरा ख्याल है सरकार के अन्दर शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती तो उग्रपंथियों को दबाने में सरकार कामयाब हो जाती। भिंडरावाले बार-बार कह देते हैं कि सरकार में साहस नहीं है। आज गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि गुरु नानक के पवित्र स्थान से उत्तेजित और भड़काने वाले ब्यान देते रहे हैं। बार-बार गुरु नानक निवास की बात आती है। सरकार क्यों नहीं कदम उठाती ? सरकार को डर लगा हुआ है। क्या सरकार पंजाब के इलैक्शन्स के लिए हिन्दुओं का बलिदान करना चाहती है। हिन्दुओं के अन्दर यह भावना पैदा हो कि हमारी सुरक्षा सिर्फ सत्तारूढ़ सरकार ही कर सकती है। जम्मू-कश्मीर के चुनाव में हमने कुछ हरकतें देखी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि ऐसी ही घटना हिमाचल में घटती है तो दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आपने क्या कभी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर से यह पूछा कि आपके यहां कैम्प कैसे लगे ? इसलिए, आपको नैतिकता का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आप अपनी सरकार को भी एक ही छड़ी से हांकेंगे तो तभी

कुछ हो सकता है। आपको यह अच्छी तरह से मालूम है कि गुरु नानक निवास एक रहने की जगह है, एक धार्मिक स्थान रहने का हो सकता है। वहां पर लोग जूते पहनकर चले जाते हैं। क्या वजह है कि आप गिरफ्तारी नहीं करते। ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि आए दिन निर्दोष लोगों को बसों से उतार कर मार दिया जाता है। कुछ पागल हैं जो और प्रांतों में हरकतें करने लगे हैं। आप कहते हैं, संवेदनशील इलाका है, सीमा पर लगा हुआ है, विदेशियों की गतिविधियां चल रही हैं। आप क्यों नहीं बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते। क्या आपके अन्दर कोई डर छिपा हुआ है? आपकी पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्रीय आन्दोलन चल रहा है, हमें बड़ी हमदर्दी है हो सकता है, फारेन अफेयर्स पर कल चर्चा आ जाए और लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। जब वहां की चिंता रहती है तो पहले देश की चिंता रहनी चाहिए। आपकी नीतियां ऐसी हैं जो आपस में टकराती हैं। अकाली दल या भिंडरावाले का मतलब सिख समुदाय नहीं है लेकिन उसे बनाने की साजिश चल रही है। कल परसों सीसगंज गुरुद्वारे का हंगामा कर दिया। भिंडरावाले का ब्यान आ गया कि वहां प्रवेश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस राजनीति के खेल में आप कहीं निर्दोष लोगों को न मरवा दें। हथियार आज तक क्यों नहीं आपने पकड़े? मंदिर में आग लगा कर लोग भाग गए, इसका विवरण आज छपा है। मोटर साइकल पर आए और भाग गए। आश्चर्य की बात है कि गुरुद्वारे में हथियार आ रहे हैं और पुलिस आपकी द्वार पर खड़ी है और वह पकड़ नहीं पा रही है। क्या वह सोई हुई है? पुलिस वहां खड़ी क्या कर रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से दूर न हटें। आप सख्त कदम उठाएं। देश को बचाने के लिए यदि सौ दो सौ जानें भी चली जाती हैं और देश बच जाता है तो उन लोगों की कीमत कुछ नहीं है। आप देश को बचाना नहीं चाहते हैं। आपका दूसरी तरफ दिमाग बना हुआ है। आप पौलिटिकल सौल्यूशन ढूंढें, आपको किसने मना किया है। आप बार बार कहते हैं कि वार्ता करेंगे। विरोधी पक्ष और अकालियों से करेंगे। किन्तु कुछ होता नहीं है, बात बनती नहीं है। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि समस्या कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो क्यों आदमी मारे जा रहे हैं। विदेशियों का हाथ इसके पीछे है तो उनकी गतिविधियों को जारी रखने की आप क्यों इजाजत देते हैं। आप ही तो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

बुनियादी प्रश्न यही है कि बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई है। काफी अर्से से यहां यह बात होती आ रही है कि लोग मारे जा रहे हैं। आप ब्यान दे देते हैं। कल भी बयान दे देंगे। हमें भी मौका तब मिल जाता है चर्चा में भाग लेने का। आम आदमी सोचने लगा है लेकिन सरकार सोचती नहीं है। सरकार चलाने का यह तरीका नहीं है। राजनीतिक तरीके भी कुछ हैं। लेकिन प्रशासनिक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं। सरकार का कुछ कर्त्तव्य भी है, फर्ज भी है और उसको उसे निभाना होगा।

कंसेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो या भिंडरांवाला कानून की नजर में सब समान हैं।

कभी कभी कह दिया जाता है कि कैम्प लगाए गए हैं, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं इस वास्ते ये घटनाएं घट रही हैं। हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारे देश के लोगों के लिए यह सोचने की बात है और वे इस पर सोच भी रहे हैं लेकिन सरकार सोच नहीं पा रही है और फैसला नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। सरकार को कमजोर नीति नहीं बल्कि मजबूत नीति अपनानी चाहिए, मजबूत कदम उठाने चाहियें। ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति भयानक बन जाएगी। जैसे उन्होंने आज यह कह दिया है कि हिन्दुओं को कत्ल कर दिया जाएगा। कल को अगर कोई हिन्दू नेता कह देता है कि सिखों को कत्ल कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी। आप कह देंगे कि

पागल की बात है और अखबार वालों ने छाप दी है। कुछ न कुछ बात होती है तभी तो अखबार वाले छापते हैं। आपकी मंशा के माफिक हो तो ठीक और विपरीत हो तो गलत, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

कितने उग्रपंथियों को आपने गिरफ्तार किया है, कितनों को अपराधी घोषित किया है और कितनों को सजा दिलवाई है, यह मैं जानना चाहता हूं। साथ ही आप यह भी बतायें कि कब तक आप भिंडरांवाला को गिरफ्तार करेंगे और खाली उसके खिलाफ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते रहेंगे। उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि देश के लोगों को यकीन हो कि देश की अखंडता आपके लिए सर्वोपरि है और साम्प्रदायिक भावना फैलाने वालों के खिलाफ फिर चाहे वह हिन्दू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, कार्रवाई की जाएगी। अगर इसी तरह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होती रही तो आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। लोगों को यकीन होना चाहिए कि सरकार सख्त कदम उठा रही है। विरोधी पक्ष भी न्यायसंगत कदम उठाने के लिए मुझे आशा है आपको पूरा समर्थन देगा।

मैं कोई उनके वक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सारे देश के लोग आपके पीछे होंगे। लेकिन यदि आप राजनैतिक उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करेंगे और पंजाब की सरकार को फिर वहां एस्टैब्लिश करना चाहेंगे तो ऐसे तरीकों से सरकार नहीं चलती है और न चल पाएगी। इससे सद्भावना पैदा नहीं होगी। इस के लिए आप को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिये और इन एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ कदम उठाना चाहिये। इसके साथ साथ पोलिटिकल साल्यूशन के लिए भी आप अपना दिमाग बना कर काम करें और एक सही भावना देश के अन्दर बनाएं जिससे देश की एकता बनी रहे, लोगों में सहयोग और सद्भावना बनी रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से देश के अन्दर ऐसी प्रतिक्रिया होगी जिस की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज सिख कहेंगे, कल हमारे मुसलमान भाई कहेंगे, परसों अछूत और हरिजन भाई कहेंगे कि उनके लिए भी कोई जगह दें। यह हालत देश की बन रही है और आप उसी के सामने झुक जाते हैं जिस के हाथ में लाठी की ताकत होती है, जिस के हाथ में लाठी की ताकत नहीं होती उसके साथ आप कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होते।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका बख्शा। आज जो बहस चल रही है यह बहुत जरूरी है और इसकी बहुत इम्पार्टेंस है। जम्मू काश्मीर और पंजाब के लोगों के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवाल है और देश की एकता, उसकी इन्टीग्रिटी का सवाल है। मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूं कि इसको पार्टी बेसिस पर या पोलीटिकल बेसिस पर नहीं बल्कि नेशनल इश्यू के तौर पर लेना चाहिये और सब को इसे समझ कर इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिये। ...(व्यवधान)...

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राष्ट्र हित के बजाय सत्य पर लेना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं स्वामी जी से यह कहना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे वह जरा सीरियसली लें। कभी किसी वक्त तो सीरियस हो जायें। कभी इधर बहकना, कभी उधर बहकना, कभी इस्रायल चले जाना, कभी चीन चले जाना, इससे कुछ हल नहीं होना। कम से कम जब मुल्क की बात होती है तब तो रंजीदगी से सुनना चाहिए। आप जब इस किस्म की बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। आप कहते हैं कि "मैं अमेरिका में प्रोफेसर रहा"। इस किस्म के प्रोफेसर इस मुल्क में हो जाएं तो फिर तो मुल्क तबाह हो जायेगा। मुझे मजबूर न करें। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हम जिम्मेदार लोग यहां बैठे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ हिस्टारिकल फैक्ट्स हैं और उसमें कुछ लोग तो जो यहां बैठे हैं वह हिस्ट्री को जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जेनुइनली ऐन्टी इम्पीरिअलिस्ट हैं, जो इम्परियलिज्म को यहां नहीं आने देना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलकुल ऐन्टी-कम्यूनल हैं, जो बिलकुल इस तरह की बातों को नहीं चाहते। लेकिन कुछ न कुछ तो बात है। आपोजीशन की नुकता चीनी सियासी नजरिए पर निर्भर है। आपका यह कहना कि हम वोट लेने के लिए पंजाब का हल नहीं होने देते, सरासर गलत है। इन हालात में क्या हिन्दू हमको वोट देंगे या अकाली हम को वोट दे देंगे, इस तरीके की बात कहना ही गलत है। यह सही अप्रोच नहीं है, यह लोगों को परेशान करने वाली अप्रोच है। इस तरह की बात कर के हम मुल्क की पब्लिक ओपिनियन के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं।

सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने दो तीन बातें कहीं वह गए, लोंगोवाल जी से मिले। मैं भी लोंगोवाल की इज्जत करता हूं। सिखों के खिलाफ न तो हमारे यहां कोई खास लोग हैं न आम तौर पर पब्लिक है न कोई पोलिटिकल पार्टी, मैं समझता हू कि इन के खिलाफ है। लेकिन जो लोग बुरी किस्म की हरकतें करते हैं, उन के खिलाफ जरूर हैं। यह कहा गया नानक निवास में कमरा नम्बर 32 को देखा, उसमें कोई नहीं है। एक कमरे में जाने से कुछ नहीं जान पड़ता अभी चन्द दिन पहले की बात है कि हिन्दू कालेज अमृतसर में अमरीक सिंह का नानक निवास से टेलीफोन आता है कि तुम ग्रन्थ साहब का पाठ कालेज में रखो नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह अमृतसर के अन्दर की बात है। प्रिंसिपल ने कहा कि आज तक यहां ग्रन्थ साहब का पाठ कभी नहीं हुआ, तो अमरीक सिंह ने कहा कि आप को करना पड़ेगा वरना हम आप की ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल साहब डी० सी० के पास गए। डी.सी. ने कहा कि दो दिन के लिए कालेज बन्द कर दो। फिर हिन्दू कालेज मैनेजिंग कमेटी के चेयर मैन चौधरी बल्देव कृष्ण नानक निवास में एक डेपुटेशन लेकर अमरीक सिंह से मिले वहां पर उन्होंने कोई बात नहीं मानी। लोगों की रेजिस्टेंस से अभी तक सिचुएशन बची हुई है। फिर भी सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि नानक निवास में कोई भी मशकूक आदमी नहीं है।

आप यह कहते हैं कि भिंडरांवाला वहां नहीं है? अगर आप अकाली लीडरों के दोस्त हैं, यदि आप पंजाब में अमन चाहते हैं तो आप कहिये कि भिंडरांवाला को बाहर निकालिए। अगर भिंडरवाला सही है उसने कोई अपराध नहीं किया है तो अदालत के सामने आये और बरी हो जाता है तो बात साफ हो जायेगी। हमको इसमें लिपटा पोची से काम नहीं करना चाहिए। नेक नियत अपोजिशन को और हमको साफ कहना चाहिए बल्कि पूरे जोर से कहनी चाहिए कि जो गड़बड़ करने वाला है उसको कहीं प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि गुरुद्वारों या दूसरे धार्मिक स्थानों की मर्यादा का उल्लंघन हो। मगर वहां के अधिकारियों की कोई जुम्मेदारियां हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दरअसल यह सब इंपीरियलिस्ड कांसप्रेसी है और आज की नहीं है। महाराजा प्रताप सिंह के जमाने से है, यह काश्मीर की बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, पता नहीं। रूस के साथ भी और चीन के के साथ इसकी सरहदें लगती हैं। ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म साम्राज्य सीयर हैड करता था उस वक्त महाराजा प्रताप सिंह को डिपोज करके इस स्टेट पर कब्जा करना चाहा तो अमृतबाजार पत्रिका के एडीटर मि० घोष ने रेजीडेंट के दफ्तर से पूरा पता कर के इस साजिश को एक्सपोज किया और इस स्टेट को बचाया और उस वक्त अंग्रेज इस रियासत पर कब्जा नहीं कर सके।

आज उन्हीं घोष साहब की बहादुरी का नतीजा है कि आज भी हिन्दुस्तान की सरहद रूस के साथ भी मिलती है, चीन के साथ भी मिलती है, उसके कुछ हिस्से पर बेशक पाकिस्तान कब्जा

कर चुका है, मगर कानूनी तौर पर पूरी रियासत भारत का अंग है। तब से लेकर बराबर यह कांसप्रेसी चल रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान कितनी दफा आर्म्ड हो चुका है। अमरीका के इंपीरियलिज्म ने उसे कभी चाइना से लड़ने और कभी रूस से लड़ने के लिएके लिए हथियार दिए जोकि हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए और यहां श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी पूछते हैं कि कौन सी फारेन पावर है जिससे आर्मामेंट पाकिस्तान में आ रहा है? आपको नजर नहीं आता, क्या आपको इसका इल्म नहीं है कि कितने खतरनाक हथियार वहां आये हैं? क्या आप जानते नहीं हैं? ये इम्पीरियलिस्ट लोग उसको असला दे रहे हैं हम पर अटैक करने के लिए, हिन्दुस्तान का मटियामेट करने के लिए। इंटरनल गड़बड़ी भी यह इम्पीरियलिस्ट करना चाहते हैं।

मैं सिर्फ घोष साहब वाली बात ही नहीं कहता, सन् 1951-52-53 में लाय हंडरसन ईरान में अमरीकी अम्बेसेडर था वह श्रीनगर में 1952 में आये, 1951 में आये और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हंडासन यहां आई थीं वह बहुत खूबसूरत औरत है और वह सारा समर वहां रहते थे और वह बारबार शेख साहब से मिलते थे। उन्होंने शेख साहब की रियासत में उलझाव पैदा कर दिया। मैं उस वक्त शेख साहिब की कैबिनेट का मैम्बर था। मेरे बाद में बोलने वाले काबली साहब असेम्बली में बोलते वक्त जो तकरीरें उन्होंने की हैं, उन्हें भी याद रखें। लाय हंडरसन के वक्त शायद छोटे बच्चे थे, उनको यह सब भी मालूम नहीं होगा। शेख साहिब के सियासी उलझाओं ने 1953 पैदा किया। 1953 के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर बख्शी साहिब ने और प्रधान मन्त्री पंडित जी ने इनको डाक्टर बनवाया और हमारी स्टेट ने इनको मदद की और ये डाक्टर बनकर इंग्लैंड चले गये और वहां जाकर ब्रिटिश सिटीजन बन गए। उसके बाद ये वापस आते हैं, वासस आकर यहां किसको लाते हैं। एक काश्मीर लीग लन्दन में है, जो भारत के खिलाफ है। ये उनके आदमियों को यहां बुलवाकर उनको साथ लेकर उनका रिसैप्शन करते हैं, उनको अन्दर बैठाकर बातें करते हैं। जब वह वापस जाते हैं तो कहते हैं कि काश्मीर का क्वैश्चन ओपन है, अन-सैटल्ड है। जाने क्या-क्या बातें हुईं? इन सब बातों को हम नहीं जानते, जो भी एवीडेंस मिलती है वह बिल्कुल एंटी-इंडिया हैं।

एक हमारे मार्शल असगर खां हैं, उनके भाई पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड आफिसर हैं। मैं अखबारों की बात नहीं कह रहा हूं, जो सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं अखबारों से कहते हैं, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। आप कहिये गलत है वैरीफाई कीजिए। मार्शल असगर खां के भाई, जो पाकिस्तान की फौज के अफसर थे, जिन्होंने रेडर्स को लीड किया था जम्मू-काश्मीर में 1947 में, वह यहां आये।

वह डा० फारूक से मिले। उन्होंने कहा कि वह पोल्ट्री खोलना चाहते है, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। काश्मीर वैली में और सारी सरहदों पर डाक्टर साहिब तीन महीने उनके साथ रहे। उसके बाद वह वापस गए।

SHRI SURAJ BHAN : This is a serious allegation. Home Minister should reply.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Home Minister is there. He should reply to it.

श्री गिरधारी लाल डोगरा : इनकम टैक्स के अफसरों ने डिफरेंट घरानों पर रेड किया, तो हमारे प्रेजेन्ट चीफ मिनिस्टर ने उनकी पिटाई कराई। उन्होंने शेख साहब की जिन्दगी में ही एक्सट्रीमिस्ट्स को, सिख यूथ फेडरेशन को, जिसके चेयरमैन अमरीक सिंह हैं, कनटेक्ट करना शुरू कर दिया था। शेख साहब की गवर्नमेंट के जमाने में ही पूंछ में जो कैम्प लगा उसमें आर्म्ज ट्रेनिंग दी गई। उसमें इनका डी सी गया। वहां पर ट्रेनिंग देते देते गोली चलने से एक सिख मारा गया। क्या-क्या बातें हुईं और हो रही हैं।

वहां पर होम मिनिस्टर साहब की इन-टेलीजेंस इनस्डीक्वेट है। वहां से बहुत कम

इनफार्मेशन आती है। उन्हें अपनी आर्गनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। वहां पर पूरी आर्गनाइजेशन रखने की जरूरत है, क्योंकि यह मुल्क की सिक्युरिटी का मामला है। शेख साहब की वफात के बाद उन्होंने उनकी कैबिनेट के बारे में कहा कि यह** है। और उनको हटा दिया उन्होंने उसकी जगह नई कैबिनेट बनाई। उसमें वह उन लोगों को लाए, जिनकी अपनी पोलिटीकल स्टैंडिंग क्वेस्चनेबल है, जिनका कोई सैकुलर स्टैंड नहीं था, जिनका कम्युनल स्टैंड था, जिनकी लीनिंग्ज थीं **नाट टुवर्ड्ज सेकुलरिज्म बट आ दि अदर साइड-आउट साइड इंडिया।**

उन्होंने स्टेट और सैंटर के रिलेशन्ज को आहिस्ता-आहिस्ता अटैक करना और वीकन करना शुरू कर दिया। वह एक रीसेटलमेंट बिल लाए और ट्रांसफर आफ चीफ जस्टिस के मामले पर बड़ा हल्ला मचाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बेइन्तहा इल्जाम लगाए। यही नहीं, उन्होंने उसके डायरेक्शन्ज को खत्म कर दिया और उसके आब्जर्वर्ज की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट टाइरेड किया। जुडिशल सर्विस के लोगों ने अपनी आर्गनाइजेशन के एक फंक्शन में उनको बुलाया। वहां पर उन्होंने ऐसी बातें कहीं, जो इस हाउस में रिपीट नहीं की जा सकतीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्टेट के लोग बाहर से आने वाले नये चीफ जस्टिस को यहां दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, के आर्डर्ज, डायरेक्शन्ज और फैसलों को टोटली डिसरिगार्ड किया और कहा कि यहां हमारा ही हुक्म चलेगा। जब इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि **आई विल हैव इलेक्शन्ज अण्डर यू एन ओसपिशिज।**

डा० स्वामी ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर कई बातें कही हैं। **वी होल्ड नो डिफेंस फार हिम।** वह योग सिखाते हैं। वह भी बिहार के हैं और पासवान साहब भी। ये लोग कभी एक तरफ की बात करते हैं, कभी दूसरी तरफ की। वह आपके हैं। हमारे साथ उनका कुछ नहीं है। **वी डू नाट मिसबिहेव विद ऐनीबाडी।** हम सब के साथ प्रेम करते हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने डा० फारूक अब्दुल्ला के साथ समझौता करने की कोशिश नहीं की ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आप कर रहे हैं। आप उनके साथ सौदेबाजी भी कर रहे हैं। हमने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की। आज उन्होंने यह फैसला कर लिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जहां भी उनको शक है यहां के लोगों ने नेशनल कानफरेंस को वोट नहीं दिये उनको फेयर प्राइस शोप्स से राशन, चीनी और किरोसिन तेल नहीं देते हैं। आज वहां की सरकार आइसोलेटेड सरकार है और मुख्य मंत्री जहां कहीं जाता है लोग उसको ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं तो उस जगह के लोगों के घरों में जा कर उनकी औरतों को, उनके बूढ़ों और बच्चों को पीटा जाता है।

क्रिकेट टैस्ट मैच में जो कुछ हुआ वह इनकी शह पर हुआ। इनके पास काफी मसलमैन हैं। एक तरफ तो 70, 80 हजार किसानों ने जब प्रोटेस्ट डे मनाया और अपना चार्टर आफ डिमान्ड लेकर सरकार के पास जाना था उनको तो वहां की सरकार ने मार पीट करवा कर भगा दिया लेकिन मैच में जो कुछ हुआ उसको चीफ मिनिस्टर साहब मजे से देखते रहे। मुझे शक है कि जो वहां एंटी इण्डिया डेमान्सट्रेशन हुआ वह चीफ मिनिस्टर ने खुद करवाया और यह वहां मैच में मौजूद भी थे।

MR. DEPUTY SPEAKER : Some more Members from your Party also want to speak. They are requesting me. So, I am requesting you to conclude now.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Are you giving your name also to him ? He is ready to finish very quickly now.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor) : What is being discussed now ?

MR. DEPUTY SPEAKER : The discussion is :

"Further Discussion on the statement made by the Minister of Home Affairs in the House on 2nd December, 1983 regarding the situation arising out of reported training camps for training of extremists of Punjab in its neighbouring areas."

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : But that is not being discussed now. Kashmir and Pakistan are being discussed. (*Interruptions.*)

श्री गिरधारी लाल डोगरा : कठुआ में सिख एक्सट्रीमिस्ट्स ने हाल ही में कैम्प किया और उसके बाद डा० फारूख साहब भिंडरावाला से जा कर भी खुद मिले और डा० फारूक ने यह एलान किया था कि मैं पेट्रो डालर लाऊंगा ।

मुझसे यू० एस० ए० का एक डिप्लोमेट हाल ही में मिलने आया था मैंने उससे पूछा कि जब यह एम० पी० थे तो स्टेट्स का ट्रिप किसने आर्गेनाइज किया था ? उसने माना कि जब यह एम० पी० थे इनका ट्रिप हमने आर्गेनाइज किया था । फिर मैंने पूछा कि इलेक्शन के पहले जब लड़के और लड़कियों को जहाज में ले गये थे अमरीका तो उसका खर्चा किसने दिया ? तो उसने कहा आई एम क्लियर अबाउट इट ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Why is he saying to much ?

SHRI G.L. DOGRA : I am saying it because it is a fact. Why does it irritate you ? It is a question of our life and death.

चिंगस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर ने बीफ टैलो पर हिन्दू ऐजीटेट कर रहे हैं, हो सकता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मुसलमानों को भी सूअर की चर्बी खिलायी हो वनस्पति में मिला कर और आप लोग बोलते नहीं हैं, ही क्यों नहीं आप लोग बगावत करते । इस तरह से लोगों को भड़काते हैं । मेरी गुजारिश है कि केन्द्र सरकार को इस तरह की बातों की इत्तला समय पर पहुंचनी चाहिये ।

इसी तरह से सर्विसेज में जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर ईमानदारी से काम करते हैं उनको एक किनारे लगा दिया गया है । आपने अखबार में पढ़ा होगा अभी पुराना ट्रैजर वहां मिला जो कि रायल ट्रैजर है । चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि इस ट्रैजर को उड़ीसा की एक फर्म को सुपुर्द कर दो जो 3 घंटे में उनके सुपुर्द कर दें और देखकर इस को वेलुएट करे । लेकिन वहां की फाइनेंस सेक्रेटरी ने जिसका नाम सुषमा चौधरी था और उसने कहा कि उड़ीसा की फर्म को पजेशन न दो बल्कि एक कमेटी बनाकर अपने सामने इवेलुएट कराया जाय । इसी तरह से जो अनकट मैफ्यिर था उसको भी उड़ीसा की फर्म को सुपुर्द करने को कहा । लेकिन जे० ऐंड० के० मिनरल कोरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पजेशन देने से इन्कार किया और उसने भी इसके लिये एक कमेटी बना दी । यह बात इन को पसन्द नहीं आयी और रात को आर्डर देकर इन दोनों अफसरों को अपनी पोस्टों से हटाकर बेकार जगहों पर बैठा दिया । भारत सरकार ने इन सब बातों के बारे में क्या सोचा है । मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां हालात बहुत ही बुरे हैं । काश्मीर केमुस्लिम सैक्युलर लोग हैं । उन की वजह से ही 1947, 1965 और 1971 के पाकिस्तानी हमलों में हम लोग बचे । वहां पाकिस्तानी ख्यालात के कुछ लोग और जरूर हैं, मगर बहुत कम हैं, लगातार इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि वे काम्यूनल हो जायें, वहां फसाद हो जाये और लोग एन्टी इण्डिया हो जाए । साम्राज्य सेक्युलरिज्य को खत्म करना चाहता है । वह भारत और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा चाहता है । भुट्टो जब हम से लड़ता था तो बहुत बहादुर था मगर जब उसने हमसे सुलह कर ली तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है । यह इम्पीरीयलिस्टीक इंट्रीग है । वहां की स्थिति से यदि कोई अन्धा भी है बहरा भी है, तो समझ जाएगा कि किस प्रकार की कोशिश वहां की जा रही है । खतरनाक हथियारों के ढेर हमारे इर्द गिर्द लगा दिये हैं ।

training extre. *neighpouring arers*

वे लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को मारना चाहते हैं, कांग्रेस के अन्दर प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते हैं।

These people, whether left or right, are all falling in line with the imperialistic forces. They are playing in their hands. They just want to oppose the Congress-I for opposition sake. Let us forget politics for the time being.

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप आई०बी० की आर्गेनिजेशन को इलेबोरेट कीजिए। इनफार्मेशन समय पर आनी चाहिए। जो काम आप को करना है, वह आपको ही करना है। वहां के बाल-बच्चों की जिन्दगी का सवाल है, जो कि खतरे में है। इस वक्त इम्पीरियलिज्म इज एट इट्स बैस्ट। पंजाब और जम्मू काश्मीर को पहले रोंदेंगे और बाद में सबको रोंदेंगे। बाद में बाकी देश को। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त वहां जो खेल खेला जा रहा है, वह बहुत ही खतरनाक खेल है कि इसलिए सब को चौकन्ना होना चाहिए। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी जो बातें मैंने कही हैं, उनकी तहकीकात करें। यदि कोई बात गलत नजर आती है तो बात कर सकते हैं। इस तरह हम ठीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इम्पीरियलिज्म किस का—रशिया या अमरीका का ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : अमेरिकन इम्पीरियलिज्म।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम माननीय गृह मंत्री जी के दो ब्यानों और कुछ और लोगों के ब्यानों पर चर्चा कर रहे हैं।

यह चर्चा चुरू के गुरुद्वारे में आग लगने के बारे में जो कुछ अखबारों में छपा वहां से शुरू हुई। चुरू के गुरुद्वारे में जो आग लगी, मैं उसकी निन्दा करता हूं, लेकिन उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इस बारे में मुझे कुछ फैक्ट्स मिले हैं। अभी वह गुरुद्वारा बना नहीं है। उसमें निशान साहब नहीं लगे, गुरुग्रन्थ साहब भी नहीं रखे गए हैं वह अभी भी अण्डर कन्स्ट्रक्शन है। वहां केवल 13 सिख परिवार हैं। उन में से एक भी सिख परिवार वहां का परमानेन्ट रेजिडेन्ट नहीं है। सारे के सारे सरकारी मुलाजिम हैं, 7 पुलिस में है और शायद एक-एक या दो-दो गवर्नमेंन्ट महकमों में मुलाजिम हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन के लिये हिन्दुओं ने भी चन्दा दिया था। अगर कोई आब्जैक्शन हुआ था तो एक श्री जोहरअली एडवोकेट थे उन्होंने ऐतराज किया था कि यह यहां पर नहीं बनना चाहिये।

मैं इसकी असल हैपनिंग पर आता हूं—ता० 26 को वहां आग लगती है, दरवाजे का थोड़ा हिस्सा जलता है और ता० 2 को आदरणीय बूटा सिंह जी ने कहा था कि उस अखबार की एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही करो। एक विनोद पाठक नाम का कारम्पोण्डेंट है जो अपने आप को एक अखबार का नुमाइन्दा बतलाता है। वह ता० 27 को यह रिपोर्ट भेजता है कि आग तो वहां लगी ही है लेकिन साथ ही कुछ सिख परिवारों को धमकी आमेज खत भी मिले हैं। वह ता० 27 को हैंड-राइटिंग में रिपोर्ट भेज रहा है और वे खत ता० 30 को उन सिखों को डिलीवर होते हैं। यानी जिन सिख परिवारों का जिक्र वह अपनी रिपोर्ट में ता० 27 को अपनी हैंड – राइटिंग में करता है उन को वे खत 4 दिन बाद मिलते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि उस को कैसे मालूम हो गया कि सिख परिवारों को धमकी-आमेज खत मिले हैं ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस हैण्ड-राइटिंग में वे खत भेजे गये हैं उसी हैण्ड राइटिंग में वह रिपोर्ट है जो प्रेस को भेजी गई थी। मैं यह निवेदन चाहता हूं - उस विनोद पाठक के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि चार दिन पहले उस को कैसे एडवांस इन्टीमेशन मिल गयी, जिस से उसने जानबूझ कर भड़काने वाली रिपोर्ट दी। उसका ताल्लुक किस पोलिटीकल पार्टी से है – अगर मैं बतलाऊंगा तो ये लोग चिल्लाने लगेंगे। लेकिन इतना जरूर

बतलाऊंगा कि विनोद पाठक के पिता श्री गंगाधर पाठक राजस्थान गवर्नमेंट के एडवोकेट-जनरल हैं, बहुत इन्फलुएन्शियल (प्रभावी) आदमी हैं। इस लिये आप विनोद पाठक के बारे में एन्कवायरी करायें कि इतनी शरारत–आमेज़ खबर उसने कैसे भेजी ? उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिये।

दो स्टेटमेन्ट्स माननीय गृह मन्त्री जी ने दिये हैं - एक कैम्पों के बारे में और दूसरा जो ता० 2 को चर्चा हुई और जिसमें आदरणीय स्पीकर साहब ने गम्भीरता से कुछ बातें कहीं थीं, उनके तैहत दिया गया। दरअसल हम यह सोच रहे थे और कुछ लोग ऐसी चर्चा भी कर रहे थे कि होम मिनिस्टर ने जो वायदा किया है कि सोमवार को स्टेटमेंट देंगे, शायद इन-बिटवीन कुछ एक्शन लेकर हाउस को बतलायेंगे कि हम ने फलां एक्शन ले लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैम्प्स के बारे में आप ने कहा है कि 14 कैम्प्स हुए थे, जिनमें 6 जम्मू-काश्मीर में, 2 हिमाचल में, लेकिन बाकी 6 के लिये आप ने कुछ नहीं बतलाया। मेरी जानकारी है कि ये पंजाब में हुए थे। आप इस बात को कन्फ़र्म कीजिये या डिनाई कीजिये और बतलाइये कि कहां-कहां क्या-क्या होता रहा है।

दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कहते हैं—

> "The Government will take all necessary steps to deal with crime and instigation of crime wherever and by whomever it may be committed."

इस से ज्यादा बुजदिलपने का और डरपोकपने का बयान नहीं हो सकता है, जो आज तक सरकार दिखाती रही है। आप ने अभी तक क्या एक्शन लिया, वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं, बल्कि आप को याद दिलाना चाहता हूं—एक बार अकाली दल ने कहा कि हम रेल-रोको आन्दोलन करेंगे, सरकार ने क्या एक्शन लिया- रेलों का चलना बन्द कर दिया। दूसरा- जब कोई कत्ल होता है, डाका पड़ता है या किसी आर्थिक स्थान की बेहुरमती होती है तो आप की तरफ़ से जवाब आता है कि सबको चौकन्ना कर दिया गया है। उससे पहले क्या सो रहे थे ? तीसरी बात जो पंजाब के गवर्नर ने कही है - उन्होंने अकाल तख्त केहैड-प्रीस्ट से अपील की है कि वह हुकमनामा जारी करें कि कत्ल नहीं होने चाहिये। मि० तोहरा जो एस० जी० पी० सी० के प्रेजिडेंट हैं उन्होंने जो स्टैण्ड लिया है या जो विरोध किया है, वह दूसरे कारण से किया है लेकिन मैं इस का विरोध किसी दूसरे कारण से करता हूं—क्या सरकार बिल्कुल नपुंसक हो गई है जो इस प्रकार का हुकमनामा अकाल-तख्त से जारी करवाना चाहती है ? कि वह हुक्म जारी करें। आपकी पुलिस और आप की हुकूमत किस लिए है ? अगर आप वहां से हुक्म जारी करवाना चाहते हैं कि बेगुनाह लोगों को मारना बंद कर दिया जाए तो आप लोग किसलिए बैठे हैं ? क्या आप का यही एक्शन है ? आप आगे और क्या एक्शन लेना चाहेंगे, यह हमें बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन चीजें गुरुनानक निवास के बारे में, मैं कहना चाहता हूं। चन्द दिनों पहले आदरणीय आर० एल० भाटिया, माननीय सदस्य ने अपनी बात कहते हुए यह कहा था कि मिस्टर सन्धु दरबारा साहब में आते हैं, ट्रिब्युन अखबार के लिए अपना इन्टरव्यू देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं उनका इन्टरव्यू अखबार में छपता भी है। मैंने उनसे पूछा कि आप की इन्टेलिजेंस और आपकी पुलिस के आदमी क्या कर रहे हैं ? सन्धु आता है और चला जाता है। चारों तरफ आपकी पुलिस बैठी है, वह क्या कर रही है ? आपको भी तो कुछ करना चाहिए।

वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में आपने बयान दिया है कि वहां विदेशों से हथियार आये हैं। किस विदेश से हथियार आये हैं, उसका आप नाम लेते ही नहीं हैं। क्यों नहीं लेते है ? क्या पाकिस्तान से आये हैं, अमेरिका से आये हैं या रूस से आये हैं ? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे हथियार वहां कैसे आते

हैं ? क्या वहां हैलिपेड बना हुआ है जिस पर कि हेलिकोप्टर से आते हैं ? वहां हथियार आते होंगे तो किस वाहन के जरिये से ही आते होंगे। वहां बाहर आपकी पुलिस खड़ी है। क्या उसको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती ? वह उनके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेती है ?

अभी डा० सुब्रह्मणयम स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर यह कहा जाय कि वहां भी कोई स्वामी और सन्त ही गड़बड़ी कर रहे हैं, मेरा मतलब इन स्वामी जी से नहीं है, ब्रह्मचारी जी से है भिण्डरावाला से है जिनको कि स्वमी या सन्त नहीं कहना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। भिण्डरावाले बयान देते हैं जो कि छपा भी है। अखबार वालों से उन्होंने कहा की मैं तो खालिस्तान का प्रचार नहीं करता लेकिन अगर खालिस्तान बन जाए तो बहुत अच्छा है। यह बात अखबारों में छपी है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि रणजीत सिंह अगर बरी हो कर बाहर आ जायेगा तो मैं उसको सोने से तोलूंगा। ऐसी चीज भी उन्होंने कही है। अकाली दल और एस० जी० पी० सी० मांग करते हैं और ऐलान भी करते हैं कि रणजीत सिंह को डिफेंड किया जाए, उसके परिवार का पालन पोषण किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि अकाली दल और भिण्डरावालां का रणजीत सिंह के साथ क्या ताल्लुक है। कोई कातिल जो कि गिरफ्तार हो गया है, उसके बारे में कोई पब्लिक का आदमी यह कहे कि मैं उसको सोने से तोलूंगा तो क्या पुलिस उसको बख्शेगी ? क्या इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ भी नहीं है ? इसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

एक बार अमृतसर के पास एक सिख कत्ल हो गया। कत्ल करने वाला सिख, इंक्वारी करने वाला सिख। भिंडरावाले की मेटाडोर उसमें थी जिसको कि इंक्वायरी के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी भिंडरावाला घोंस दिखाने के लिए बयान देता है कि अगर शाम को पांच बजे तक उसकी बस छोड़ी गयी तो वह पांच हजार हिन्दुओं का कत्ल कर देगा। इसमें हिन्दू बीच में कहां से आ गये ? राजस्थान के चुरू में ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं जितना कि खामखाह बात को उछाला गया है। उसके बाद भी वह कहते हैं कि मैं पंजाब से किसी को निकलने नहीं दूंगा, सभी हिन्दुओं को कत्ल कर दूंगा। उसके पहले ब्यान के बाद सैर करने वाले बसों में सफर करने वाले हिन्दु कत्ल किये गये। इससे क्या आप इंकार कर सकते हैं ? आज तक उनके ब्यान के बाद क्या कार्यवाही की गई ? क्या आप ने इसके लिए इंतजाम किया कि इस किस्म की चीजों की वहां बढ़ौतरी न हो ?

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि वहां अभी कितना खून और बहाना बाकी है, कितनी बहिनों का सुहाग उड़ाना बाकी है ? आप पंजाब को खून की नदियों से कब तक निजात दिलाना चाहते हैं या नहीं चाहते है ? क्या यह तब तक होता रहेगा जब तक की पंजाब में अकाली दल के साथ आपकी हुकूमत नहीं बन जाती ?

क्या यही मकसद है। अगर यह मकसद नहीं है तो साफ कह दीजिए। आखिर यह सब क्या हो रहा है। अन्त में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

19.40 hrs.

[SHRI SUNIL MAITRA *in the Chair*]

आपका नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट बना हुआ है। उसकी क्लाज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। क्लाज 3 (1) में लिखा है—

"The Central Government or, the State Government, may, after satisfying with respect to any person with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the security of the State or, from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, make an order, directing that such person be detained."

जो कुछ भिंडरावाला ने कहा है क्या यह क्लाज उस पर लागू नहीं होती। अगर होती है तो इस नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट में उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। विद्यार्थी कुछ बात कहते हैं, उनको आप नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर लेते हैं। मजदूर अपनी मांग करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। बेकार नौजवान अपनी बात कहता है तो आप उसको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं। भिंडरावाला पर यह एक्ट लागू नहीं होता, उसका क्या कारण है ? अगर कोई डर है तो इसी डर, भय के कारण आज पंजाब आग का शिकार बना हुआ है। यह कब तक जलता रहेगा ? अगर हुकूमत करनी है तो ढंग से कीजिए। लोगों की जान-माल बरबाद मत कीजिए।

दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के गवर्नर ने एक बयान दिया कि पंजाब के हालात में कोई विदेशी हाथ नहीं है। एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि है। अब यह कंट्राडिक्शन है। अगर पंजाब के गवर्नर की बात वाकयी गलत है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

मैं पंजाब के गवर्नर की एक और बात आपके सामने लाना चाहता हूं। एस० जी० पी० सी० का चुनाव हुआ। उसमें श्री गुरचरण सिंह टोहरा प्रधान चुने जाते हैं और हमारे पाण्डे जी उनको मुबारकबाद का तार देते हैं। क्या जरूरत थी। और अगर यह प्रथा डालनी है तो अखिल भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का चुनाव होगा और पंजाब का आदमी इलेक्ट होगा तो क्या मिस्टर पाण्डे उसको भी टेलीग्राम देंगे और धार्मिक संस्थाओं के चुनाव पर भी टेलीग्राम देंगे ? क्या यह प्रथा गलत नहीं है। क्या यह गलत किस्म की चापलूसी नहीं है ?

अभी 4 दिन पहले का वाकया है। गोल्डन टैंपल की एक रेलवे की एजेंसी है। बाहर कुछ दूकानें बनी हुई हैं। उनमें एक दूकान है वहां पर बुकिंग होती है। कुछ तलवारें चार बोरों में बुक करके जगाधरी भेजे गए। कब से यह हो रहा था पता नहीं। यह तो अचानक एक बोरा फट गया और तलवारें नजर आ गईं। बोरा पकड़ लिया गया। जिस आदमी के नाम था, उसको गिरफ्तार किया गया। तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।

19.43 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

और गिरफ्तार करते ही छोड़ दिए गए। कोई पूछताछ, कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं किया गया। पूछताछ इसलिए नहीं हुई कि जगाधरी के डी० एस० पी० और एस० एच० ओ० को एक वी० वी० आई० पी०, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके आर्डर पर ट्रांस्फर कर दिया गया। नए डी० एस० पी० और एस० एच० ओ० फिर कैसे कार्यवाही करते। उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाती, ट्रांस्फर हो जाता। बोरे कहां से आए, क्या इससे पहले भी इस तरह की बुकिंग हुई है। क्या उनके ऊपर लिखा हुआ था "आर्नामेंटल फ्रेट्स" और कितने बोरे इस तरह के लाए गए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आखिर इस मामले का हल होना चाहिए। अब जहां तक पानी का ताल्लुक है वह तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। चण्डीगढ़ और फाजिल्का अबोहर का आपने फैसला किया। या तो आप कहिए कि आपका अवार्ड ठीक है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अगर गलत है तो उसको रिवाइज कीजिए। कुछ तो कहिए। इसको कब तक लटका कर रखेंगे ? इसको लटकाने के कारण मुल्क को नुक्सान पहुंचा है, मुल्क आग की लपटों में फंसता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अकाली दल से बात कर लीजिए, विरोधी दलों से भी बात कर लीजिए, निरंकारियों से भी बात कर लीजिए। ख्वाहमख्वा सैकड़ों बेगुनाओं का खून बहाया जा रहा है। इस चीज का जिस संजीदगी से आदरणीय अध्यक्ष जी ने दो तारीख को कहा था, मेहरबानी

करके उसी संजीदगी से इस मामले को लेते हुए इसमें कुछ कार्यवाही कीजिए ताकि मुल्क को कुछ राहत मिले । मुझे इतना ही कहना है ।

SHRI P.K. KODIYAN : Mr. Deputy Speaker, Sir, I do not know what purpose will be served by this discussion here because the Punjab issue has been discussed here on more than one occasion. Government has failed to respect the sentiments expressed in this House and Government has not come forward to find a satisfactory solution to the Punjab issue.

Now, Sir, the existence of the extremists' training camps in Punjab and its neighbourhood is only an offshoot of the main problem, that is, the problem arising out of the Akali agitation in Punjab. I do not want to repeat what other hon. Members have already stated. I want to point out that unless a political solution is found out for the Punjab issue the situation in Punjab may go out of control and it will produce very serious repercussions in other parts of the country.

Sir, already the situation in Punjab is very serious. A problem which requires a political solution cannot be solved through administrative measures, by imposition of President's rule and by deployment CRP and BSF.

Sir, at the time of imposition of President's rule the claim was made that it was necessitated by the serious situation in Punjab. So, in order to tackle the situation effectively such an action was warranted. But after the inposition of President's rule we have seen that the law and order situation instead of improving in Punjab has worsened. Series of violent incidents that have taken place in recent weeks in Punjab show that the President's rule has failed to control the law and order situation.

Now, after having this very unhappy experience the question is raised on other issues the solution of which even if we succeed to find out may not result in further improvement of the situation. Now, Sir, we are all against the pronouncement made by Bhindranwalle. Extremely provocative poisonous pronouncements he had been making and strong action should be taken against him. Nobody has any doubt about it. But is it the only solution to the Punjab problem ? Even if people like Mr. Bhindranwale and others are arrested, the Punjab problem will continue to remain and continue to bother all of us and will create problems for the whole country. That is why I would request the hon. Minister to look at this not merely from the point of view of law and order situation, but as a situation which requires political handling, tactful handling and political solution. Therefore, I would request the hon. Minister, not to delay even a moment in convening tripartite meeting to which he himself has committed several times in the meeting of the Consultative Committee of his Ministry. He, had made that statement outside also on several occasions what prevents him from convening a tripartite meeting ? As other hon. Members have already pointed out, the differences have been narrowed down. Only the territorial dispute now remains to be solved. The question of Fazilka Abhor and Chandigarh. This territorial question can be settled by negotiation across the table. Therefore, there is no justification in not convening such a tripartite meeting. The hon. Minister should explain why he is not doing it. If a political solution is found out, then the extremists including Mr. Bhindranwale can be isolated and any action which would help in isolating the ex tremist elements in Punjab will heartily be welcomed by an everwhelming majority of the people of Panjab. At the same time, I sh ould also say here that the Akalis also have a responsibility to find a solution to this difficoult problem. They should unequivocally condemn extremist activities. They should dissociate themselves from the activities of Bhindranwale and other extremists. They should also suspend their agitation in order to create a congenial atmosphere for a negotiated settlement. So, in my opinion, if all the parties are involved in this dispute, we can tackle the Punjab problem. It is a very serious national problem and we can tackle it above narrow sectional party interests. So far as my party is concerned, we are preped to all possible assistance for finding a suitable negotiated settlement on a political basis. The only thing is that the Govelrnment should not delay the matter. The Government should immediately take action. Thank you.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने कहा कि कुल जो 14 कैम्प्स लगे हैं उसमें से 6 जम्मू और काश्मीर में लगे और दो हिमाचल प्रदेश में लगे। लेकिन बाकी का नहीं बताया कि और कहां कहां लगे। इससे पहले एक वक्तव्य और उन्होंने दिया था, उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी एक कैम्प लगा था। तो यह तो गनीमत समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक ही कैम्प लगा क्योंकि वहां तो कोई जितने चाहे उतने कैम्प लगा सकते हैं क्योंकि वहां तो कोई सरकार है ही नहीं। पता नहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई कैम्प लगा है या नहीं। लेकिन जम्मू और काश्मीर का नाम इतना प्रामिनेन्टली क्यों लिया गया ? सबसे ज्यादा शक इसलिए होता है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार को हमारे केन्द्र की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और उस सरकार को किसी तरीके से बरखास्त करना चाहती है। इसलिए उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। लेकिन यह इल्जाम ऐसा लगाया जिससे कि उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इसके साथ तमाम कांग्रेस (आई) की सरकारें भी उस में इन्वाल्व्ड हो जाएंगी इसलिए उस मामले में तो मकसद पूरा नहीं हो पाया।

अब सवाल यह है कि अगर धार्मिक प्रशिक्षण के लिए कोई कैम्प नहीं लगाया जाता है तो उसको रोका जाय या न रोका जाय ? अगर धार्मिक प्रशिक्षण के लिए कैम्प लगाने को रोकने का कोई मकसद या नीति है तो सरकार यह स्पष्ट करे और सारी राज्य सरकारों को लिखे कि ऐसे कैम्प आगे न लगाए जाएं। लेकिन अभी तक जो कैम्प लगते रहे हैं उनको रोका नहीं जाता था। इसके बाद अगर वहां हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया तो इसके बारे में सरकार को पता करना चाहिए और सारे देश के सामने उस बात को लाना चाहिए।

अभी दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य गुलाम रसूल मट्र साहब ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है 16 नवम्बर को जिसका उत्तर उन्हें अभी तक नहीं मिला है। उसमें उन्होंने जानने की कोशिश की है कि जम्मू काश्मीर में कैम्प कहां कहां लगाये गये, सेंट्रल गवर्नमेंट को कब पता चला और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बारे में उनको कब पत्र लिखा ? इसके बारे में गृह मंत्री जी कुछ बता सकें तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काश्मीर में तो बहुत सी बातें इस तरह की होती हैं। जैसे सरकार को एक बात का पता लग गया कि कैम्प वहां लगाए गए उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए। काफी बातों की भी जानकारी इस सरकार को होनी चाहिए। जैसे स्पेन की बनी हुई बन्दूकों के बैरेल वहां पकड़े गए, इस बात की जानकारी सरकार को नहीं हो पायी। दूसरी बात, जिस दिन यह बात अखबारों में छपी थी कि स्पेन की बनी हुई बन्दूकों के बैरल वहां पकड़े गए हैं उसी दिन यह बात भी छपी थी कि कांग्रेस (आई) जो सत्ताधारी दल है यहां पर उसके एक सदस्य रोशेसनिस्ट ऐक्टिविटीज के लिए पकड़े गए हैं, जो अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं उसके सिलसिले में वह पकड़े गए हैं। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर केन्द्र सरकार को एक साथ विचार करना चाहिए और उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। जहां तक स्पेन की बनी हुई बैरेल्स का सम्बन्ध है उससे तो केन्द्र सरकार का सीधा सम्बन्ध है क्योंकि इस प्रकार के बैरल बिना सरकारी लाइसेंस के इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते और इम्पोर्ट का मामला भी केन्द्र सरकार का है। अगर सरकार ने इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया था और स्मगलिंग हुई है तो स्मगलिस को रोकने का भी कार्य केन्द्र सरकार का है, इसलिए केन्द्र सरकार को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसी तरह से जैनुल बशर साहब ने एक बात कही।...(**व्यवधान**)...गृह मंत्री जी ने कहा कि उग्रवादियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें से कुछ राज्यों का नाम उन्होंने बताया, लेकिन सत्ताधारी दल के एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ उग्रवादियों

को प्रशिक्षण पाकिस्तान में दिया जा रहा है। तो कुछ बातों की जानकारी सरकार को है और कुछ बातों की जानकारी सरकारी पार्टी के सदस्यों को है। तो सवाल यह है कि क्या भारत सरकार उन सरकारों से जो कि उग्रवादियों को प्रशिक्षण देते हैं उनसे कोई वार्ता चला रही है? क्या उनसे उसने यह कहा कि हमारे देश में अस्थायित्व पैदा करने की चेष्टा वह न करें? अगर वह ऐसा करेंगे तो हमारे उनके राजनयिक सम्बन्धों पर असर पड़ेगा, और अगर वह नहीं माने तो हम अपने राजनयिक सम्बन्ध भी उनसे खत्म करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान राजनीतिक तरीके से ढूंढना चाहिये। इस प्रकार के जो उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिये जा रहे हैं उनके बारे में सारे सदन ने अपनी राय माननीय गृहमंत्री जी के माध्यम से सरकार को पहुंचा दी है। लेकिन आमतौर से जो समस्या है, उसका समाधान राजनीतिक तौर से ढूंढना चाहिये और उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर): जनाबे सदर, अव्वल बात यह है कि हमारे सामने इस वक्त डिस्कशन का जो मौजूअ है वह यह है कि सेठी साहब ने 2 दिसम्बर को जो इस सदन में बयान दिया था, उस पर हम विचार कर रहे हैं। जब मैं उसको फिर से पढ़ता हूं तो मुझे लग रहा है कि इसमें पंजाब की नेवरिंग स्टेट के बारे में उनसे हमें रोशनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है, एवस्ट्रीमिस्ट्स कहां-कहां अपने आपको मुसल्लाह कर रहे हैं और देश-विरोधी काम में जुट गये हैं, उसका उपाय होना चाहिए। लेकिन सेठी साहब ने जो बयान दिया है, उसका एक ही टारगेट है जो कि रियासत जम्मू-काश्मीर के बारे में है।

जम्मू-काश्मीर की स्टेट के बारे में सेठी साहब ने इस बयान में कहा है कि इस वक्त तक 14 इस किस्म के कैम्प हुए जहां स्टेट, और मुल्क के बारे में, मुल्क की दुश्मनी के मुताल्लिक या आर्म्ड ट्रेनिंग के सिलसिले में काम हुआ है। उसमें से रियासत जम्मू-काश्मीर में 6 कैम्प लगे, 2 हिमाचल में लगे और जो बाकी बचते हैं उनके बारे में कोई इशारा नहीं मिलता है। यह सदन की राय बनी है, अपोजिशन की तरफ से इस एवान को उन्हें बताना पड़ेगा कि यह बाकी के और कैम्पस कहां पर लगे हैं जो कि उन्होंने अपने स्टेटमैंट में कहा है।

उन्होंने बयान में कहा है कि रियासत जम्मू-काश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी एक ऐसे कैम्प में गए और उन्होंने वालेन्टियर्स की हौसला-अफज़ाही की।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी: आप ध्यान से पढ़ें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली: कैम्प में आए हुए लोगों का उन्होंने हौंसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्टेटमैंट से जो इस किस्म की फिज़ा कायम की गई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं यह मानता हूं कि हमारे सिख भाइयों की तरफ से गुरद्वारों में इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ होगा जिसमें कि वह अपने धार्मिक विचार लायें या कोई ऐसी बात की जो रिलीजस फीलिंग को इंजर करे। गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर में बैठकर इस मुल्क के विधान ने रिलीजन की फ्री आजादी दी है, हो सकता है कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करें लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन रियासत जम्मू-काश्मीर में जो कैम्पस हुए, यहां चर्चा हुई इस पार्लियामेंट में कि वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, उनको आर्म्ड किया गया है और उसमें मुलव्वस रियासत सरकार का उनको सहयोग मिला है तो जो इस तरह के एक्सटामिस्ट्स हैं, स्लीमेंट्स हैं, मुझे याद है, सदन को भी याद होगा कि पंजाब में गवर्नर रूल के बारे में जो यहां चर्चा हुई उसमें सेठी साहब ने खुद फरमाया कि आर्म्ड ट्रेनिंग नहीं दी गई। लेकिन 2 दिसम्बर को जो सेठी साहब ने बयान दिया, उसमें वह बात नहीं

बल्कि कंट्राडिक्शन है। मुझे बड़ा दुःख है। जहां आर्म्ड ट्रेनिंग की बात कही है, वहां आज के स्टेटमैंट में आर्म्ड ट्रेनिंग की बात की है। इससे लगता है कि उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है। मुझे इसका बड़ा शौक है। मुझे याद है कि उस दिन के [illegible] इन्डिया और दूसरे पत्रों ने हैडलाइन्ज दीं कि मि० सेठी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है : **नो आर्म्ड ट्रेनिंग वाज इमपार्टिड टु दी एक्सट्रीरिस्ट्स इन जम्मू एण्ड काश्मीरा (व्यवधान)** मैं अखबारात की बात आपके सामने रख रहा हूं। आज यहां पर कांग्रेस (आई) के आनरेबल मेम्बरान की तरफ से जम्मू-काश्मीर के बारे में चर्चा हुई है। आप शिकायत कर सकते हैं कि स्टेट के डेवेलपमेंट प्रोग्राम में कहीं बाधा पड़ गई है, या आप कह सकते हैं कि हमसे और कोई खता हुई। लेकिन जम्मू-काश्मीर के साथ यह नाइन्साफी की बात होगी कि आप स्टेट के लोगों या गवर्नमेंट के बारे में कहें कि वे कम्युनल इन-कैरेक्टर हैं। यह आप कभी नहीं कह सकते।

हमें इस बात का फख्र है कि हमने 1947 के बाद और उससे पहले जब इस मुल्क में पाकिस्तान और टू नेशन्ज का नारा लगा, तो रियासत जम्मू-काश्मीर के लोगों ने अपने आपको हिन्दुस्तान के साथ वाबस्ता किया। नेशनल कान्फ्रेंस ने इसके लिए सेक्रीफाइसिज कीं। मेरे मोहतरिम डोगरा साहब भी उसके मेम्बर थे, और वह जम्मू-काश्मीर स्टेट की पहली केबिनेट के मैम्बर भी थे, जिसके वजीरे-आज़म शेख अब्दुल्ला थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह नेशनल कांफ्रेंस की ट्रेडीशन है, नेशनल कांफ्रेंस एक मूवमेंट है, जो काश्मीरियों ने चलाई। उसे आप अपने तरीकों और स्टेटमेंट्स से न बुझाइए। यह एक विचारधारा है, जिसको पूरे मुल्क में बढ़ाना है, उसको कमजोर नहीं करना है। उस शमा और उस रोशनी को नहीं बुझाना है, जिसे काश्मीर की मुस्लिम मैंजोरिटी ने अपने खून से सींचा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे शेरवानी कौन थे, जो बारहमूला के महाज़ पर पाकिस्तान के रेडर्ज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए, जिनको फांसी लगाई गई ? मुजफ्फराबाद के मास्टर अब्दुल अजीज कौन थे ? वह नेशनल कान्फ्रेंस के स्टाल्वर्ट थे, जो पाकिस्तान के रेडर्ज के हाथों मारे गए। 1947 में सैकड़ों काश्मीरियों ने कुर्बानियां दीं। जब सारा मुल्क कम्युनल फ्रेंजी में जल रहा था, उस वक्त भी रियासत जम्मू-काश्मीर ने सेकुलरिज्म के झंडे को ऊंचा रखा।

अगर आज पंजाब में स्थिति खराब है, तो उसमें काश्मीर का क्या दोष है ? अगर पंजाब की स्थिति को ठीक करना है, तो कीजिए, उसमें हमारा सहयोग आपके साथ है हम आपकी मदद करेंगे। पंजाब जल रहा है, हम उस आग को बुझाना चाहते हैं। रूलिंग पार्टी यकीन करे कि हम आपोजीशन की तरफ से आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में डा० फारूक अब्दुल्ला ने भी कोशिश की। वह कई बार दिल्ली भी आए और अमृतसर भी गए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई देश-विरोधी कार्य नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। वह इस मुल्क के बाशिन्दे ही नहीं, जम्मू-काश्मीर के लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर भी हैं। वह खुद उन लोगों पर मुसल्लत नहीं हुए हैं।

मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि काश्मीर में एक नई जाग्रति आई है। जब 1975 में प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने मरहूम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ एक पैक्ट—काश्मीर समझौता, काश्मीर एकार्ड—किया, तो उस वक्त के वजीरे आला, सैयद मीर कासिम, को इन्दिरा जी के कहने पर कुर्सी छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी ? हमारी स्टेट में एक्स्ट्रीमिस्ट फोर्सिज और कम्युनल फोर्सिज पूरे देश के लिए खतरा थीं और वहाँ पर शेख अब्दुल्ला और उनकी जमात ही सेकुलरिज्म को बचा सकती थी, उस स्टेट को इस देश का पक्का हिस्सा बना सकती थी। इस बिना पर प्राइम मिनिस्टर को भी जरूरत पड़ी। इसलिए एक प्लान के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत वहां पर नेशनल

कांफ्रेंस की सरकार बनी। बाद में इलेक्शन में नेशनल कांफ्रेंस को कामयाबी मिली। लोगों ने उसको वोट दिया और उसको चुना। जब डोगरा साहब उन लोगों को उनकी सेकुलरिज्म के लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि वे हर इम्तहान में कामयाब होते रहे हैं, तो उनको यह भी सोचना चाहिए कि नेशनल कांफ्रेंस की सरकार उन्हीं लोगों की चुनी हुई सरकार है और उन लोगों को उस पर विश्वास है।

आज इस मुल्क में यह सारी बहस काश्मीर के बारे में चली है। हम आज बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की रूलिंग पार्टी-कांग्रेस और स्टेट की पार्टी-नैशनल कांफरेंस दोनों लोगों की अदालत में खड़ी हैं। और हम तैयार हैं उसके लिये कोई भी इन्वेस्टीगेशन हो। पार्लियामेंट का कोई कमीशन कायम कीजिये हम उसको फेस करने के लिये तैयार हैं। वह आल पार्टी पार्लियामेंटरी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में जाय और देखें कि कहां हमने ऐक्सट्रीमिस्ट्स को सपोर्ट किया है। हम इस डेलीगेशन को रियासत में घूमने की पूरी आजादी देंगे। अगर हमने कोई कसूर किया है तो वह बात यह डेलीगेशन सदन के सामने लाये। लेकिन एक तरफ जब हम हाथ उठा रहे हैं और जब हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने वहां आर्म्स लाना शुरू किया था स्मगल करना शुरू किया, ऐसे लोगों पर जब हम हाथ डालते हैं तो कांग्रेस सरकार क्यों नाराज होती है। शिवा गन फैक्ट्री में 500 विदेशी मारकिंग की बन्दूकें पकड़ी गईं वह कहां से आयीं और कैसे आयीं इसका पता लगाना कोई गलत बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक भी बन्दूक विदेशी कहीं भी पकड़ी जाय वह गलत है। जैसा सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा दो बन्दूक पकड़ी जाने पर तो इतनी बड़ी चर्चा हुई लेकिन 500 स्पेनिश मारकिंग की बन्दूकें जब पकड़ी गईं तो इस सदन ने डिमान्ड की कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसका इन्वेस्टीगेशन करे तो कोई नाजायज बात नहीं है। लेकिन आप उसे सहयोग दे रहे हैं। हमारी सूबे की सरकार कहती है कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जो लाइसेंस मिला है वह एक फ्राड है और हम उसके कैंसिलेशन के लिये कह रहे हैं, हम उस मामले को इन्टरपोल को देना चाहते हैं ताकि जांच हो कि कहाँ से स्मगल करते हैं और देशद्रोही काम करते हैं। यह कोई गलत बात नहीं है। हम किसी भी इम्तहान के लिए तैयार हैं। आप जो भी हम पर इल्जाम दें, हो सकता है कहीं हमसे कमजोरी हुई हो, लेकिन बेबुनियाद इल्जाम न लगाइये, इससे मुल्क को नुकसान है।

जो पंजाब में हुआ उससे हमें दुख होता है। एक गाड़ी के हादसे में पहले 6 हिन्दुओं को गोली से मार दिया गया और फिर दूसरी घटना हुई जिसमें 4 हिन्दुओं को मारा गया हमें इसका बेहद दुख है। हम रो रहे हैं पंजाब के हालात पर, दिल से रोते हैं क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है यह तबाही की तरफ हमें ले जायगा, पूरे देश को इससे खतरा है और इसीलिये कह रहे हैं कि खुदा के लिये आप वहाँ का कोई हल निकालिये। जो आपने डिस्कशन का सिलसिला शुरू किया था वह क्यों टूटा? सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा उनकी एक मांग है चंडीगढ़ की और जो आप डिले कर रहे हैं उससे देश को बड़ा नुकसान होगा।

जब पंजाब के बारे में हम महसूस करते हैं कि वहां पर ज्यादती हो रही है वही मैं बताना चाहता हूं कि इस मुल्क के अन्दर यू० पी० में जो कम्युनल टेंशन हुई 10, 11 और 17, 18 अक्तूबर को जिसमें 21 आदमी मारे गये जिनमें 19 मुसलमान और 2 हिन्दू थे, जो गरीब, बैकवर्ड क्लास के थे और भंगी भी थे उसको कुचलने के लिये आपने क्या किया? कत्लेआम करने वाला जो भी होगा वह मुसलमान, हिन्दू या सिक्ख नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी सरकार इन कातिलों के खिलाफ क्या करने जा रही है। पंजाब में क्या इन्वेस्टीगेशन किया? कितनों को पकड़ा जो बेगुनाहों को मार रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पंजाब में आपने गवर्नर रूल कर दिया फिर भी वहां की हालत अच्छी नहीं है।

فیجاباد جلے میں ٹانڈا میں جو کچھ ہوا وہ نہایت ہی شرمناک واکیا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک ڈاکومینٹ بھیجا ہے جو میں یہاں ہوم منسٹر کو دوں گا جس سے آپکو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے اس ملک کے اندر لوگ دیش-دروہ کا کام کر رہے ہیں اور کمیونل وائرس پھیلا رہے ہیں۔ 1947 میں تو نقصان ہوا ہے، آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آپکو سختی سے پیش آنا چاہیئے۔

اسی طرح سے جو پنجاب میں ہوا ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے آج چورو کے واقعات کی وجہ سے یہ چنگاری پڑی ہے۔ کل ایک مندر میں نقصان پہنچایا گیا، اسکی بےعزتی کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں سرکار سے دو باتیں کہہ کر اپنی بات سماپت کروں گا۔ میں مانگ کرتا ہوں کہ پارلیامینٹری ڈیلیگیشن جموں اور کاشمیر جاکر انویسٹیگیٹ کریں۔ اسمیں پورے سدن کا، چاہے اپوزیشن ہو یا رولنگ پارٹی کے لوگ ہوں، رپریزینٹیشن ہونا چاہیئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اسکو نیشنل ایشو سمجھیئے، اسکو پارٹی ایشو مت بنایئے۔ اسمیں سب لوگوں کا سہیوگ تلاش کیجیئے۔

اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

شری عبدالرشید کابلی (شری نگر):

جناب صدر! اوّل بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب نے ۲ دسمبر کو جو اس سدن میں بیان دیا تھا اس پر ہم وچار کر رہے ہیں۔ جب میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پنجاب کو نیرنگ اسٹیٹ کے بارے میں ان سے ہمیں روشنی چاہیئے تھی کہ کیا ہو رہا ہے ایکسٹریمسٹس کہاں کہاں اپنے آپ کو مصلح کر رہے ہیں اور دیش وروھی کام میں جٹ گئے ہیں اس کا پتا ہونا چاہیئے۔ لیکن سیٹھی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا ایک ہی تارگیٹ ہے جو کہ ریاست جموں و کشمیر کے بارے میں ہے۔

جموں کشمیر کی اسٹیٹ کے بارے میں سیٹھی صاحب اس بیان میں کہا ہے کہ اس وقت تک ۱۴ اس قسم کے کیمپ ہوئے جہاں اسٹیٹ اور ملک کے بارے میں ملک کے دشمن کے متعلق یا پاک آرمس ٹریننگ کے سلسلے میں کام ہوا ہے۔ اس میں سے ریاست جموں کاشمیر میں ۶ کیمپ لگے ۲ ہماچل میں لگتے اور جو باقی چار بچتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ یہ سدن کی رائے بنی ہے اپوزیشن کی طرف سے اس ایوان کو نہیں بتانا پڑے گا کہ یہ باقی کے اور کیمپس کہاں پر لگتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمینٹ میں کہا ہے۔

انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاست جموں کاشمیر کے چیف منسٹر بھی ایک ایسے کیمپ میں گئے اور انہوں نے والنٹیرس کی حوصلہ افزائی کی۔

شری پرکاش چندر سیٹھی:
آپ دھیان سے پڑھیں۔

شری عبدالرشید کابلی:

کیمپ میں آئے ہوئے لوگوں کا انہوں نے حوصلہ بڑھایا۔ ہمت بڑھائی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ سے جو اس قسم کی فضا قائم کی گئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے سکھ بھائیوں کی طرف سے گردواروں میں اس طرح کا کوئی سمتیلن ہوا ہوگا جس میں کہ وہ اپنے دھارمک وچار لائے یا کوئی ایسی بات کی جو ریلجن فیلنگ کو انجر کرے۔ گردوارے ہندو مسجد میں بیٹھ کر اس ملک کے ودھان نے ریلجن کی فری آزادی دی ہے۔ ہوسکتا ہے کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کریں لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیئے۔ لیکن ریاست جموں کاشمیر میں جو کیمپس ہوئے یہاں چرچا ہوئی اس پارلیمنٹ میں کہ وہاں پر ٹریننگ دی گئی ہے۔ ان کو آرمڈ کیا گیا ہے اور اس میں ملوث ریاست سرکار کا ان کو سہیوگ ملا ہے تو جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹس ہیں۔ ایلیمنٹس ہیں۔ مجھے یاد ہے سدن کو بھی یاد ہوگا کہ پنجاب میں گورنروں کے بارے میں جو یہاں چرچا ہوئی اس میں سیٹھی صاحب نے خود فرمایا کہ آرمڈ ٹریننگ نہیں دی گئی۔ لیکن ۲ دسمبر کو جو سیٹھی

صاحب نے بیان دیا اس میں وہ بات نہیں بلکہ کنٹراڈکشن ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے۔ جہاں آرمڈ ٹریننگ کی بات کہی ہے وہاں آج کے اسٹیٹمنٹ میں آرمڈ ٹریننگ کی بات کی ہے۔

اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹینڈ بدل دیا ہے۔ مجھے اس کا بڑا شوق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن کے ٹائمز آف انڈیا اور دوسرے پیپروں نے یہ ہیڈ لائنز دیں کہ مسٹر سیتھی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے:

نو آرمڈ ٹریننگ واز امپارٹڈ ٹو دی ایکسٹریمسٹس ان جموں اینڈ کشمیر۔ (انٹرپیشنز)

میں اخبارات کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج یہاں پر کانگریس (آئی) کے آنریبل ممبران کی طرف سے جموں کشمیر کے ساتھ یہ ناانصافی کی بات ہوگئی کہ آپ اسٹیٹ کے لوگوں یا گورنمینٹ کے بارے میں کہیں کہ وہ کمیونل ان کریکٹر ہیں یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔

ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے ۱۹۷۴ء کے بعد اور اس سے پہلے جب اس ملک میں پاکستان اور ٹوٹپشنس کا نعرہ لگا۔ تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ وابستہ کیا۔ نیشنل کانفرنس نے اس کے لئے سیکری فائسز کیں میرے محترم ڈوگرا صاحب بھی اس کے ممبر تھے اور وہ جموں کشمیر کی پہلی کیبنٹ کے ممبر بھی تھے جس کے وزیر اعظم شیخ عبداللہ تھے۔

میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل کانفرنس کی ٹریڈیشن ہے۔ نیشنل کانفرنس ایک موومینٹ ہے جو کشمیریوں نے چلائی۔ اسے آپ اپنے طریقوں اور اسٹیٹمنٹ سے نہ بھائیے۔ یہ ایک دھارا ہے جس کو پورے ملک میں بڑھانا ہے۔ اس کو کمزور نہیں کرنا ہے۔ اس شمع اور اس روشنی کو نہیں بجھانا ہے جس کو کشمیر کی مسلم میجورٹی نے اپنے خون سے سینچا ہے۔

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شیروانی کون تھے جو بارہ مولا کے محاذ پر پاکستان کے ریڈرز کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے جن کو پھانسی لگائی گئی۔ مظفر آباد کے ماسٹر عبدالعزیز کون تھے؟ وہ نیشنل کانفرنس کے اسٹالورٹ تھے جو پاکستان کے ریڈرس کے ہاتھوں مارے گئے۔ ۱۹۷۴ء میں سیکڑوں کشمیریوں نے قربانیاں دیں۔ جب سارا ملک کمیونل فرینزی میں جل رہا تھا اس وقت بھی ریاست جموں کشمیر میں سیکولرزم جھنڈے کو اونچا رکھا۔

اگر آج پنجاب میں استھتی خراب ہے تو اس میں کشمیر کا کیا دوش ہے۔ اگر پنجاب میں استھتی کو ٹھیک کرنا ہے تو کیجئے۔ اس میں ہمارا سہیوگ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پنجاب جل رہا ہے ہم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ رولنگ پارٹی یقین کرے کہ ہم اپوزیشن کی طرف سے آپ کو پورا سہیوگ دے رہے ہیں۔

اس بیک گراؤنڈ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی کوشش کی۔ وہ کئی بار دلی بھی آئے اور امرت سر بھی گئے۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کوئی دیش ورودھی کاریہ نہیں کیا۔ کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ اس ملک کے باشندے ہی نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے چنے ہوئے چیف منسٹر بھی ہیں۔ وہ خود ان لوگوں پر مسلط نہیں ہوئے ہیں۔

میں کانگریس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں ایک نئی جاگرتی آئی ہے۔ جب ۱۹۷۵ء میں پرائم منسٹر اندرا گاندھی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ایک پیکٹ کشمیر سمجھوتہ اکارڈ کیا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید میر قاسم کو اندرا کے کہنے پر کرسی چھوڑنی پڑی۔ کیوں چھوڑنی پڑی۔ ہماری اسٹیٹ میں کیا انکسٹریمیٹ کورسز اور کمیونل کورسز پورے دیش کے لئے خطرہ تھیں اور وہاں پر شیخ عبداللہ اور ان کے جماعت ہی سیکولرزم کو بچا سکتی تھی۔ اس اسٹیٹ کو اس دیش کا پکا حصہ بنا سکتی تھی۔ اس بنا پر پرائم منسٹر کو بھی ضرورت پڑی اس لئے ایک پلان کے تحت اس انڈر اسٹینڈنگ کے تحت وہاں پر نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی۔ بعد میں الیکشن میں نیشنل کانفرنس کو کامیابی ملی۔ لوگوں نے ووٹ دیا اور اس کو چنا۔ جب ڈوگرا صاحب ان لوگوں کو ان کی سیکولرزم کے لئے شردھانجلی پیش کرتے ہیں انہیں بدھائی دیتے ہیں کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار انہیں لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے اور ان لوگوں کو اس پر وشواس ہے۔

آج اس ملک میں یہ ساری بحث کشمیر کے بارے میں چلی ہے۔ ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی رولنگ پارٹی کانگریس اور اسٹیٹ کی پارٹی نیشنل کانفرنس دونوں لوگوں کی عدالت میں کھڑی ہے۔ اور ہم تیار ہیں اس کے لئے کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو۔

پارلیمنٹ کا کوئی بھی کمیشن قائم کیجئے ہم ان کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں۔ وہ آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جموں کشمیر میں جائیں اور دیکھیں کہ کہاں ہم نے ایکسٹریمسٹس کو سپورٹ کیا ہے۔ ہم اس ڈیلیگیشن کو ریاست میں گھومنے کی پوری آزادی دیں گے۔ اگر ہم نے کوئی قصور کیا ہے تو وہ بات یہ ڈیلیگیشن سدن کے سامنے آئے۔ لیکن ایک طرف جب ہم ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں اور جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں آرمس لانا شروع کیا یا اسمگل کرنا شروع کیا یا ایسے لوگوں پر جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو کانگریس سرکار کیوں ناراض ہوتی ہے۔ شوا گن فیکٹری میں ۵۰۰ ودیشی مارکنگ کی بندوقیں پکڑی گئیں وہ کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں۔ اس کا پتہ لگانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بھی بندوق ودیش کہیں بھی پکڑی جائے وہ غلط ہے۔ جیسا سبرامنیم سوامی نے کہا دو بندوقیں پکڑی جانے پر تو اتنی بڑی چرچا ہوئی لیکن ۵۰۰ اسپیشل مارکنگ کی بندوقیں جب پکڑی گئیں تو اس سدن نے ڈمانڈ کی کہ سینٹرل گورنمنٹ اس کا انویسٹیگیشن کرے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ لیکن آپ اسے سہیوگ دے رہے ہیں۔ ہماری صوبے کی سرکار کہتی ہے کہ سوامی دھیریندر برہمچاری کو جو لائسنس ملا ہے وہ ایک فراڈ ہے اور ہم اس کے کینسلیشن کے لئے کہہ رہے ہیں۔ ہم اس معاملے کو انٹرنیشنل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ جانچ ہو کہ کہاں سے اسمگل کرتے ہیں اور دیش دروہی کام کرتے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم کسی بھی امتحان کے لئے تیار ہیں۔ آپ جو بھی ہم پر الزام دیں ہو سکتا ہے کہیں ہم سے کمزوری ہوئی ہو لیکن بے بنیاد الزام نہ لگائیے اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔

جو پنجاب میں ہوا اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی کے حادثے میں پہلے ۶ ہندوؤں کو گولی سے مار دیا گیا اور پھر دوسری درگھٹنا ہوئی جس میں ۴۰ ہندوؤں کو مارا گیا ہمیں اس کا بے حد دکھ ہے۔ ہم رو رہے ہیں پنجاب کی حالت پر دل سے روتے ہیں کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تباہی کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ پورے دیش کو اس سے خطرہ ہے اور اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لئے آپ وہاں کا کوئی حل نکالئے۔ جو آپ نے ڈسکشن کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ کیوں ٹوٹا۔ سبرامنیم سوامی نے کہا ان کی ایک مانگ ہے چنڈی گڑھ کی اور جو آپ ڈے کر رہے ہیں۔ اس سے دیش کو ۲ نقصان ہو گیا۔

جب پنجاب کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ وہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یو۔پی۔ میں جو کمیونل ٹینشن ہوئی ۱۱-۱۰۰-۱۱ اور ۱۷-۱۸ اکتوبر کو جس میں ۲۱ آدمی مارے گئے جن میں ۱۹ مسلمان اور دو ہندو تھے۔ جو غریب بیک ورڈ کلاس کے تھے اور بھنگی بھی تھے۔ اس کو کچلنے کے لئے آپ نے کیا کیا۔ قتل عام کرنے والا جو بھی ہوگا وہ مسلمان، ہندو یا سکھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی سرکار ان قاتلوں کے خلاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب میں کیا انویسٹیگیشن کیا۔ کتنوں کو پکڑا جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی ذمے داری نہیں لے رہا ہے۔ پنجاب میں آپ نے گورنر رول کر دیا پھر بھی وہاں کی حالت اچھی نہیں ہے۔

فیض آباد ضلع میں ٹانڈا میں جو کچھ ہوا وہ نہایت ہی شرمناک واقعہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک ڈاکومینٹ بھیجا ہے جو میں یہاں ہوم منسٹر کو دوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے اس ملک کے اندر لوگ دیش دروہ کا کام کر رہے ہیں اور کمیونل وائر پھیلا رہے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں تو نقصان ہوا ہی تھا، آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کو سختی سے پیش آنا چاہئے۔

اس طرح سے جو پنجاب میں ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج چورو کے واقعات کی وجہ سے یہ چنگاری پڑی ہے۔ کل ایک مندر میں نقصان پہنچایا گیا۔ اس کی بے عزتی کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں سرکار سے دو باتیں کہہ کر اپنی بات سماپت کروں گا۔ میں مانگ کرتا ہوں کہ ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جموں اور کاشمیر جا کر انویسٹیگیٹ کرے۔ ان میں پورے سدن کا چاہے اپوزیشن ہو یا رولنگ پارٹی کے لوگ ہوں رپریزنٹیشن ہونا چاہئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا حل ڈھونڈھنا ہوگا۔ اس کو نیشنل اشو سمجھئے۔ اس کو پارٹی اشو مت بنائیے۔ اس میں سب لوگوں کا سہیوگ تلاش کیجئے۔

اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। साथ ही होम मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूं कि अब केन्द्रीय सरकार को कुछ थोड़ा सा रियलाइजेशन आ गया है। जिसके लिए मैं पिछले तीन-चार साल से, गला फाड़-फाड़ कर चीख रहा था, कह रहा हूं कि जम्मू काश्मीर हमारे मुल्क के इन्टरैस्ट में नहीं जा रहा है। जो रिफ्रेसेस आपने स्टेटमेंट में पेश किए हैं, मैं उसका वैपकम करता हूं। यहां पर बहुत सारे नुकते उभारे गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ ट्रेनिंग कैम्पस के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि ट्रेनिंग कैम्पस हुए तो क्या हुआ। उसमें फायर आर्मस ट्रेनिंग नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि लाठियां इस्तेमाल की गईं, कुछ लोगों ने कहा कि तलवारें इस्तेमाल की गईं। मैं पूंछ में जो ट्रेनिंग कैम्प हुए, वहां बन्दूकें चलने से जो शक्स मारा गया, उसके बारे में पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि लाठियों और तलवार का इस्तेमाल जायज है, क्योंकि यह सिक्खों के रिलीजीयस सैन्टीमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां बन्दूक का क्या काम था। जब भी वहां खालिस्तान का नारा दिया जाता था, तो दर्जनों हवाई फायरिंग होती थी। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर बन्दूक का क्या काम था ?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जो नारे बुलन्द किए गए, वे काबिले गौर है। मैं, अक्तूबर 1983 के काश्मीर टाइम्स से कोट करता हूं —

> "It was asserted that the Sikhs did not accept the Indian Constitution and the National Anthem, nor did they recognise Mahatma Gandhi as the Father of the Nation. Hindu religion and some of its practices were subjected to severe criticism during the camp."

यह वाक्या 26 जून, 1983 को रियासी तहसील जम्मू-काश्मीर में हुआ। दूसरा कैम्प जुलाई 8 से 10 तक पुंछ में हुआ था-जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जिसमें बन्दूकें चलीं और एक आदमी मारा गया था। उसके बारे में कहा गया है (काश्मीर टाइम्स-9 अक्तूबर 1983)

> "Sikhs were exhorted not to respect the Indian national flag and the national anthem while Hinduism was condemned for idol worship and other social evils. The role of Sant Bhindrawale in uplifting the Sikh community was eulogised."

तीसरा कैम्प जिस में ऐसे स्लोगन लगाए गए थे-पलवाना में हुआ था जो जुलाई 15 से 21 तक चला और जो बाद में जुलूस की सूरत में शेख फारूख साहब से मिलने गया। उन्होंने सेक्रेटेरियट के सामने फारूख साहब की मौजूदगी में खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए और फारूफ साहब ने भी उन स्लोगन्ज में हिस्सा लिया था।

यहां में "काश्मीर टाइम्स" का फिर कोट करता हूं-यह 9 अक्तूबर का अखबार है-यह भी बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है -डिगाना आश्रम में लोग जमा हुए थे वहां भी इस तरह की बातें कही गई थी। लड़कियों के लिए एक ट्रेनिंग कैम्प आर्गनाइज किया गया था जिस में लड़कियों से कहा गया कि तुम साड़ी मत पहनो, क्योंकि साड़ी हिन्दू पहनते हैं। इस तरह के नारों को वहां एन्कैज करना सिख रिलीजन में नहीं हो सकता है जिससे दो कम्यूनिटीज के बीच में ताल्लुकात खराब हों या उन में आपस में नाराज़गी पैदा करने की कोशिश की जाय।

जहां तक काश्मीर गवर्नमेंट की बात है— मैं जनाब काबुल साहब से पूछना चाहता हूं— क्या यह हकीकत नहीं है कि मौलाना फारूक काश्मीर की जनता से प्लैबिसाइट की बात कर रहे हैं ? क्या यह भी हकीकत नहीं है कि शेख फारूक साहब उस जल्से में मौजूद थे, बल्कि प्लेटफार्म पर मौजूद थे, जिसमें मौलाना फारूक

ने कहा था कि काश्मीर के फ्रीडम स्ट्रगल को जो 1931 में चलाया गला था, उस को आगे ले जाना है और उस को चीफ मिनिस्टर ने एन्डोर्स भी की किया था ? इसके क्या मायने हैं—क्या यह सीसेस्निस्ट टेंडेन्सी नहीं है ?

डोगरा साहब ने कुछ हिस्टोरीकल फैक्ट्स बतलाए हैं-उन्होंने शेख साहब के बारे में 1953 के एण्डर्सन वाली बात का जिक्र किया—यह बिलकुल हकीकत है। यह एक कांनपीरेसी थी। एक मि० डिक्सन होते थे जो यू० एन० ओ० में अमरीकन रिप्रेजेन्टेटिव होते थे—एण्डरसन और उनकी बीबी ने मिल कर एक स्कीम 1953 में बनायी थी और जिसका नतीजा यह निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को एक्शन लेना पड़ा, वरना वहां पर इण्डिपेण्डेन्ट काश्मीर की बात की गई थी। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं - फारूक साहब के दिमाग में भी कहीं वही बात तो नहीं है। सिख एक्सट्रीमिस्ट्स को कहते हैं कि यहां स्टेट में आओ, तुम को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको बाजबता सरकारी तौर पर राशन दिया जाता है। वहां के लोगों को राशन नहीं मिलता है, लेकिन जो ट्रेनीज़ बाहर से आए हैं, जहां पर बन्दूकें चली थीं, वह पुंछ के डी० सी० ने उन को राशन सैंक्शन किया, शुगर सैंक्शन की और जो जरूरियात की चीजें थी वहां गोदाम से सप्लाई की गई।

हम मीर-वाएज़ की बात कर रहे थे—उन्होंने कई बार, बल्कि हमेशा उसी बात को रिपीट करते रहते हैं।

आज भी उनके साथ में है। पिछली दफा इलेक्शन में उनके साथ गठजोड़ हुआ था, अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में गठजोड़ है। जो लोग प्लेबिसाईट की बात करते हैं, सेप्रेट कश्मीर की बात करते हैं, इंडीपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं, जमायते इस्लामी, जमायते तुलबा, महाजे आजादी मौलाना फारूख की राशन कमेटी के ये सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं और आप कहते रहे कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के लोगों ने कश्मीर के लिए लाखों नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। हम लोगों ने चार लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ लड़ी, चीन के साथ लड़ाई लड़ी। इन कुर्बानियों की आप जाया न होने दीजिए। आप लोग पोलिटिकल मफाद के लिए बात करते हो, जब मौका आयेगा तब आप लोग पछताओगे।

आज सुबह श्री चन्द्रजीत यादव ने एक बात भूल से कह दी, बाद में उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकला गया, मेरा मतलब यह नहीं है कि गुरुद्वारे में पुलिस जाये। आप यहां पर तो बहुत कहने की जुर्रत करते हैं लेकिन जब वहां पुलिस भेजने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं आप सरकार से कहते हैं ? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है ? क्या आप यहां के शहरी नहीं हैं। अगर कल को गवर्नमेंट कुछ करेगी तो आप ही लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया है। आप ही लोग सब से पहले यहां बोलने आयेंगे।

कश्मीर एक बहुत ही सेन्सीटिव एरिया है। फारूख साहब यहां कहते हैं कि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल हो चुका है और वे साउदी अरेबिया में जा कर स्टेटमेंट देते हैं कि मसला हल-तलब है और जो भी फैसला करना होगा वह कश्मीर के लोगों को साथ में रख कर करना होगा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बात हम लोगों को मंजूर नहीं है। यह चीज़ क्या मायने रखती है ? यह खतरनाक बात उनके मुंह से बदबू निकलती है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। जैसा कि अभी काबुली साहब ने कहा कि वहां पर एक पार्लियामेंटरी डेलीनेशन जाना चाहिए, मैं उसकी हिमायत करता हूं और कहता हूं कि जाना चाहिए। यही नहीं कि वह जम्मू-कश्मीर में जाए, वह लद्दाख में भी जाए और वहां के कौने-कौने में जाए। वहां जा कर देखे कि माइनोरिटी के साथ क्या हो रहा है। (व्यवधान)

ब्रह्मचारी की बात तो हरेक ने की है लेकिन वहां पर एक दूसरी फर्म खैरुद्दीन संस का नाम भी शामिल है। आप क्यों नहीं उसका नाम लेते हैं? क्या वहां से बन्दूक नहीं पकड़ी गयीं? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आपकी यह पौलिटिक्स है। (व्यवधान) काबुली साहब ने पुरानी हिस्ट्री की बात कही। शहीद शेरवानी का जिक्र किया जो शहीद हुए, हम उन लोगों की कद्र करते हैं। वे उस वक्त के नेशनल कांफ्रेंस के लोग थे जो कि बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह आपकी खिचड़ी नेशनल कांफ्रेंस है जिसका कि न सिर है, और न पैर है। यह उन लोगों वाली नेशनल कांफ्रेंस नहीं थी।

शेख साहब की बात भी कही कि वहां पर कासिम साहब को हटा कर शेख साहब को लाया गया। शेख साहब ने यह कहा था कि 'आई विल रिटर्न टू दा नेशनल मेनस्ट्रीम'। उन्होंने यह रिक्वेस्ट की थी और वे नेशनल स्ट्रीम में वापस आना चाहते थे। क्या आज नेशनल कांफ्रेंस भारत की एकता की बात करती है? ऐसा नहीं कि मुंह में राम-राम और बगल में छुरी, ऐसा नहीं चलेगा। यह समझ लीजिए। बहुत संजीदगी से काम लेना चाहिए। कश्मीर को पोजीशन बहुत एक्सप्लोसिव है। इसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। डोगरा साहब ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मौजूदा काश्मीर को सरकार इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानती, चीफ जस्टिस की बात भी नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानती लोगों की भलाई के लिए जो कानून पास करती है, उनको भी नहीं मानती यह सेपरेटिज्म की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इनको देखने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही मशकूर हूं डिप्टी स्पीकर साहब का कि आपने मुझे वक्त दिया और सेठी साहब का भी मशकूर हूं कि जिन्होंने पहली बार काश्मीर का जिक्र अपने स्टेटमेंट किया।

शरी पी नाम गियाल (लद्दाख):

मानेय डेपुटी स्पीकर साहब! मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिये समय दिया। साथ ही होम मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूं कि अब केन्द्र से सरकार को कुछ थोड़ा सा लाइबरेशन आ गया है। जिस के लिये मैं पिछले तीन चार साल से गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क के इन्टीग्रेटेड में नहीं जा रहा है। जो रिफरेन्सेज आप ने स्टेटमेंट में पेश किये हैं। मैं उन का वेलकम करता हूं। यहां पर बहुत सारे नुक्ते उभारे गये हैं। लेकिन मैं सिर्फ ट्रेनिंग कैम्पस के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि ट्रेनिंग कैम्पस होते तो क्या हुआ। इस में Fire arms ट्रेनिंग नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि लाठियां इस्तेमाल की गईं। कुछ लोगों ने कहा कि तलवारें इस्तेमाल की गईं। मैं पूंछ में जो ट्रेनिंग कैम्प है वहां बन्दूकें चलने से जो शख्स मारा गया इस के बारे में पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि वहां लाठियों और तलवारों का इस्तेमाल जायज है क्योंकि ये सिखों के रेलीजस सेन्टीमेन्ट से तअल्लुक रखते हैं तो वहां बन्दूक का क्या काम था। जब भी वहां खालिस्तान का नारा दिया जाता था तो जो हवाई फायरिंग होती थी। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर बन्दूक का क्या काम था।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो नारे बुलन्द किये गये

वह काबिले गौर हैं। मैं कश्मीर टाइम्स १९ अक्तूबर १९८३ से कोट करता हूं।

> "It was asserted that the Sikhs did not accept the Indian Constitution and the National Anthem, nor did they recognise Mahatma Gandhi as the Father of the Nation. Hindus religion and some of its practices were subjected to severe criticism during the camp."

यह वाकया २६ जून १९८३ को रियासी तहसील जम्मू कश्मीर में हुआ। दूसरा कैम्प जो जुलाई ८ से। अतक पूंछ में हुआ था जिस का मैं ने अभी अभी जिक्र किया था। जिस में बन्दूकें चलीं और एक आदमी मारा गया था। इस के बारे में कहा गया है। (कश्मीर टाइम्स ९ अक्तूबर १९८३

"Sikhs were exherted not to respect the Indian national flag and the national anthem while Hinduism was condemned for idol worship and other special evils. The role of Sant Bhindrawale in uplifting the Sikh community was eulogised."

کا نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایکشن لینا پڑا اور نہ وہاں پر انڈیپینڈینٹ کاشمیر کی بات کی گئی تھی۔ میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ فاروق صاحب میں بھی کہیں وہی بات تو نہیں ہے۔ سکھ ایکسٹریمسٹس کو کہتے ہیں کہ یہاں اسٹیٹ میں آؤ تم کو ٹریننگ دی جائے گی۔ جو لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو باضابطہ سرکاری طور پر راشن دیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو راشن نہیں ملتا ہے لیکن جو ٹرینیز باہر سے آئے ہیں جہاں پر بندوقیں چلی تھیں وہاں پونچھ کے ڈی۔ سی۔ نے ان کو راشن سیکشن کیا شوگر سیکشن کی اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہاں گودام سے سپلائی کی گئی۔

ہم میرواعظ کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار بلکہ ہمیشہ اسی بات کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔

آج بھی وہ ان کے ساتھ میں ہیں۔ پچھلی دفعہ الیکشن میں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا تھا۔ ابھی میونسپل الیکشن میں گٹھ جوڑ ہے۔ جو لوگ پلے بسائٹ کی بات کرتے ہیں سیپریٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں انڈیپینڈینٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ جماعتِ اسلامی، جماعتِ طلبا محاذ آزادی مولانا فاروق کی ایکشن کمیٹی کی یہ سارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیئے کہ ہمارے دیش کے لوگوں نے کشمیر کے لئے لاکھوں نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ ہم لوگوں نے چار لڑائیاں پاکستان کے ساتھ لڑیں۔ چین کے ساتھ لڑائی لڑی۔ ان قربانیوں کو آپ ضائع نہ ہونے دیجئے۔ آپ لوگ پولیٹکل مفاد کے لئے بات کرتے ہو جب موقع آئے گا تب آپ لوگ پچھتاؤ گے۔

آج صبح شری چندر جیت یادو نے ایک بات بھول سے کہہ دی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردوارے میں پولیس جائے۔ آپ یہاں پر تو بہت کہنے کی جرأت کرتے ہیں لیکن جب وہاں پولیس بھیجنے کی بات آتی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ سرکار سے کہتے ہیں۔ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا ہے۔ کیا آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں۔ اگر کل کو گورنمنٹ کچھ کرے گی تو آپ ہی لوگ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے غلط کام کیا ہے۔ آپ ہی لوگ سب سے پہلے یہاں بولنے آئیں گے۔

تیسرا کیمپ جس میں ایسے سلوگن لگائے گئے تھے۔ پلوامہ میں ہوا تھا جو جولائی ۱۵ سے ۲۱ تک چلا اور جو بعد میں جلوس کی صورت میں شیخ فاروق صاحب سے ملنے گیا۔ انہوں نے سکریٹریٹ کے سامنے فاروق صاحب نے بھی ان سلوگنز میں حصہ لیا تھا۔ میں کاشمیر ٹائمز کو پھر کوٹ کرتا ہوں۔ یہ ۹ اکتوبر کا اخبار ہے۔ یہ بھی بہت ڈسٹربنگ رپورٹ ہے۔ ٹگانا آشرم میں لوگ جمع ہوئے تھے وہاں بھی اس طرح کی باتیں کہی گئی تھیں۔ لڑکیوں کے لئے ایک ٹریننگ کیمپ آرگنائز کیا گیا تھا جس میں لڑکیوں سے کہا گیا کہ تم ساڑھی مت پہنو کیونکہ ساڑھی ہندو پہنتے ہیں۔ اس طرح کے نعروں کو وہاں انکریج کرنا سکھ ریلجن میں نہیں ہو سکتا ہے جس سے دو کمیونیٹیز کے بیچ میں تعلقات خراب ہوں یا ان میں آپس میں ناراضگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

جہاں تک کاشمیر گورنمنٹ کی بات ہے۔ میں جناب کابلی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا فاروق کاشمیر کی جنتا سے پلے بسائٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ شیخ فاروق صاحب اس جلسے میں موجود تھے بلکہ اس پلیٹ فارم پر موجود تھے جس میں مولانا فاروق نے کہا تھا کہ کاشمیر کے فریڈم اسٹرگل کو ۱۹۳۱ء میں چلایا گیا تھا اس کو آگے لے جانا ہے اور اس کو چیف منسٹر نے اینڈورس بھی کیا گیا تھا۔ اس کے کیا معنی ہیں۔ کیا یہ سیسیشنسٹ ٹینڈینسی نہیں ہے۔

ڈوگرا صاحب نے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس بتلائے ہیں۔ انہوں نے شیخ صاحب کے بارے میں Anderson والی بات کا ذکر کیا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ ایک کانسپیریسی تھی۔ ایک مسٹر ڈکسن ہونے تھے جو یو۔ این۔ او۔ میں امریکن ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے۔ اینڈرسن اور ان کی بیوی سے مل کر ایک اسکیم ۱۹۵۳ء میں بنائی تھی اور جس

کشمیر ایک بہت ہی سینسیٹو ایریا ہے۔ فاروق صاحب یہاں کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو چکا ہے اور وہ سعودی عربیا میں جا کر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مسئلہ حل طلب ہے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ کشمیر کے لوگوں کو ساتھ میں رکھ کر کرنا ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بھی بات ہم لوگوں کو منظور نہیں ہے۔ یہ چیز کیا معنے رکھتی ہیں۔ یہ خطرناک بات ان کے منہ سے بد بو نکالتی ہے۔ اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیئے۔ جموں کشمیر بھارت کا ایک حصہ ہے جیسا کہ ابھی کابلی صاحب نے کہا کہ وہاں پر ایک پارلیامینٹری ڈیلیگیشن جانا چاہیئے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جانا چاہیئے۔ یہیں نہیں کہ وہ جموں کشمیر میں جائے وہ لداخ میں بھی جائے اور وہاں کے کونے کونے میں جائے۔ وہاں جا کر دیکھے کہ مائنورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ (انٹرپشنز)

برہمچاری کی بات تو ہر ایک نے کی ہے لیکن وہاں پر ایک دوسری فرم خیرالدین سنز کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کیوں نہیں اس کا نام لیتے ہیں۔ کیا وہاں سے بندوق نہیں پکڑی گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آپ کی یہ پولیٹیکس ہے۔ (انٹرپشنز)

کابلی صاحب نے پرانی ہسٹری کی بات کہی۔ شہید شیروانی کا ذکر کیا جو شہید ہوئے ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے جو کہ بعد میں کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ آپ کی کھچڑی نیشنل کانفرنس ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے یہ ان لوگوں والی نیشنل کانفرنس نہیں تھی۔

شیخ صاحب کی بات بھی کہی کہ وہاں پر قاسم صاحب کو ہٹا کر شیخ صاحب کو لایا گیا۔ شیخ صاحب نے یہ کہا تھا کہ "آئی ول ریٹرن ٹو دی نیشنل مینسٹریم"۔ انہوں نے یہ رکویسٹ کی تھی اور وہ نیشنل اسٹریم میں واپس آنا چاہتے تھے۔ کیا آج نیشنل کانفرنس بھارت کی ایجنسی کی بات کرتی ہے؟

ایسا نہیں کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ سمجھ لیجئے۔ بہت سنجیدگی سے کام لینا چاہیئے۔ کشمیر کے پوزیشن بہت ایکسپلوزو ہے۔ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیئے۔ ڈوگرا صاحب نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ موجودہ کشمیر کی سرکار الیکشن کمیشن کی بھی نہیں مانتی۔ چیف جسٹس کی بات بھی نہیں مانتی۔ سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مانتی ہے۔ لوگوں کی بھلائی کے لئے ہو قانون پاس کرتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ سیدھے بزم کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔

ان شبدوں کے ساتھ میں بہت ہی شکور ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور بیٹھی صاحب کا بھی شکور ہوں کہ جنہوں نے پہلی بار کشمیر کا ذکر اپنے اسٹیٹمنٹ میں کیا۔

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मुझे पहली बार इस सदन में अहसास हो रहा है कि जो अपने को राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग कहते हैं, ट्रेजरी बैंच के लोग कहते हैं उनके दिमाग से राष्ट्रीय विचारधारा खत्म हो गई है और सभी हमारे साथी काबुली जी ने कहा, में उनसे हण्डरेड परसेंट सहमत हूं कि पहला दफा हिन्दूस्तान में कोई मुख्यमन्त्री, जम्मू कश्मीर के मुख्य मन्त्री देश में घूम-घूम कर कह रहे हैं कि मैं मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और पहली दफा हिन्दुस्तान के इतिहास में हमारे ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है इसको कार्नर करने का, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक एग्जापिल मैंने उस दिन भी दिया था, उसको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन क्या कारण है कि आल इण्डिया रेडियो पर एक दिन मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के 8 आदमी जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए। यह बात सवेरे भी आई, दोपहर को भी आई, रात को भी आई। हर न्यूज में कहा गया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हमारे राज नारायण जी एक हजार जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर के निवास स्थान पर गिरफ्तार हुए, लेकिन कोई जिक्र नहीं किया गया।

पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ दिखाया गया, वहां के मुख्य मन्त्री ने इन्क्वारी कमीशनर बिठा दिया। फिर 6 दिन बाद टेलीवीजन में दिखाते हैं कि पाकिस्तान झंडा लहरा रहा है।

यह साबित करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि इस सरकार को सेठी साहब को जब करना होगा तो करने के समय हमसे कभी नहीं पूछेंगे। 1975 में में लोक नायक जय प्रकाश नारायण की गिरफ्तारी की बात चली तो 5 मिनट में गिरफ्तार कर लिया गया। जनता की इच्छा के विरुद्ध गिरफ्तार कर लिया गया। आज आप पूरे हिन्दुस्तान में वहां मुसलमान को बली का बकरा बना रहे हैं, कहां हिन्दू को बली का बकरा बना रहे हैं कहां अपोजीशन को बली का बकरा बना रहे हैं और रोज हमसे सर्टीफिकेट लेते हैं। रोज हमारे नजदीक हमको ही ब्लैकमल किया जाता है। आप क्या चाहतें हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं खालिस्तान के मामले में, पंजाब के मामले में। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार इस मामले में कुछ करने वाली नहीं है। सरकार के सामने सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी है। सरकार भिंडरावाला को गिरफ्तार करेगी उस वक्त जब पूरा देश धू-धू करके जलने लगेगा और इलेक्शन जीतने का मामला आएगा, तब सरकार कार्यवाही करेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं, इस सदन को नोट करवाना चाहता हूं। इस बात को साफ करना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, सेठी साहब ने पहले एक स्टेटमट दिया था। मैं सेठी साहब की बहुत इज्जत करता हूं। बहुत ही गम्भीर आदमी हैं। कितनी ही उनके ऊपर बौछार की जाए, मुस्करा कर सुनते रहते हैं। एक बात कहूंगा कि जब वे जबाब दें तो बात साफ कर दें। उस दिन जब स्टेटमैंट दिया गया था तो उत्तर प्रदेश का नाम भी लिया गया था कि वहां भी कैंप चलाए गए। आज उत्तर प्रदश का नाम निकाल दिया गया। कहां से दबाव पड़ा, क्या दबाव पड़ा कि उत्तर प्रदेश का नाम इसम से निकाल दिया गया और जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा का पूरा हमला किया गया है। मैं सरकार से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक ही बात यदि दरबारा सिंह कहे तो दरबारा सिंह राष्ट्रभक्त और वही बात लोंगोवाल कहे तो वह राष्ट्रद्रोही हो जाता है। एक ही बात यदि भिण्डरावाले करे तो वह राष्ट्रद्रोह हो जाता है, वही बात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी करें तो वह राष्ट्रप्रेमी हो जाता है। नेशनल कांफेंस के लोग देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें तो वे देश-द्रोही हैं। यह सब चलने वाला नहीं है। आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी काग्रेस आई की है, उसको इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। आपके सामने पार्टी, इलैक्शन और देश का मामला है। मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। हमारे साथियों ने कहा कि उग्रवादी और राष्ट्रवादी सिख में कोई अन्तर न रखें। आज जितना सिख समुदाय है, जिसको पकड़ने में आप लोग लगे हुए हैं, वह अपने आपको अपराधी महसूस करता है। यही कारण है कि भिण्डरावाले को उसका लाभ मिल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इन दोनों को जोड़ने का काम मत कीजिए। मैं जनता पार्टी की हैसियत से इस सदन में कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब के लोगों की मांग के साथ हूं। जो एक्स्ट्रीमिस्ट काम है, मैं उसका विरोधी हूं। हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भिंडरावाले जैसे लोगों को पैदा करने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है और आप लोग ही उससे निपट सकते हैं। सत्तारूढ़ दल की है और आप लोग ही उससे निपट सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के पास नीयत नहीं है भले ही रेडियो रात-दिन हिन्दू सेंटीमेंट्स को जगाने का काम करे। जहां तक कारगर कदम उठाने का सवाल है, इनके पास कोई हल नहीं है। गृह मन्त्री जी जब जबाव दें तो ज़रूर इस बात को बता दें कि कितने लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जो मारे गए है या पकड़े गए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। पटियाला, जालन्धर और अमृतसर में जहां जहां आपका खुफिया विभाग काम कर रहा है, जहां हिन्दू हैं, सिख हैं और

सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है वहां इस तरह की कार्यवाही हो रही है। अगर सरकार यह नहीं बताती कि कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया है तो मैं निश्चित रूप से चार्ज लगाता हूं कि इन सारी घटनाओं के पीछे भारत सरकार और कांग्रेस आई हुकूमत का हाथ है। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी नीतियों के कारण आसाम जलकर राख हो गया है और पंजाब जल रहा है और जम्मू-काश्मीर में आप आग लगाने की कोशिश कर रहे है। हम आपके इस नापाक इरादे को चलने नहीं देंगे। आपका पर्दाफाश करेंगे। आप चाहे आज या कल इलैक्शन करवा दें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : Sir, about 13 hon. Members have participated in this debate. Though originally it was a Calling Attention notice, yet the desire of the House was to have a discussion and the Speaker was kind enough to convert it into a discussion under Rule 193.

Now, Sir, as far as my statement is concerned, many of the hon. Members have asked me why I have not given the names and list of the total number of camps. The total number of camps which were held is 14, out of which six were held only in the State of Jammu and Kashmir, two in Himachal Pradesh, three in Punjab, two in Uttar Pradesh and one in West Bengal. So, these constitute the total number of 14 camps which were held. So there is no question of hiding It or deleting Uttar Pradesh.

As far as the training programme is concerned, whatever I have said about the training is that although ostensibly they are intended for training in religious matters, it has beed reported that inflammatory speeches preaching secessionist and sectarian views were made. And it is understood that in some these camps training in arms and working of lathis was imparted and terrorists methods were eulogised. Therefore, this statement which I have given now is based on the latest information. Whatever may be my previous statement, this statement is based on the latest information.

I would again reiterate that it is true that the Chief Minister of Jammu and Kashmir did not go to the camp. But when the camp mates came to see him, he did meet them and hon. Member would not be justified in denying this blatant fact.

As far as States are concerned, we have asked all the State Governments to take proper action in this matter and to watch the situation and to see that no such arms training is given in any of the camps.

As far as the Punjab issue is concerned, I would like to again say, and that I have said in my statement itself, that we are prepared to have a dialogue with them provided it is a meaningful dialogue, provided it is not one-sided affair.

As far as the territorial dispute is concerned, we are prepared to hand over Chandigarh. But the hon. Members of opposition have to state what is their stand on Abohar and Fazilka. If they want to stand by 1970 Award, then Abohar and Fazilka has to go to Haryana. Whatever decision we take should be with the consent of all the parties and the concerned States. We cannot take unilateral decision in this matter.

As far as action against Bhindrawale and other extremists is concerned, it is not proper for me to discuss in this House the details of what the Government will do and intends to do in this matter. These are matters which have to be dealt with at an appropriate level by a competent authority. Therefore, I would request the hon. Members that they should still persuade the Akali Dal to disassociate themselves from the extremists. As the suggestion has come, I would request through this august House. Sant Longowal and Shri Gurucharan Sings Tohra to ask Shri Bhindrawale to leave the premises of Guru Nanak Niwas and surrender himself to the concerned authorities where cases have been registered against him.

I want to thank the hon. Chair and the Members who have participated in the debate. I have carefully taken notes about what they have said and I want to assure that we will do everything possible to maintain the national integrity and national unity.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 6,1983 Agrahayana 15, 1905 (Saka).

Printed at S. Narayan & Sons, 7117/18, Pahari Dhiraj, Delhi-6.